उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड का संबंध बड़े छोटे भाई जैसा

– पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

साम्प्रदायिक आग्रहों की चौड़ी होती खाइयां

मूल्य 30/-

मई, 2022

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह.. संवाद की राह

विश्वयुद्ध व परमाणु युद्ध की आशंका

आपूर्ति शृंखला का टूटना

जलवायु परिवर्तन का संकट : बढ़ता तापमान – पिघलते ग्लेशियर

रुस-यूक्रेन युद्ध व हथियारों की होड़

आर्थिक मंदी

मुद्रा स्फीति – महंगाई – बेरोज़गारी

खाद्य व जल संकट

ड्रग्स, पोर्नोग्राफी व नशाखोरी

बाढ़, सुखाड, चक्रवात, गर्म हवायें चलना व तीव्र लू का बढ़ता क्रम

ख़तरनाक जीवाश्म ईंधन : खनिज तेल, गैस, कोयला व मांसाहार का बढ़ता चलन

कोविड -19
महामारी व लॉकडाउन

जैव विविधता सिकुड़ने, जंगल नष्ट होने व मृदा क्षरण का संकट

माँग आपूर्ति के चक्र का बिगड़ना

देश व दुनिया

महाचुनौतियों का समय

कालाधन, भ्रष्टाचार, नक़ली करेंसी, मनी लॉंडरिंग व घोटाले

प्रदूषण और घटिया, नकली व मिलावटी खाद्य सामग्री

रासायनिक खाद, कीटनाशक व प्लास्टिक के खतरे

धार्मिक व जातीय उन्माद और तनाव

ग़रीबी, विस्थापन, बीमारियां व भुखमरी

Career Magazine

DIALOGUEINDIA

... Dialogue for Change in Education

Portal for Current News & Analysis :
www.dialogueindia.in

राजनीतिक पत्रिका

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह - संवाद की राह

Portal for Career & Competition
www.dialogueindiaacademia.com

6th DIALOGUEINDIA Academia Conclave 2022

New Education Policy and Prospects of Internationalization of India Higher Education

11th DIALOGUE INDIA National Ranking 2022

(For Private Higher Education Institutions in India)

8th DIALOGUE INDIA International Academia Awards 2022

(For Private Higher Education Institutions in India)

Awards

BEST Colleges

1st Week of August, 2022 at New Delhi (India)

INTERNATIONAL AWARD CATEGORIES

- Engineering
- Medical
- Dental
- Law
- Management
- Hotel Management
- Fashion & Design
- Fine Arts
- Pharmacy
- Mass Comm.

Best Colleges / Universities of all categories on Overall / Infrastructure / Placement / Research & Innovation / Upcoming wise.

Best V.C. / Director / Principal of Universities / Institutes / Colleges of India.

Best College / Universities : State / Zone / National wise.

Editor Choice Education Excellency Award.

To Participate in Survey Please log on to our website
dialogueindiaacademia.com

For Business Enquiry Please Contact
dialogueindiaacademia@gmail.com (#08860787583)

विषय सूची

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की वाहक संवाद की राह

मई, 2022

06

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड का संबंध बड़े छोटे भाई जैसा - पुष्कर सिंह धामी - मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

08

साप्रदायिक आग्रहों की चौड़ी होती खाइयां

26

कोरोना की चौथी लहर, कितने तैयार हैं हम?

32

देश व दुनिया
महाचुनौतियों का समय

40

क्या रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग तीसरे विश्वयुद्ध में बदल गई है?

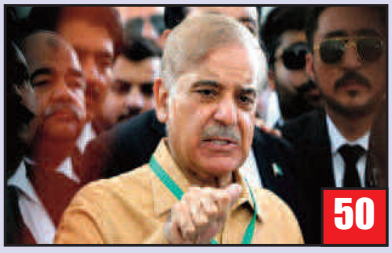
50

शहबाज शरीफ का कश्मीर राग दुर्भाग्यपूर्ण

54

धरती बचाने की अंतिम चेतावनी

66

अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची विश्व खाद्य जिंसों की कीमतें - एफएओ

78

तो हिन्दी से दूर जाती कांग्रेस

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की चाह संवाद की राह

वर्ष- 13 अंक- 9

संपादक
अनुज कुमार अग्रवाल
प्रबंध संपादक
डॉ. सारिका अग्रवाल
विशिष्ट संपादक
अमित त्यागी
विशेष संवाददाता
शरीफ भारती, डॉ. अर्चना पाटिल
आदित्य गोयल, डॉ. यशवंत चौधरी
उप संपादक
नेहा जैन
मुख्य प्रबंधक (डिजिटल मीडिया)
सम्यक अग्रवाल
मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)
विजय कुमार
जन सम्पर्क अधिकारी
पंकज कुशवाहा
ब्यूरोचीफ
उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह
मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया
राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे
उत्तराखंड - रूपक कुमार
महाराष्ट्र - तेजेन्द्र सिंह
दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी
गौतमबुद्ध नगर - मनीष गुप्ता
गाजियाबाद - घनश्याम शर्मा
डिजाइन एवं ग्राफिक्स
विकास, मनीष, दीपक, रजत
मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39
अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन : 011-27652829, 08860787583
फैक्स : 011-27654588
ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in
dialogueindia.in@gmail.com
ई-पत्रिका : www.dialogueindia.in
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित
© सर्वाधिकार सुरक्षित

मई, 2022 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

अस्तित्व के संकट की महाचुनौती

अगर गहराई से देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार मानव व प्रकृति अस्तित्व के इतने घने संकट से गुज़र रहे हैं। जिस भयावह तरीके से कोरोना महामारी दुनिया में आई व काल बनकर लोगों व अर्थव्यवस्था को निगलती गयी उसके बाद भी लाख उपायों व वैक्सीनेशन के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रही , नित नए - नए वेरिएंट के साथ नई लहर पैदा करती रहती है उससे विशेषज्ञों ने भी कहना शुरू कर दिया कि यह बीमारी लंबी चलेगी और इंसानो को इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए।

कुछ ऐसा ही हाल ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तनों का भी है। लालच व स्वार्थ पर टिकी हुई जीडीपी व विकास पर आधारित वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधन के बढ़ रहे अतिशय उपयोग से निकली कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैसों ने पृथ्वी का ताप बढ़ा रखा है और लाख उपायों के बाद भी यह कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। जिस कारण बाढ़ , सुखाड़ व चक्रवात दुनिया भर में आम जीवन का हिस्सा बन गए और अब विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि गर्म पृथ्वी अब सच्चाई है और लोगों को इसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी।

सोवियत संघ के विभाजन के साथ शीत युद्ध समाप्त होने के बाद पिछले बीते तीन दशकों में दुनिया में युद्ध सीमित जो गए थे और हुए भी तो अमेरिका द्वारा इकतरफ़ा सैन्य कार्यवाही अधिक थे। किंतु चालीस लाख करोड़ से अधिक के नुकसान, पचपन लाख लोगों के यूक्रेन छोड़ देने व दो करोड़ लोगों के देश में ही विस्थापित होने व भयंकर तबाही और लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के दो माह से अधिक हो जाने पर भी युद्ध जारी है और अमेरिका व नाटो देश यूक्रेन को अनवरत सैन्य सहायता देते जा रहे हैं, साथ ही यह भी कह रहे हैं कि यह युद्ध कई वर्षों तक चल सकता है और लोगों को युद्ध के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब युद्ध का क्षेत्र मोलदोवा व यूरोप के अन्य देशों तक फैलने की आशंका है।

'इसके बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा किया और कहा- बाहर (यूक्रेन)जो हो रहा है अगर कोई (अमेरिका व नाटो देश) इसमें दखलअंदाजी करने का इरादा रखता है, तो उन्हें पता होना चाहिए ये रूस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे हम बिजली की तेजी से और घातक तरीके से जवाब देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा- हमारे पास इसके लिए सभी जरूरी हथियार हैं। हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जिन पर कोई और घमंड नहीं कर सकता। हम उनके बारे में शेखी नहीं बघारना चाहते, लेकिन हम उनका इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के मामले में दखलअंदाजी करने वाले देश अगर हमें धमकी देते हैं तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी हिचकिचाएगा नहीं।'

पुतिन का यह वक्तव्य दुनिया में अफरातफरी, भय व आशंकाएँ बढ़ाने के लिए पर्याप्त है और बता रहा है कि दुनिया में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो सकता है व उसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग निश्चित है।

देश और दुनिया में एक साधारण इंसान के लिए इन भयंकर चुनौतीपूर्ण वातावरण

में जीवन जीना अत्यंत दुष्कर कार्य है।महामारी , जलवायु परिवर्तन और युद्ध कब उसके जीवन को बर्बाद कर दें या लील जायें उसे पता नहीं है।प्रत्येक मानव के लिए व पृथ्वी के लिए भी यह महा – चुनौतियों का समय है। हर व्यक्ति हर समय विश्व युद्ध व परमाणु युद्ध की आशंका,रुस यूफ्रेन युद्ध व हथियारों की होड़,जलवायु परिवर्तन का संकट = बढ़ता तापमान – पिघलते ग्लेशियर,ख़तरनाक जीवाश्म ईंधन खनिज तेल , गैस, कोयला व मांसाहार का बढ़ता चलन ,खाद्य व जल संकट,आर्थिक मंदी,आपूर्ति श्रृंखला का टूटना,जैव विविधता सिकुड़ने, जंगल नष्ट होने मृदा क्षरण का संकट,माँग आपूर्ति के चफ्र का बिगड़ना,धार्मिक व जातीय उन्माद व तनाव ,मुद्रास्फीति – महंगाई – बेरोज़गारी,ग़रीबी , विस्थापन, बीमारियां व भुखमरी,बाढ़, सुखाड़, चफ्रवात, गर्म हवायें चलना व तीव्र लू का बढ़ता फ्रम ,प्रदूषण व घटिया, नकली व मिलावटी खाद्य सामग्री,कोविड –19 महामारी व लॉकडाउन,ड्रग्स, पोर्नोग्राफ़ी व नशाखोरी,काला धन , भ्रष्टाचार, नक़ली करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग व घोटाले, रासायनिक खादों, कीटनाशकों व प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग जैसी बाह्य चुनौतियों से घिरा है जिससे उसकी मानसिक, शारीरिक व बौधिक के साथ ही आर्थिक व सामाजिक स्थिति बिगड़ रही है।

अगर ध्यान से देखें तो मध्य मार्च से ही देश व दुनिया के दो तिहाई हिस्से में औसत तापमान 4 से 8 डिग्री तक ज्यादा चल रहा है। लगातार बढ़ती तपिश ने रबी की फसलों को एक महीने पहले ही पका दिया या जला दिया। सब्जियों की एक पूरी फसल ही निबट चुकी है। गेहूं छोटे व हल्के पैदा हुए और कुल फसल अलग अलग क्षेत्रों में दस से तीस प्रतिशत तक कम पैदा हुई है। यही हाल सरसों का है। गेहूँ के निर्यात को उत्सुक भारत सरकार अब कितनी फसल बचा पाती है यह वक़्त ही बताएगा क्योंकि गर्मी से पहले की इस गर्मी ने सबकी गर्मी निकाल दी है और अभी मई और जून की गर्मी व जुलाई ,अगस्त व सितंबर की उमस भी बाक़ी है। यूँ तो मौसम विभाग कह रहा है कि देश में सामान्य मानसून रहेगा किंतु यह बात छुपा दी कि ऐसा कई बार होगा कि ढेर सारी बारिश कुछ ही समय में ताबड़तोड़ तरीके से ही हो जाएगी व बड़ा समय सूखा ही निकल जाएगा। कुछ वैसा ही जैसा केलिफ़ोर्निया, कुलालमपुर, ब्रिसबेन अमेरिका, यूरोप ,चीन, ब्राज़ील व भारत के अनेक हिस्सों जैसे सैकड़ों शहरों में पिछले दो वर्षों में हुआ और दक्षिण अफ्रीका के डरबन सहित अनेक भागों में इन दिनों चल रहा है। यह खेल लाखों करोड़ रुपयों व जान माल की बर्बादी कर रहा है। सूखे के साथ आग और बारिश के साथ बाढ़ अब आम हो गया है और दिनों दिन बढ़ रहा है। भारत व दुनिया गहरे खाद्य व जल संकट के चफ्रव्यूह में फँसती–धंसती जा रही है जो हर दिन के साथ बढ़ता जाएगा। कोरोना महामारी और रूस –यूफ्रेन युद्ध के कारण पहले से ही दुनिया उत्पादन व वितरण यानी माँग व आपूर्ति श्रृंखला टूटने के कारण वस्तुओं व जिंसों की कमी व महंगाई से जूझ रही है। पिछले दो वर्षों में हर चीज़ की कीमत डेढ़ से दो गुनी हो गई हैं। लोगों की आमदनी घटती जा रही है और वे कुपोषण, मानसिक व शारीरिक बीमारियों, गरीबी, बेरोजगारी व असमय मौत के शिकार हो रहे हैं। अनेक देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर गहराएगा यह सभी समस्याएं और तीव्रता से बढ़ेगी और दुनिया भयंकर अराजकता के चफ्र में फँसती जाएगी। इस संकट के मूल में खनिज तेल , गैस, कोयला व मांसाहार के साथ ही केमिकल , खाद , कीटनाशकों, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि का प्रयोग व अय्याशी पूर्ण जीवन शैली है। दुनिया की आधी मिट्टी, जैव विविधता , पशु, पक्षी नष्ट हो चुके है व शेष तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इन संकटो के कारण इस वर्ष के अंत तक दुनिया के तीन सौ करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएँगे।ग्रीन एनर्जी का प्रयोग व जैविक कृषि अपनाने व खनिज तेल , गैस, कोयला व मांसाहार के साथ ही केमिकल , खाद , कीटनाशकों, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि से तुरंत मुक्ति से ही मानव सभ्यता के बचने की कुछ संभावना है।

इन भयावह परिस्थितियों में भारत क्या कर सकता है? दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री जयशंकर ने जितनी तेज़ी से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को उभारा है वह प्रशंसनीय है। भारत आज बड़ी क्षेत्रीय शक्ति है जिसका सभी बड़े देशों से संबंध व सहयोग है और विभिन्न गुटों से संतुलन भी। अगर वह वैकल्पिक वैश्विक दृष्टि व प्रकृति केंद्रित जीवन शैली जो भारत की सनातन संस्कृति में आदिकाल से रही है को नए परिप्रेक्ष्य में परिमार्जित कर उपरोक्त सभी समस्याओं के रामबाण इलाज के रूप में स्वीकृत करवा उनका अनुपालन करवा पाया तो ही मानव व पृथ्वी अस्तित्व के संकट से उभर पाएँगे।प्रधानमंत्री मोदी जी शीघ्र ही जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएँगे व दूसरे भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे व इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता 24 मई को जापान में होने वाले फ्राड शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं।इसके साथ ही आस्ट्रेलिया, जापान , ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों से भी उनकी मुलाकात होगी। व फ्राड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे । अपनी इन यात्राओं का उपयोग वे विश्व जनमानस को मौजूदा चुनौतियों से निपटने में भारत के दृष्टिकोण से सहमत कराने में कर सकते हैं। अन्यथा पृथ्वी पर मानव जीवन की यह अंतिम सदी हो सकती है।

अनुज अग्रवाल
संपादक

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड का संबंध बड़े छोटे भाई जैसा

- पुष्कर सिंह धामी - मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत कम समय में लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज से एक साल पहले उत्तराखंड में भाजपा के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं दिख रही थी। पार्टी के अंदर की अंतर्कलह और संगठन की दरारे किसी से छिपी नहीं थी। इसके बाद जब धामी को मुख्य मंत्री के रूप में लाया गया तब ऐसा लगा जैसे भाजपा केवल मुख्यमंत्री बदलती रहेगी और कांग्रेस हाथ मार लेगी। किन्तु धामी ने आते ही जिस तरह युवाओं के मन में जगह बनाई। ताबड़तोड़ फैसले लिए उसके बाद तो भाजपा को एक संजीवनी मिल गयी। धामी ने भाजपा की दुबारा सत्ता में वापसी भी करा दी किन्तु पार्टी के अंदर छिपे विभीषणों के कारण वह स्वयं का चुनाव हार गए। अब वह चंपावत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर उनके द्वारा की गयी पहल ने उन्हे योगी की तरह का नेता साबित करने की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी से डाइलॉग इंडिया के विशिष्ट संपादक अमित त्यागी ने सहयोगी अभिषेक सिंह के माध्यम से सवाल जवाब किए।

चुनाव हारने के बाद भी आप मुख्यमंत्री बनें, क्या प्राथमिकताओं में कुछ बदलाव आया है?

जब मैंने प्रथम बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय ही हमारी सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने को लेकर है, और सभी विभाग इस विजन को सामने रखकर कार्य करने के प्रति संकल्पित है। हम विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

भाजपा की अंतर्कलह ने पार्टी के साथ साथ आपको भी नुकसान किया है। क्या कठोर निर्णयों की कोई योजना है?

हर चुनाव की अपनी परिस्थितियां होती हैं और वही परिस्थितियां जीत और हार के अंतर को पैदा करती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक

लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम व प्रत्येक चुनाव की समीक्षा की जाती है। पार्टी अपने लक्ष्य के प्रति एकजुट है और अंतर्कलह जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की मिसाल है कि हमारी पार्टी में बड़े से बड़े बदलाव भी कार्यकर्ताओं द्वारा सहर्ष स्वीकार किए जाते हैं।

गढ़वाल और कुमायूं की फेर में फंसी उत्तराखंड की राजनीति को आप एक सूत्र में कैसे जोड़ेंगे ?

इसका उत्तर तो चुनाव परिणामों ने स्वयं ही दे दिया है। पूरे उत्तराखंड ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और यह इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की जनता केवल और केवल विकासपरक राजनीति देखना चाहती है।

उत्तराखण्ड सनातन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, क्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलकर किसी योजना पर काम करेंगे?

मैंने सदैव कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का संबंध बड़े भाई और छोटे भाई जैसा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम से लेकर अयोध्या, मथुरा और काशी विश्वनाथ धाम तक सनातन आस्था के अनेकों पूजनीय स्थल देवभूमि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं। सनातन संस्कृति अक्षुण्ण रहे व इसका प्रसार बड़े स्तर पर हो, इसको लेकर मिलजुल कर ही कार्य किया जाना चाहिये।

आप बहुत कम समय मे देश मे उत्तराखण्ड का चेहरा बन गये हैं। 2024 में कितना जादू दिखा पाएंगे?

देखिए चेहरा बनने जैसी कोई बात नहीं है। यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने तथा हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस बार इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार प्रदेश की सत्ता की बागडोर सौंपी है। मैं इस पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका को एक समर्पित कार्यकर्ता से अधिक कुछ भी नहीं समझता हूं। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनावों की बात है तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी तथा उत्तराखंड की सभी पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी।

योगी और मोदी में आपको कौन ज़्यादा पसंद है?

(हंसकर) यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि यहां पर आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। क्या कांग्रेस में कभी कोई यह पूछ सकता है कि आपको गांधी परिवार के अतिरिक्त कोई और पसंद है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई पूछ सकता है कि उनको मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के अतिरिक्त कोई पसंद है? क्या अन्य दलों ने आपको यह सुविधा प्रदान की है कि आप ऐसे सवाल पूछ सकें। आप नहीं पूछ सकते क्योंकि वहां पर कोई विकल्प नहीं है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यहां पर बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है और हम सभी उस दी गई भूमिका का सम्यक निर्वहन करते हैं। इसी कारण हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां के समान है। हम सभी इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंग है और परिवार में कम और ज्यादा जैसी कोई बात होती नहीं है। ■

साम्प्रदायिक आग्रहों की चौड़ी होती खाइयां

● ललित गर्ग

समस्याएं अनेक हैं। बात कहां से शुरू की जाए। खो भी बहुत चुके हैं और खोने की रफ्तार तीव्र से तीव्रत्तर होती जा रही है जिनकी भरपाई मुश्किल है। भाईचारा, सद्भाव, निष्ठा, विश्वास, करुणा यानि कि जीवन मूल्य खो रहे हैं। मूल्य अक्षर नहीं होते, संस्कार होते हैं, आचरण होते हैं। हम अपने आदर्शों एवं मूल्यों को खोते ही जा रहे हैं, एक बार फिर रामनवमी और हनुमान जयंति के अवसरों पर देश के कई प्रदेशों में हिंसा, नफरत, द्वेष और तोड़-फोड़ के दृश्य देखे गए। उत्तर भारत के प्रांतों के अलावा ऐसी घटनाएं दक्षिण और पूर्व के प्रांतों में भी हुईं। ऐसे सांप्रदायिक दंगें और खून का बहना कांग्रेस के शासन में होता रहा, लेकिन पिछले एक दशक में ऐसी हिंसात्मक साम्प्रदायिक घटनाएं पहली बार कई प्रदेशों में एक साथ हुई है, ऐसा होना काफी चिंता का विषय है।

उन्माद, अविश्वास, राजनैतिक अनैतिकता और दमन एवं संदेह का वातावरण एकाएक उत्पन्न हुआ है। उसे शीघ्र दूर करना होगा। ऐसी अनिश्चय और भय की स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए संकट की परिचायक है और इन संकटों को समाप्त करने की दृष्टि से देश के कई राज्यों में घटी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसलों का महत्व समझा जा सकता है। योगी सख्त प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं और उनके ताजा निर्देश इस बात इंगित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि नए धार्मिक जुलूसों की इजाजत न दी जाए और न ही नए धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की। पारंपरिक जुलूसों और शोभायात्राओं के संदर्भ में भी उन्होंने तय मानदंडों का हरहाल में पालन कराने का निर्देश दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि आस्था नितांत निजी विषय है और देश का कानून अपने सभी नागरिकों को उपासना की आजादी देता है। लेकिन आस्था जब प्रतिस्पद्धा में तब्दील होने लगे, तब वह कानून के दायरे में भी आ जाती है।

पिछली सरकारें समाधान के लिए कदम उठाने में भले ही राजनीति नफा-नुकसान के गणित को देखते हुए भय महसूस करती रही हो, उन्हें सत्ता से विमुख हो जाने का डर सताता रहा हो। लेकिन योगी और मोदी इन भयों से ऊपर उठकर कठोर एवं साहसिक निर्णय ले रहे हैं, यही कारण है कि साम्प्रदायिक नफरत, हिंसा एवं द्वेष फैलाने वाले समय रहते पृष्ठभूमि में जाते देखे गये हैं। क्योंकि यदि इस तरह के दायित्व से विमुख हुए तो देश के नागरिक युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। लोकतंत्र में साम्प्रदायिकता, जातीयता, हिंसा एवं अराजकता जैसे उपाय किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। इस मौलिक सत्य व सिद्धांत की जानकारी से आज का नेतृत्व वर्ग भलीभांति भिज्ञ है, यही इस राष्ट्र की एकता और अखण्डता को जीवंतता दे सकेगा।

बहुधर्मी भारतीय समाज में पूजा-इबादत की विविधता इसके सांस्कृतिक सौंदर्य का अटूट हिस्सा है और दुनिया इसकी मिसालें भी देती रही है और यही इस राष्ट्र की ताकत भी रहा है। यह विशेषता एकाएक हासिल नहीं हुई, समाज ने सहस्राब्दियों में इसको अर्जित किया है। लेकिन आजाद भारत में कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक नफरत एवं द्वेष की तल्ख घटनाओं को कुरेदने की राजनीति से भाईचारे की संस्कृति को चोट पहुंचाई जा रही है। स्वार्थ एवं संकीर्णता की राजनीति से देश का चरित्र धुंधला रहा है। सत्ता के मोह ने, वोट के मोह ने शायद उनके विवेक का अपहरण कर लिया है। कहीं कोई स्वयं शेर पर सवार हो चुका है तो कहीं किसी नेवले ने सांप को पकड़ लिया है। न शेर पर से उतरते बनता है, न सांप को छोड़ते बनता है।

धरती पुत्र, जनक रक्षक, पिछड़ों के मसीहा और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर का मुखौटा लगाने वाले आज जन विश्वास का हनन करने लगे हैं। जनादेश की परिभाषा अपनी सुविधानुसार करने लगे हैं। कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता, कोई किसी का

जहांगीरपुरी बवाल में बांग्लादेशियों के 'हाथ' को भी देखिए

इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई तो उस दौर में राजधानी दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले हजारों लाखों लोगों को उनके घरों से उजाड़कर अलग-अलग जगहों में बसाया गया था। उसमें उत्तर-पश्चिम दिल्ली का जहांगीरपुरी नाम का इलाका भी था। उसे इन अभागे लोगों के लिए ही बसाया गया। इधर मुख्य रूप से नई दिल्ली तथा साउथ दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वालों को उठाकर ले जाया गया था। ये अधिकतर वाल्मिकी या धोबी समाज से थे। वक्त बदला तो जहांगीरपुरी में आबादी का चरित्र बदलने लगा। यहां पर ज्यादातर आ गए बांग्लादेशी मुसलमान। ये यहां पर कच्ची शराब बनाने से लेकर सट्टेबाजी के धंधे में लग गए। इन्होंने कभी शांत समझे जाने वाले जहांगीरपुरी में छोटे-मोटे अपराध करने भी शुरू कर दिए। जहांगीरपुरी में रोज क्लेश होने लगा। इनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। दिल्ली के लोकप्रिय नेता मदन लाल खुराना भी राजधानी में बांग्लादेशियों की बढ़ती हुई जनसंख्या से डरे-सहमे हुए रहते थे। वे बार-बार कहते थे कि इनको दोनों देशों की सीमा पार करके यहां आने की इजाजत नहीं मिले। पर यह हो न सका। खुराना जी तो संसार से चल गए और बांग्लादेशी दिल्ली और देश के दूसरे भागों में आते रहे।

खैर, जहांगीरपुरी की आबादी के चरित्र किस हद तक बदला, इसका पता चला जब हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकली शोभा यात्रा के वक्त कसकर बवाल काटा इन बांग्लादेशियों ने। वैसे ये अपने को पश्चिमी बंगाल का ही नागरिक बताते हैं। हालांकि जन्नत की हकीकत कुछ और है। इन्होंने हनुमान जन्मोत्सव मना रहे एक जुलूस पर ताबड़-तोड़ हमला करने के बाद यहां तक झूठ आरोप मढ़ दिया कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने एक मस्जिद पर अपना झंडा भी लगाने की कोशिश की थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की तफ्तीश से यह साफ हो गया है कि मस्जिद पर झंडा लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई। जहांगीरपुर में हुई हिंसा के लिए जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, वे लगभग सब बांग्लादेशी मुसलमान हैं।

अब जरा गौर करें कि इन देश विरोधी तत्वों को साथ मिल रहे हैं कुछ कथित नामवर बुद्धिजीवी भी। उनमें पत्रकार राणा अयूब भी हैं। दरअसल जहांगीर पुरी में हुई हिंसा के बाद एक वीडियो पर राणा अयूब ने ट्वीट किया तो जानी मानी पूर्व अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी और कोच मार्टिना नवरातिलोवा ने भी उनका समर्थन किया।

राणा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि, 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस वीडियो को देखें। हिंदू कट्टरपंथी पिस्टल और हथियार लहराते हुए एक मस्जिद के आगे से गुजर रहे हैं। और क्या होता है? 14 मुसलमानों को गिरफ्तार करके आरोपी बनाया गया है। यह सब नरेंद्र मोदी के निवास से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है।' यह वही राणा हैं जिन पर हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया था कि वह एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि को लेकर गंभीर अपराध में संलिप्त हैं। यह केस फिलहाल कोर्ट में है। राणा को पिछली 29 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। वह 29 मार्च को लंदन जाने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची थी । लंदन में वह महिला पत्रकारों पर साइबर हमलों की वैश्विक समस्या पर कार्यक्रम में शामिल होने वाली थीं। अब गौर करें कि इतनी संदिग्ध छवि वाली राणा अनाप-शनाप ट्वीट कर रही हैं। उस पर एक महान टेनिस खिलाड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। यानी जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में हुए बवाल का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश की इज्जत तार-तार हो गई। राणा के प्रति सम्मान का भाव तो तब जागता अगर वह जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी मुसलमानों की करतूतों पर भी ट्वीट करती। लेकिन वह यह क्यों करेंगी।

जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में बांग्लादेशियों का रोल धीरे-धीरे सामने आ रहा है। बेशक, उस दिन की हिंसा में जो शामिल हैं उन्हें कठोर दंड मिले। देखिए राजधानी दिल्ली में एक अनुमान के अनुसार, बांग्लादेशियों की आबादी 5 लाख तक हो गई है। ये लगातार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। याद करें जब कुछ साल पहले राजधानी के विकासपुरी में बांग्लादेशी गुंडों ने डॉ.पंकज नारंग का कत्ल कर दिया था। डॉ.पंकज नारंग की हत्या से सारी दिल्ली सहम गई थी। ज़िन्दगी बचाने वाले डॉक्टर की सरेआम हत्या कर दी गई, पर तब राणा अयूब या कोई अन्य 'सुबुद्धिजीवी' नहीं बोला था। तब कहां गई थी असहिष्णुता? जहांगीरपुरी की घटना पर केन्द्र सरकार तथा पुलिस की निंदा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डॉ. पंकज नारंग के घर जाने की जरूरत नहीं समझी थी। क्या किसी सेक्युलरवादी ने उनकी पत्नी, बेटे और विधवा मां से पूछा कि उनकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है? उस अभागे डाक्टर का कसूर इतना ही था कि उन्होंने कुछ युवकों को तेज मोटर साइकिल चलाने से रोका था। बस इतनी सी बात के बाद बांग्लादशी युवकों ने डॉ. पंकज नारंग का कत्ल कर दिया था। देखिए सरकार को बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या घुसपैठियों के मसले पर गौर करना होगा। इस पर सिर्फ चिंता जाहिर करना पर्याप्त नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इन्हें इनके मुल्क में वापस भेजा जा सकता है। पर इनकी हरकतों पर लगाम तो लगाई ही जा सकती है ताकि भविष्य में फिर से जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं न हों। कुछ सियासी दल बांग्लादेशियों के खिलाफ राजनीतिक लाभ या कहें कि वोट बैंक की राजनीति के चलते सामने नहीं आते। इसलिए सरकार को अब सियासत और वोट बैंक की परवाह किए बिना इन घुसपैठी बांग्लादेशियों को तो कसना ही होगा। यही नहीं भारत-बांग्लादेश की सीमा को सील भी करना होगा ताकि ये भारत में घुस न पाएं। इस लिहाज से अब और ढील नहीं दी जा सकती है। एक और अहम बात यह भी है कि उन तत्वों को भी न छोड़ा जाए जो बिना पुलिस की अनुमति के ही शोभा यात्रा निकालने लगते हैं। कानून तो सबके लिये समान है और समान रूप से ही लागू होना चाहिये।

आर.के. सिन्हा
(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

जिसका बुलडोजर, उसका सच

मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाज़ी की तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। घटना के अगले ही दिन जिन घरों से ऐसी पत्थरबाज़ी हुई उन्हें बुलडोज़र से गिरा दिया गया। तर्क दिया गया कि ये सारे अवैध निर्माण थे। कुछ लोगों ने सरकार की इस कठोर कार्रवाई का समर्थन किया, तो कुछ ने इस कार्रवाई को कानून सम्मत नहीं माना।

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब इस बारे में एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका जवाब था कि हमने कानून के मुताबिक ही ये किया है। हालांकि वो ये नहीं बता पाए किस कानून के तहत सरकार को ये अधिकार है कि वो बिना अदालत गए खुद ही कार्रवाई कर दे। उल्टा वो ये पूछने लगे कि जिन दंगाइयों ने ये सब किया है आप उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है।

जब एंकर ने उनसे ये पूछा कि आपने कैसे पता लगाया कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं? तो उनका जवाब था कि तस्वीरों में सब साफ दिख रहा है! इसके बाद एक-आध सवाल और हुआ और बातचीत ख़त्म हो गई। लेकिन मिश्रा साहब का 'तस्वीरो में सब साफ दिख रहा है' वाला जवाब अब भी मेरे ज़हन में कौंध रहा था।

मैं सोचने लगा कि अगर तस्वीरों में दिखने भर से सरकारों को Instant इंसाफ की छूट मिल जाती है तो इस हिसाब से अजमल आमिर कसाब को तो अगले दिन ही फांसी हो जानी चाहिए थी। यहां तो मामला साम्प्रदायिक हिंसा में कुछ लोगों के घायल होने और पत्थरबाज़ी का था। लेकिन 26/11 को मुम्बई पर हुआ आतंकी हमला तो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। यहां तो हिंसा में शामिल लोग अपने देश के थे, कसाब तो था भी पाकिस्तानी। फिर भी भारत सरकार ने Instant इंसाफ करते हुए फांसी देने के उसे वकील रखने की छूट दी। सालों साल अदालत में उस पर मुकदमा चला। दोषी साबित होने पर उसने ऊपरी अदालत में अपील भी की। वहां भी सजा कम नहीं हुई, राष्ट्रपति के पास माफी का आवेदन भी भेजा और जब वो दया याचिका भी खारिज हो गई तब जाकर उसको फांसी हुई।

इन सारी बातों का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न, अपराधी के खिलाफ जनता का गुस्सा कितना ज़्यादा क्यों न हो, उसके अपराध में शामिल होने के सबूत कितने भी साफ क्यों न हो लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में चीजें कानून के मुताबिक ही चलती हैं। सबूत के फुटेज कितने भी साफ क्यों न हों, लेकिन उन सबूतों को देखकर अदालत फैसला करती हैं न कि सरकार!

दूसरी बात जो समझने की है कि वो ये कि नागरिक भले ही अपने आचरण में कितना गुस्सा दिखाएं, गैरजिम्मेदार हो जाएं लेकिन सरकार को ये छूट नहीं होती कि वो बदले की कार्रवाई करती दिखे। जैसे किसान आंदोलन के दौरान हुआ। केंद्र सरकार भले ही कितनी आश्वस्त थी कि कृषि कानून सही हैं। उसके

पास इस बात के भी सबूत थे कि कुछ अलगाववादी तत्व इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। हर कोई ये भी देख रहा था कि कैसे आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने रास्ते रोककर शहरों को बंधक बना लिया था। लेकिन इस सबके बावजूद सरकार ने आखिरी वक्त तक उनसे बात करके ही रास्ता निकालने की कोशिश की, न कि गैर कानूनी तरीके से रास्ता रोकने को बहाना बनाकर उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। सरकारों के पास ताकत होती है। ये ताकत उन्हें जिम्मेदारी बनाती हैं। वो जनता के लिए चुनी गई होती हैं। इसलिए उसी जनता में से कुछ लोग हिंसक क्यों न हो जाएं, सरकार खुद माफिया बनकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। उसी तरह कश्मीर में भारत विरोधी कितने भी आंदोलन क्यों न हो जाएं। इन आंदोलनों में आम आदमी की भागीदारी भी कितनी भी स्पष्ट क्यों न हो लेकिन हर भारत सरकार कश्मीरियों को साथ लेकर चलने की वकालत ही करती है न कि ऐसे आंदोलनों की दुहाई देकर जनता को गाली देने लगती है। मतलब जनता और सरकार के बीच ये ऐसा रिश्ता है जिसमें जनता भले ही दगाबाज हो जाए, असंयमी हो जाए, उपद्रवी भी क्यों न हो जाए लेकिन सरकार कभी अपनी बड़प्पन नहीं छोड़ती। वो अपने ही लोगों से बराबरी पर आकर बदले नहीं लेने लगती।

इसलिए रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की तस्वीरें भले ही कितनी साफ थीं लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी तरह से कानून का पालन ही करना चाहिए था।

यहां ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई करते वक्त शायद सरकारें भी जानती है कि ये कानून सम्मत नहीं। लेकिन उसे भी शायद पता होता है कि ऐसे बुलडोजरिय न्याय पर उसका वोट बैंक ताली बजाएगा। वो वाह वाह कर उठेगा...वो कहेगा कि ये लोग इसी लायक हैं। बेशक लोकतंत्र में अपने वोट बैंक का ऐसा समर्थन किसी भी सरकार को आत्मविश्वास देता है मगर इस समर्थन के गुरूर में उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र और कमर्शियल सिनेमा में फर्क होता है।

जनता तो पोर्न देखकर भी बड़ा खुश होती है। उत्तेजना महसूस करती है। उसे तो फिल्मों में हिंसा भी बड़ी अच्छी लगती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसी जनता को उत्तेजित करने के लिए वो अपने व्यवहार में अश्लील होती जाए। ये अश्लीलता जनता को पसंद जरूर आएगी। वो सीटियां जरूर बजाएगी। चुनावी जीत के तौर पर आपकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छी होगी। लेकिन उसे ये नहीं भूलना सिनेमा की सफलता इस पर है कि आप जनता

से कितना अच्छा कलेक्शन करते हैं और सरकारों की इस पर कि वो जनता से कितना अच्छा कनेक्शन करती है।

कुछ सवाल 'पीड़ितों' से

लेकिन सरकारी कार्रवाई इस पूरे मामले का एक पहलू हैं। अगर इस मामले में हम 'पीड़ितों' से कुछ सवाल नहीं करेंगे तो शायद चर्चा अपने जायज अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसी 'पीड़ित' जनता से मेरा कहना है कि जब आपका असली सरोकार इंसाफ न होकर अपने दुश्मन से बदला लेना हो, तो फिर आप शिकायत करना बंद कर दीजिए। मसलन शिवसेना से विवाद के बाद जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया, तो 'सामना' में बड़ी बेशर्मी से छापा गया... गिरा दिया! और विडंबना देखिए जो लोग आज बुलडोजर न्याय से सबसे ज़्यादा आहत हैं, उसे गलत बता रहे हैं। कंगना के दफ्तर गिराए जाने पर सबसे ज़्यादा चटकारे इन्हीं लोगों ने लिए थे। जिन्होने चटकारे नहीं भी लिए वो जानबूझकर खामोश रहे क्योंकि वो अंदर ही अंदर मानते थे कि 'कंगना जैसी' के साथ ऐसा ही होना चाहिए था।

तब उनमें से शायद ही किसी ने सवाल किया कि अगर कंगना के ऑफिस का एक हिस्सा अवैध था, तो क्या उसे गिराने के लिए इस विवाद का इंतजार किया जा रहा था। नहीं, तब ये लोग या तो जश्न मना रहे या खामोश थे, क्योंकि वो मानते थे ठीक हुआ!

इसी तरह पैगम्बर साहब को लेकर कथित टिप्पणी पर जब दिनदिहाड़े कमलेश तिवारी का गला रेत दिया गया, तब इन्हीं लोगों में से किसी ने इसकी आलोचना नहीं की। तब भी या तो ज़्यादातर लोग खामोश थे या चुपचाप जश्न मना रहे थे। तब भी किसी ने नहीं कहा कि अगर कमलेश तिवारी ने कुछ आपत्तिजनक कहा भी है, तो उसका फैसला अदालत को करने देते। किसी ने हत्यारों की आलोचना करते हुए ये नहीं कहा कि उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था।

यहां तक कि हिजाब विवाद पर जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने मनमाना फैसला नहीं सुनाया, तब भी ज्यादातर मुस्लिम विचारकों, नेताओं ने यही कहा कि जजों को कुरान के रास्ते में आने का कोई हक नहीं। तब किसी ने नहीं कहा कि अगर एक बार अदालत ने फैसला सुना दिया है तो ये चर्चा यहीं खत्म हो जानी चाहिए। इसी तरह अफजल गुरू से लेकर याकूब मेमन की फांसी तक अदालतों के खिलाफ क्या टिप्पणी की गईं ये सब जनता के सामने हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये टिप्पणियां किसी राह चलते ने की हों, ये सब वरिष्ठ संपादकों, पत्रकारों, मुस्लिम बुद्धिजीवियों और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की गईं। की गईं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अदालत के सही होने के बावजूद उनकी टारगेट ऑडियंस, उनका टारगेट वोटर, उनके ट्विटर फॉलोअर्स यूट्यूब ऑडियंस यही सुनना चाहती है। जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को लग रहा हो कि भले ही ये सब कानून सम्मत नहीं है लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस यही सब देखना चाहती है।

और ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि 'अपनी जनता' को प्रसन्न करने की इस सोच ने ही इस देश की राजनीति से लेकर बौद्धिक वर्ग को मक्कार बना दिया है। आज इस वर्ग की जिम्मेदारी सच के प्रति न होकर अपनी टारगेट ऑडियंस को हरदम खुश करते रहने की है। फिर भले ही उसके लिए कुछ सच नजरअंदाज करने पड़े। कुछ जुल्मों पर चुप रहना पड़े।

क्या आपने गौर किया है कि कोई फिल्म आपको कितनी भी अच्छी क्यों न लगती हो लेकिन आप एक से दूसरी, तीसरी बार देखने पर उससे भी ऊबने लगते हैं। एक बार थिएटर से फिल्म उतर जाती है तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो दोबारा रिलीज हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक-एक घटना से परिचित होने के बावजूद, एक-एक अध्याय जानने के बावजूद, क्यों हर साल देश के हर गली-नुक्कड़ में रामलीलाओं का मंचन होता है। वो हर साल पूरे देश में उसी उत्साह से रिलीज हो जाती है!

क्या वजह है कि एक समाज के तौर पर हम आज भी उससे बोर नहीं होते। उससे ऊबते नहीं है। वो आज भी ताजा भी उतनी ही ताजा बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि रामायण में किसी 'टारगेट ऑडियंस' को खुश करने की कोशिश नही की गई। उसमें जनता को उत्तेजित करने के लिए कोई झूठ नहीं बुना गया। वो उत्तेजना की नहीं, नीति की बात करती है। वो किसी लोकप्रिय झूठ पर नहीं, निरपेक्ष सच पर आधारित है। और असल सच हमेशा समय हीन होता है इसलिए उसकी पुनरावृति हमें कभी बोर नहीं करती! मगर जिन सरकारों की इकलौती चिंता अगली चुनावी जीत और जिन बौद्धिकों का असली कंसर्न अगले यूट्यूब वीडियो का धमाकेदार थंब हो, वो ऐसे किसी सच के झंझट में नहीं पड़ते और यही आज बड़ी चिंता है। समाज अगर यूं ही 'लोकप्रिय इंसाफ' की तरफ बढ़ता रहा तो अगला बुलडोजर अदालत पर चलेगा!

निर्माता नहीं होता-भारतीय संस्कृति के इस मूलमंत्र को समझने की शक्ति भले ही वर्तमान के इन तथाकथित राजनीतिज्ञों में न हो, पर इस नासमझी से सत्य का अंत तो नहीं हो सकता। अंत तो उसका होता है जो सत्य का विरोधी है, अंत तो उसका होता है जो जनभावना के साथ विश्वासघात करता है। जनमत एवं जन विश्वास तो दिव्य शक्ति है। उसका उपयोग आदर्शों, सिद्धांतों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए हो।

तभी अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। तभी होगा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। तभी होगी अपनत्व और विश्वास की पुन: प्रतिष्ठा। तभी साम्प्रदायिकता के अंधेरा को दूर किया जा सकेगा। वरना ईमानदारी की लक्ष्मण रेखा जिसने भी लांघी, वक्त के रावण ने उसे उठा लिया।

कैसी विडम्बना है कि इस तरह के सांप्रदायिक दंगे और हिंसात्मक घटना-क्रम का आरोप भाजपा लगाया जाता है, जबकि कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों और समाजवादियों ने अपने गिरते राजनीतिक वर्चस्व के कारण इन सब घटनाओं को अंजाम दिया हैं। भला कोई भी सत्ताधारी पार्टी ऐसे दंगों एवं साम्प्रदायिक हिंसा को अंजाम देकर अपनी शासन-व्यवस्था पर क्यों दाग लगायेगी? इस देश की बढ़ती साख एवं राष्ट्रीयता को गिराने की मंशा रखने वाले राजनीतिक दलों एवं समुदायों का यह स्थायी चरित्र बन गया है कि वे अपने राष्ट्र से भी कहीं ज्यादा महत्व अपने स्वार्थ, अपनी जात और अपने मज़हब को देते हैं। 1947 के बाद जिस नए शक्तिशाली और एकात्म राष्ट्र का हमें निर्माण करना था, उस सपने का इन संकीर्ण एवं साम्प्रदायिक दलों की राजनीति ने चूरा-चूरा कर दिया। थोक वोट के लालच में सभी राजनीतिक दल जातिवाद और सांप्रदायिकता का सहारा लेने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। जो कोई अपनी जात और मजहब को बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें उसकी पूरी आजादी होनी चाहिए लेकिन उनके नाम पर घृणा फैलाना, ऊंच-नीच को बढ़ाना, दंगे और तोड़-फोड़ करना कहां तक उचित है? यही प्रवृत्ति देश में पनपती रही तो भौगोलिक दृष्टि से तो भारत एक ही रहेगा लेकिन मानसिक दृष्टि से उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। यह खंड-खंड में बंटा भारत क्या कभी महाशक्ति बन सकेगा? क्या वह अपनी गरीबी दूर कर सकेगा? क्या वह विकास योजनाओं

जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग और ओखला में भी चलेगा बुलडोजर, बनाई जा रही इलाकों की सूची

दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सूत्रों की मानें तो निगम अधिकारियों को सूचना मिली है कि कबाड़ के काम की आड़ में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना तय है।

जहांगीरपुरी इलाके के बाद दक्षिणी दिल्ली के ओखला और शाहीन बाग इलाके में भी नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municipal Corporation) ने तैयारी कर ली है। कुछ ही दिनों में यह कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए कार्रवाई का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। उन इलाकों की सूची तैयार की जा रही है जहां पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना है।

ईस बाबत दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सूत्रों की मानें तो निगम अधिकारियों को ओखला और शाहीन बाग समेत छह से ज्यादा इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी मिली है, जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा कबाड़ के काम की आड़ में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के साथ-साथ अवैध निर्माण और लूट और झपटमारी की जितनी घटनाएं हो रही हैं, उनमें भी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का हाथ होता है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से न केवल अवैध और अतिक्रमण पर लगाम लगेगी, बल्कि अपराध में भी कमी आएगी।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के समय दक्षिणी दिल्ली इलाके में जो उपद्रव हुआ था उसमें भी बड़ी संख्या में शाहीन बाग और ओखला में रहने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम के शामिल होने की बात आई थी।

'रोहिंग्या को भगाने के लिए भाजपा करेगी आंदोलन'

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भाजपा दिल्ली सरकार पर दबाव बनाएगी। इसे लेकर भाजपा जल्द ही आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के समर्थन से घुसपैठिये राजधानी में जगह-जगह अतिक्रमण किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगमों को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए तीनों निगमों को पत्र लिखकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है।

आदेश गुप्ता ने प्रेसवार्ता में कहा, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना किसी पूर्व नोटिस के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो सकती है। जहांगीरपुरी में निगम सात बार कार्रवाई कर चुका है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद उपद्रवियों का समर्थन करने वाले सक्रिय हो गए हैं। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले वकील अब उपद्रवियों के अवैध कब्जे को बचाने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। ये पुलिस और अन्य निर्दोष लोगों पर पथराव व फायरिंग करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने व टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले अब घुसपैठियों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं।

- निहाल सिंह

तू इधर उधर की ना बात कर ...

दिल्ली में जहां हनुमान जयंती की शोभायात्रा पर हमला हुआ उस सड़क पर अवैध कब्जा कर के कबाड़ियों की दर्जनों दुकानें बनी हुई हैं। उन्हीं कबाड़ियों का सरगना है अंसार। हनुमानजी की शोभायात्रा का मास्टरमाइंड भी वही है। सरेआम सड़क कब्जा कर के बनी, कबाड़ियों की उन दर्जनों दुकानों में से एक भी दुकान को अभी तक छुआ भी नहीं गया है, हटाना तो दूर की बात।

एक अन्य तथ्य पर भी ध्यान दीजिए। कबाड़ियों की वो दुकानें हनुमानजी की शोभायात्रा से एक दो दिन पहले नहीं बनी हैं। बरसों पुरानी हैं, सड़क पर अवैध कब्जा हटाने की जिम्मेदार पुलिस और दिल्ली नगरनिगम की ही है। यह दोनों ही भाजपा के पास हैं। दंगाई कबाड़ियों के गिरोह पर बरसों से क्यों मेहरबान है नगरनिगम पर काबिज भाजपा और दिल्ली पुलिस? यहां तक कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद भी दंगाई कबाड़ियों की शत प्रतिशत अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाने के लिए भाजपा और दिल्ली पुलिस किस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रही है?

सातों सांसदों समेत दिल्ली के एक भी भाजपा नेता ने दंगाई कबाड़ियों की उन अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग नहीं की है। दंगाई कबाड़ियों पर भाजपा की इस अथाह अपार शत प्रतिशत मेहरबानी का कारण क्या है? वो केवल कड़ी निंदा और कठोर कार्रवाई के वायदे के झुनझुने से दिल्ली का दिल बहला रहे हैं।

अतः केजरीवाल को कोसने के राजनीतिक पाखंड से काम नहीं चलेगा।

- सतीश चंद्र मिश्रा

जहांगीरपुरी हिंसा में सामने आया PFI का कनेक्शन

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दो साल पहले हुए दंगे की तरह ही जहांगीरपुरी में भी हिंसा की साजिश रची गई थी। क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों की मानें तो इसके लिए न सिर्फ पीएफआइ ने फंडिंग की है, बल्कि कई दिन पहले से इसकी साजिश रचना भी शुरू कर दिया था।

यही नहीं, हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले ही पीएफआइ के सदस्यों ने जहांगीरपुरी में बैठक कर शोभायात्रा को बाधित करने और हिंसा को अंजाम देने की रणनीति तैयार की थी। इस बैठक में अंसार, सोनू चिकना और सलीम सहित करीब 25 लोग शामिल हुए थे। हालांकि, क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस बारे में अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे और शाहीन बाग के प्रदर्शन के मामले में पीएफआइ की संलिप्तता का पहली बार पता चला था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की मानें तो इन दंगों में जिस तरह से पीएफआइ के जरिये फंडिंग की गई थी। ठीक उसी तरह से जहांगीरपुरी हिंसा के लिए फंडिंग किए जाने की जानकारी क्राइम ब्रांच को अब तक की जांच में मिली है। इसके बाद गोपनीय तरीके से क्राइम ब्रांच ने फंडिंग के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों का कहना है कि जांच में 20 से 25 ऐसे लोगों की क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली है, जो कि सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन के साथ ही उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे के दौरान सक्रिय रहे थे। इन सभी की लोकेशन 15 अप्रैल को जहांगीरपुरी में मिली है। इसके बाद ही क्राइम ब्रांच की जांच इस दिशा में आगे बढ़ी है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली से भी बड़ा दंगा कराने की थी साजिश

क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उत्तर-पूर्वी दिल्ली से भी बड़ा दंगा कराने की साजिश जहांगीरपुरी में रची गई थी। इसके लिए पीएफआइ के सदस्यों ने कई बैठकें की थीं। इसके बाद उपद्रवियों को हथियार मुहैया कराए गए थे।

उपद्रवियों को उम्मीद थी कि शोभायात्रा पर पथराव और फायरिंग करते ही भगदड़ मच जाएगी। इसमें कई लोगों की जान जाएगी और बड़े स्तर पर हिंसा भड़केगी। इसके लिए पीएफआइ के करीब 20 सदस्य लोगों को उकसाने के लिए हिंसा वाले दिन जहांगीरपुरी में मौजूद थे। जहांगीरपुरी में 100 से अधिक पीएफआइ स्टूडेंट विंग के सदस्य भी रहते हैं।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा में सामने आया था पीएफआइ लिंक

दिल्ली दंगा मामले में पिछले दिनों जो पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। उसमें भी पीएफआइ का लिंक उजागर हुआ है। आरोप पत्र में इस संगठन के तार आतंकी डा.सबील अहमद से जुड़े होने की बात कही गई है। सबील अहमद स्काटलैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। एनआइए ने इसी आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि सबील व अन्य आतंकियों से पीएफआइ का संपर्क है।

को आकार दे सकेगा?

बेहतर तो यही होता कि सभी धर्मों के शीर्ष लोग मिलते और ऐसी मिसालें पेश करते कि साम्प्रदायिक दंगों की नयी पनपती विकृति विराम लेती। वे अपने-अपने समुदाय का मार्गदर्शन करते, मगर जब राष्ट्र से ज्यादा वजनी सम्प्रदाय हो जाये, सांप्रदायिक दुराव शांति-व्यवस्था के लिए खतरा जाये, तो राज्य-सत्ता का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। ऐसा करना सरकर एवं प्रशासन का दायित्व भी है और जरूरत भी। देश को समग्र तरक्की के लिए शांत भारत चाहिए। दंगे और तनाव उसकी खुशहाली व प्रतिष्ठा को ग्रहण ही लगाएंगे। ऐसे में सशक्त भारत-विकासशील भारत का सपना आकार कैसे ले सकेगा?

कैसी विसंगतिपूर्ण साम्प्रदायिक सोच है कि जब हमारी ऊर्जा विज्ञान व पर्यावरण, शिक्षा एवं चिकित्सा के जटिल मुद्दों को सुलझाने में खर्च होनी चाहिए थी, वो ऊर्जा सांप्रदायिक ताकत को बढ़ाने के लिए खर्च हो रही है। ऐसा क्यों है? यह दूषित एवं संकीर्ण राजनीति एवं तथाकथित सम्प्रदायों के आग्रहों-पूर्वाग्रहों का परिणाम है। किसी भी धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा के मार्ग, समय-अवधि या इसमें शिरकत करने वाले श्रद्धालुओं के संख्याबल को लेकर पुलिस की अपनी नियमावली है। यदि इसका ईमानदारी से पालन हो, तो न ट्रैफिक की समस्या हो सकती है और न सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है, पर अक्सर इसकी अनदेखी होती है, जैसा कि जहांगीरपुरी विवाद में बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी का उत्तर प्रदेश में इसे सख्ती से लागू करने और पारंपरिक जुलूसों व शोभायात्राओं से पहले सभी धर्मों के सम्मानित गुरुओं की बैठकें करने का निर्देश टकराव टालने में अहम साबित होगा। प्रशासन को शोभायात्राओं में घातक हथियारों के प्रदर्शन के मामले में भी कठोर निगरानी करनी चाहिए। इसी तरह, मौजूदा यांत्रिक युग में अब बहुत ऊंची आवाज लगाने की आवश्यकता भी नहीं रह बची है। साम्प्रदायिक आग्रह-पूर्वाग्रह जब जीवन का आवश्यक अंग बन जाता है तब पूरी पीढ़ी शाप को झेलती, सहती और शर्मसार होकर लम्बे समय तक बर्दाश्त करती है। साम्प्रदायिक आग्रह-पूर्वाग्रह के इतिहास को गर्व से नहीं, शर्म से पढ़ा जाता है। आज हमें झण्डे, तलवारे और नारे नहीं सत्य की पुनः प्रतिष्ठा चाहिए। ■

देश के कई राज्यों में रामनवमी के दिन हिंदू संगठनों पर सुनियोजित हमला

हिंदू समुदाय अब असुरक्षित और खतरे में

● प्रेरणा कुमारी

राम नवमी के अवसर पर देश के कई राज्यों से हिंदू संगठनों द्वारा निकाले गए शोभा यात्रा पर एक के बाद एक पथराव, आगजनी के साथ-साथ व्यापक हिंसा की खबरें हमारे सामने आ रही हैं जो बिल्कुल अमानवीय और इस देश में बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदू समुदाय अब असुरक्षित और भय में जीवम जी रहा है। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार और उनकी हत्या की जा रही है। हिंदू अपने त्योहारों में शोभा यात्रा निकालते हैं तो कुछ कट्टरपंथियों का यह कहना है कि इस प्रकार की शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों से निकली है और वहां पर जय श्रीराम के नारे लगे हैं, तो कहीं पर डीजे बज रहा है जो उन्हें उत्तेजित करता है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से निकले अर्थात मुसलमानों को पत्थर फेंकने, पेट्रोल बम फेंकने और आगजनी करने का लाइसेंस मिल जाता है। हिंदुओं की हत्या लोकतंत्र की हत्या है। उन पर कार्रवाई करने की बजाय लुटियंस पत्रकार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सेकुलरिज्म के नाम पर आप देश को बांटने की राह पर चल पड़े हैं हिंदुओं पर हमला करने वाले मुसलमानों कि आप पैरवी कर रहे हैं और दंगाइयों को विक्टिम बता रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें और देश में धर्म के नाम पर आतंक को बढ़ावा देकर आप मुसलमानों का भला नहीं बल्कि उन्हें नेपथ्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। क्या हिंदुओं द्वारा रामनवमी में या दुर्गा पूजा में शोभा यात्रा निकालना एक अपराध है? क्या अब इस देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या हिंदू अपने त्यौहार नहीं मना सकते, उसकी इजाजत भी इन कट्टरपंथियों से लेना होगा?

हिंदुओं परऐसे लक्षित जानलेवा हमले इस देश के लिए त्रासदी पूर्ण घटना है जो भविष्य में देश के लिए घातक सिद्ध होगी। इस देश को कुछ कट्टरपंथी हिंदू-मुसलमान के नाम पर फिर से बांटना चाह रहे हैं अब कहां गई गंगा जमुनी तहजीब? यदि सच में इस देश में गंगा जमुनी तहजीब होती तो हिंदुओं को उनके त्यौहारों को हर्षोल्लास से मनाने दिया जाता न कि उन पर जानलेवा हमले किए जाते। अत्यंत दुख के साथ यह कहा जा सकता है कि देश में अब राम का नाम लेना और उनकी शोभा यात्रा मुस्लिम क्षेत्रों से निकालना, भले ही इसकी इजाजत आपको सरकार दे रही है और इस देश में लोकतंत्र होने के बावजूद इनके इलाके से रैली निकलती है तो आप इनको भड़का रहे है, उत्तेजित कर रहे हैं। ये आप पर हमला कर सके है परन्तु इनके जुलूस कहीं से निकल सकते है। इस प्रकार के नरेटीव सेट कर रहे हैं ये बुद्धिजीवी पत्रकार। देश में जो हिंदू मुसलमान भाईचारा है वह समाप्त हो जाए और देश पुन: बंटवारे और नरसंहार के लिए तैयार करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है अन्यथा सभी एकमत से हिंदुओं पर दंगाइयों द्वारा पथराव और आगजनी की भर्त्सना करते न कि उनका समर्थन।

स्वतंत्र भारत में हिंदू संगठनों द्वारा निकाले गए शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना कई राज्यों और जेएनयू जैसे शैक्षिक संस्थान में भी हुई। पहले राजस्थान उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्यों में राम नवमी के अवसर पर जो शोभायात्रा निकाली गई उस पर दंगाइयों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि अब शैक्षणिक संस्थान भी इससे अछूते नहीं रहे। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में रामनवमी के दिन हिंदू विद्यार्थियों के पूजा और हवन को बाधित किया गया। शिक्षण संस्थान में इस घटना की निंदा की जानी चाहिए वही इस घटना के बचाव में लोग कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान में पूजा करने की क्या आवश्यकता है?

वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा में रामनवमी की शोभा यात्रा जैसे ही खरगोन के तालाब चौक में पहुंची तभी दंगाई मुस्लिमों की भीड़ ने पथराव, आगजनी और पेट्रोल बम फेंकने आरंभ कर दिए। सूत्रों के मुताबिक तुरंत बाद ही, अलग-अलग क्षेत्रों में भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ घरों में आगजनी की गई वही शीतला माता मंदिर में तोड़फोड़ किया गया। खरगोन हिंसा में घायल शिवम की हालत नाजुक बताई जा रही है क्या गलती है उस मासूम की? शिवम के भाई ने बताया कि लोग बुर्का पहनकर पत्थरबाजी कर रहे थे। इनके घर पर अचानक ही सौ से डेढ़ सौ लोगों ने हमला कर दिया सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायर भी किए लेकिन दंगाइयों ने दूसरे क्षेत्रों में

वो पत्थर मार मार कर तुम्हें जगा रहे हैं, तुम्हारी नींद नहीं टूटती तो वो क्या करें ?

जहांगीरपुरी में शोभायात्रा पर हमला करने वाला गिरोह का सरगना है ये अंसार जो शराब की बोतल खोल रहा है।

कौन नहीं जानता कि इस्लाम में शराब हराम है। लेकिन बात भारत के मुसलमानों की हो तो सबकुछ हलाल है बस वह हिन्दुओं से लड़ने का जब्जा रखता हो।

अंसार भी एक पेशेवर अपराधी, जुआरी और शराबी है। वह जुए के अड्डे चलाता था। शराब के ठेके लेता था और आम आदमी पार्टी के उदय के बाद जो बेदाग और सच्चरित्र लोग इस पार्टी की सेवा में हाजिर हुए उसमें अंसार भी है। उसकी योग्यता को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उसे मालामाल कर रखा है।

बदले में वह अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का जाली दस्तावेज बनवाकर उन्हें भारत का नागरिक बनाता है और उन्हीं नागरिकों से आम आदमी पार्टी को वोट दिलवाता है।

ये अंसार जो हिरासत में आने के बाद भी 'मैं झुकेगा नहीं साला' के इशारे कर रहा है उसका कारण ये है कि वो जानता है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन जेल में ही तो बिताने हैं। उसके बाद बाहर निकलेगा तो फिर सब जस का तस।

उसके गैर कानूनी और आपराधिक काम जस के तस जारी रहेंगे। पुलिस और नेता को चंदा मिलता रहेगा और उसका धंधा चलता रहेगा।

नहीं नहीं अमित शाह जी। ऐसे दिल्ली दंगाइयों से मुक्त नहीं होगी। दंगाइयों, उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ योगी की बुलडोजर नीति ही सर्वश्रेष्ठ है। जब वो जान जाएंगे कि उनका साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा तो फिर अगली बार दंगा कराने से दूर हो जाएंगे।

जहांगीरपुरी में मस्जिद के आसपास सड़क पर दोनों ओर बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा है। अगर उन्हें कभी कुछ कहो तो वो तुरंत चिल्लाते हैं कि 'हिन्दू' से झगड़ा हो गया और देखते ही देखते मरा हुआ बच्चा भी बिस्तर से उठकर लड़ाई करने आ जाता है।

बताइये हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो आना जाना दूभर हो गया है। हम तो गाते बजाते शोभायात्रा लेकर जा रहे थे। एक दो मुस्लिम मुहल्ले से भी गये लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मस्जिद के सामने पहुंचे एकदम से उन्होंने बहस शुरु कर दी। फिर मस्जिद से पत्थर, पेट्रोल बम चलने लगे। हमारे पास कुछ नहीं था। जो जहां भाग सकते थे, भागकर अपने आप को बचाया।

(जहांगीरपुरी में मुस्लिम दंगाइयों के शिकार दो प्रत्यक्षदर्शी)

अगर आपसे कोई कहे कि फलां व्यक्ति ने आपको गाली दिया है तो आप क्या करेंगे?

अगर वह व्यक्ति आपका पहले से शत्रु है तो आप तत्काल उस बात पर विश्वास कर लेंगे और उसे सौ गालियां देंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति आपका परिचित और मित्र है तो आप पहले जांच परख करेंगे। पता करेंगे कि क्या सचमुच उसने गाली दिया है।

मतलब आपका दिमाग ठीक उसी घटना पर दो अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। अगर किसी के प्रति मन में नफरत भरी हो तो हम दी गयी सूचना पर सोच विचार नहीं करते बल्कि तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मन में उसके प्रति प्रेम हो तो हम एकदम से कोई प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। सच्चाई जानना चाहते हैं, तब कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं।

मनुष्य के इस स्वभाव को आप जहांगीरपुरी वाली घटना से जोड़कर देखेंगे तो मोमिनों का मन समझने में आपको मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि जुलूस के पहले मोमिनों के मोहल्ले में किसी ने अफवाह फैला दिया कि वो लोग उनकी मस्जिद में घुस गये हैं। बस तत्काल हजार दो हजार लोग तलवारों, ईंट पत्थरों और दूसरे हथियारों से लैस होकर निकल पड़े। मस्जिद में तो कोई काफिर नहीं घुसा था फिर भी मोमिनों ने जबर्दस्त हिंसा और आगजनी कर दिया।

क्यों किया ऐसा? अव्वल तो अगर उनके पास दिमाग होता तो वो पता करते कि जो अफवाह फैलाया गयी वो सच है या नहीं। फिर जब पता चल भी गया कि ऐसा कुछ नहीं है फिर उन्होंने भयंकर हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी क्यों किया?

इसलिए क्योंकि दिलों में पहले से नफरत भरी हुई है। जैसे ही कोई अफवाह सुनाई पड़ती है वो तत्काल पत्थर और तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। प्रेम होता तो पता करते कि जो सूचना मिली है, वो सही है या गलत।

- संजय तिवारी मनिभद्र

आगजनी शुरू कर दी। घरों और वाहनों पर पेट्रोल बम फेंके गए। मंदिरों और हिंदुओं के कुछ घरों में आग लगा दी गई। 3 से ज्यादा दुकानें जला दी गई। पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू की घोषणा की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दंगाई हाथ में तलवार और पत्थरबाजी करते लोग नजर आ रहे हैं दूसरे वीडियो में पेट्रोल बम चलाते दिख रहे हैं दंगाई। मध्य प्रदेश के 13 स्थानों पर पथराव और आगजनी की घटना सामने आई है इससे यह साफ हो जाता है कि यह सब अचानक तो नहीं हो सकता, छत पर पत्थर और पेट्रोल बम पहले से मौजूद थे तो यह कहा जा सकता है कि यह सब सुनियोजित प्लान के तहत किया गया। झारखंड के लोहरदगा और बोकारो में भी रामनवमी के दिन शोभायात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना सामने आई है। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस पर भी पत्थर फेंके गए। गुजरात में साबरकांठा स्थित हिम्मतनगर के छपरिया में भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया इसके बाद इन्होंने कई दुकानों और मकानों में आग लगा दी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी शोभायात्रा जब हावड़ा रामकृष्ण पुर घाट पर पहुंची तब शिवपुर थाना के अंतर्गत आने वाले पीएम बस्ती इलाके में दंगाइयों ने श्रद्धालुओं पर अचानक हमला कर दिया। नवरात्र के पहले दिन भी राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर पत्थर फेंके गए और आगजनी की गई उसके बाद, कई हिंदुओं के मकान को लूटा गया और फिर उसमें आग लगा दिया गया।

क्या इस तरह देश में दंगा फैला कर शांति की कल्पना की जा सकती है? कट्टरपंथी नेता और लुटियंस पत्रकार इन सभी दंगाइयों और आतंकी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को सोचने की आवश्यकता है कि वह अपने बच्चों के हाथ में किताब देना चाहते हैं या पत्थर। क्योंकि यही उनके भविष्य को तय करेगा कि वे प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं या नेपथ्य।

(स्वतंत्र लेखन एवं अनुवाद में सक्रिय हैं)

क्यों हिन्दू पर्व हिंसा का शिकार हों?

■ ललित गर्ग

रामनवमी एवं हनुमान जयन्ती पर एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों ने जो हिंसा, नफरत एवं द्वेष को हथियार बनाकर अशांति फैलायी, वह भारत की एकता, अखण्डता एवं भाईचारे की संस्कृति को क्षति पहुंचाने का माध्यम बनी है। क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि क्यों शांति एवं सद्भाव का संदेश देने वाले पर्व और उनसे जुड़े आयोजन हिंसा का शिकार हों? ध्यान रहे कि जब ऐसा होता है तो बैर बढ़ने के साथ देश की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। नि:संदेह इस सम्प्रदाय विशेष को भी यह समझने की आवश्यकता है कि जब देश कई चुनौतियों से दो-चार है, तब राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव को बल देना सबकी पहली और साझी प्राथमिकता बननी चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। एक विभाजित और वैमनस्यग्रस्त समाज न तो अपना भला कर सकता है और न ही देश को आगे ले जा सकता है। समय आ गया है कि उन मूल कारणों पर विचार किया जाए, जिनके चलते तनाव बढ़ाने वाली घटनाएं थम नहीं रही हैं।

विडंबना यह है कि हिंसा, असहिष्णुता और घृणा की ये घटनाएं भगवान श्रीराम के जन्मदिन पर हुईं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो भारतीयता के प्रतीक है और नीतिपरायणता की साक्षात मिसाल हैं। ऐसी दिव्यआत्मा की जन्मजयन्ती पर देश के विभिन्न भागों में शोभायात्राओं पर हमले होना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि यह राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचाने की कुचेष्टा भी है। अभी रामनवमी पर हमलों एवं अशांति फैलाने की घटनाओं की चर्चा जारी ही थी कि दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई एक शोभायात्रा भी हिंसा की चपेट में आ गई। इसी तरह की हिंसा हरिद्वार में भी हुई और आंध्र एवं कर्नाटक के शहरों में भी। इसके पहले हिंदू नववर्ष के अवसर पर भी हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें राजस्थान के करौली की घटना की गूंज तो अभी तक सुनाई दे रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक तानेबाने को क्षति पहुंचाने के साथ कानून एवं व्यवस्था के समक्ष चुनौती भी खड़ी करती हैं। यह चिंता की बात है कि यह एक चलन सा बनता जा रहा है कि जब सार्वजनिक स्थलों पर कोई धार्मिक आयोजन होता है तो प्राय: पहले किसी बात को लेकर विवाद होता है और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। कई बार तो यह हिंसा बड़े पैमाने पर और किसी सुनियोजित साजिश के तहत होती दिखती है। मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के हिम्मतनगर एवं खंभात में हुई भीषण हिंसा यही संकेत करती है कि उसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की हिंसा भी इसी ओर इशारा कर रही है।

देश का चरित्र बनाना है तथा स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण समाज की रचना करनी है तो हमें एक ऐसी आचार संहिता को स्वीकार करना होगा जो जीवन में पवित्रता दे। राष्ट्रीय प्रेम व स्वस्थ समाज की रचना की दृष्टि दे। कदाचार के इस अंधेरे कुएं से निकाले। बिना इसके देश का विकास और भौतिक उपलब्धियां बेमानी हैं। व्यक्ति, परिवार और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इरादों की शुद्धता महत्व रखती है, जबकि हमने इसका राजनीतिकरण कर परिणाम को महत्व दे दिया। घटिया उत्पादन के पर्याय के रूप में जाना जाने वाला जापान आज अपनी जीवन शैली को बदल कर उत्कृष्ट उत्पादन का प्रतीक बन विश्वविख्यात हो गया। यह राष्ट्रीय जीवन शैली की पवित्रता का प्रतीक है। इसी तरह भारत भी आज विश्वविख्यात होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, तो उसकी बढ़ती साख एवं समझ को खण्डित करने वाली शक्तियों को सावधान करना ही होगा। भारत जैसी माटी में जन्म लेना बड़ी मुश्किल से मिलता है। विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा वाला यह राष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों एवं सम्प्रदायों को अपने में समेटे है तो यह यहां के बहुसंख्यक समुदाय की उदार सोच का ही परिणाम रहा है, इसी बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय को आखिर कब तक कमजोर किया जाता रहेगा? क्यों किया जायेगा? कल पर कुछ मत छोड़िए। कल जो बीत गया और कल जो आने वाला है- दोनों ही हमारी पीठ के समान हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। आज हमारी हथेली है, जिसकी रेखाओं को हम देख सकते हैं। अब हथेली की रेखाओं को कमजोर करने एवं उसे लहूलुहान होते हुए नहीं देखा जा सकता?

आस्था के कवच में कानफोड़ू शोर

पर्यावरण में प्रदूषण पर चिंता कुछ कम हो गयी दिखती है। पिछले दशक में जल, वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण पर गहरी चिंता जतायी जा रही थी। अब ऐसा नहीं दीखता या तो हमने ठीक-ठाक कर लिया है या आंखें फेर ली हैं। नजर डालने से पता लगता है कि हालात हम सुधार नहीं पाए। यानी कि हमने आंखे मूंद ली हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा इसकी चर्चा आगे करेंगे लेकिन फिलहाल यह मुद्दा तात्कालिक तौर पर भले ही ज्यादा परेशान न करे लेकिन इसके असर प्राण घातक समस्याओं से कम नहीं हैं।

हाल ही में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सामाजिक स्तर पर कुछ सक्रियता दिखी है। खास तौर पर धार्मिक स्थानों पर। लाउडस्पीकर से ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जा रही है। मनोवैज्ञानिक और स्नायुतन्त्रिकाविज्ञान के विशेषज्ञ प्रायोगिक तौर पर अध्ययन जरूर कर रहे हैं। लेकिन उनके शोध अध्ययन सामाजिक स्तर पर जागरूकता या राजनैतिक स्तर पर दबाव पैदा करने में बिलकुल ही बेअसर हैं। कुछ स्वयमसेवी संस्थाएं जरूर हैं जो गाहेबगाहे आवाज उठाती हैं । लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें किसी क्षेत्र से समर्थन नहीं मिल पाता। हो सकता है ऐसा इसलिए हो क्योंकि ध्वनि प्रदूषण की समस्या प्रत्यक्ष तौर पर उतनी बड़ी नहीं समझी जाती और शायद इसलिए नहीं समझी जाती क्योंकि हमारे पास विलाप के कई बड़े मुद्दे जमा हो गए हैं।

80 और 90 के दशक में जब अंधाधुंध विकास के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई थी तब उद्योगीकरण, बड़े बांध, रासायनिक खाद और मिलावट जैसे मुद्दों पर बड़ी तीव्रता के साथ विरोध के स्वर उठे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्रदूषण पर चिंता हलकी पड़ गयी। तब इस मुद्दे पर बहसों के बीच प्रदूषण विरोधियों को यह समझाया गया कि विकास के लिए प्रदूषण अपरिहार्य है। यानी निरापद विकास की कल्पना फिजूल की बात है। साथ ही जीवन की सुरक्षा के लिए विकास के अलावा और कोई विकल्प सूझता नहीं है। विकास के तर्क के सहारे आज भी हम नदियों के प्रदूषण और वायु प्रदूषण को सहने के लिए अभिशप्त हैं।

जब तक हमें कोई दूसरा उपाय ना सूझे तब तक आर्थिक विकास के लिए सब तरह के प्रदूषण सहने का तर्क माना जा सकता है। लेकिन धार्मिक स्थानों से हद से ज्यादा तीव्रता की आवाजें बढ़ती जाना और इस हद तक बढ़ती जाना कि वह ध्वनि प्रदूषण तक ही नहीं बल्कि सामुदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के खिलाफ एक सांस्कृतिक प्रदूषण भी पैदा करने लगे ङ्क यह स्वीकारना मुश्किल है।

क़ानून है कि 75 डेसिबल से ज्यादा तीव्रता की ध्वनि पैदा करना अपराध है लेकिन इस क़ानून का पालन कराने में सरकारी एजंसियां या पुलिस बिलकुल असहाय नजर आती हैं। धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकरों की यह समस्या आस्था के कवच में बिलकुल बेखौफ बैठी हुई है और इसके बेखौफ हो पाने का एक पक्ष वह राजनीति भी है जो अपने वोट बैंक को संरक्षण देने के लिए कुछ भी करने की छूट देती है।

जहां तक सवाल आस्था या धार्मिक विश्वास का है तो समाज के जागरूक लोग और विद्वत समाज क्या दृढता के साथ नहीं कह सकता कि धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा कर दिन रात जब चाहे तब जितनी बार तेज आवाजें निकलना सही नहीं है। ये विद्वान क्या मजबूती के साथ यह नहीं कह सकते कि इसका आस्था या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आस्था बिलकुल निजी मामला है। धार्मिक विश्वास नितांत व्यक्तिगत बात है। उसके लिए दूसरों को भी वैसा करने को तैयार करना उन पर दबाव डालना या अपने ही वर्ग के लोगों को भयभीत करना बिलकुल ही नाजायज है।

चलिए जागरूक समाज हो विद्वत समाज हो या क़ानून पालन करने वाली संस्थाएं हों या फिर राजनितिक दल ये सब अपनी सीमाओं और दबावों का हवाला देकर मूक दर्शक बनीं रह सकती हैं लेकिन हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है कि किसी भी तरह के अन्याय या अनदेखी के खिलाफ न्यायपालिका सजग रहती है। आस्था और धार्मिक विश्वासों के कारण पनपी जटिल समस्याओं के निदान के लिए न्यायपालिका ही आखरी उपाय दीखता है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि अदालतों को भी साक्ष के तौर पर समाज के जागरूक लोगों, विद्वानों और विशेषज्ञों का सहयोग चाहिए। आस्था और धार्मिक क्षेत्र की जटिल समस्याओं के निवारण के लिए न्यायपालिका को दार्शनिकों की भी जरूरत पड़ सकती है।

ग़ौरतलब है कि दुनिया में कई देशों में लाउडस्पीकर द्वारा अजान की ध्वनि सीमाएं तय की गई हैं। इनमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, निदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और बेल्जियम जैसे देश शामिल हैं। लाओस और नाइजीरिया जैसे देशों ने स्वयोषित रूप से भी लाउडस्पीकर द्वारा अजान की या तो सीमाएं तय की हैं या फिर मस्जिदों में लाउडस्पीकर को प्रतिबंधित किया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2014 में मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें देश के सभी धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। मेरे वकील विवेक नारायण शर्मा ने याचिका में साम्प्रदायिक दंगों के इतिहास की सूची भी जोड़ दी थी जो इन लाउडस्पीकर्स के कारण देश में हुए थे। इस याचिका से सभी धर्मों के मानने वाले बहुत प्रसन्न हुए थे।तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश श्री एच एल दत्तु ने याचिका को कुछ सुनवाई के बाद ये कह कर लौटा दिया कि अदालत पहले ही ध्वनि प्रदूषण के स्तर की सीमा निर्धारित कर चुकी है। इसलिये शासन व पुलिसकर्मी से कहो कि वो उस आदेश को लागू करवाएं। पर क्या धरातल पर ऐसा कभी होता है? नहीं होता।

आज मस्जिदों में अजान के लाउडस्पीकर पर शोर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसका जवाब पांच बार हनुमान चालीसा पढ़ना या लाउडस्पीकर मंदिरों को बांटना नहीं है। इससे तो शोर और बढ़ेगा, शांति भंग होगी और दंगे भी भड़केंगे।

- विनीत नारायण

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज समाज में जहर बांट रही

फेक न्यूज ऐसी खबरें, कहानियां या झांसे हैं जो जानबूझकर गलत सूचना देने या पाठकों को धोखा देने के लिए बनाई जाती हैं। आमतौर पर, इन कहानियों को या तो लोगों के विचारों को प्रभावित करने, राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने या भ्रम पैदा करने के लिए बनाया जाता है और अक्सर ऑनलाइन प्रकाशकों के फायदे के लिए होती है। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगे के नकली वीडियो ने सांप्रदायिक भावनाओं को हवा दी।

सोशल मीडिया ने राजनीति को अस्त-व्यस्त कर दिया है और लोगों को अपने आसपास के परिवेश से अलग होने पर मजबूर किया है। सोशल मीडिया के कारण हमारे राजनीतिक विमर्श में गिरावट आई है, जहां 'हॉट टेक' और मीम्स ने गंभीर जुड़ाव की जगह ले ली गई है। मीडिया में फैली गलत सूचना और दुष्प्रचार एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनता जा रहा है। यह वेब पोर्टल्स पर जहरीला माहौल पैदा कर रहा है और सड़क पर दंगों और लिंचिंग का कारण बन रहा है।

इंटरनेट के युग में (व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर) यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि भारत में 35 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच आसानी से अफवाहें, मॉर्फ्ड इमेज, क्लिक-बैट्स, प्रेरित कहानियां, असत्यापित जानकारी, विभिन्न हितों के लिए रोपित कहानियां फैलती जा रही है। ऑनलाइन अफवाहों के कई उदाहरण हैं जिनमें निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं। कुछ मामलों में, मंत्रियों ने पहले साझा की गई फर्जी खबरों को महसूस करने के बाद ट्वीट्स को हटा दिया है। अनपढ़ लोगों को आर्थिक रूप से धोखा देने के लिए फेक न्यूज का भी इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण- चिटफंड योजनाओं ने स्पैम ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल बुने हैं। फेक न्यूज ने सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों का विश्वास कम किया है और मीडिया के लाभों को प्रभावित किया है।

नकली समाचारों की वर्तमान प्रतिक्रिया मुख्य रूप से तीन पहलुओं के इर्द-गिर्द घूमती है - खंडन, नकली समाचारों को हटाना और जनता को शिक्षित करना। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि दुर्भावनापूर्ण संपादन और गलत आरोपण जैसी त्रुटियों को इंगित करके नकली समाचारों को खारिज कर दिया जाता है। मगर अब फेसबुक और यूट्यूब जैसी तकनीकी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से लगातार फर्जी खबरों को हटाने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही, व्हाट्सएप ने संदेशों को अग्रेषित करने की एक सीमा निर्धारित की है, ताकि फेक न्यूज के प्रसार को सीमित किया जा सके।

ऐसे माहौल में सरकार को इस सूचना युद्ध की वास्तविकताओं से जनता के सभी वर्गों को अवगत कराने की पहल करनी चाहिए और इस अघोषित युद्ध से लड़ने के लिए आम सहमति विकसित करनी चाहिए। साथ ही फेक न्यूज देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उदाहरण के लिए इटली ने प्रयोगात्मक रूप से स्कूली पाठ्यक्रम में 'फर्जी समाचारों की पहचान' को जोड़ा है। भारत को सभी स्तरों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा, इंटरनेट शिक्षा, फर्जी समाचार शिक्षा पर भी गंभीरता से जोर देना चाहिए।

चैटबॉट और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फैलाए जा रहे समाचारों को स्वचालित रूप से विशेष स्क्रीनिंग के लिए चुना जाना चाहिए। सरकार को फर्जी खबरों को नियंत्रित करने के मुद्दों के संबंध में हि एक मसौदा तैयार करना चाहिए। सोशल और अन्य मीडिया में प्रसारित किए जा रहे डेटा को सत्यापित करने के लिए सरकार के पास स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसी को वास्तविक तथ्य और आंकड़े पेश करने का काम सौंपा जाना चाहिए।

एक लोकपाल संस्थान के द्वारा फर्जी खबरों की शिकायत प्राप्त करना और तत्काल कार्रवाई शुरू करना चाहिए। सोशल मीडिया वेबसाइटों को ऐसी गतिविधियों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए ताकि फर्जी खबरों के प्रसार पर बेहतर नियंत्रण रखना उनकी जिम्मेदारी बन जाए। नकली समाचार की समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों, विशेष रूप से मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का लाभ उठाया जा सकता है।

फेक न्यूज देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचित विकल्पों को प्रभावित करती है, जिससे लोकतंत्र का अपहरण होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस खतरे से व्यापक रूप से निपटने के लिए इसमें शामिल सभी हितधारकों का सामूहिक प्रयास हो।

भारत में फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक नियामक निकाय है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकता है, निंदा कर सकता है या निंदा कर सकता है या संपादक या पत्रकार के आचरण को अस्वीकार कर सकता है यदि यह पाता है कि समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता की नैतिकता का उल्लंघन किया।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन निजी टेलीविजन समाचार और करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। ये निकाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के खिलाफ शिकायतों को देखता है। प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद टीवी प्रसारकों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी सामग्री और फर्जी खबरों की शिकायतों को स्वीकार करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाना या अपवित्र करना) को नकली समाचारों से बचाने के लिए लगाया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति, बेईमानी से या कपटपूर्वक, धारा 43 (कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान) में निर्दिष्ट कोई कार्य करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। ये तीन साल तक हो सकती है या पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और धारा 500 (जो कोई भी दूसरे को बदनाम करेगा, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ) मानहानि के मुकदमे का प्रावधान है।

प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत से ही फेक न्यूज का अस्तित्व रहा है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में, इसने एक जबरदस्त मंच पाया है। सोशल मीडिया और सर्च इंजन के एल्गोरिदम का हेरफेर अब एक वैश्विक प्रवृत्ति है। मीडिया में फैली गलत सूचना और दुष्प्रचार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और गलत सूचना समाज में जहर बांट रही है,एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनती जा रही है।

-प्रियंका सौरभ

दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का जहांगीरपुरी वार्ड का बड़ा नेता था

अंसार खुद एक बांग्लादेशी था और उसने हजारों बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़कर उन्हें आम आदमी पार्टी का वोटर बनाया और फिर देखते ही देखते केजरीवाल की कृपा से बहुत बड़ा नेता और बहुत पैसे वाला व्यक्ति बन गया

अंसार और आम आदमी पार्टी

इलाके में अवैध शराब की दुकान चलाता था फिर केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के तहत उसे 5 ठेके मिल गए यहां तक कि उसके पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी तक है और लोग बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के पहले यही अनुसार एक दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था

इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ यह हमेशा देखा जाता था।

इसने इतनी खतरनाक प्लानिंग बनाई थी कि 300 से ज्यादा भगवा कपड़े अपने लोगों को पहना कर दंगे करने के लिए भेजे थे ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह संदेश जाए कि यह दंगा हिंदुओं ने यानी भगवा लोगों ने किया।

ताजा घटनाओं के मूल में भड़काऊ नारे एवं संकीर्ण राजनीति के मनसूंबे सामने आये हैं। इन आरोपों की जांच होने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ राजनीतिक दल किसी भी बहाने भड़कने और हिंसा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? वास्तव में जैसे यह एक सवाल है कि क्या भारतीय संस्कृति के अस्तित्व एवं अस्मिता से जुड़े इन धार्मिक आयोजनों पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करना जरूरी समझ लिया गया है? इन प्रश्नों पर दलगत राजनीति से परे होकर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यह देखना होगा कि वैमनस्य बढ़ाने वाली घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं?

हिजाब, हलाल और अजान के नाम पर साम्प्रदायिक शक्तियों को संगठित करने एवं दूसरे धर्मों के आयोजनों पर हिंसक हमलों ने आज तेजी के साथ हिंसा, असहिष्णुता, नफरत, बिखराव और घृणा की साम्प्रदायिक जीवन शैली का रूप ग्रहण कर लिया है। यह खतरनाक स्थिति है, कारण सबको अपनी-अपनी पहचान समाप्त होने का खतरा दिख रहा है। भारत मुस्लिम सम्प्रदायवाद से आतंकित रहा है। जब इस्लामवाद भारत की मूल संस्कृति को लहूलुहान करने पर आमादा दिख रहा है और प्रतिक्रिया स्वरूप यदि उदार हिन्दू भी इसी आधार पर गोल बन्द हो रहे हैं तो गलती किनकी मानी जायेगी। आवश्यकता है धर्म को प्रतिष्ठापित करने के बहाने राजनीति का खेल न खेला जाए। धर्म और सम्प्रदाय के भेद को गड्मड् न करें। धर्म सम्प्रदाय से ऊपर है। राजनीति में सम्प्रदाय न आये, नैतिकता आए, आदर्श आए, श्रेष्ठ मूल्य आएं, सहिष्णुता आये, सह-अस्तित्व के प्राचीन मूल्य एवं जीवनशैली आये। नैतिकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। 'कर्तव्य' और 'त्याग' भावना पूर्ति करने वाली है। अत: न ही इनका विरोध हो और न ही इनकी तरफ से दृष्टि मोड़ लेना उचित है। अत: सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर सार्वभौम धर्म का साक्षात्कार ही हममें नवीन आत्मविश्वास, सशक्त भारत-विकसित भारत का संचार करेगा। जो समाज को धारण करे, उसे धर्म कहते हैं। लेकिन आज के युग में इसका सीधा अर्थ हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन आदि में से किसी एक को लिया जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि सभी मनुष्य सुखी हों, सभी भयमुक्त हों, सभी एक-दूसरे को भाई समान समझें। यह भारतीय धर्म चिन्तन का निचोड़ है और यही हिन्दू धर्म का निचोड़ है। जहां विश्व एक ही नीड़-सा लगे।

प्रश्न उठता है, आखिर सार्वभौम मानव धर्म क्या है? भारतीय दृष्टि में पाश्चात्य मत ही धर्म की अवधारणा एकांगी और सम्प्रदाय की अवधारणा के अधिक नजदीक है। जबकि धर्म शब्द 'रिलिजन' से ज्यादा व्यापक है। भारतीयों ने इस शब्द का प्रयोग कभी सम्प्रदाय या पंथ के लिए नहीं किया, अपितु सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्यों, अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम, करुणा, सह-अस्तित्व, सहिष्णुता तथा मानवता के लिए किया। अन्याय का प्रतिकार करना आत्मा का गुण-धर्म है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर तथा भोग से त्याग की ओर जाना ही धर्म है। यह धर्म देश, काल की सीमा तक सीमित न रहकर देशकालातीत है।

धर्म की विशालता के आगे सम्प्रदाय छोटे-छोटे द्वीप दिखाई देते हैं। सबकी पूजा, प्रार्थना, उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यही सबको भयमुक्त रखता है। किसी का कोई विरोध नहीं। सम्प्रदाय नहीं लड़ता है सम्प्रदायवाद लड़ता है। यह सम्प्रदायवाद तब बनता है जब इसका प्रयोग किसी दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध राजनीतिक या सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दरअसल साम्प्रदायिक विद्वेष के बीज वहीं जन्म लेते हैं जहां एक सम्प्रदाय का हित दूसरे सम्प्रदाय के हितों से टकराता है। भारत में हिन्दू-मुस्लिम हित परस्पर टकरा रहे हैं, इसलिए साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। धार्मिकता नष्ट हो रही है। साम्प्रदायिकता का जन्म अनेक जटिल तत्वों से जुड़ा है - आर्थिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक। इसमें मनोवैज्ञानिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन दिशासूचक बने। गिरजे पर लगा दिशा-सूचक नहीं, वह तो जिधर की हवा होती है उधर ही घूम जाता है। कुतुबनुमा बने, जो हर स्थिति मे सही दिशा बताता है। ■

राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती गहलोत सरकार

● प्रेरणा कुमारी

राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष पर बाइक रैली निकाल रहे हिंदुओं पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर पत्थर बरसाए और आगजनी की गई। यह अत्यंत भयानक घटना है जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। कई लोगों की दुकानों को लूट लिया गया और बाद में, उसमें आग लगा दिए गए। सोचने वाली बात ये है किये सारे दुकान हिंदुओं के थे। कांग्रेस सरकार के राज में इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं जिसमें साफ तौर से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है और 12 अप्रैल तक इसे बढ़ा दिया गया है साथ ही साथ इंटरनेट सेवा भी बंद है। इस भयानक स्थिति में अशोक गहलोत ने इस घटना के लिए मोदी और अमित शाह से अपील कर रहे हैं कि यह देश में कानून व्यवस्था ठीक करें और देश को संबोधित करें और माहौल को ठीक करें।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में शांति और कानून व्यवस्था ठीक करने की बजाय केंद्र सरकार को निशाना बना रही है और अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में खुलेआम हिंदू संगठनों पर पत्थर फेंके गए। लाठी चलायी गई और वहां की पुलिस हाथ पर हाथ धरे देखती रही।

करौली शहर में हुई साम्प्रदायिक हिंसा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर यह है कि हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई शोभायात्रा पर योजना बनाकर पथराव किया गया। बीसों हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल फूंक दी गई। तथाकथित करौली के हटवाड़ा बाजार के एक मकान में करीब 150 असामाजिक तत्व एकत्रित थे। नव संवत्सर पर हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा, जब हटवाड़ा बाजार पहुंजी तो छतों से पथराव शुरु हो गए। इसके बाद कई सारे लोग जीम से हाथ में लाठी और अन्य औजार लेकर हिंदू संगठनों पर हमला शुरु कर दिया।

करौली को हिंसा में झोंक दिया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है पुलिस उनके अंडर में है लेकिन गहलोत सरकार राज्य को सही तरीके से चलाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। हिंदू की दुकानों को पहले लूटा गया फिर उनको जलाया गया और अब इतना डर फैलाया जा रहा है जिससे हिंदू वहां से पलायन करने करने पर मजबूर किए जा रहे हैं। इस तरह का जंगलराज राजस्थान में कायम किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार राज्य में डिस्कॉम ने रमजान के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश दिए थे। इस तरह की हिंदू विरोधी नीतियों को राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है क्या गहलोत सरकार को हिंदुओं की नवरात्रि नहीं दिख रही है। इस पर बीजेपी के विरोध करने पर इस आदेश को वापस लिया गया। इस तरह के दोहरे चरित्र के बावजूद ये कांग्रेस और उनकी सरकार देश में धर्मनिरपेक्षता की ढोल पीटती नजर आती है।

नवरात्रि के अवसर पर हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा बकायदा प्रशासन से इजाजत लेने के बाद निकाली गई। प्रशासन ने ही रूट तय किया था लेकिन जैसे ही शोभायात्रा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से निकलने लगी तो दंगाइयों ने वहां पत्थरबाजी शुरू कर दी। यह सब अचानक तो नहीं हुआ होगा इसकी पूरी तैयारी पहले से की गई थी। मस्जिद के पास पहुंचने पर पत्थरबाजी शुरू हो जाते हैं छतों से बड़े-बड़े पत्थर फेंके गए हैं। शहर में हिंसा भड़क गई और आग लगा दी गई आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस की छानबीन में हिंसा के पीछे एक कांग्रेस के नेता का नाम आया है पुलिस ने इस हिंसा का मास्टरमाइंड कांग्रेसी पार्षद मतलूब अहमद को बताया है। एफ आई आर के मुताबिक मतलूब ने लोगों को उकसाया और बाइक रैली पर पत्थर बरसाए। इस पर हिंसा, पथराव और भीड़ को संगठित करने का इल्जाम लगाया गया है। सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया है मुख्य आरोपी मतलूब को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई है परंतु अब तक इसे पकड़ा नहीं गया है हिंसा के मामले में 13

करौली की घटना के दिन सुबह से घटने वाली संदेहास्पद घटनाएं

1 आम दिनों में करौली में पूरे शहर में रात 11 बजे तक ऑटो चलते हैं जिनमे से 90 प्रतिशत ऑटो समुदाय विशेष के हैं। घटना वाले दिन या तो समुदाय विशेष अपने ऑटो लेकर आया ही नहीं और आया भी तो घटना से पहले-पहले ही ऑटो लेकर अपने इलाके में चले गए।

2 घटना वाले दिन समुदाय विशेष ने अपनी दुकान नहीं खोली और खोली भी तो दोपहर तक बंद कर दी। यहां तक की हॉस्पिटल के बाहर फलों की दुकान जो कभी बंद नहीं होती उस दिन वो दुकाने भी बंद थी।

3 घटना वाले दिन सुबह मंडी में भी समुदाय विशेष के दुकानदार नहीं गए जबकि उस दिन शनिवार था।

4 घटना वाले दिन हटवाड़ा में डॉक्टर मक़सूद अहमद, मतलूब और अंचू के जिम, घर और मस्जिद ढोली खार और चिड़ चिड़ी के लड़के देखे गए। जबकि ये मोहल्ले घटनास्थल से बहुत दूर के हैं।

5 किसी भी घर और मस्जिद पर इतने पत्थर सामान्य तौर पर नहीं हो सकते और अगर हो भी तो भावनाये भड़कने के बहाने हाथो हाथ इकट्ठे नहीं किए जा सकते।

6 कोई 50-100 लोग मिलकर किसी 4000 के आसपास की भीड़ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते जब तक की उनको प्लानिंग के तहत उनको बैकअप प्लान का सपोर्ट नहीं हो।

7 घटना में एक भी समुदाय विशेष का व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है की हमला कितना सुनियोजित था।

8 करौली नगर पालिका सभापति रशीदा खातून हैं फिर अमीनुद्दीन खान को प्रशासन अपनी मीटिंग में क्यों बुला रहा है जबकि अमीनुद्दीन खान सट्टे के अपराध में कई बार पुलिस की पकड़ में आ चूका है।

करौली में पिछले सालों में क्या-क्या संदेहास्पद हो रहा था, जिससे वर्तमान घटना के सूत्र जुड़ते हैं।

1 करौली शहर में घुसने और बाहर आने के लिए 6 बड़े दरवाजे और 12 छोटे रास्ते हैं।
इनमे केवल 02 दरवाजों के पास ही मुस्लिम आबादी रहती थी।लेकिन पिछले सालों में अचानक हर दरवाजे के अंदर और बाहर मस्जिदों की बाढ़ आ गई है।वो सब की सब अवैध वो भी बिना किसी सरकारी परमिशन के।

2 सारी मस्जिदे हिन्दू बहुल इलाकों में बनायीं गईं, जिनपर प्रशासन को कई बार ध्यान दिलाया गया लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। करौली के लोगों ने कभी भी करौली में बाहर के मुसलमान नहीं देखे थे। लेकिन पिछले सालों में करौली में देवबंद और तब्लीगी जमात के बाहर के लोगों का जमावाड़ा बढ़ गया है।जिसको प्रशासन ने कभी गंभीरता से नहीं लिया।

3 ताम्बे की टौरी जो की रियासतकालीन होने के साथ साथ करौली का सबसे संवेदनशील इलाका है क्योंकि ये हिन्दुओं के पलायन के कारण कसाइयों के मोहल्ले ढोलीखार से लग चुका है। इस मोहल्ले में नगर परकोटे के पास मासलपुर दरवाजे के बाहर करौली शहर के ऐतिहासिक श्मसान घाट हैं और हनुमानजी के कई प्राचीन मंदिर हैं। इस मोहल्ले में मासलपुर दरवाजे के अंदर पिछले 3 सालों में अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई है। जबकि ये मोहल्ला हिन्दुओं का है। यहां समुदाय विशेष आबादी है ही नहीं। इस मस्जिद के बनते ही शमशान और मंदिरों को जाने वाले रास्ते में इस मस्जिद के इलाके में तेजी से मुस्लिमो को उठना बैठना शुरू हो गया। जिससे मोहल्ले में कई बार असहज सिथि उत्पन्न हुई।

4 मस्जिद बनाने के बाद ऐतिहासिक करौली के परकोटे को जगह-जगह तोड़ दिया गया है और अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रशासन का इस इसको गंभीरता नहीं हुई।

5 मस्जिद के बनने के बाद एक घटना घटी जिसने 02 अप्रैल 2022 को घटने वाली घटना के संकेत दे दिए थे। नवम्बर 2021 में ताम्बे की टौरी मोहल्ले के लोगों को एक घटना ने झकझोर दिया। टौरी मोहल्ले में जिस जगह मस्जिद बनाई गई है उसके बाहर सिद्ध हनुमान का मंदिर है। परकोटे ले अंदर वाले हिस्से से परकोटा तोड़कर मंदिर की जमीन की तरफ समुदाय विशेष आबादी को बढ़ाने की कोशिश की गई। जब मोहल्ले के लोग साफ-सफाई और बॉउंड्री का निर्माण करने लगे तो मुस्लिम इकट्ठे हुए और सीधी धमकी पर आ गए की यहां कुछ नहीं बनेगा। जबकि जमीन मंदिर की थी।टौरी के हिन्दू लोग इस बात से चिंतित हुए की मस्जिद बनने से पहले ये लोग प्यार प्रेम से रहते थे और मस्जिद बनने के बाद अचानक ये मोहल्ले में विवाद करने लगे।

6 जब ये अतिक्रमन की कोशिश की जा रही थी तो वर्तमान नगर सभापति (तथाकथित) अमीनुद्दीन खान का छोटा भाई भी यहां साथियों छुट्टरव लेकर दूर उपस्थित था। जबकि उसका निवास दूर मोहल्ले में है।इसकी सूचना कलेक्टर सहित प्रशासन को दी गई। इसके उपरांत भी नगर सभापति प्रतिनिधि (तथाकथित) अमीनुद्दीन खान ने मंदिर की जमीन पर नगर पालिका का सरकारी बुलडोजर भेजा जिसका साफ सफाई का बहाना बनाया गया। लोगों ने फिर शिकायत की तब बुलडोजर मंदिर की जमीन से बाहर गया।

7 गौरतलब बात ये है की जिस अमीनुद्दीन खान को नगर सभापति की हैसियत से मीटिंग में शामिल कर रही है वो नगर सभापति है ही नहीं अमीनुद्दीन की मां चेयरमैन है। ये अमीनुद्दीन तो सट्टे के अवैध कारोबार में कई बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसके बाद भी सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसपी इसको ससम्मान अपने साथ बिठाते हैं। इससे प्रशासन की मनोस्थिति समझी जा सकती है।

8 इसके बाद पिछले महीने इन्ही लोगों ने करौली के श्मसान की जमीन पर अपना हक़ जताने की कोशिश की, जबकि ये स्थानीय लोग पिछले सैंकड़ों सालों से जानती हैं कि श्मसान घाट राजकीय समय से ही हिन्दुओं का है।

9 ठीक इसी तरह करौली के नदी दरवाजे के बाहर बैठे हनुमान के आसपास तेजी से समुदाय विशेष आबादी बढ़ा दी गई है। वहां पर पिछले बर्षों में बैठे हनुमान जी के पास कुंड के शीतल कुइया महादेव मंदिर में शिवलिंग तोड़ फोड़ की गई।

10 ठीक इसी प्रकार हिंडौन दरवाजे के बाहर मस्जिद बनाकर नूर कालौनी बसा दी गई। जबकि वहां केवल 10 समुदाय विशेष परिवारों की आबादी होगी।

11 ठीक इसी तरह शिकारगंज वाले रोड पर अपनी आबादी बढाकर पूरा एरिया कब्जा लिया गया है, और वहा ही माहौल तनावपूर्ण बना दिया गया है।

12 ठीक इसी प्रकार वजीरपुर गेट पर हिन्दुओं को मस्जिद के आगे हिन्दुओं को अपनी बारात के छ्टु बंद करने पड़ते हैं। यहां तक की जब करौली के आराध्य मदन मोहन जी की पोशाक गाजे बाजे के साथ जाती है, तब भी बाजे को बंद करना पड़ता है।

इस तरह पूरी करौली में पिछले 05 सालों में करौली में बहुत संदेहास्पद और तनावपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसकी लेकिन प्रशासन ने इसको कभी ध्यान नहीं दिया।

लोगों को गिरफ्तार किया गया है 33 से ज्यादा लोगों को कर्फ्यू तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

तथाकथित इसमें पीएफआई का हाथ भी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने 2 दिन पहले ही प्रशासन को बता दिया था कि अगर हिंदू संगठन रैली निकालेगी तो हिंसा हो सकती है। यह चिट्ठी अशोक गहलोत और डीजीपी करौली राजस्थान के पास भेजा गया था जिसमें साफ-साफ हिंसा की चेतावनी दी गई थी और मतलूब अहमद पीएफआई का एक्टिव मेंबर भी रहा है। इस तरह यह कहने में कोई हर्ज ना होगा कि एक तरफ पीएफआई चेतावनी दे रहा है तो वही दूसरा मतलूब अहमद पूरे प्लान को कार्यान्वित करता है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साजिश के तहत हिंदुओं पर हमला किया गया जिसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही दिखाई दे रही है या यूं कह सकते हैं कि प्रशासन की अप्रत्यक्ष सहमति थी इस दंगे को भड़काने में। देश में नववर्ष मनाने पर दिक्कत हो रही है। इस प्रकार के आतंक को बढ़ावा सरकार दे रही है और हिंदुओं की दुकानों को आग लगाने वाले को सरकार इनको संरक्षण दे रही है। सेक्युलरिज्म का सियासी खेल चल रहा है क्या? अब लोकतंत्र खतरे में नहीं नजर आ रहा है जब खुलेआम हिंदुओं की हत्या की जा रही है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य में तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले यह लोग राज्य में हिंदूओं पर सरेआम पत्थर फेंक रहे हैं। हिंदुओं की दुकानों में आग लगाई गई और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है इतना डर और दहशत का माहौल बना दिया गया है जिससे हिंदू वहां से भागने के लिए तैयार हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का मदद या उन हत्यारों को पकड़ने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही है। गहलोत सरकार देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले बयान दे रही है। वहीं करौली हिंसा मामले में भाजपा ने न्यायिक जांच की मांग की है। प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि करौली हिंसा में जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनकी दुकानों में आग लगी है उनकी एफ.आई. आर. तक पुलिस दर्ज नहीं कर रही है । दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मोटरसाइकल जला दी गई उनकी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहें। एक गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति के हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर के कारण ऑपरेशन हुआ था। उसे पानी पिला रहे भाई को पुलिस जबरन पकड़ ले गई। प्रशासन ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को चारों वीडियों के आधार पर एक्शन लेने की बात कही थी लेकिन मुख्यमंत्री के बयान पर कि रैली से

उत्तेजित नारे लगे थे इस कारण यह दंगा हुआ। उसके बाद तो मुख्यमंत्री के पदचिन्हों पर चलते हुए अब पुलिस डीजीपी ने करौली की घटना को एक्शन का रिएक्शन कहकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। और कांग्रेसी पार्षद मतलूब अहमद को भी बचाने की कोशिश की जा रही है परन्तु डीडी पी साहब यह भूल गए की उनकी स्थानीय पुलिस ने ही एफ.आई.आर. में मतलूब पर दंगा भरकाने और पत्थर मारने का आरोप लगाया है। उस घटना के बाद मतलूब अहमद गायब है। लेकिन अब प्रशासन के हवाले से कहा जा रहा है कि उत्तेजित करने वाले नारे लगे थे जिसके कारण एक्शन का रिएक्शन हुआ है अर्थात आप समझ सकते हैं कि इस देश में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है वह अपने धर्म और अपने भगवान का नारा नहीं लगा सकते हैं यदि वह जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो दूसरे पंत के लोग उन पर पत्थर चलाने का हक रखते हैं। पत्थर चलाने वालों वाले दंगाइयों को इस तरह गहलोत सरकार समर्थन कर रही हैं।

राठौड़ ने आरोप लगाया किइन सब ऊपरी दबाव के कारण स्थानीय प्रशासन किसी प्रकार की मदद को तैयार नहीं है। अब तक 156 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उसमें एक ही प्रकार के लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3-3- दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। मुख्यमंत्री पर्टिकुलर वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए अपने पक्ष में मजबूत कर रही है। राठौड़ के नेतृत्व में बनाई गई भाजपा की सात सदस्यीय कमेटी ने हिंसा वाले इलाके का दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंप दिया है। राठौड़ ने इस हिंसा को सुनियोजित बताया है और कहा कि जब प्रशासन को इस मार्ग से रैली निकाली गई तो दंगे हो सकते हैं तो फिर चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया। जिस तरह से पथराव हुआ है, उससे साफ है कि उपद्रवियों ने पहले ही तैयारी कर ली थी। रैली पर कई लोगों ने तलवार और लाठियों से हमले किए।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर मामले की न्यायिक जांच कराने, प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को लेकर दखल देने की मांग की। जयपुर में पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण का नकाब उजागर हुआ है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अराजक गतिविधियां करने वाले पीएफआई संगठन को कोटा में रैली करने की परमिशन देती है जबकि उस समय कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा था और दूसरी ओर करौली हिंसा की घटना के आड़ में पूरे राज्य में रामनवमी के रैली पर पाबंदी लगाई है। बहुत सारे जिलों में तो धारा 144 लगा हुआ है। बहुसंख्यक लोगों को पिटने और पलायन के लिए सरकार लोगों को मजबूर कर रही है। जिसकी जांच खुद बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने करौली जाकर की है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गहलोत सरकार की अन्याय की पराकाष्ठा है कि हिंडोन में लोगों को नोटिस दिया गया जिससे लोग रामनवमी तक नहीं मना पाए।

स्वतंत्र लेखन एवं अनुवाद में सक्रिय हैं।

सरकार नई परेशानी वही

● अपूर्व बाजपेयी

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की रैलियों के दौरान विपक्ष द्वारा सत्ता में आसीन सरकार पर यह आरोप मुख्यत: लगाए गए थे कि सरकार भर्ती परीक्षाओं को कराने में असफल रही है, फिर चाहे उस असफलता का कारण पिछली भर्तियों का समय से पूरा न होना हो अथवा नई भर्तियों के पेपर लीक होना। चूंकि युवाओं की संख्या प्रदेश में वृहद स्तर पर है लिहाजा इस मुद्दे का चुनावी मुद्दा बनना लाजमी भी था। चुनाव के करीब ही यूपी टेट का पेपर लीक हुआ और अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत बारहवी कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर प्रदेश के 24 जिलों में लीक हुआ।

दरअसल वर्तमान समय में शिक्षा केवल ज्ञान का स्त्रोत न होकर व्यावसायिक हो चुकी है, बड़े बड़े माफिया दस से पंद्रह कमरों के हॉल को कॉलेज का नाम देकर मान्यता हासिल करते है, इनमे माननीयों के विद्यालय भी शामिल है, जिनमे नकल कराए जाने के नाम पर धन उगाही का काम होता है।

भारतवर्ष में जहां एक ओर शिक्षा में बदलाव का दौर प्रारंभ हो रहा है, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इस परिवर्तन का जहां स्वागत होना चाहिए था वहीं सबसे इसका एक दुखद पहलू यह भी है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में भारत का एक भी विद्यालय जगह नहीं पाता है। यदि इन्ही रिपोर्ट को आधार मानकर बात की जाए तो भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार और गुणवत्ता के दावे जरूर किए जाते है लेकिन ये सभी दावे जमीनी स्तर पर अमल में लाए नहीं जाते।

शिक्षा के क्षेत्र में सेंध लगाने वाला तंत्र शिक्षा माफिया, नकल माफिया है। जिसने समय समय पर नियम कायदे कानून को धता बताकर खासकर उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में अपनी पैठ बनाई है। यह संभव नहीं है कि इनके तंत्र में शिक्षा विभाग के कर्मचारी सम्मिलित न हों। इस तंत्र के द्वारा नकल कराने के साधनों का प्रयोग भी समय समय पर बदल बदलकर किया गया है, पहले जहां ये कॉपी लिखवाकर, बोलकर नकल कराते थे, अब वही आधुनिक पद्धति में मोबाइल, ब्लूटूथ, व्हाट्सएप के माध्यम से ये चलन प्रचलित है। सरकारें इन पर कार्यवाही का लाख दावा करें लेकिन हकीकत ये है कि ये आज भी उसी दमखम के साथ शिक्षा तंत्र में सक्रिय है। हर साल नए नए विद्यालयों के लिए दौड़ लगाते लोग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

सरकार और लोगों को भी सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्ट नकल माफिया के कारण लीक होते पेपर, परीक्षा परिणाम में देरी उस व्यक्ति के लिए कितने कष्टदायी होते है जिसने ईमानदारी से तैयारी करके अपनी परीक्षा दी, लेकिन किसी अन्य की गलती के कारण उसका भविष्य खराब हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां 1991 में कल्याण सिंह की सरकार ने शिक्षा माफिया पर नकेल कसी वही उसके बाद की किसी भी सरकार ने तत्कालीन सरकार की शिक्षा माफिया के विरुद्ध चलाई गई मुहिम को आगे बढ़ाया जाना उचित नहीं समझा लिहाजा नकल माफिया और सक्रिय हो गए।

यूपी में वर्तमान सरकार को भी अब गंभीरता से ये सोचना होगा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा तंत्र खड़ा करना है जो नकल माफिया, शिक्षा माफिया पर अंकुश कस सके, उनकी अपराधिक गतिविधियों को समाप्त कर सके, तभी प्रदेश के युवाओं को असली उन्नति हासिल होगी। ■

यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों पर लगाम

यूपी में खामोशी और शांति: धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों पर लगाम, 4,258 हटे तो 28,186 की आवाज हुई कम।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने से शुरू कर दिए हैं या उनकी ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुसार कम करनी शुरू कर दी है। इस बीच बुधवार दोपहर तक पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों से 4,258 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं जबकि 28,186 लाउडस्पीकरों की ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुरूप कम करा दी गई है।

जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आगरा जोन में धार्मिक स्थलों से 30 लाउडस्पीकर हटाए गए जबकि 905 स्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई। मेरठ जोन में 1,215 लाउडस्पीकरों को उतारा गया जबकि 5,976 लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई। बरेली जोन में चार लाउडस्पीकरों को उतारा गया जबकि 5,469 लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई जा चुकी है।

सूचना के अनुसार, लखनऊ जोन में 912 लाउडस्पीकरों को उतारा जा चुका है जबकि 6,400 लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई है। लखनऊ कमिश्नरेट में 190 लाउडस्पीकरों को उतारा जा चुका है जबकि 1,235 लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई है।

बता दें कि हाल ही में ध्वनि प्रदूषण के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा धार्मिक स्थलों से तेज आवाज के लाउडस्पीकर हटाने और छोटे लाउडस्पीकर से परिसर के अंदर ही आवाज सीमित रखने के आदेश दिए थे। जिसके चलते मंगलवार शाम को सीओ ने कोतवाली में धर्म गुरुओं के साथ बैठक की।

धर्म दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है

● प्रियंका 'सौरभ'

आये रोज आपने हनुमान चालीसा मंदिरों, घरों और यहां तक कि मन में भी पढ़ी होगी। जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर के बारे कहते हैं जो सच्ची श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपके दुश्मन परास्त हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को जेल जाना पड़ा। इसके बावजूद कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाए जाने के बाद महाराष्ट्र में विवादों का एक नया सेट सामने आया है और चेतावनी दी है कि अगर 3 मई तक उन्हें नहीं हटाया गया, तो उनकी पार्टी जोर से हनुमान चालीसा बजाएगी।

इस विवाद के बारे में जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों पर भरोसा कर सकती है। चुनाव है इसलिए धर्म भी दांव पर लगा दिया है; लम्बे चले बुलडोजर के बाद देश में अब बजरगंबली की आराधना का मुद्दा गरमा गया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने सवाल खड़ा किया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया? वैसे, राजद्रोह के आरोप का यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल के वर्षों में कई लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगे तो काफी विवाद हुआ। आम लोगों पर केस की जानकारी तो सबको नहीं हुई लेकिन जब राजनीतिक हस्तियों पर आरोप लगे तो हंगामा हो गया। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आखिर राजनीतिक विरोध का मामला राजद्रोह तक कैसे पहुंच गया?

भारतीय दंड संहिता राजद्रोह (धारा 124 ए) को एक अपराध के रूप में परिभाषित करती है जब 'कोई भी व्यक्ति शब्दों द्वारा, या तो बोले या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा या अवमानना, या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या करता है। या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है।' अप्रसन्नता में बेवफाई और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं। हालांकि, उत्तेजना या घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता को उत्तेजित करने के प्रयास के बिना टिप्पणी, इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

भारत में राजद्रोह कानून का इतिहास देखे तो 1837 में थॉमस मैकाले (भारतीय शिक्षा पर अपने मैकाले मिनट 1835 के लिए प्रसिद्ध) ने 1837 में दंड संहिता का मसौदा तैयार किया। धारा 113 के रूप में दंड संहिता 1837 में देशद्रोह रखा गया। बाद में, इसे छोड़ दिया गया, केवल 1870 में सर जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा दंड संहिता में वापस पढ़ा गया। भारत में ब्रिटिश राज ने इस धारा को 'रोमांचक असंतोष' शीर्षक के तहत राजद्रोह पर पेश किया था। 1898 का आईपीसी संशोधन अधिनियम: इसने 1870 में दंड संहिता के माध्यम से लाए गए परिवर्तनों में संशोधन किया। वर्तमान धारा 124ए को 1937, 1948, 1950, और भाग बी राज्यों (कानून) अधिनियम, 1951 में किए गए कुछ चूकों के साथ 1898 में किए गए संशोधनों के समान कहा जाता है।

हनुमान चालीसा विवाद के बीच महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपति आज कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस ने राणा दंपति की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। नवनीत राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खार पुलिस स्टेशन में अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं। इसमें से 2 मामले नवनीत राणा के खिलाफ तो वहीं तीसरा केस भीड़ के खिलाफ दर्ज किया गया है। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था। अब बांद्रा कोर्ट ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बयानबाजी पर राजद्रोह के आरोप लगना ठीक है? इस पर अक्सर बहस होती रहती है कि अंग्रेजों के समय के कानून की आज के समय में क्या जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है।

जो अभिव्यक्ति या विचार उस समय की सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है, उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। 1979 में, भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की पुष्टि की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों को निर्धारित करता है।

हालांकि, देशद्रोह का दुरुपयोग और मनमाने ढंग से आरोप लगाना भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए धारा 124ए का दुरुपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। केदार नाथ मामले में दी गई एससी कैविएट, कानून के तहत मुकदमा चलाने पर इसके दुरुपयोग की जांच कर सकती है। जब भी इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक शख्स पर होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी पर वैसे ही आरोप लगते हैं जैसे इस समय भाजपा लगा रही है। इसे खामोश कराने का हथकंडा बताया जाता है। संबंधित राज्य के अधिकारी और पुलिस इस राजद्रोह कानून का इस्तेमाल लोगों में भय का माहौल बनाने और सरकार के खिलाफ असंतोष को कुचलने के लिए करते हैं। देखें तो यह एक तरह से सियासत में 'बदलापुर' की तरह लगता

हिन्दुत्व का नया चेहरा बनकर उभरीं नवनीत राणा

महाराष्ट्र की सियासत हनुमान जी के इर्द-गिर्द घूम रही है। पहले हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार को घेरा। लेकिन नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी और शिवसेना आमने-सामने हैं। देवेंद्र फडणवीस सवाल पूछ रहे हैं कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें मंदिरों में सिटी बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए बल्कि गदाधारी हिंदू चाहिए। विवादों की एक चिंगारी कैसे दहकती आग में बदल जाती है, इसको आप अजान के बदले हनुमान चालीसा के विवाद से समझ सकते हैं। वो विवाद लाउडस्पीकर से शुरू हुआ लेकिन उस पर राजनीति बेहद लाउड है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिसको हनुमान चालीसा पढ़ना है, वो अपने घर में पढ़े लेकिन सड़कों पर दादागिरी करने के लिए उतरेगा तो उसको सही जवाब दिया जाएगा। इस पर बीजेपी ने पूछा कि सड़क पर नमाज पढ़ते समय ये ज्ञान कहां चला जाता है।

अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की शनिवार को हुई गिरफ्तारी और उसके बाद जेल में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नवनीत राणा केस में पूरी जानकारी मांगी गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि MHA ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ़्तारी और खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा विशेषाधिकार और आचार समिति ने MHA से पहले एक रिपोर्ट मांगने को कहा था।

सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर महाराष्ट्र DGP भेजेंगे स्पीकर को रिपोर्ट

इधर, जेल में हुए बर्ताव को लेकर सांसद नवनीत राणा की शिकायत के बाद अब महाराष्ट्र DGP रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। महाराष्ट्र के गृहमंत्रालय के सूत्रों ने दी जानकारी दी है। बता दें कि रविवार को लोकसभा के स्पीकर को नवनीत राणा ने अपने वकील के माध्यम से शिकायत की थी। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने 24 घंटे के भीतर फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी थी। अब महाराष्ट्र के DGP रिपोर्ट बनाकर आगे भेजेंगे। DGP फैक्चुअल रिपोर्ट बनाकर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे और फिर चीफ सेक्रेटरी इसे लोकसभा को भेजेंगे।

महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि जितने भी आरोप नवनीत राणा ने लगाए हैं वो ग़लत हैं। उनके साथ जेल में किसी ने भी दुर्व्यवहार नहीं किया। पानी देने से किसी ने इंकार नहीं किया। गौरतलब है कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी। राणा ने पत्र में कई हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा, मुझे 23 अप्रैल 2022 को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूरी रात मैंने पुलिस स्टेशन में बिताई। जब मैंने पीने के लिए पानी मांगा तो मुझे पानी तक नहीं दिया गया। शिकायत के बाद स्पीकर ने फैक्चुअल रिपोर्ट देने की मांग की थी।

सेशंस कोर्ट से राणा दंपत्ति को नहीं राहत

मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान के बाद विवादों में आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट से मंगलवार को कोई राहत नहीं मिली है। अब इस मामले में राणा की जमानत याचिका कर 29 तारीख तक पुलिस को उनका जवाब देने के निर्देश कोर्ट ने दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद सुनवाई की तारीख रखी जाएगी।

इससे पहले, नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने राणा दंपति की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत में अभी जमानत अर्जी पर कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में सेशन कोर्ट में अर्जी कैसे डाल सकते हैं। राणा के वकील ने उनकी जमानत याचिका सुनने के लिए नजदीक की तारीख मांगी।

है। समयानुसार इसे बदले हुए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत और आवश्यकता, आनुपातिकता और मनमानी के निरंतर विकसित होने वाले परीक्षणों के आधार पर जांचने की आवश्यकता है।

जिस हिन्दू राज में हनुमान चालीसा पढ़ने पर बंदिशें हों, वहां सत्ता की बू सबको समझ आती है। सत्तालोलुप होकर उद्धव ने अपने ही विचार को विस्मृत कर दिया। ऐसे विवादों की जड़ संवैधानिक त्रुटियों से फूटती हैं। दोहरे मापदण्डों ने सत्यानाश कर दिया। आज देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है और समान व्यवहार संहिता भी। अजान मंजूर और हुनमान चालीसा नामंजूर! ये कैसा दस्तूर? सड़कों पर और लोगों के घरों के सामने हनुमान चालीसा सिर्फ इस बात का संकेत है कि अपनी-अपनी आस्था को अपनी चारदीवारी में शांत तरीके से प्रतिपुष्ट करें। लोगों की शांति भंग न करें।

हमें सभी धर्मों को दिलों में रखिए सम्मान दीजिए क्योंकि धर्म जब तक दिल में होता है तो सुकून देता है, लेकिन दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। बजरंगबली और हनुमान चालीसा को किसी विवाद में घसीटना सनातनी संस्कृति नहीं हैं। अनेकाएक व बारंबार पाठ करें लेकिन अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए, किसी का विरोध करने के लिए नहीं। ■

कोरोना की चौथी लहर, कितने तैयार हैं हम?

● आर.के. सिन्हा

पिछले साल अप्रैल के महीने में आई कोरोना वायरस की भीषण लहर ने देश में प्रलय मचा कर रख दी थी। उन दिनों को याद करके भी घबराहट होने लगती है। एक साल के बाद फिर से कोरोना की चौथी लहर का खतरा हमारे सामने है। कोरोना के नये केस सामने आ रहे हैं। इनकी संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। इससे पहले कोरोना के ओमिक्रान वैरियंट के लगभग बेअसर रहने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि कोरोना का अब नाश हो गया है। लेकिन, कहते ही हैं कि वायरस कभी खत्म नहीं होता। हां,उसका असर कमजोर पड़ने लगता है। तो ओमिक्रान के बाद आने और चले जाने के बाद यही लग रहा है कि अगर चौथी लहर आई भी तो वह भी समुद्री लहर की तरह सागर किनारे आकर वापस चली जाएगी। यानी वह घातक नहीं होगी। पर यह सब पक्के से तो नहीं कहा जा सकता है।

देखिए कोरोना के नए-नए वेरिएंट्स अपने साथ नए-नए लक्षण साथ लेकर आने लगे हैं। एक बात पर आपने गौर किया होगा कि जैसे ही कोरोना के नियमों में ढील दी जाने लगी। लगभग तब ही कोरोना फिर से सामने आ गया। इसने लोगों को अपनी चपेट में लेना चालू कर दिया। स्कूल-कॉलेज खुले तो छात्रों में कोरोना फैलना शुरू हो गया है। तो बहुत साफ है कि कोरोना का असर कम भी होने पर मास्क लगाना ही होगा तथा सामाजिक दूरी अपनानी ही होगी।

हाल ही में आईआईटी-कानपुर ने अपने एक शोध के बाद दावा किया है कि भारत में जून में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। यह कहना होगा कि जिस प्रकार से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है आईआईटी का दावा सही हो सकता है। पर क्या यह दूसरी लहर जितनी घातक होगी? इस

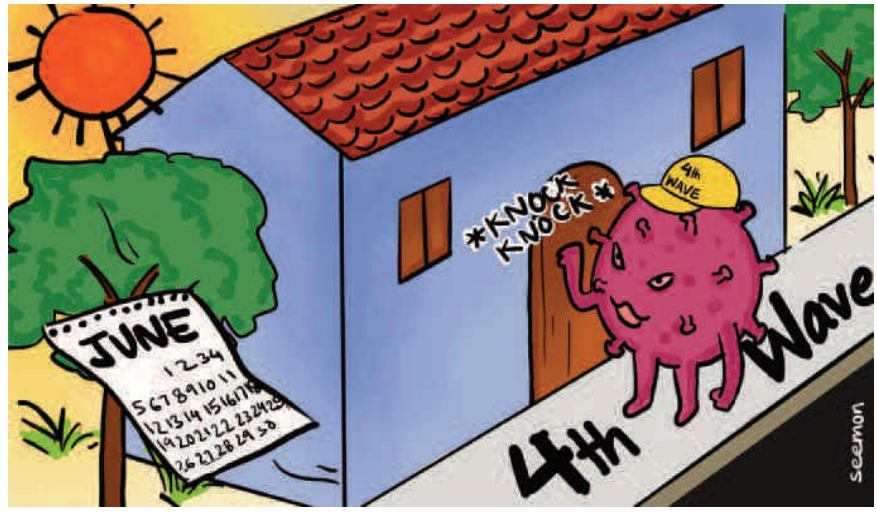

सवाल का जवबा देने की स्थिति में तो अभी कोई नहीं है।

बहरहाल, जिस किसी ने कोरोना की दोनों डोज ले ली है, वे काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। उन पर कोरोना के नए-नए वेरियंट का असर कम होगा। अब कहा जा रहा है कि 18 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को भी ऐहतियातन बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए।

लेकिन, यह जानना आवश्यक है कि टीका लगवाने के बाद जो ऐंटिबॉडी बनती है, वह ज्यादातर मामलों में 8 महीनों तक ही रहती है। एक बात और कि फिलहाल तीसरी डोज उन लोगों को लगवा लेनी चाहिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इसे

अस्पतालों, पुलिस तथा बैंकों कर्मियों को लगवा लेनी चाहिए। कैंसर, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स खासकर टीबी की बीमारी के रोगी भी इसे लगवा लें।

देखिए कोरोना के नए-नए वेरिएंट्स अपने साथ पहले से अलग नए लक्षण लेकर आ रहे हैं। जैसे कि कंपकंपी के साथ बुखार होना या थकान महसूस करना, शरीर में दर्द होना, गले में खराश, नाक का बहना या बंद होना आदि। खैर, यह तो सब मानते हैं कि अब हमें कोरोना के नए-नए वेरिएंट के साथ ही जिंदा रहना सीखना होगा। पर इसके लिए जरूरी है कि अगर हमने अभी तक भी दोनों टीके नहीं लगवाए तो हम अब देर न करें। हमारे अपने देश में अभी तक 65 प्रतिशत लोगों ने ही दोनों टीके लगवाए हैं। एक तिहाई जनता को एक ही टीका लगा है। बच्चों को टीके पूरे नहीं लगे। यह जान लें कि यदि टीका लग गया है तो कोरोना का वायरस कमजोर पड़ेगा। यह अफसोस की बात है कि तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद अब भी बहुत से लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। वे अब भी इसको लेकर सवला खड़े कर रहे हैं। मेरे अपने सर्किल में कुछ लोग समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। इस तरह के लोग अपने को खतरे में डाल रहे हैं। अब वे लोग फिर से मास्क पहन लें जो इसे उतार चुके थे। निश्चित रूप से मास्क कोरोना के नया वेरिएंट के विरूद्ध खड़ा तो होता ही है।

हालांकि अभी कोरोना की चौथी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू ही किया है, इसलिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे कि कोरोना रोगियों के लिए अलग से वॉर्ड तथा बिस्तरों की व्यवस्था करना,पर्याप्त मात्रा में

क्या हर छह महीने पर कोरोना वैक्सीन लेनी होगी, यह जानते हुए भी कि इनसे संक्रमण नहीं रुक रहा?

ऐसा लगता है कि कोरोना की चौथी लहर की दस्तक हो चुकी है। राजधानी दिल्ली के पिछले कुछ दिनों के आंकड़े इसका संकेत कर रहे हैं। हालांकि जिस XE वेरिएंट को इसका कारण माना जा रहा है, उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया ने ओमिक्रोन का ही सब-वेरिएंट बताया है। तीसरी लहर में ओमिक्रोन के कारण भारत में संक्रमण तो बहुत तेज गति से फैला था, लेकिन दूसरी लहर की तरह ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था।

इन सबके बीच मेरे मन में वैक्सीनों को लेकर शुरू से ही सवाल थे, जो आज भी कायम हैं। मेरे सवाल विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नकारात्मक राजनीति के कारण उठाए जा रहे सवालों से अलग विशुद्ध व्यावहारिक (और शायद वैज्ञानिक भी) सवाल थे। ये सारी वैक्सीनें नए कोरोना वायरस को बिना ठीक से समझे बेहद हड़बड़ी में बनाई गई थीं। लगभग सभी वैक्सीनों को बिना प्रॉपर ट्रायल के इमरजेंसी मंजूरी दी गई। इसलिए मुझे शुरू से यह लगता रहा कि दावे चाहे कुछ भी हों, लेकिन इनका लाभ न के बराबर होना है।

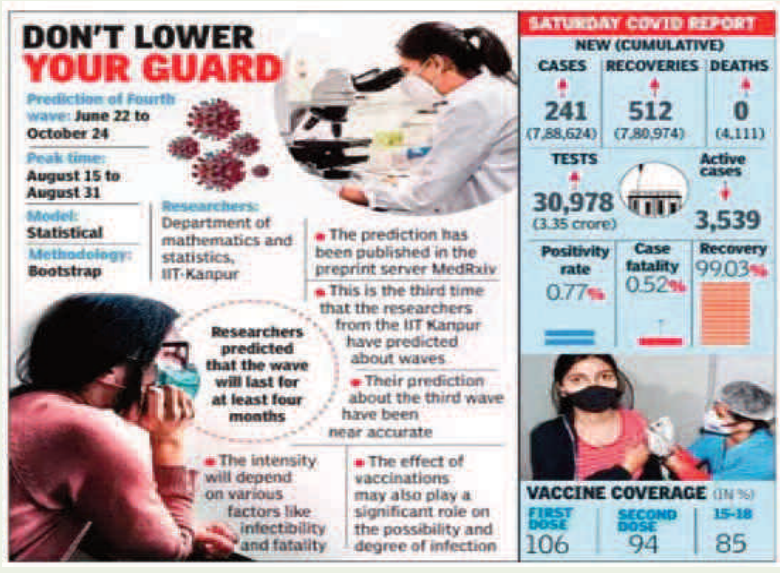

हालांकि यह बात मैं एक बार संकेतों में बोलकर बस इसलिए चुप हो गया था कि यदि लोगों को इसका थोड़ा भी फायदा मिल रहा हो, या कम से कम इतना मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिल रहा हो कि हम प्रोटेक्टेड हैं या डरने की कोई बात नहीं है, तो इसे चलने दिया जाए।

लेकिन आज थोड़ा अधिक खुलकर इसलिए बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि वैक्सीनें हमें संक्रमण से सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। हां, जीवन की सुरक्षा कितना कर पा रही हैं, कितना नहीं कर पा रही हैं, इसके बारे में अब भी मिश्रित राय हो सकती है।

इसलिए अब समय आ गया है कि या तो पुरानी वैक्सीनों की ईमानदारी से समीक्षा की जाए, या फिर कुछ नई वैक्सीनें आएं, जो पहले से अधिक रिसर्च करके, ज़्यादा समय लेकर और अधिक प्रामाणिकता से ट्रायल करके तैयार की गई हों।

याद कीजिए, शुरू में वैक्सीन की एक ही डोज को रामबाण बताया गया था। फिर दो डोज को रामबाण बताया गया। फिर बूस्टर डोज को रामबाण बताया गया। लेकिन तथ्य यह है कि दुनिया के कई देशों में अब वैक्सीन की चौथी डोज लगाई जा रही है, फिर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है और डर का माहौल कायम है। लगभग हर वक्त किसी न किसी देश/देशों में कोरोना का कहर चल ही रहा है, कभी रुका नहीं है।

यदि ऐसे ही चलता रहा तो संभव है कि लोगों को हर छह-आठ महीने पर वैक्सीनें भोंकी जाती रहेंगी और लोग फिर भी संक्रमित होते रहेंगे। हां, जो संक्रमण से आसानी से रिकवर हो जाएंगे, वे इसका क्रेडिट इन वैक्सीनों को अवश्य दे सकते हैं। लेकिन यह भी तो सच है कि अब लोग कोरोना को पहले से अधिक समझने लगे हैं, पहले से अधिक सावधान हो गए हैं, पहले से बेहतर उपचार कर ले रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहले से बेहतर हो गयी हैं! तो पहले की तुलना में अब कम मृत्यु दर का क्रेडिट क्या अकेले वैक्सीनों को दिया जा सकता है?

इसके अलावा, इस बात पर भी तो विचार करना होगा कि कोरोना से सुरक्षा के नाम पर हर छह-छह महीने पर हम जो वैक्सीनें लेंगे, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों अथवा हमारे सम्पूर्ण स्वास्थ्य पर उनके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे? क्या कुछ भी साइड इफैक्ट नहीं होगा? क्या यह संभव है?

इसलिए आप सहमत हों या न हों, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि कोरोना से भारत की सर्वाधिक सुरक्षा आयुर्वेद ने की थी और सर्वाधिक नुकसान मॉडर्न मेडिकल साइंस द्वारा संचालित लूटखोर अस्पतालों ने पहुंचाया था। यह एक ऐसा बिंदु था, जिसपर मेरी राय बाबा रामदेव की राय से लगभग मैच कर रही थी। हालांकि बाबा रामदेव ने जिस लहजे में इस मुद्दे को उठाया था, मैंने उसका समर्थन नहीं किया था।

इसलिए मैं तो कहूंगा कि चूंकि कोरोना अब जाने वाला नहीं है और अगले कुछ साल यह हर छह-छह महीने पर परेशान करता रहेगा, इसलिए सरकार, अस्पतालों और वैक्सीनों पर निर्भर होने के बजाय हमें निम्नलिखित तीन चीजों को मिलाकर अपना सुरक्षा मॉडल विकसित कर लेना चाहिए:

1. प्राकृतिक तरीके से अपनी इम्युनिटी बढ़ाना।
2. अधिकतम सावधानी बरतना।
3. आयुर्वेद को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना, क्योंकि आयुर्वेद एक जादू है, ईश्वरीय वरदान है और मानवता के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा की गई सर्वोत्तम खोज है।

- अभिरंजन कुमार

कोरोना के नए XE वेरिएंट के लक्षण आए सामने, इस तरह बरतें सावधानी

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE के लक्षण

थकावट
बुखार
हाइपोक्सिया
नींद या बेहोशी में बोलना
ब्रेन फॉग
मानसिक भ्रम
वोकल कॉर्ड न्यूरोपैथी
हार्ट रेट हाई होना
त्वचा पर रैशेज या रंग बदलना

अगर आपको गंध और स्वाद का पता नहीं चल रहा है। लगातार बुखार और खांसी बनी हुई है तो आपको कोविड हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें

सभी को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए और समय पर अपनी बूस्टर डोज लें।
जब भी भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाएं हमेशा मास्क पहनकर रहें।
पब्लिक प्लेस पर कपड़े के मास्क की जगह सर्जिकल मास्क या N95 मास्क का ही इस्तेमाल करें।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें।
बाहर से आने के बाद हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें और साबुन से धोएं।
कहीं बाहर से आने पर नहाएं और अपने कपड़े वॉश करें।
सर्दी-खांसी से बचाव रखें और गरारे करते रहें।
इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फल और सब्जियों का सेवन करें।

कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए-नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में लंदन में कोरोना के नए वेरिएंट XE के कुछ मामले सामने आए हैं। अब भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट XE के 2 मामले सामने आए हैं। ऐसे में लोगों के अंदर कोरोना की चौथी लहर को लेकर डर पैदा हो रहा है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया XE वेरिएंट ओमिक्रोन से भी 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में आपको पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। नए XE वेरिएंट के लक्षण काफी हद तक ओमिक्रोन से मिलते जुलते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट एक्सीई भी इतना ज्यादा गंभीर नहीं है। हालांकि आपको सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। जानते हैं कोरोना के नए XE वेरिएंट के लक्षण और कैसे इससे बचा जाए।

ऑक्सीजन सप्लाई सुनिशिचत करना तथा एम्बुलेंस सेवा को तैयार करना। यह सब जानते हैं कि किसी भी राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का काम राज्य सरकार ही देखती है। हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन पर चलते हुए सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य कोरोना की दूसरी लहर के वक्त इससे होने वाली मौतों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दे रहे थे। हालांकि तब तमाम राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोग मारे भी गए थे। लेकिन, सरकारें नहीं मानती कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन, जरा उनसे भी तो पूछिए जिनके परिजन ऑक्सीजन की कमी के कारण संसार से विदा हो गए। मुझे नहीं पता कि सरकारी दावों का क्या आधार है कि कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की जान नहीं गई। हालांकि सच इससे बहुत ही अलग तथा बहुत कठोर है। तब ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लाखों लोग कितने बेबस और बेहाल थे, यह सबको पता है। मुझे याद है तब इंडियन मेडिकल एसोसिशन (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ विनय अग्रवाल तब हालातों से इतने खिन्न हो गए थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि सरकारों ने ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर न बनाया तो वे खुदखुशी कर लेंगे। जरा सोचिए कि देश के डॉक्टरों की सर्वोच्च संस्था का नेता कितना असहाय था तब। डॉ. अग्रवाल ने इस तरह की चेतावनी इसलिए दे डाली थी क्योंकि उनका कहना था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डॉक्टर रोगियों का सही से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इस विकट स्थिति से सैकड़ों डॉक्टर गुजरे थे। भगवान न करें कि अब वही स्थिति फिर कभी आए। तब सारा देश घरों में दुबका हुआ था और सड़कों पर सिर्फ एंबुलेंसों के सायरन बजने की आवाजें आती थीं। सारे माहौल में भय तथा डर था। ऐसे माहौल को फिर से कभी आने नहीं देना है।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

महामारी के बाद कैसा होगा
कल का 'नया' सामान्य

● रमेश शर्मा

महामारी के समाप्त होने की अप्रत्याशित लंबी प्रतीक्षा से उकताई दुनिया में एक नयी विचारधारा पनप रही है कि आखिर, कल का 'नया सामान्य' क्या होगा?

महामारी के संक्रमण के समाप्त होने की अप्रत्याशित लंबी प्रतीक्षा से उकताई दुनिया में एक नयी विचारधारा पनप रही है जिसका केन्द्रबिन्दु है कि आखिर, आगामी कल का 'नया सामान्य' क्या होगा?

वास्तव में वर्तमान दौर का नया सामान्य, व्यवस्था के गहरे दरारों के मध्य हमारे अंत:करण में उगी हुई एक नयी उम्मीद है। महामारी के एकांतवास नें कदाचित पहली बार हमें, हमारे ही कद का अहसास करा दिया है – जिसे दुनिया के कृत्रिम रफ्तार में हमनें खो दिया था। एकाकीपन नें समाज को कठघरे में खड़ा करके यह बताने का प्रयास किया कि अग्रगामी होने का सामान्य अर्थ विवेक के साथ आगे बढ़ना है।

नया सामान्य, मजबूरी में ही सही पूरी दुनिया की सामान्य और समसामयिक सोच का नया विवेकपूर्ण आयाम है। दरअसल यह विवेकपूर्ण विचार, व्यवस्था और समाज के जिन अनुत्तरित सवालों से उपजा है – उनके अंतर्विरोधों को सुलझाने-उलझाने में पीढ़ियां गुजर गयीं। महामारी के मातम नें उन सवालों को हम सबके सामने खड़ा कर दिया।

क्या संभावित आर्थिक मंदी की नई महामारी कोरोना से ज्यादा घातक होगी? क्या अनिश्चित तालाबंदी (या लॉकडाउन) समाज में किसी नये मनोरोग का नया कारण बनेगा? क्या जर्जर होते राजतंत्रों से मोहभंगों की कोई नई व्याधि आयेगी? क्या वैश्वीकृत उदारवादी स्वार्थी समाज की नैतिकता के नये पतन का दौर शुरू होगा? क्या हम अपने ही द्वारा पर्यावरण के प्रति किये गये अक्षम्य विश्वासघात को भूल जाना चाहेंगे? क्या संचितों और वंचितों के मध्य हम उन आर्थिक भेदभाव और अंतहीन लालच को समाप्त करना चाहेंगे? क्या एक जवाबदेह नागरिक होकर हम ढांचागत हिंसा के विरूद्ध मुखरित होना चाहेंगे?

या फिर नये सामान्य को हमनें भी क्या एक सैद्धांतिक सहूलियत मान लिया है? या हम अकारण भयातुर होकर 'नयेपन' में कोई नई सुरक्षा तलाश और तराश रहे? या नये सामान्य के नाम पर हम समाज और प्रकृति के प्रति अपने कारगुजारियों से मुक्त होना चाहते हैं? तथा स्वयं सीखते हुये नयी पीढ़ी को विवेकपूर्ण आचरण के साथ जीना सिखाना चाहते हैं?

प्रगतिशील होने की अपनी ही गढ़ी गयी परिभाषाओं में हमनें विनाश को भी विकास का पर्याय मान लिया। संसाधनों की अंधाधुंध लूट-खसोट को 'न्याय' साबित करने का प्रयास किया, जहां सम्पन्नता के तमाम अवसर चंद लोगों के विशेषाधिकार बन गये। मानव इतिहास में पहली बार 'सम्पन्नों और विपन्नों' के मध्य, लगभग दो-तिहाई दुनिया खड़ी कर दी गयी। ऐसे संक्रमणकाल में नया सामान्य उन दो तिहाई से अधिक लोगों का सपना (भी) है जो महामारी के बाद एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुसंख्यक विपन्न समाज को लगता है कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य मुमकिन है।

लेकिन, तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि पूरी व्यवस्था और समाज 'अहिंसा' को केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित नहीं कर लेता। व्यक्तिवादी सोच पर टिकी शिक्षा; और उस शिक्षा के उत्पाद के रूप में गलाकाट प्रतिस्पर्धा में लिप्त समाजतन्त्र; और उस समाजतन्त्र को पोषित करने के लिये बनाया गया हिंसक अर्थतंत्र; और उस हिंसक अर्थतंत्र की संरक्षक राजतंत्र – वास्तव में इन सबका समुच्चय ही उस ढांचागत हिंसा (अन्याय, असमानता और अलगाव) के रूप में हमारे सामने है जिसे महामारी के मातम ने पर्दाफाश कर दिया है। नये सामान्य के नये दौर के बरअक्स इससे मुक्त होना अब विकल्प ही नहीं बल्कि समाज की सामूहिक इच्छाशक्ति है।

वैसे विगत आधी सहस्राब्दि के संक्षिप्त इतिहास में नयापन अक्सर अपेक्षाकृत 'नई त्रासदी' के साथ ही चलता आया है। इसलिये नयेपन के पूर्वाग्रह को हमें पूरी तरह आत्मसात करने से बचना चाहिये – और होता भी यही है। परिवर्तन की धारा के विरुद्ध तैरना साहस नहीं,

महामारी से बचने के लिए वैश्विक संधि को मुनाफाखोरों से कैसे बचाएं?

संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्था (विश्व स्वास्थ्य संगठन) महामारी आपदा प्रबंधन और महामारी से बचाव के लिए वैश्विक संधि बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। जन सुनवाई हो रही हैं और सरकारों द्वारा आधिकारिक संवाद आगे बढ़ रहा है। पर आरम्भ से ही यह प्रक्रिया संदेह उत्पन्न कर रही है क्योंकि सबको आधिकारिक रूप से अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल रहा है। 200 से अधिक संस्थाओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कानूनविद ने सरकारों से अपील की है कि प्रभावकारी संधि बनाने के लिए यह जरूरी है कि सभी को अपनी बात कहने का मौका मिले और जिन लोगों ने महामारी के दौरान भी मुनाफाखोरी की है उनको संधि प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाए।

यदि महामारी प्रबंधन और आपदा से बचाव के लिए संधि कमजोर बनेगी तो महामारी से मुनाफाखोरी करने वालों पर अंकुश कैसे लगेगा? नतीजतन असामयिक मृत्यु होती रहेंगी और स्वास्थ्य सेवा की कीमतें बढ़ती रहेंगी। रोजगार नष्ट होते रहेंगे और महामारी और मानवीय आपदा व्याप्त रहेगी। और मुनाफाखोर अधिक धनाढ्य होते रहेंगे। यही हाल अनेक संधियों में हुआ है, जहां औद्योगिक और व्यापारिक हित भारी पड़ रहे हैं और जनहित दरकिनार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक संधि में वह उद्योग जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, उनका हस्तक्षेप सर्वविदित है।

कोविड महामारी के दौरान भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारों ने एकजुट होकर महामारी प्रबंधन नहीं किया। अमीर देशों ने अपनी आबादी से अनेक गुना अधिक वैक्सीन टीके होड़ किए, कंपनियों ने मुनाफाखोरी की, दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी हुई, कीमतें आसमान छू रही थीं, महामारी के कारण अनावश्यक लोग संक्रमित हुए, मृत हुए। हाल ही में ओमिक्रोन कोरोना वायरस वाली लहर में 90 प्रतिशत से अधिक लोग जिनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह लोग थे जिनको टीके की एक भी खुराक नहीं लगी थी। दुनिया की कुल आबादी 7 अरब से अधिक है और 12 अरब टीके लग चुके हैं पर ग़रीब देशों के 2 अरब से अधिक लोगों को एक भी खुराक आज तक नहीं नसीब हुई है जब कि अमीर देशों में टीके की चौथी खुराक भी लग रही है। जब ओमिक्रोन लहर में अधिकांश अस्पताल-वेंटिलेटर की जरूरत और मृत्यु तक उन्हीं लोगों में हुई जिन्हें टीका नहीं लगा था तो इन मृत्यु के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए - यदि सबको टीके लगे होते तो अस्पताल-वेंटिलेटर की जरूरत और मृत्यु का खतरा अत्यंत कम रहता। जिन लोगों ने वैक्सीन की होड़ की, और टीके खराब हो कर फेकें गए पर जरूरतमंद से साझा नहीं किए, उनको जिम्मेदार ठहराना जरूरी है कि नहीं?

यदि महामारी और अन्य आपदा से बचना है और उनके प्रबंधन में सुधार करना है तो सबसे पहले व्याप्त सामाजिक अन्याय और ग़ैर-बराबरी को खत्म करना होगा। सामाजिक अन्याय और ग़ैर-बराबरी वाली व्यवस्था के चलते हम मात्र जांच-दवा से स्वास्थ्य आपदा से बच ही नहीं सकते।

यह भी समझना जरूरी है कि सामाजिक अन्याय और ग़ैर-बराबरी वाली व्यवस्था से 99 प्रतिशत आबादी को नुक़सान होता है और उनके मौलिक मानवाधिकार का पतन होता है तो वहीं 1 प्रतिशत अमीर लोग इसी विकृत व्यवस्था के कारण, और अधिक सम्पत्ति और धन पर क़ब्जा करते हैं। इसीलिए कोविड महामारी में भी इनकी सम्पत्ति बढ़ी, धन बढ़ा, जबकि अधिकांश दुनिया ने आर्थिक तंगी झेली, महामारी की वीभत्सता झेली, और तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न मानवीय आपदा की मार भी झेली।

इसीलिए सैंकड़ों लोगों ने एक खुले पत्र के माध्यम से सरकारों से अपील की है कि वैश्विक संधि प्रक्रिया को मुनाफाखोरों के हस्तक्षेप से बचाना जरूरी है। जन-हित सर्वोपरि रहे न कि व्यापार। धनाढ्य देशों और लोगों ने ही कोविड वैक्सीन टीके बराबरी से साझा होने नहीं दिए। बल्कि जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी तो उन्होंने सरकारों पर दबाव बना कर, स्वास्थ्य के निजीकरण को ही बढ़ावा दिया है। इसका एक और उदाहरण है जब दुनिया कि सबसे बड़ी तम्बाकू कम्पनी जो एक दवा कम्पनी की भी मालिक है, उसने महामारी का फायदा उठा कर सरकारों और संयुक्त राष्ट्र पर फिर दबाव डालना शुरू किया। वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि में तम्बाकू कम्पनी के हस्तक्षेप पर क़ानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि जो कम्पनी वैश्विक तम्बाकू महामारी के लिए जिम्मेदार है वह कैसे तम्बाकू नियंत्रण नीति में भाग ले सकती है? यही कम्पनी तो तम्बाकू महामारी की जड़ है। इसीलिए महामारी के दौरान इस तम्बाकू कम्पनी ने, अपनी ही दवा कम्पनी की आड़ में फिर से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। यदि प्रभावकारी वैश्विक संधि बनानी है जिससे कि महामारी प्रबंधन कुशलता से हो और आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न ही न हो, तो इस पूरी प्रक्रिया में, मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले और मुनाफाखोरी में लिप्त कम्पनी और व्यक्तियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाना जरूरी है। पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व ने जोर दिया है कि इस संधि प्रक्रिया में सभी की 'भागीदारी' हो जो मुनाफाखोरी करने वालों के लिए खुला निमंत्रण है।

कोरपोरेट अकाउंटबिलिटी की शोध निदेशक अश्का नाइक ने कहा कि वैश्विक संधि प्रक्रिया में हम लोग, दोराहे पर हैं। क्या सरकारें, मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगी और मुनाफाखोरी और उद्योग की वकालत करने वालों पर अंकुश लगाएंगी, या फिर महामारी और आपदा में मुनाफाखोरी करने वालों को खुली छूट दी जाएगी?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे पहली

संधि थी: वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि (फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन टुबैको कंट्रोल)। इस संधि के आरम्भ से ही तम्बाकू उद्योग का हस्तक्षेप इतना अधिक रहा था कि सरकारों ने वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि के आर्टिकल 5.3 की गाइडलाइन पारित की जिससे कि तम्बाकू उद्योग को संधि प्रक्रिया से बाहर निकाला जाए और संधि और तम्बाकू नियंत्रण में उद्योग के हस्तक्षेप को बर्दाश्त न किया जाए। इसी वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि के आर्टिकल 19 के अनुसार, तम्बाकू उद्योग को उसके द्वारा किए गए मानव जीवन के सर्वनाश और पर्यावरण आदि के नुक़सान के लिए क़ानूनी और आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि में जनसमूह आदि सभी की खुली भागेदारी रहती है परंतु तम्बाकू उद्योग और उसके अनेक बहुरूपिये वाले समूह को बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

वैश्विक महामारी प्रबंधन के लिए संधि प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध रही है। जन-सुनवाई कब होगी, और उसका समय एवं प्रक्रिया क्या रहेगी जैसी महत्वपूर्व बात सिर्फ चंद दिन पहले ही बताए गए हैं। जिन लोगों को विस्तार से मौखिक बोलने का मौका दिया जा रहा है उन्हें 2 मिनट प्रति व्यक्ति का समय दिया गया है, और लिखित सुझाव आदि 250 शब्द से अधिक नहीं हो सकते।

जेनीवा ग्लोबल हेल्थ हब की सह-अध्यक्ष नीकोलेटा डेंटिको ने कहा कि जन-सुनवाई का स्वागत है पर यह सिर्फ नाम-मात्र की जन-सुनवाई नहीं होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया में सामाजिक और जन संगठनों की भागेदारी होनी जरूरी है। हमें बेहतर दुनिया के लिए क्या करना चाहिए - ऐसी एक लम्बी सूची बनाने के बजाए हम लोग यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न देशों को क्या करना होगा जिससे कि भविष्य में आपदा स्थिति पैदा न हो और महामारी प्रबंधन बेहतर हो सके। यह प्रक्रिया चंद हफ़्तों में कैसे पूरी होगी?

जन समूह के खुले पत्र में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महामारी प्रबंधन और आपदा से बचने की बात तो हो रही है पर अनेक सामाजिक अन्याय और पर्यावरण से जुड़े कारण जिसकी वजह से आपात-स्थिति पैदा होती है उनकी बात नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पर, खाद्य असुरक्षा, पशुपालन, ऐसी जीवनशैली जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन होता हो, आदि। सबके लिए समान स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना सतत विकास सम्भव ही नहीं।

इटली की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गिलिया ग्रिलो ने कहा कि जब तक सबके लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं होगी तब तक महामारी प्रबंधन कैसे सुधरेगा और भविष्य में हम कैसे महामारियों से बचेंगे?

सितम्बर 2022 तक, महामारी के बेहतर प्रबंधन और आपदा स्थिति से बचाव हेतु इस वैश्विक संधि का मसौदा आने की सम्भावना है।

- बॉबी रमाकांत

बल्कि विवेक के पैमाने पर होना चाहिये। इसलिये छद्म आचरण में नयेपन के बजाये जरूरत, विवेक को जाग्रत करने की है। उसके बाद नये अथवा पुराने का आग्रह - दुराग्रह अपने आप गौण हो जायेगा।

नया सामान्य कैसा होना चाहिये ? प्रथमत: यह देखने समझने की शिद्दत से कोशिश हो कि क्या व्यवहार की दृष्टि से 'नया' और 'सामान्य' परस्पर विलोम नहीं है? तब जबकि विगत इतिहास यह साबित करता है हर नयेपन नें 'सामान्य' को थोड़ा और 'असामान्य' बना दिया। और तब भी जबकि 'असामान्य' होने को 'सामान्य' होने की अनायास सामाजिक स्वीकृति मिलती गयी।

फिर जब भरा पूरा समाज ही 'सामान्य और असामान्य' के वर्गभेद में दिग्भ्रमित हो तब किसी नये सामान्य का नया मोक्ष इस प्राचीन धरती और उसके सबसे विवेकी जीव को बचा पायेगा इसमें संशय के पर्याप्त कारण (हम) हैं।

वर्ष 2008 में पहली दफा 'नये सामान्य' की धारणा उस दौर मे आयी जब आर्थिक मंदी, राजनैतिक टकराहट, सामाजिक विखंडन और अराजकताओं के चलते सार्थक परिवर्तन की सामूहिक सोच पनपनी शुरू हुई। लगभग 12 बरसों की प्रतीक्षा के पश्चात् महामारी के अवसाद नें पुन: 'नये सामान्य' के सामान्यीकरण पर विश्वास करने मजबूर कर दिया। विडंबना ही है कि जिस 'राज्य व्यवस्था' से असामान्य अराजकता जनमीं, महामारी ने उस पर ही खतरनाक हद तक निर्भर बना दिया। यथार्थ में यह असामान्य की नयी शुरुआत है।

एक और पूर्वाग्रह है - जब 'परिवर्तन' को हमने नयेपन का पर्याय मान लिया। परिवर्तन की अन्त:प्रक्रिया शुरू होनें से पूर्व ही समाज में परिवर्तन लाद देनें से, समाज अवसादों से भर गया। कालांतर में उस समाज को ही हमनें परिवर्तन के विरुद्ध और दकियानूसी ऐसा साबित कर दिया। नयापन तो सैद्धांतिक रूप से उनके लिये है / और होगा - जिन्होनें कुछ मान्यताओं को सच में पुराना मान लेने की सनक पाल रखी है। नयापन व्यवहारिक रूप से उनके लिये भी नया होगा जिन्हें अपनें ही कल से सीखनें में डर लगता है।

तब, क्या 'नये सामान्य' की नई परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिये? उत्तर हां भी है और नहीं भी। 'हां' उनके लिये जिनके पास उम्मीदों भरा एक कल है। और 'नहीं' उनके लिये जो कल के लिये अपेक्षाकृत अधिक उम्मीदग्रस्त हैं। हमें एक 'नई समग्र उम्मीद' के प्रति संवेदनशील होना होगा। एक ऐसी उम्मीद जिसमें हमें सायास कुछ खारिज नहीं करना है बल्कि उन स्थापित मान्यताओं को आत्मसात के लिये प्रयास करना है जिसनें हमें एक 'जिम्मेदार मनुष्य' होनें का अवसर दिया - बस उसे ही साबित करना है। आज और अभी।

(लेखक एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं)

● **अमित त्यागी**

विश्व सागर में प्रकृति एक विशिष्ट आवरण एवं आकृति है, जो प्राकृतिक सुन्दरता, विकटता विभिन्नता एवं विषमता के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। अपने चारों तरफ के विहंगम एवं विभिन्नता से परिपूर्ण दृश्यों को ही प्राकृतिक सौन्दर्य कहते है। जो ब्रहम स्वरूप हैं और स्वत: व्याप्त है। जिसमें कृत्रिमता का कोई समावेश नहीं है। भूमण्डल में फैले मैदान, पठार, रेगिस्तान, चट्टान, हिमाच्छादित पर्वत, नदी-नाले, झील और जंगल आदि सभी प्रकृति का फैला हुआ साम्राज्य है । सृष्टि निर्माण के दौरान ईश्वर का परमोद्देश्य भी यही रहा है कि यह समस्त जीवों , प्राणियों के जीवनानुकूल रहते हुए उनका मार्ग प्रशस्त करे । मानवता को जीवन की आवश्कतानुसार प्रकृति ने अथाह प्राकृतिक संसाधन दिये हैं और उनका दोहन कर उपभोग करने का अधिकार भी। इसके साथ साथ प्रकृति हमसे अपना संरक्षण एवं संवर्धन सम्बन्धी कर्तव्यों का निर्वहन भी चाहती है। प्रकृति के असीमित भण्डार का दोहन एवं उपभोग करना तो उचित है किन्तु प्रकृति का अनैतिक दोहन किया गया तो प्रकृति द्वारा चेतावनी के तौर पर समय-समय पर प्राकृतिक व दैवीय प्रकोप व घटनाओं के माध्यम से सचेत करने के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति धैर्यवान है। क्षमाशील है किन्तु अपने साथ हो रहे अन्यायों को प्रकृति ज़्यादा देर तक सहन नहीं करती है। प्राकृतिक आपदाओ के रूप मे वो मानवता के अस्तित्व को चुनौती दे ही देती है। सम्पूर्ण विश्व में इस समय सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर अनियमित वर्षा चक्र, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग जैसे विषय अपना असर

विकसित देशों के विकास मॉडल और कथित आर्थिक प्रगति की बहुत बड़ी कीमत सम्पूर्ण विश्व चुका रहा है। प्राकृतिक दोहन करने वाले इस भोगवादी माडल में विकसित देशों की 20 प्रतिशत जनसंख्या कुल संसाधनों का 80 प्रतिशत उपयोग करती है। जबकि इन 20 प्रतिशत लोगों के पास कुल संसाधनों का सिर्फ 50 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। अकेला अमेरिका एक साल में इतना अलुमिनियम का कचरा फेंकता है जिससे 6000 जेट विमान बनाए जा सकते हैं। यूरोपियन और अमेरिकी जीवन शैली के में अगर देखा जाये तो इसमे संसाधनो का इतना ज़्यादा दोहन होता है कि अगर इस मॉडल को सम्पूर्ण विश्व में लागू कर दिया जाये तो शायद यह विश्व रहने लायक ही न बचे। सम्पूर्ण विश्व को चुनौतियों मे धकेलने वाले इस मॉडल में आर्थिक संपन्नता को विकास का मापदंड मान लिया गया है। इस माडल के कारण इन देशों में मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परेशानियां आ रही हैं। विवाह संबंध टूट रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं। नशे का सेवन चलन बन गया है। इन देशों में आधी से ज़्यादा आबादी किसी न किसी रोग से ग्रसित है। और विडम्बना देखिये कि इन रोगों में भी इन्होने स्वास्थ्य का व्यापार माडल ढूंढ कर उसे भी आय का जरिया बना लिया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों ने बहुत धन कमाया है। विश्व में दो साल के कोरोना काल/ लाकडाउन के कारण गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रही सही कसर रूस और यूक्रेन युद्ध से पूरी हो गयी है। हाल ही में ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार साल के अंत तक दुनिया भर में करीब 86 करोड़ लोग 145 रुपए (1.9 डॉलर) प्रति दिन से कम में गुजारा करने को मजबूर होंगें। 420 रुपए (5.5 डॉलर) प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 2022 के अंत तक दुनिया भर में करीब 330 करोड़ लोग गरीबी की मार झेलने को मजबूर होंगें। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बढ़ती गरीबी के लिए मुख्य रूप से महामारी को जिम्मेदार कारक माना गया है। बढ़ती असमानता, खाद्य कीमतों में होती वृद्धि और यूक्रेन में जारी युद्ध भी इसकी वजह बताई गयी है। इसके साथ ही सम्पूर्ण विश्व इस समय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन सहित कई चुनौतियों से जूझ रहा है। एक ओर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व में दो ध्रुव बन गए हैं तो हथियारों की होड के बीच परमाणु खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। आपूर्ति श्रंखला के टूटने के कारण वैश्विक आर्थिक हालत बेहद खराब होते दिखने लगे हैं। खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का असर गेंहू की पैदावार पर पड़ा है और गेंहू का दाना सामान्य से छोटा देखा गया है। इस कारण भारत में पर्याप्त उत्पादन के बावजूद गेंहू की पैदावार घट गयी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश के कारण सरकार को स्वास्थ्य आपातकाल लगाना पड़ा तो साइबेरिया जैसे ठंडे प्रदेशों में ग्लेसियर सामान्य से बहुत ज़्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अनियमित जलवायु चक्र सबसे बड़ी समस्या एवं चुनौती बन गया है। इन सबके बीच अगर समाधान की प्रक्रिया पर विचार करें तो भारतीय जीवन शैली आधारित माडल सम्पूर्ण विश्व को समाधान देता दिख रहा है। भारतीय जीवन शैली में उतना ही संसाधन उपयोग का कहा गया है जितनी की आवश्यकता है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि भारत में सुख समृद्धि थी जिसमे धन सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम था न कि सफलता का मापदंड। नैतिकता को धन के ऊपर स्थान दिया जाता था। पश्चिम के व्यापार माडल ने भारत में भी अब वह वर्ग पैदा कर दिया है जिसके लिए धन की प्रचुरता ही सफलता का मापदंड है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि प्राकृतिक असंतुलन, महामारी और पर्यावरण के प्रभाव से धन सम्पदा नहीं बचा सकती है, इसके लिए सम्पूर्ण विश्व को भोगवादी जीवनशैली को त्यागना होगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े बड़े सम्मेलन नहीं बल्कि जमीन पर वास्तविक कार्य करना होगा। मानवाधिकार की आड़ लेकर विकसित देशों को तीसरी दुनिया के देशों में घुसकर उनकी खनिज और संपदाओं का दोहन बंद करना होगा। क्योंकि, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। हम बचेंगे तब देश बचेगा। देश बचेगा तो वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य बचेगा।

दिखाने लगे हैं। औद्योगिकीकरण के कारण मानव इतना ज़्यादा प्रदूषण उत्सर्जित कर चुका है कि प्रकृति अब उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में भी नहीं दिख रही है। पर्यावरण पर शोध करने वाली संस्थाओं की रिपोर्ट मानव को प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन बताती रही है। हमारी असीमित इच्छाओं की परिणीती यह है कि विकास की बात करते करते हमने जंगल काट डाले हैं। जमीन से कोयला और तेल निकालकर जैविक संतुलन बिगाड़ दिया है। संगमरमर और अन्य खूबसूरत पत्थरों के लिए पहाड़ों को काटकर समतल कर दिया है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर वायु और नदियों के जल को अशुद्ध कर दिया है।

यानि कि जल, जमीन और आसमान हर स्तर पर प्रकृति के क्षेत्र में हमने अतिक्रमण किया है। प्रकृति अपने साथ हुयी क्रूरता का बदला क्रूरतम तरीके से लेती है। प्राकृतिक चक्र यदि नियंत्रित है तो सर्वत्र खुशहाली है और अगर एक बार यह अनियंत्रित हो गया तो इसके भयावह परिणाम की कल्पना करना भी आसान नहीं है। कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। यूक्रेन युद्ध के बाद तो हालत सुधरने की शुरुआत से पहले ही बदतर हो गए हैं। रूस और उक्रेन से सामान की आपूर्ति एकदम ठप्प हो गयी है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं और रूस से आयात होने वाले सामान की आपूर्ति बाधक होती चली जा रही है। एक ओर सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देश तेल का उत्पादन बढ़ाने से मना कर रहे हैं तो वहीं रूस से तेल की आपूर्ति की श्रंखला ही टूटने के कगार पर है। भारत अपनी जरूरतों का 80

महंगाई : आयातित चीनी सामान बनाम आत्मनिर्भर भारत

जिस देश में जीतने ज़्यादा उद्योग हैं उस देश ने उतना ही ज़्यादा नुकसान पर्यावरण का किया है। वैश्विक महंगाई की बड़ी वजह चीन है जहां इस समय कई प्रान्तों में लाक डाउन लगा है। उत्पादन ठप्प है। मांग और आपूर्ति का संतुलन गड़बड़ा गया है। चीन की आर्थिक स्थिति डांवाडोल होने का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ता है क्योंकि चीन एक बड़ा निर्यातक देश है। कई तरह के आंतरिक संकटों से जूझते चीन के अंदर वित्तीय भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है। ज़्यादातर देशों में स्वनिर्मित होने वाली वस्तुओं का कच्चा माल भी चीन से आता है। बुखार की दवाई पैरासेटामॉल के लिए भी हम चीन पर आश्रित हैं। वैश्विक परिदृश्य का ताना बाना कुछ ऐसा बन गया है कि देशों में आपसी सामंजस्य बिगड़ने पर आर्थिक सामंजस्य बिगड़ जाता है। चीन वर्तमान में तीन गंभीर संकटों से जूझ रहा है। पहला, विश्व के तमाम देशों में चीन द्वारा चलायी जा रहीं ढांचागत परियोजनाएं निरस्त की जा रहीं हैं। दूसरा, चीन की रीयल एस्टेट कंपनी एवर ग्रैंड पर वित्तीय संकट दिख रहा है। तीसरा, चीन के बिजली उत्पादन में लगातार कमी आ रही हैं। यह तीनों संकट देखने में सामान्य दिख रहे हैं किन्तु इनके प्रभाव बहुत व्यापक हैं। इसको समझने के लिए चीन के पिछले 30 साल के आर्थिक इतिहास को समझना होगा। पिछले तीन दशक में चीन का निर्यात काफी बढ़ा है। चीन द्वारा आर्थिक सहायता देकर अन्य देशों में ट्रेड यूनियन खड़ी की गई जिसकी वजह से अन्य देशों में चीन उत्पादन कम करवाने में कामयाब रहा। भारत में देखें तो उत्पादन का प्रमुख केंद्र कोलकाता में ट्रेड यूनियन के वर्चस्व ने हावड़ा में बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद करा दिया। चूंकि, मांग और पूर्ति के सिद्धान्त में मांग तो कम नहीं हुयी इसलिए पूर्ति के लिए पहले हम आत्मनिर्भर थे, अब चीन पर निर्भर हो गए। चीन ने ऐसा भारत में ही नहीं किया बल्कि वैश्विक बाजार के ज़्यादातर देशों में ऐसा किया। पिछले दो दशक में इस तरह चीन के पास काफी धन उपलब्ध हो गया।

इस धन को चीन ने दूसरे देशों में बुनियादी संरचना खड़ा करने के क्रम में कर्ज देने में प्रयोग किया। चूंकि चीन में घरेलू बचत दर भी ऊंची थी इसलिए चीन के पास धन आवश्यकता से अधिक था। ढांचागत निवेश के द्वारा चीन अन्य देशों में अपनी पैठ बढ़ाता चला जा रहा था। चीन ने इस परियोजना को बीआरआई प्रोजेक्ट(बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव) नाम दिया। 2019 में विश्व बैंक ने इस परियोजना का अध्ययन किया और पाया कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा अन्य देशों को भी लाभ हो सकते हैं। इसके बाद जब इन प्रोजेक्ट्स की जांच हुयी तो पता चला कि इनमे तो व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट्स से जुड़े देश अपने अपने हाथ पीछे खींचने लगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स कई देशों में चल रहे हैं। चीन से यूरोप तक एक रेल लाइन बिछाई जा रही है। यह कजाखिस्तान और पोलैंड से होकर जाती है। म्यांमार में एक बन्दरगाह का निर्माण चल रहा है। पाकिस्तान से होकर एक कॉरीडोर बन रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में भी इसी तरह के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चीन के इन प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार के चलते इनमे कई डूबने की तरफ बढ़ रहे हैं। कई देशों की सरकारें इनसे पीछे हटने लगी हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बीआरआई को उपनिवेशवाद का नया प्रारूप बताया है। म्यांमार ने क्यौकप्यू बन्दरगाह परियोजना को निरस्त कर दिया है। मालद्वीप में चीन समर्थित प्रोग्रेसिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों ने भी इन प्रोजेक्ट्स के स्वरूप को बदलने का आग्रह किया है।

यह कुछ ऐसी बातें हैं जो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। चूंकि, चीन विश्व बाजार में एक बड़ा उत्पादक देश है इसलिए जो जो देश आत्मनिर्भर होंगे वह चीन की घटती अर्थव्यवस्था में खुद को बचा ले जाएंगे। जिन देशों की चीन पर निर्भरता ज़्यादा रहेगी वह स्वयं को संभाल पाने की स्थिति में भी नहीं होंगे। अब अगर चीन के अंदर के दूसरे संकट की बात करें तो वह एवरग्रैंड कंपनी का है। यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मौलिक विचार रहा है। इसमे उनका मानना है कि प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करना अब ज़्यादा आवश्यक हो गया है। इस क्रम में ऋण के मानक काफी कड़े किए गए हैं। इसके लिए तीन मानक बनाए गए हैं। ऋण के सामने कंपनी की संपत्ति, अल्पकालिक कर्ज की तुलना में नकदी, कुल ऋण की तुलना में पूंजी। अगर एक भी मापदंड कमजोर पड़ता है तो उसे ऋण नहीं दिया जाता है। एवरग्रैंड ने समय रहते

अपनी परियोजनाओं को पूर्ण तो किया था किन्तु कोरोना संकटकाल में उसके फ्लैटों की बिक्री कम हो गयी। इससे निपटने के लिए चीन सरकार को अपनी ही सरकारी इकाइयों को आदेश देना पड़ा कि वह इस परियोजना की इकाइयों को खरीद लें। सरकार द्वारा परियोजना को अपने हाथों में लेना दिखाता है कि संकट कितना बड़ा है। यह कुछ उस तरह का संकट है जब 2008 में अमेरिका ने जनरल मोटर्स को वित्तीय सहता देकर बचाया था।

चीन के अंदर तीसरा बड़ा संकट बिजली का है। उसका प्रभाव व्यापक वैश्विक महंगाई का आधार भी बनने जा रहा है। शी जिनफिंग ने प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता दूर करने का जो संकल्प लिया है उसके क्रम में उन्होने अपने यहां के थर्मल संयंत्र एवं अन्य बिजली उत्पादक संयंत्रों को प्रदूषण कम करने का आदेश दिया है। जो बिजली संयंत्र इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे उनमे से कई को बंद कर दिया गया है। चीन में इस कारण बिजली का उत्पादन काफी कम हो गया है। कम उत्पादन के कारण कई व्यावसायिक इकाइयों को बिजली देना बंद कर दिया गया है। 24 घंटे बिजली की उपलब्धता वाले शहरी क्षेत्र भी वर्तमान में बिजली कटने की समस्या से दो चार हैं। अब चूंकि व्यवसायिक क्षेत्र में बिजली कटौती की जा रही है इसलिए बहुत से कुटीर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। घरेलू मांग की आपूर्ति तो शायद चीन पूरी कर लें पर इसका प्रभाव निर्यात पर अवश्य पड़ने जा रहा है। चूंकि, चीन पर बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था भी निर्भर है इसलिए चीन का यह प्रभाव वैश्विक परिदृश्य में अनियंत्रित महंगाई के रूप में भी पड़ने जा रहा है।

-अमित त्यागी

प्रतिशत तेल आयात करता है इसलिए तेल के दाम बढ़ने पर भारत में हर स्तर पर महंगाई का असर दिखने लगता है। कीमतों में उछाल दिखने पर मुनाफाखोर भी सक्रिय हो जाते हैं और परिस्थितियों से उपजी महंगाई विकराल दिखने लगती है। वर्तमान में तेल की कीमतें 105 डालर प्रति बेरल के आस पास चल रही है। तेल की खुदरा दरे देश में 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हैं। डीजल में व्यावसायिक डीजल के दाम ज़्यादा हैं। जेट का ईधन और गैस के दाम भी बहुत ज़्यादा हैं। यानि कि अन्तराष्ट्रिय परिदृश्य का असर भारत पर दिखने लगा है। चीन के कई प्रान्तों में इस समय लाक डाउन है इसलिए चीन से आयात भी लगभग बंद है। चूंकि, कोरोना का असर चीन के उत्पादन पर भी पड़ा है इसलिए चीन से जो आयात हो भी रहा है वह भी बेहद महंगा है। इस समय विश्व की निर्भरता चीन पर बहुत ज़्यादा है इसलिए जो जो देश स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते चले जाएंगे वह स्वयं को श्रीलंका वाली स्थिति से बचाते चले जाएंगे। विश्व पर आए संकट की पुष्टि आक्सफेम की रिपोर्ट कर रही है।

बढ़ती गरीबी, अमीर हो रहे और अमीर :

2022 के अंत तक दुनिया भर में करीब 86 करोड़ लोग 145 रुपए (1.9 डॉलर) प्रति दिन से कम में गुजारा करने को मजबूर होंगें। ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट 'फर्स्ट क्राइसिस, देन कैटास्ट्रोफे' के अनुसार यदि 420 रुपए (5.5 डॉलर) प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 2022 के अंत तक दुनिया भर में करीब 330 करोड़ लोग गरीबी की मार झेलने को मजबूर होंगें। यह रिपोर्ट दुनिया भर में बढ़ती गरीबी, महामारी के कारण आए संकट, बढ़ती असमानता, खाद्य कीमतों में होती वृद्धि और यूक्रेन में जारी युद्ध को प्रमुख वजह बता रही है। ऐसा अनुमान है कि साल के अंत तक पहले के मुकाबले 26.3 करोड़ लोग भीषण गरीबी का सामना करने को मजबूर होने जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन हमने पिछले बीस सालों में किया है उतना पिछले सौ सालो में भी नहीं किया था। खाड़ी देशों से लाखों गैलन तेल रोजाना निकाला गया जिसके कारण वहां जमीन के अंदर एक शून्य पैदा हुआ। पारिस्थितिक चक्र प्रभावित हुआ। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला निकाला गया। नदियों को रोककर बांध बनाए गए। विकास के नाम पर और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य ने भूमि, जल, आकाश तीनों स्थानों पर अतिक्रमण किया। अब रिपोर्ट बता रही हैं कि हम विकास के मापदंड पर दो दशक पीछे पहुंच गए हैं। यानि यह बात तो स्पष्ट है कि विकास के नाम पर हम प्रकृति का दोहन करते रहे और प्रकृति ने एक झटके में मानव जाति को बीस साल पीछे धकेल दिया। हम न तो प्रकृति को संरक्षित रख पाये न मानव जाति को। न खाद्यान्न में महंगाई को नियंत्रित रख पाये न मांसाहार से बचकर जीवों को सुरक्षित रख पाये। यानि कि विकास का यह मॉडल हर स्तर पर सुधार की गुंजाइश वाला मॉडल है। पूंजीवाद का यह माडल मानवता के अस्तित्व के संदर्भ में असफल माडल है।

प्राकृतिक महाचुनौती का समाधान हैं स्मार्ट गांव

परंपरागत शैली को छोडकर हमने पाश्चात्य की यह शैली अपनाकर विकसित देशों का अनुकरण तो किया किंतु उनके दुष्प्रभाव से भी हम बच नहीं पाये। विकसित देश आर्थिक खुशहाली का दंभ तो भरते हैं किन्तु मानसिक खुशहाली उनके पास नही है। फ्रॉस के पूर्व राष्टपति निकोलस सरकोजी ने एक दशक पूर्व समग्रता में खुशहाली ढूंढने के लिए आग्रहपूर्वक कई नोबेल विजेता जैसे लेआर्ड, अमर्त्य सेन, स्टिंगलिज्ग, पार्थदास गुप्ता जैसे अर्थशास्त्रियों को मानवीय खुशहाली का पैमाना निर्माण करने को कहा था जिसका आधार आर्थिक न होकर जीवन स्तर, बेहतर पर्यावरण एवं नागरिक हित हों। उस दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भी कानून पारित करके ऐसे इंडीकेटर बनाने के लिए कहा था जिसमें खुशहाली का आधार जीडीपी व आर्थिक समृद्धि न हो। इसी कारण अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के देशों में शहरी जनसंख्या अब गांव का रुख कर रही है जबकि भारत मे इसका उल्टा हो रहा है। जिस तरह की प्राकृतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं उसका समाधान शहरीकरण में नहीं है। इसके लिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन रोककर गांवों को सुविधा युक्त बनाना होगा। हमें स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव की आवश्यकता है। इसके लिए जीडीपी के मानक भी बदलने होंगे। वर्तमान जीडीपी के मानक भारतीयता, कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अवधारणा के प्रतिकूल हैं। अगर गाय के गोबर एवं अन्य परंपरागत तरीके से कृषि करें तो जीडीपी नहीं बढ़ती है किन्तु अगर रसायन एवं फर्टिलाइजर से स्वास्थ्य को हानि वाली कृषि करें तो जीडीपी बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति योग करके स्वस्थ रहता है तो जीडीपी नहीं बढ़ती है किन्तु यदि बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होता है तो जीडीपी बढ़ती है। यदि गरीब और जरूरतमन्द को दान करें तो जीडीपी नहीं बढ़ती है किन्तु अगर आयकर बचाने के लिए 80-जी के द्वारा फर्जी भी दान करें तो जीडीपी बढ़ती है। दूध दही पीने से जीडीपी नहीं बढ़ती है किन्तु शराब, गुटखा, सिगरेट के सेवन से बढ़ती है।

यानि की जीडीपी के मानक ऐसे हैं जो सिर्फ व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले हैं। आगे यही क्रम सिर्फ भौतिकतावादी चीजों के उपभोग के द्वारा जीडीपी को बढ़ाने का काम करता रहता है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म 'मेकंजी' की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2025 के बीच के दशक में विकसित देशों के 18 प्रतिशत बड़े शहरों में आबादी प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत की दर से कम होने जा रही है। पूरी दुनिया में 8त्न शहरों में प्रतिवर्ष 1-1.5 प्रतिशत शहरी जनसख्या कम होने का रुझान होना संभावित है। भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी किन्तु कृषि व्यवस्था चौपट होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या का पलायन शहरों की तरफ हुआ। शहरीकरण में गौवंश एवं पशुपालन कम हो गया। भारत में गांव से शहर की तरफ पलायन निरंतर बढ़ते क्रम में दिखता है। यदि पिछले 70 सालों की जनसंख्या औसत की तुलना करें तो 1951 में शहरों में रहने वाली जनसंख्या 17.3 प्रतिशत थी। 2011 में यह औसत 31.16 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह हमारी नीतियों, उनके अनुपालन में कोताही एवं अधिकारों के जमीनी स्तर पर न पहुचने का दुष्परिणाम है कि पिछले सात दशक में ग्रामीण जनता का शहरों की तरफ आकर्षण बढ़ा। वर्तमान में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। एक बड़ा शिक्षित वर्ग पढ़ा लिखा होने के बावजूद बेरोजगार है। इसकी वजह हमारी शिक्षा प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था के वर्तमान मापदंड हैं।

जब तक हमारे यहां ग्रामीण स्तर पर शिक्षित होने का अभियान नहीं चला था तब तक गांव में हर व्यक्ति के पास एक रोजगार था। माली, माली का काम कर रहा था। नाई गांव में बाल काटता था। कुम्हार बर्तन बनाता था। धीरे धीरे हमने शिक्षा के नाम पर उनको उनके व्यवसाय में ट्रेंड नहीं किया बल्कि उनको डिग्रियां थमा दी। अब उन्होने अपना मूल काम भी छोड़ दिया। इसके बाद अधिकतर को नौकरी भी मुहैया नहीं करा पाये। पढ़ने के बाद लोगों ने अपने पैतृक कार्य को करना अपनी कमजोरी माना। एक बड़ी आबादी शहरों का रुख करने लगी। वहां जाकर पढे लिखे बेरोजगारों की फौज ने एहसास किया कि वह तो कम रुपये की नौकरी तलाश रहे हैं जबकि इससे ज़्यादा के मालिक तो वह अपने गांव में पहले से हैं। सनातन संस्कृति की जीवन शैली में स्वच्छता का ध्यान, ट्रेफिक नियमों का पालन, जल व्यर्थ न बहना जैसे विषय अब वैश्विक स्तर पर नियम बनाये जा रहे हैं। स्मार्ट गांव के द्वारा प्राकृतिक असंतुलन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जनता के जागरूक होने एवं सामाजिक जिम्मेदारी समझने के बाद बड़ा परिवर्तन भी आ जाएगा।

-अमित त्यागी

अब अगर आक्सफेम की रिपोर्ट को ही माने तो अकेले वैश्विक खाद्य कीमतों में होती बढ़ोतरी करीब 6.5 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल देगी। वहीं विश्व बैंक का अनुमान है की कोविड-19 महामारी के चलते 2022 में 19.8 करोड़ लोग भीषण गरीबी का सामना कर रहे होंगें। बढ़ती गरीबी के कारण लोग अपना पेट भरने के लिए भी संघर्ष करने को मजबूर हो जाएंगे। अनुमान है कि 2022 के अंत तक कुपोषण के शिकार लोगों का आंकड़ा बढ़कर 82.7 करोड़ तक जा सकता है। अकेले पूर्वी अफ्रीका में करीब 2.8 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। अकेले 2020 में कोरोना महामारी के कारण उपजे संकट के चलते महिलाओं की आय को 60.9 लाख करोड़ रुपए की हानि हुई थी जोकि 98 देशों के कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। विश्व बैंक के अनुसार महामारी और बढ़ती असमानता ने पिछले दो दशकों में हुई प्रगति को पलट दिया है। जिनके कारण अकेले 2022 में करीब 19.8 करोड़ लोग चरम गरीबी का शिकार हो जाएंगे। आज दुनिया की एक बड़ी आबादी बढ़ती कीमतों के चलते जीवन-यापन के लिए जद्दोजहद कर रही है। उनके लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी आय खाने पर खर्च करे या उससे अपने चिकित्सा सम्बन्धी बिलों का भुगतान करे। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भुखमरी और कुपोषण का शिकार बनेंगे। पूर्वी अफ्रीका, यमन और सीरिया जैसे देशों में लोग भूख और गरीबी से बुरी तरह त्रस्त हैं। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। वहां सरकार के कुप्रबंधन के कारण सरकार ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ कमजोर देश बढ़ते कर्ज के भंवर जाल में बुरी तरह उलझ गए हैं और उन देशों में मजदूरी और क्रय शक्ति कम हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ गया है। अरबपतियों की संपत्ति नए कीर्तिमान बना रही है। ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र है जिनकी महामारी के दौरान संपत्ति आठ गुना बढ़ गई है। उन्हें जीवाश्म ईंधन से काफी लाभ हुआ है। यानि कि प्रकृति से निकले ईधन से लाभ हुआ है। विडम्बना देखिये कि प्राकृतिक असंतुलन को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति इस माडल के अनुसार सफल है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क मंगल पर मानवता को बसाने जा रहे हैं। एक तरफ पृथ्वी पर करोड़ों लोगों के सामने अस्तित्व बचाने का संकट है तो दूसरी तरफ अमीर लोग मंगल पर मानवता की बात कर रहे हैं।

प्रकृति पारायण बने हम लोग :

प्रकृति अपने साथ हुई क्रूरता का बदला क्रूरतम तरीके से लेती है। कंक्रीट के जंगलों का निर्माण करने के बाद इस बात का एहसास हो चुका है कि वास्तविक जंगल ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे लोग कर्तव्य पारायण होते हैं वैसे ही हमें स्वयं को प्रकृति-पारायण बनाने पर विचार केन्द्रित करना चाहिए।

जैसे जैसे हम उत्पत्ति के स्रोत को स्वीकृति एवं सम्मान देते हैं। भावनाएं एवं ब्रह्माण्ड की शक्तियां आशीर्वाद के रूप मे प्राकृतिक संपदाओं से हमें फलीभूत करने लगती हैं। ये एक प्रकार का प्राकृतिक चक्र है जो यदि नियंत्रित है तो सर्वत्र खुशहाली है और अगर एक बार यह अनियंत्रित हो गया तो इसके भयावह परिणाम की कल्पना करना भी आसान नहीं है। पर्यावरण के विचलित होने से प्रदूषण का प्रभाव बढ़कर मानव ही नहीं अपितु सम्पूर्ण प्राणी-जगत के सम्मुख स्वस्थ जीवन जीने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। नैसर्गिक सुंदरता के निर्माण मे समय लगता है। जिस सुंदरता को हम अभी देख रहे हैं उसके निर्माण में बरसों का समय लगा है। जो हम नष्ट कर रहे हैं उसकी भरपाई भी बरसों मे ही संभव है। यदि आज से हम प्रकृति पारायण बनेंगे तब आने वाली पीढ़ियों के लिए मनभावन नैसर्गिक सुंदरता का अस्तित्व रह पाएगा। जो हम पाना चाहते हैं उसके बीज बोने का आरंभ तो आज से ही कर देंना होगा। यही बीज मंत्र है 'पर्यावरण संरक्षण' का ।

आज हम जिन पेड़ों के फल खा रहे है क्या हमने इन्हें लगाया था ? यह पेड़ हमारे पुरखों द्वारा बीजारोपित किये गए, उनके द्वारा ही अभिसिचिंत किए गए। हम तो उनके प्रयास को प्रसाद के रूप में पा रहे हैं । अब हमें अपनी आने वाले वंश के लिए वन वनस्पतियों एवं जड़ी बूटियों को बोना चाहिए। यह पेड़ पौधे ही जड़ी बूटियां हैं। रोग निवारण का स्तम्भ हैं। हमारे स्वस्थ जीवन का आधार हैं । प्राकृतिक संसाधनों को भी समय समय पर नवसृजन की आवश्यकता होती है अन्यथा दोहन के साथ साथ बड़े भण्डार भी समाप्त हो जाते है। हमारे पास संसाधनों के संरक्षण का बीज मंत्र है। इस मंत्र की व्यापकता को समझने की आवश्यकता है। शरीर, बुद्धि और भावनाएं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ हम सबमें ही नैसर्गिक रूप से पाई जाती है । धन तथा संसाधनों को हम अर्जित भी करते हैं । अर्थात वह स्वउपार्जित होता है तथा पूर्वजों के द्वारा पूर्व संचित धन-संसाधन भी हमें उत्तराधिकार में मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में आज हम स्वउपार्जन से विमुख हुए हैं। हम संसाधनों को उत्तराधिकार में अधिकता से पा रहे है किन्तु हम इनका मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं, तभी अपने कर्तव्य से विमुख है। संसाधनों की बर्बादी कर रहे है। यदि हम पेड़ काटते रहे, वन विनाश करते रहे किन्तु हमने नये पेड़ नहीं रोपे तो एक ऐसी रिक्तता आ जाएगी जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। संतुलन के लिए आवश्यक है कि हम संसाधनों का समय समय पर मूल्यांकन और अंकेक्षण करते रहें। हमारी जीवन शैली भी दो चक्रों पर आधारित है। एक चक्र है

परम्परा, जिसमें आस्था-विश्वास रहता है, दूसरा चक्र है कथित वैज्ञानिक सोच जिसमें विकास रहता है किन्तु शायद हम विकास एवं विनाश की सही विभाजक रेखा का निर्धारण नहीं कर पा रहे है। यही वर्तमान समस्या का कारण है। हमें इन सभी दर्शनों मे सामंजस्य बनाना है। बौद्धिकता तथा नैतिकता से तालमेल साधना है ।

जहां मानवता कार्य क्षमता एवं प्राणी प्रेम के आधार पर एक नर है, वहीं प्रकृति उस सुन्दर आवरण, आकृति तथा उत्पादन क्षमता के आधार पर स्त्रीलिंग के अन्तर्गत रूत्री स्वरूपिणी नारी है। नर का नारी के साथ का परिणाम संतानोंत्पत्ति है। इसी प्रकार मानवता का प्रकृति के साथ विलय निरन्तर प्रगतिशीलता का घोतक है। जैसे जीवन मे स्पर्श का बड़ा महत्व है। मां का स्पर्श बच्चे का दर्द खत्म कर देता हूं। कष्टों को हरने मे सहायक होता है। हमें अपने आने वाले वंश के लिए प्रकृति मां को संरक्षित करना चाहिए। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो भी मां उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं करती। समय समय पर कुछ नसीहत देकर सचेत अवश्य करती है, ऐसी ही नसीहते प्राकृतिक असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के द्वारा प्रकृति हमें दे रही है। इस संदेश को समझना हमें हैं। प्रकृति का स्पर्श मानवता को संतुलित रखता है। मानव द्वारा प्रकृति के शोषण से प्रकृति मां नाराज तो अवश्य है किन्तु मां तो मां है। मान भी जाएगी। सिर्फ एक कोशिश हमें करनी है। मांसाहार भी एक तरह से प्रकृति से खिलवाड़ ही है। शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है इसको अब पश्चिम ने भी स्वीकार कर लिया है। मांसाहार के साथ एल्कोहल का सेवन विचारों को अशुद्ध करता है और स्वभाव में आक्रामकता लाता है। इसके बाद अपराध को प्रेरित करने वाले कारक सक्रिय हो जाते हैं।

ड्रग्स, मांसाहार, पोर्नोग्राफी व नशाखोरी :

समाज में यह चारों चीजें एक कोढ़ की तरह है जिसके कारण न सिर्फ व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है बल्कि विचारों में आक्रामकता आने के कारण परिवार बिखर रहे हैं। आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ने की वजह भी भौतिक जीवन शैली के साथ इन चारों का होना है। इन लतों में उलझे लोग सिर्फ प्रकृति का अनावश्यक दोहन नहीं कर रहे हैं बल्कि उस वास्तविकता से भी दूर हैं जिसमे उनके देश कर्ज के भंवर जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब वापस यदि ओक्सफेम की रिपोर्ट की तरफ लौंटे तो रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर देश बढ़ते कर्ज के भंवरजाल में बुरी तरह उलझ गए हैं। एक ओर उन देशों में मजदूरी और क्रय शक्ति कम हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ गया है। ड्रग्स, शराब, पॉर्न उद्योग कॉर्पोरेट की कमाई का एक बड़ा बाजार है। इस व्यापार के द्वारा समाज और व्यक्ति का कितना नुकसान हो रहा है इस पर कार्पोरेट खामोश रहता है। यह भी एक प्राकृतिक असंतुलन का स्वरूप है जिसमे हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। ये चारों कृत्रिमता के वातावरण के द्वारा काल्पनिक सुख तो प्रदान कर

देती हैं किन्तु धीरे धीरे व्यक्ति को अवसाद की ओर ले जाती हैं। जब बात नशे की होती है तब कुछ लोग इसे सुरूर और आनंद का नाम देते हुये इसके समर्थन में तर्क गढ़ने लगते हैं। कुछ लोग इसे खुशी बांटने का माध्यम बताते हैं तो कुछ गम मिटाने का एक तरीका। कुछ लोग इसे थकान मिटाने के रूप में देखते हैं तो कुछ इसे दोस्ती बढ़ाने का विकल्प बताते हैं। सबके अपने तर्क होते हैं नशे को जायज ठहराने के। सरकारें इसमे अपना राजस्व देख लेती हैं। इसलिए सब कुछ जानते हुये भी सब अपना अपना हिस्से का मुनाफा लेकर खामोश रहते हैं।

इसी तरह जब हम पॉर्न की बात करते हैं तब हमारे जेहन मे नग्नता और अडल्ट फिल्म की तस्वीर उभरती है। हम यह मान कर चलते हैं कि यह व्यस्कों के मनोरंजन का साधन मात्र है। क्षणिक सुख के लिए समाज का एक वर्ग पॉर्न फिल्मों की तरफ आकर्षित होता है। यहां तक देखने पर कोई भी व्यापक दुष्प्रभाव दिखाई नहीं देता है किन्तु शराब और पॉर्न फिल्मों का कॉकटेल समाज में एक नये तरीके का अपराधी वर्ग पैदा कर रहा है। इन दोनों के बीच में उत्प्रेरक का काम करता है उत्तेजना फैलाने वाला विज्ञापन उद्योग। विज्ञापनों में उत्तेजित करते दृश्य धीरे धीरे कब मानसिक विकृति पैदा कर देते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। भोगवादी इस मॉडल को अब एक परिदृश्य के जरिये इसके पीछे के अपराध को समझने का प्रयास करें तो विज्ञापनों मे सिगरेट का धुआं उड़ाता नौजवान चुटकियों मे बड़े बड़े काम कर देता है। खूबसूरत लड़की उसके आस पास मंडराने लगती है। डीओ की खुशबू जैसे लड़की पटाने का माध्यम ही होती है। डिओ लगाओ और अपने आस पास कम कपड़े वाली लड़कियों का जमावड़ा पाओ। इसके बाद खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं तीन यार। यही दर्शक वर्ग जब इन उत्पादों के प्रयोग के बाद नशे की हालत मे पॉर्न को देखता है तो ये उसकी विकृत मानसिकता के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। अब वो मानसिक रूप से अपराध करने के लिए तैयार हो चुका है। हालांकि, उसे खुद मे अभी ज्ञान नहीं है कि उसके द्वारा किया जाने वाला कृत्य एक घिनौना अपराध है। कुछ समय बाद जब व्यक्ति को होश आता है तब तक घटना हो चुकी होती

है। उसके द्वारा अपराध किया जा चुका होता है। उत्प्रेरक अपना दुष्प्रभाव दिखा चुका होता है। अब उसे समझ आता है कि विज्ञापन और पॉर्न मे दिखने वाली सुंदर कन्याएं तो विषकन्याएं थी जिन्होने उसे अपराधी बना दिया है। अब समाज भी उसे धिक्कार रहा है और परिवार भी। जेल की सलाखों के पीछे वो तीन यार भी नदारद हैं जिनके साथ रंग जमाने का दावा किया गया था।

घटना के बाद तरह-तरह के प्रदर्शन और बयानबाजी होती है। कुछ लोग महिलाओं पर अत्याचार के नाम पर झण्डा बुलंद करते हैं। कुछ लोग कानून को कमजोर बताते हैं। कुछ लोग भारतीय संस्कृति के नैतिक पतन पर व्याख्यान देते हैं। कुछ बुद्धिजीवी टीवी चैनल पर प्राइम टाइम की शोभा बढ़ाने बैठ जाते हैं। विपक्ष धरना, प्रदर्शन और रेल रोको के माध्यम से खुद पर ध्यान केन्द्रित करवाने मे कामयाब हो जाता है। यानि कि सब कहीं न कहीं अपनी अपनी जिम्मेदारियों मे व्यस्त हो जाते हैं और कहीं दूर कोई अन्य धुआं, डिओ और तीन यार से प्रभावित होकर ड्रग्स, शराब और पॉर्न से एक नयी घटना को अंजाम दे रहा होता है। इन सब घटनाओं से इतर इस व्यवसाय से जुड़े अरबपतियों की संपत्ति नए कीर्तिमान बना रही है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट 'इंटरनेशनल डेब्ट स्टेटिस्टिक्स 2022' के अनुसार पहले ही गरीबी की मार झेल रहे देशों पर 2020 में 12 फीसदी की वृद्धि के साथ कर्ज का बोझ बढ़कर रिकॉर्ड 65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं यदि निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर कुल विदेशी कर्ज की बात करें तो वो 2020 में 5.3 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 654.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। भारत पर कुल 42.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। इस हिसाब से हर भारतीय करीब 30,776 रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। कर्ज का यह बोझ 2010 में करीब 21.9 लाख करोड़ रुपए का था, जो पिछले 10 वर्षों में 96 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 2020 में 42.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें से 84,254 करोड़ रुपए का तो केवल ब्याज है, जिसे लम्बी अवधि के दौरान चुकाया जाना है।

वैश्विक समाधान के लिए भारत की तरफ देखते देश :

प्राकृतिक असंतुलन और मौसम को नियंत्रित करने के लिए भारतीय जीवन शैली एक कारगर समाधान है। इस जीवन शैली में प्रकृति से उतना ही लिया जाता है जितनी आवश्यकता होती है। प्रकृति को जीव जंतुओं से कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि वह प्रकृति से अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं लेते हैं। पेड़ काटकर कागज बनाना, फर्नीचर बनाना। पहाड़ काटकर पत्थर और अन्य संसाधन निकालना जानवर की आदत नहीं है। जानवर स्वाद के लिए किसी को भोजन नहीं बनाते बल्कि जरूरत होने पर ही शिकार करते

हैं। जानवरों में स्टेटस सिंबल नहीं होता और वह एक दूसरे से होड़ नहीं करते हैं। शायद इसलिए ही प्रकृति को इंसान नहीं जानवर पसंद आते हैं। जानवरों को कोरोना या कैंसर नहीं होता है। जानवरों को बीपी, शुगर नहीं होता है क्योंकि वह जरूरत के लिए खाते हैं स्वाद के लिए नहीं। सनातन जीवन शैली में भी सिर्फ जरूरत का सामान प्रकृति से लेने की धारणा रही है। और इसी आयुर्वेदिक जीवन शैली में समस्या का समाधान पूरे विश्व को दिख रहा है। आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है बल्कि एक पूरी जीवन शैली है।

मानव शरीर पंचतत्व से निर्मित है। ये पंचतत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु । शरीर में जो ठोस है वह पृथ्वी तत्व है। जो तरल द्रव्य है, वह जल है। ऊष्मा अग्नि है। प्रवाहित होने वाला तत्व वायु है। समस्त छिद्र आकाश है। इन सब तत्वों के मध्य सामंजस्य रखने वाला विज्ञान आयुर्वेद है। अगर जीवन शैली संयमित है तो स्वाभाविक रूप से आयुर्वेद शरीर को अपना योगदान देता रहता है और प्रकृति को भी नुकसान नहीं करता है। आयुष और वेद के संयोजन से बने इस शब्द का अर्थ है 'जीवन का विज्ञान' । इस चिकित्साव विज्ञान में आध्यागत्मिक कल्याणि के द्वारा सिर्फ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पक्ष ही नहीं बल्कि नैतिक पक्ष को भी मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। एक ओर अन्य चिकित्सा विज्ञान वाह्य स्रोतों से शरीर की जरूरत पूरी करने पर आधारित हैं वहीं दूसरी यह भारतीय विज्ञान स्वास्थ्य को जीवन शैली से जोड़कर इसको जीवन का ही एक अभिन्न अंग बना देता है। प्रात: काल ब्रह्म-मुहूर्त मे उठते ही योग एवं आयुर्वेद स्वत: अपने प्रभाव मे आ जाता है। इसको तीन भागों में बांटा गया है।

पहले भाग में सुबह सवेरे की जाने वाली योग क्रियाएं हैं। दूसरे भाग मे आहार का स्थान है। शाकाहारी भोजन मे नियमित रूप से प्रयुक्त होने वाले मसाले जैसे हींग, कलौंजी, अदरक, मैथी, अजवाइन, काली मिर्च आदि वह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनके द्वारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। पाचन के लिए आवश्यक अग्नि संतुलित रहती है। मांसाहार और शराब इसमे वर्जित है तीसरे भाग में संस्कार एवं शिक्षा का स्थान है। संस्कार के द्वारा मानसिक उन्नति सुनिश्चित होती है। अपराध नियंत्रित होता है। नैतिकता का मार्ग प्रशस्त होता है। इस तरह से तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आयुर्वेद का आध्यात्मिक चक्र पूर्ण होता है। अब ऑक्सफेम की रिपोर्ट, प्राकृतिक असंतुलन, मौसम का प्रभाव, महंगी चिकित्सा सेवाएं, ड्रग्स और पॉर्न के द्वारा होने वाले अपराध, मानसिक अवसाद, पिघलते ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, जंगलों का कटान, जंगल में लगने वाली असमय आग, समुन्द्र के जल स्तर का बढ़ना और ग्लोबल वार्मिंग जैसे न जाने कितने विषय है जिसका समाधान तीन चरण के इस भारतीय विज्ञान में छिपा है। ■

क्या रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग तीसरे विश्वयुद्ध में बदल गई है?

● संपादन - अनुज अग्रवाल

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल गया है। अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतों ने रूस को हराने के लिए हाथ मिलाया है।

रूस और यूक्रेन की जंग की शुरुआत के 54 दिन बीत गए हैं लेकिन युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हर दिन युद्ध की स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि सेना ने 2 नेप्च्यून मिसाइलों के जरिए ब्लैक सी में तैनात रूस के सबसे बड़े युद्ध पोत को तबाह कर दिया है।

दुनियाभर में इस बात की चिंता है क्या रूस-यूक्रेन का सैन्य संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल गया है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ अकेला रूस है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो देश और यूरोप की महाशक्तियों ने यूक्रेन का साथ देने के लिए हाथ मिला लिया है।

Lviv में एक के बाद कई मिसाइल अटैक, रूस के हमले में तबाह हो गया यूक्रेन का यह शहर

रूस ने भले ही न माना हो कि उसका युद्ध पोत यूक्रेन ने तबाह किया है लेकिन सच्चाई यही है। ब्लैक सी में रूसी जंगी जहाज पर हुआ हमला आसान नहीं है। रूस ने कहा था कि युद्ध पोत में तैनात सभी 500 नौसैनिक और अधिकारी सुरक्षित हैं। वहीं यूक्रेन के दावे इससे अलग हैं।

विश्व युद्ध की हो गई है शुरुआत!

जंगी जहाजों का डूबना, यूक्रेन के शहरों का तबाह होना फिर रूस का अप्रत्याशित रूस से यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करना यह साबित कर रहा है कि युद्ध में वैश्विक ताकतें दखल दे रही हैं। रूस के युद्ध पोत का तबाह होना क्यों यूक्रेन युद्ध में अहम मोड़ है यह जानना जरूरी है।

डूब गई रूस की जंगी जहाज

वैश्विक इतिहास में ऐसे बेहद कम मौके आए हैं किसी जंग में किसी दुश्मन देश ने अपने विरोधी की जंगी जहाज ही डुबो दी हो। विश्व इतिहास में 40 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी देश के युद्ध पोत को एक युद्ध के दौरान दुश्मन देश ने तबाह कर दिया है।

Mariupol में फेल हो गई रूस की धमकी, यूक्रेन ने कहा - मरेंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे

आखिरी बार साल 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच चले युद्ध के दौरान ऐसी ही घटना हुई थी जब बाद में एंटी वॉर शिप मिसाइलों के साथ एक विशाल ब्रिटिश युद्ध पोत तबाह हो गया था। दोनों देशों के बीच युद्ध उतना ही भयानक था जितना कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है।

वैश्विक ताकतों की वजह से थमने लगा है रूस का सैन्य अभियान

अगर यूक्रेन का दावा सच है तो युद्ध पोत को हुआ नुकसान रूस के लिए मौद्रिक और रक्षा दोनों ही लिहाज से बहुत बड़ा झटका साबित होगा। यह रूसी युद्ध पोत जिसे यूक्रेन ने तबाह किया है उसकी कीमत लगभग 5 हजार 718 करोड़ रुपये थी। कीव का कहना है कि उसने 100 करोड़ की लागत वाली दो मिसाइलों के साथ युद्ध पोत को तबाह कर दिया था।

रूस को कितना हुआ है जंग में नुकसान?

रूस के 5,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य के युद्ध पोतों को नष्ट करने में यूक्रेन को केवल 200 करोड़ खर्च करने पड़े। युद्ध जीतने की लालसा रखने वाला रूस बड़े झटके से जूझ रहा है। रूस की सैन्य योजनाएं भी इस जंगी जहाज के डूबने से प्रभावित हुई हैं। रूसी युद्ध पोत एंटी वॉर शिप, आधुनिक हथियार प्रणालियों, एंटी मोर्टार सिस्टम और टॉरपीडो ट्यूब्स से लैस था। यह एक अत्याधुनिक वॉर शिप था जिससे दुश्मन देश कांपते थे।

यूक्रेन की सेनाएं आधुनिक हथियारों से हैं लैस, किन देशों के पास हैं ऐसे खतरनाक युद्ध पोत?

चीन समुद्र का बेताज बादशाह बनता चला जा रहा है। चीन के पास सबसे ज्यादा 777 युद्धपोत हैं। रूस के पास 605, अमेरिका के पास 484 और कोलंबिया और उत्तर कोरिया के पास 450 युद्ध पोत हैं।

Kyiv की सड़कों पर बिखरी लाशें, 900 से ज्यादा मिले शव, रूसी हमले के बाद यूक्रेन में बेघर हुए 50 लाख लोग। अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने दिखाई है रूस के खिलाफ एकजुटता

रूस इस युद्ध को क्यों बता रहा है World War 3?

रूस इस युद्ध को तीसरा विश्व युद्ध कह रहा है।

भारत की अमेरिका को खरी-खरी

विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने अमेरिका की सारी चौधराहट को उसी के धरती पर, उसके हलक में वापस डाल दिया।

अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत में मानवाधिकार हनन को लेकर टिप्पणी के बाद, भारत ने भी उसी की भाषा में, अमेरिका में हो रहे नस्लीय भेदभाव को लेकर मानवाधिकार हनन का आरोप उसी की धरती पर खड़ा होकर लगाया। अमेरिका सपने में भी यह सोचा नहीं होगा कि उसी के जमीन पर खडा होकर भारत उसके आरोपों की धज्जियां उड़ा देगा !?

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका, भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर लगातार नजर बनाए हुआ है ! उसने आगे कहा कि भारत में

मानवाधिकार हनन के मामलों में ज्यादा बढ़ौतरी हुई है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अमेरिकीयों के वाम प्रशासन की इस मानवाधिकार रिपोर्ट का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि भारत को भी अमेरिका में हो रहे मानवाधिकार हनन की बहुत चिंता है, इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का मुंह शर्म से लाल लाल हो गया, आज तक अमेरिका के उपर किसी देश ने मानवधिकार हनन के आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया था।

इस घटना के बाद, अमेरिका से ज्यादा भारत के लिबरल, वामी, कांगी, दलाल मीडिया, गद्दार आदि सदमे में है।

धन्यवाद, सुब्रह्मण्यम जयशंकर जी।

परमाणु युद्ध की चेतावनी के बाद रूस ने रोकी पोलैंड की गैस सप्लाई

यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। इसके साथ ही रूस ने पोलैंड को गैस सप्लाई भी रोक दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध के लिए भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में परमाणु युद्ध के खतरे को कमतर आंका नहीं जाना चाहिए। सर्गेई ने यह आरोप लगाया कि यूक्रेन को हथियार दे रहे पश्चिमी देश और नाटो रूस के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। इधर, यूक्रेन पर रूस के हमले को दो महीने पूरे हो गए। रूसी सेना अब पूर्वी यूक्रेन को निशाना बना रही है। इस इलाके में हवाई हमलों के साथ ही मिसाइलें भी दागी जा रही हैं।

निजी ब्राडकास्टर पोलसैट न्यूज और ओनेट डाट पीएल वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यमल करार के तहत पोलैंड को रूसी गैस की सप्लाई हो रही थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। गैजप्रोम से दीर्घकालिक अनुबंध के तहत गैस खरीदने वाली कंपनी पीजीएनआइजी एसए ने इस खबर पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। इस अनुबंध की अवधि इस साल के खत्म हो रही है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, रूसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, सर्गेई ने एक इंटरव्यू में कहा कि नाटो सेना हथियार उपलब्ध कराकर आग में घी डालने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम चाहता है कि यूक्रेन युद्ध जारी रहे।' सर्गेई ने यूक्रेनी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे नाटो को युद्ध में शामिल होने के लिए कहकर रूस को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'नाटो प्रभावी रूप से रूस के साथ युद्ध में शामिल है और पर्दे के पीछे से हथियार मुहैया करा रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि हम किसी भी स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध की अनुमति नहीं दे सकते।' सर्गेई के इस बयान के जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा, 'रूस हमारे देश का समर्थन कर रही दुनिया को डराने की आखिरी उम्मीद खो चुका है। इसलिए वह तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि रूस को यूक्रेन में हार का आभास है।'

क्रेमिन्ना पर रूस का कब्जा

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेनी शहर क्रेमिन्ना पर रूसी बलों ने कब्जा कर लिया है। ब्रिटिश मंत्रालय ने यह जानकारी मंगलवार को ट्वीट के जरिये दी। ट्वीट में कहा, 'क्रेमिन्ना पर कब्जे की खबर है और इजियम में बड़े पैमाने पर लड़ाई चल रही है। जबकि रूसी बल पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क और क्रामटोरस्क की तरफ बढ़ रहे हैं।' क्रेमिन्ना यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 575 किलोमीटर दूर है। इधर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन के सात बंदरगाहों पर 18 देशों के 76 पोतों को रोका गया है।

मास्को पहुंचे यूएन प्रमुख ने की संघर्ष विराम की अपील

मास्को, एपी : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रमुख एंटोनियो गुटेरस मंगलवार को रूस की राजधानी मास्को पहुंचे। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और यूक्रेन में संघर्ष विराम की अपील की। गुटेरस ने कहा कि यूक्रेन में चल रही लड़ाई का दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहे प्रभाव को कम करना चाहते हैं। यूएन महासचिव इसी हफ्ते यूक्रेन की राजधानी कीव भी जाएंगे।

यूक्रेन को वैश्विक ताकतें प्रत्यक्ष सैन्य सहायता दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध के एक अप्रत्यक्ष पक्ष दूसरे यूरोपीय देश बन गए हैं। अब तक यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने यूक्रेन को 12 हजार 355 करोड़ रुपये की सैन्य सहायता दी है। अमेरिका फरवरी की शुरुआत से ही यूक्रेन को 19 हजार करोड़ रुपये की सैन्य मदद दे रहा है।

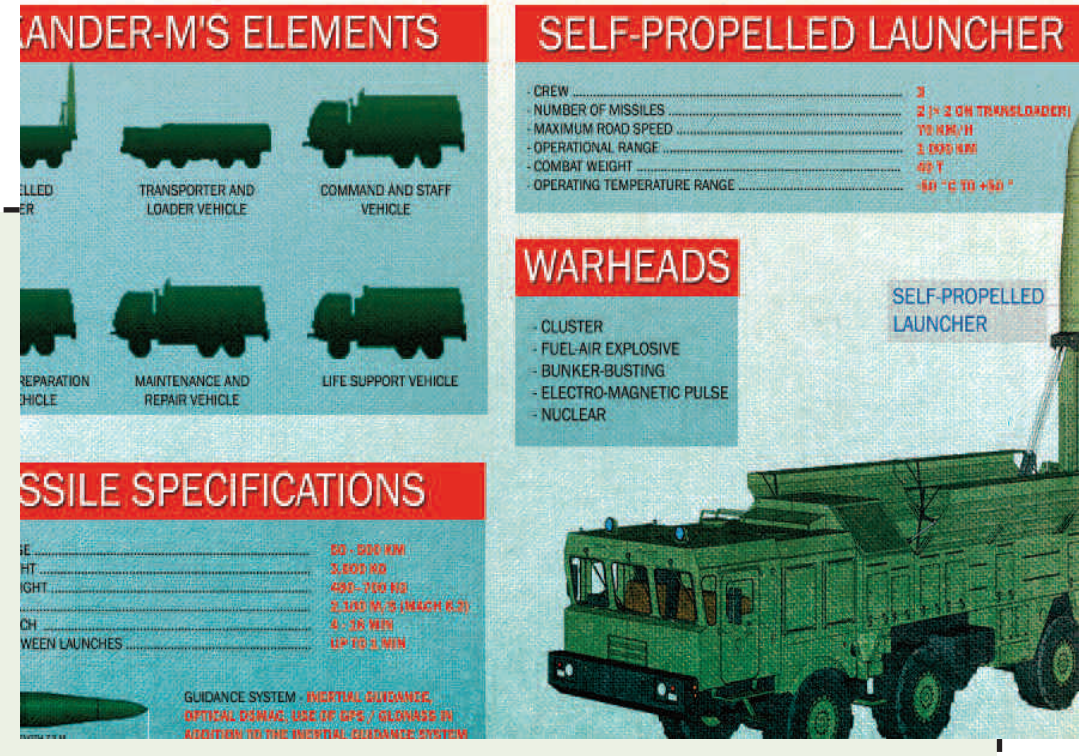

रूस की इस्कंदर मिसाइल कितनी खतरनाक?

रूस की इस्कंदर मिसाइल (9K720 Iskander) ने यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के परमाणु ठिकानों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्हें आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन पहले ही अमेरिका समेत पूरे नाटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे रखी है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई दूसरा देश यूक्रेन युद्ध में शामिल होता है तो उसके ऐसे परिणाम होंगे, जिसे आपने अपने इतिहास में पहले कभी नहीं देखे हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी ऐसी ही आशंका जता चुके हैं।

यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका से डरा है अमेरिका

न्यूजवीक ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि रूस को यूक्रेन में सिर्फ हताशा ही हाथ लगी है। सभी की निगाहें मारियुपोल पर टिकी हुई हैं, लेकिन यूक्रेन के बाकी किसी भी हिस्से में रूस को बहुत कम या कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बीच नाटो ने यूक्रेन के साथ एकता दिखाते हुए अब तक अरबों रुपये के हथियार दिए हैं। इन्हीं के दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। बाइडेन प्रशासन ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि 80 करोड़ डॉलर कीमत के हथियार यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने एंटी टैंक मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, प्रोटेक्टिव सूट समेत कई हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। अमेरिका ने रूसी सेना की हर हलचल की जानकारी भी यूक्रेन को दी है।

रूस के इस्कंदर मिसाइल पर अमेरिका की नजर

अमेरिका के खुफिया और सैन्य अधिकारियों का कहना है कि रूस ने अब तक परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाया है। इसके बावजूद वे रूस के सभी परमाणु ठिकानों पर नजर बनाए हुए हैं। इसमें इसमें Tu-160 ब्लैकजैक और Tu-95 बीयर बॉम्बर भी शामिल हैं। इन दोनों बॉम्बर्स का इस्तेमाल रूस पर परंपरागत बमों से हमला करने के लिए किया जा चुका है। रूस का इस्कंदर मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। सबसे ज्यादा संभावना है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करे। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह बनाई हुई हैं।

कितना ताकतवर है इस्कंदर मिसाइल सिस्टम

रूस का इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसे साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया गया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम का नाटो नाम एसएस-26 स्टोन है। यह सिस्टम वर्तमान में रूसी सेना, आर्मीनियाई सेना और अल्जीरियाई सेना में कमीशन है। यह मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। इसकी मिसाइलें मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं।

इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में कई तरह के हथियार शामिल

इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में अलग-अलग तरीके के हथियार शामिल होते हैं। इसमें क्लस्टर मुनिशन वारहेड, बंकर बस्टिंग के लिए एक अर्थ पेनेट्रेटर और एंटी-रडार मिशन के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस शामिल है। इस सिस्टम की मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। रूस ने स्कड मिसाइल को बदलने के लिए इस्कंदर मिसाइल को शामिल किया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को 1988 में डिजाइन किया गया था, जिसे रूसी सेना में 2006 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था।

लक्ष्य का पीछा कर नष्ट कर सकती है इस्कंदर मिसाइल

इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की सबसे लेटेस्ट मिसाइल इस्कंदर एम को 2018 में लॉन्च किया गया था। इस्कंदर-एम सिस्टम दो सॉलिड-प्रोपेलेंट सिंगल-स्टेज गाइडेड मिसाइल है। इस सिस्टम की हर मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है। इनमें से सभी मिसाइलों में अलग न होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है। जिस कारण ये मिसाइलें स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें नष्ट करने में सक्षम हैं। इस मिसाइल ने रूस जॉर्जिया युद्ध, सीरिया सिविल वॉर, नोर्गोनो कारबाख युद्ध और यूक्रेन में रूस के हमले के दौरान अपनी ताकत दिखाई है।

नाटो (NATO) भी रूस के खिलाफ मिसाइल और अन्य खतरनाक हथियार मुहैया कराकर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। सभी देश, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस के खिलाफ कार्रवाई की है, युद्ध के सक्रिय पक्ष बन गए हैं। यही कारण है कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध को 'विश्व युद्ध 3' कह रहा है।

रूस के लिए यूक्रेन जंग में 'जीत' की तरह से है मारियुपोल पर कब्जा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के रणनीतिक रूप से बेहद अहम शहर मारियुपोल पर जीत का दावा किया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में चली इस सबसे बड़ी जंग में रूसी सेना ने मारियुपोल को 'मुक्त' करा लिया है। मारियुपोल से आ रही रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि पूरे शहर में हर तरफ रूसी झंडे देखे जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि अभी तक रूसी सेना पूरे मारियुपोल शहर पर कब्जा नहीं कर सकी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब दूसरे महीने में पहुंच चुकी है और पुतिन इसे जल्द से जल्द जीत में बदलना चाहते हैं। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि रूस का मारियुपोल पर कब्जा यूक्रेन की जंग में जीत की तरह से है। आइए समझते हैं क्यों मारियुपोल पर जीत अहम है।

विशेषज्ञों के मुताबिक अजोव सागर के तट पर बसे यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल पर कब्जा रूस को उसके नियंत्रण वाले क्रीमिया से स्वयंभू डोनेट्स्क रिपब्लिक के बीच तक जमीनी रास्ता मुहैया कराएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले डोनेट्स्क और लुहान्स्क रिपब्लिक को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी थी। दरअसल, रूस ने 24 फरवरी को तीन मोर्चों यूक्रेन के उत्तरी इलाके में बेलारूस सीमा से कीव और खारकीव, पूर्वी इलाके में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले दोनबास और दक्षिण में क्रीमिया से हमला करना शुरू किया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 58वां दिन है और पुतिन की सेना ने अब पूरा जोर यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर कब्जा करने में लगा दिया है।

हिटलर के कब्जे में रह चुका है मारियुपोल, स्टील बनाने का हब

रूसी सेना ने दक्षिण और उत्तरी इलाके से जारी अपने अभियान को रोक दिया है। रूस का पूरा फोकस मारियुपोल पर कब्जा करने का था जिसे उसने लगभग हासिल कर लिया है। 18वीं सदी के रूसी राजा मारिया फिओडोरोवना के नाम पर बसा यह मारियुपोल शहर रूस में शाही शासन के दौर में अजोव गवर्नर के नियंत्रण में था। 18वीं सदी में रूस ने इस इलाके में आर्थोडॉक्स ईसाइयों को क्रीमिया से मारियुपोल में अजोव सागर के तट पर बसाया। इसके बाद के सालों में यह ब्लैक सी और अजोव तट पर सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में शामिल हो गया। 19वीं सदी में मारियुपोल शहर स्टील बनाने का हब बन गया। इससे यहां पर हजारों की तादाद में कामगार आए।

रूसी हमले में 90 फीसदी मारियुपोल शहर तबाह

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान मारियुपोल पर हिटलर के नेतृत्व वाली जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया जो करीब दो साल तक चला। इस दौरान नाजी सेना ने स्थानीय लोगों की मदद से यहूदियों के खात्मे का अभियान शुरू किया। इसके बाद मारियुपोल शहर को रूस की लाल सेना ने मुक्त कराया और इसका नाम सोवियत वामपंथी नेता एंद्रेई झदानोव के नाम पर झदानोव रखा। साल 1989 में सोवियत संघ के पतन से दो साल पहले इसका नाम एक बार फिर से मारियुपोल रखा गया। ब्रिटिश सेना के पूर्व कमांडर जनरल सर रिचर्ड बैरन ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि मारियुपोल पर कब्जा रूस के युद्ध के प्रयासों के लिए बेहद अहम है। युद्ध खत्म होने पर मारियुपोल से जमीनी रास्ता मिलने को रूसी बड़ी रणनीतिक सफलता के रूप में देखेंगे।

काला सागर के तटीय इलाके के 80 फीसदी क्षेत्र पर रूसी कब्जा

काला सागर में मारियुपोल बंदरगाह का अहम है। स्थान मारियुपोल पर कब्जे के साथ ही रूस ने अब यूक्रेन के काला सागर के तटीय इलाके के 80 फीसदी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इससे यूक्रेन न केवल समुद्री व्यापार से कट जाएगा बल्कि दुनिया से अलग-थलग पड़ जाएगा। रूस ने मारियुपोल पर तोपों, रॉकेट और मिसाइलों से इतनी ज्यादा तबाही मचाई है कि करीब 90 फीसदी शहर बर्बाद हो गया है। मारियुपोल तट गहरा समुद्री बंदरगाह है। यहां से यूक्रेन स्टील, कोयला और मक्के को खाड़ी देशों को निर्यात करता था। यही नहीं मारियुपोल पर कब्जे के बाद अब पुतिन इसे अपनी जनता को जीत के रूप में दिखा सकेंगे जो इस जंग का विरोध कर रही है। पुतिन के लिए यह एक तरह से निजी मामला था जो यूक्रेन के ब्लैक सी से सटे इलाके को 'नए रूस' के हिस्से के रूप में देखते हैं। इसीलिए पुतिन ने इसे 'मुक्ति' नाम दिया है। उधर, यूक्रेन के लिए यह जंग में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। मारियुपोल यूक्रेन का पहला बड़ा शहर है जो रूस के कब्जे में आया है। ■

क्या ताइवान पर हमला कर सकता है चीन?

अमेरिका को चिंता है कि चीन आने वाले समय में ताइवान पर सैन्य हमला कर सकता है। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि सीधे युद्ध के बजाय चीन मनोवैज्ञानिक रूप से ताइवान को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है।

अमेरिकी सैन्य कमांडरो ने आगाह किया है कि चीन ताइवान पर फिर से नियंत्रण कायम करने को उतावला है। लेकिन कुछ जानकारों के मुताबिक बड़ा खतरा चीन की छिपी हुई 'ग्रे जोन रणनीति' में निहित है।

अमेरिकी आशंका का आधार क्या है?

एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर ने आगाह किया है कि ताइवान पर सैन्य हमले की चीन की धमकी, जितना लोग सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा तीखी और दमदार है। उनके मुताबिक ताइवान पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चीन की सबसे पहली प्राथमिकता है।

अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर पद के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एडमिरल जॉन एक्विलिनो को चुना है। एक्विलिनो के मुताबिक, 'मेरा मानना है कि यह समस्या जितना दिखती है, उससे ज्यादा नजदीक और आपात है।' अपने नामांकन पर सीनेट की मुहर के लिए उसके समक्ष पेशी के दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'सबसे खतरनाक चिंता यह है कि ताइवान पर सैन्य हमला हो सकता है।'

एक्विलिनो ने अमेरिकी प्रशासन से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा हितों को मजबूत करने के लिए 27 अरब डॉलर की योजना के प्रस्ताव को निकट भविष्य में तत्काल मंजूरी देने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी, 'चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इलाके में कुछ ऐसी क्षमताएं हासिल कर ली हैं जिनका मकसद हमें वहां से बाहर रखने का है।'

ताइवान पर चीनी हमले की क्या संभावना है?

मार्च महीने में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के अमेरिकी कमांडर फिलिप डेविडसन ने कहा था कि वे यह मान कर चलते हैं कि अगले छह वर्षों में चीन ताइवान का रुख करेगा। डेविडसन ने मार्च में सीनेट की एक कमेटी की बैठक के दौरान कहा, 'मुझे चिंता है कि 2050 तक नियम-कायदों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिकी नेतृत्व की जगह लेने और उसे नीचा दिखाने के लिए चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को फैला रहा है। ताइवान उसकी एक पुरानी लालसा है और इस दशक के दौरान, बल्कि अगले छह साल की अवधि में यह डर बिल्कुल स्पष्ट हुआ है।' लेकिन कुछ जानकार ताइवान पर चीनी हमले की आशंका को खारिज करते हैं।

वॉशिंगटन स्थित सामरिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में चाइना पावर प्रोजेक्ट की निदेशक बोनी ग्लेसर ने डीडब्लू को बताया, 'चीनी हमले के जोखिम को अनदेखा न करना तो ठीक है लेकिन मैं मानती हूं कि निकट भविष्य में ऐसा कोई हमला नहीं हो सकता। अगर चीन को लगेगा कि उनके सारे विकल्प खत्म हो गए तब वे हमले जैसी किसी आखिरी चाल के बारे में सोच सकते हैं।'

ग्लेसर के मुताबिक चीन के पास घरेलू स्तर पर और भी सरदर्द हैं, फिर भी अगले दो वर्षों में ताइवान के सामने सबसे बड़ा खतरा चीन की दबीछिपी रणनीतियों का है।

चीन की दबीछिपी रणनीतियां क्या हैं?

ग्लेसर बताते हैं कि अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन पड़ोसी देशों के खिलाफ ग्रे जोन टेक्टिक अपनाता है। कुछ दिन पहले दक्षिणी चीन सागर में एक चट्टान के पास 200 से ज्यादा चीनी जहाज देखे गए थे। इस जगह पर फिलीपींस अपना दावा करता है। फरवरी में जापान और अमेरिका ने चीन के नए कोस्टगार्ड कानून पर चिंता जताई थी। उक्त कानून के तहत चीनी तटरक्षक दल को विवादित जल क्षेत्र में विदेशी जहाजों पर गोलियां चलाने का अधिकार

दिया गया है। इस विवादित क्षेत्र में पूर्वी चीन सागर का सेनकाकु द्वीप भी शामिल है।

चीन की सबसे ताजा सैन्य कार्रवाइयों और फैसलों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सैन्यकरण को लेकर उसके पड़ोसी देशों का डर फिर से बढ़ा दिया है। ग्लेसर के मुताबिक चीन जानता है कि अन्य देशों पर दबाव डालने में वो उन तरीकों के जरिये समर्थ बना है जो अमेरिका की ओर से संभावित सैन्य प्रतिक्रिया को उकसाने से बस जरा ही कम हैं।

ग्लेसर कहती हैं, 'अगर चीन अन्य देशों को सिर्फ डराता है, परेशान करता है और धमकाता है तो असरदार ढंग से इसका जवाब देने की चुनौती अमेरिका की होगी। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बड़ी संख्या में तटरक्षकों या समुद्री मिलिशिया जहाजों का इस्तेमाल करने की क्षमता, चीन के संप्रभुता के दावों को ही मजबूत करेंगे। इसका मकसद दूसरे देशों को यह याद दिलाने का भी है कि वे चीनी हितों को चुनौती न दें या अंजाम भुगतने को तैयार रहें।'

ताइवान पर चीन किस तरह दबाव बना रहा है?

ताइवान की तामकांग यूनिवर्सिटी में सामरिक अध्ययन के प्रोफेसर एलेक्सैंडर ह्वांग कहते हैं कि ग्रे जोन रणनीति खुल्लमखुल्ला युद्ध जैसी नहीं होती है, फिर भी चीन ऐसे तरीकों से ताइवान पर बहुत दबाव बनाए रखता है।

ह्वांग ने डीडब्लू को बताया, 'चीन की ग्रे जोन तरतीबें ताइवान की लड़ाका क्षमताओं पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती हैं। और चूंकि यह मुकम्मल युद्ध नहीं है तो ताइवान पर यह एक निरंतर दबाव की तरह बना रहता है। मेरे ख्याल से ताइवान को इन ग्रे जोन रणनीतियों के खतरों पर खासतौर से ध्यान देना चाहिए।'

ताइवान स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैन्य विमानों ने 2020 के दौरान ताइवान के हवाई जोन का 380 बार अतिक्रमण किया था।

ताइवान के खिलाफ चीन का 'मनोवैज्ञानिक युद्ध'

ग्लेसर के मुताबिक चीन की ये चालें ताइवान को आगे चलकर बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर

करेंगी। उन्होंने डीडब्लू को बताया, 'विमानों की देखरेख के खर्चों और पायलटों के तनाव और दबाव को देखते हुए ताइवान बड़ी कीमत चुका ही रहा है। अगर पायलट खाली बैठे, दिन में किसी एक जवाबी मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो इस चक्कर में दूसरी किस्म की ट्रेनिंग भी छूट रही है जो ज्यादा जरूरी है। मुझे डर है कि ताइवान के पायलटों को वैसी ट्रेनिंग मिल ही नहीं पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है क्योंकि वे इस खास मिशन पर बहुत ज्यादा समय खर्च कर रहे हैं।'

चीन की ग्रे जोन टेकटिक्स को ग्लेसर ताइवान के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध मानती हैं। वे कहती हैं, 'आखिरकार, चीन इस ग्रे जोन दबाव के जरिये ताइवान के लोगों के जेहन में यह बात डाल देना चाहता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है और एक न एक दिन उन्हें चीन का हिस्सा बनना ही होगा।'

पिछले हफ्ते ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह 'प्रतिक्रिया' टुकड़ी की त्वरित तैनाती के जरिए चीन के इन लगातार हवाई और समुद्री अतिक्रमणों का जवाब देने की योजना बना रहा है।

चीन-ताइवान मामले पर पड़ोसी देशों का रवैया

ताइवान पर चीन के सैन्य दबाव ने पड़ोसी देशों को भी ताइवान क्षेत्र में सैन्य संघर्ष के संभावित प्रभाव पर अलग नजरिया अख्तियार करने को मजबूर किया है। जापानी समाचार एजेंसी क्योडो ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रविवार को बताया कि पिछले हफ्ते, जापानी और अमेरिकी रक्षा प्रमुखों ने टोक्यो में एक बैठक के दौरान, ताइवान और चीन के बीच सैन्य टकराव की स्थिति में, आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जतायी। ताइवान की तामकांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ह्वांग कहते हैं कि 'अच्छी बात ये कि अब ज्यादा से ज्यादा देश ताइवान पर मंडराते संभावित खतरे पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बुरी बात ये है कि ताइवान के संकरे समुद्री गलियारे में खतरे का स्तर इतना ज्यादा है कि पड़ोसी देशों को तो वास्तव में इस पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।'

ग्लेसर के मुताबिक जापान-अमेरिका समझौते ने एक अहम संकेत दिया है कि जापान, चीन को ताइवान के अस्तित्व पर मंडराते खतरे की तरह देखता है। ग्लेसर ने डीडब्लू को बताया, 'यह जरूरी नहीं है कि युद्ध होने पर हम क्या करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि शांति के इस वक्त में अभी हम क्या कर सकते हैं ताकि हम अपना बचाव भी मजबूत रख सकें।'

वह कहती हैं, 'ऊंचे स्तर पर एक बार इशारा हो जाए कि दोनों देश इस विषय पर बातचीत को अपने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अहम मानते हैं तो इससे निचले स्तरों के लोगों में इस विषय पर बातचीत शुरू करने का माहौल और मौका बनेगा। मुझे लगता है कि आगे चलकर ऐसे ही और अवसर बनेंगे। ■

चीन-पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें सीमाओं को मजबूत रखना होगा

● सत्यवान 'सौरभ'

सन् 1970 और 80 के दशक में चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध विकसित हुए। इनसे मुकाबला करना भारत की पहल था। चीन-पाकिस्तान की धुरी दो मोर्चों पर युद्ध की संभावना को खोलता है, इसलिए भारत को सीमाओं पर अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखना अत्यंत जरुरी है। कुछ समय पहले तक, दो मोर्चों पर युद्ध की बातों ने दो परस्पर विरोधी मतों को जन्म दिया। मगर भारत की सेना का दृढ़ मत था कि चीन-पाकिस्तान सैन्य खतरा एक वास्तविक संभावना है, और हमें इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए क्षमताओं का विकास करना चाहिए। दूसरी ओर, सामान्य रूप से राजनीतिक वर्ग और देश के रणनीतिक समुदाय के मुख्य वर्ग ने महसूस किया कि अतिरिक्त संसाधनों और धन के लिए दबाव बनाने के लिए सेना द्वारा दो-मोर्चे के खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐतिहासिक रूप से, चीन ने कभी भी भारत-पाकिस्तान संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है और भारत और चीन के बीच आर्थिक, राजनयिक और राजनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच किसी भी सशस्त्र संघर्ष से इंकार करते हैं। नतीजतन, भारतीय रणनीतिक सोच पाकिस्तान और वहां से निकलने वाले सुरक्षा कारणों पर अत्यधिक केंद्रित थी।

चीनी धन और सामग्री (चीनी निर्मित हथगोले सहित) का उपयोग करके पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बनाए रखने में सक्षम है। जो सीमाओं पर भारत के सुरक्षा तंत्र के लिए खतरा है। वे म्यांमार और बांग्लादेश के साथ खुली और झरझरा सीमाओं का शोषण करके सीमा प्रबंधन को अस्थिर करने के अपने प्रयासों को मिलाने में सक्षम हैं। पीओके के माध्यम से चीन-पाकिस्तान इकनोमिक कॉरिडोर का पारित होना भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय

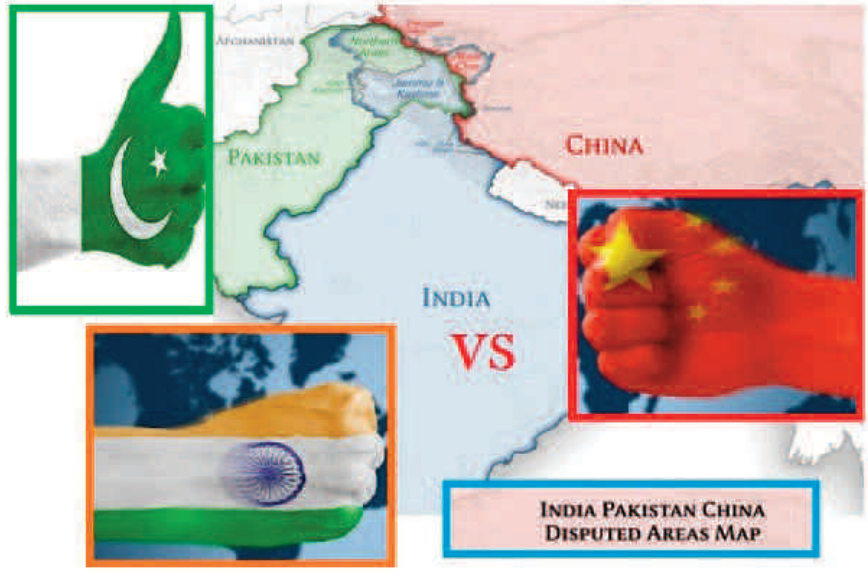

अखंडता को प्रभावित करता है। पाकिस्तान सीमाओं पर दोनों सैन्य उद्देश्यों के लिए बेईदोउ का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे अमेरिका स्थित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर उनकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चीन-पाक की धुरी से निपटने के लिए सीमा ढांचे को मजबूत रखा चाहिए। बॉर्डर रोड इन्फ्रा अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को नियंत्रित करके शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। बुनियादी ढांचे का निर्माण कर भारत सैनिकों की आवाजाही के लिए समय कम करने के लिए ढोला-सादिया पुल जैसे कुछ महत्वपूर्ण पुलों का भी निर्माण कर रहा है। भारत ने चीन को नियंत्रित करने के लिए उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आक्रामक रूप से विकसित करने के लिए जापान के साथ हाथ मिलाया है।

पाकिस्तान से घुसपैठ के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना की शांति समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छह सीमा निगरानी प्रबंधन प्रणालियों (बीएसएमएस) की खरीद कर रहा है। बोल्ड-क्यूआईटी व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के तहत तकनीकी प्रणालियों को स्थापित करने की एक परियोजना है, जो बीएसएफ को ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बिना बाड़ वाले नदी क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सीमाओं को विभिन्न प्रकार के सेंसर से लैस करने में सक्षम बनाती है। यूएवी और अन्य सर्विलांस गैजेट्स जो पहले से ही इंस्टालेशन के अधीन हैं, ने मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली घटनाओं को काफी कम कर दिया है। मिनी यूएवी का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए टोही करना भी है। भारत को इस बात से चिंतित होने की जरूरत है कि चीन पीओके में उस अच्छी नीति को दोहराने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने पहले तिब्बत, शिनजियांग और पूरे मध्य एशिया में लागू किया था। बीजिंग उन अंतरालों

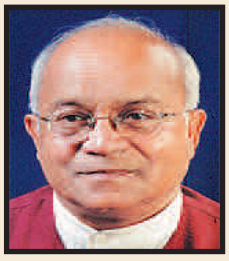

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत-ब्रिटेनः नया धरातल

ब्रिटेन के कई प्रधानमंत्री और महारानी एलिजाबेथ भी भारत आ चुकी हैं लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यह यात्रा दोनों देशों के लिए जितनी सार्थक रही है, वह अपने आप में एतिहासिक उपलब्धि है। जॉनसन का साबरमती आश्रम जाना अपने आप में एक घटना है। जो आश्रम महात्मा गांधी ने बनाया था और जिस गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं, उस गांधी के आश्रम में कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री जाए और जमीन पर बैठकर चरखा चलाए, यह अपने आप में एक किस्सा है। चार किलोमीटर के रास्ते में जॉनसन का हजारों लोगों ने जैसा भाव-भीना स्वागत किया, वैसा उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि उन्हें अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसा अनुभव हो रहा है। ये ऐसे पहले अंग्रेज प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत आकर हिंदी में मोदी को कहा कि वे उनके 'खास दोस्त' हैं।

अंग्रेजी भाषा के गुलाम भारत में आकर कोई अंग्रेज प्रधानमंत्री हिंदी में बोले, यह अपने आप में अजूबा है। इसका पहला कारण तो यह है कि विश्व राजनीति और व्यापार में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरा, आजकल की ब्रिटिश राजनीति में भारतीय मूल के नागरिकों का बढ़ता हुआ वर्चस्व है। अब क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर आ गया है, इसलिए भारत-जैसे बड़े राष्ट्रों के साथ उसे अपने राजनीतिक, व्यापारिक और सामरिक संबंध घनिष्ट भी बनाने हैं। यदि दिवाली तक दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया तो निश्चय ही कुछ वर्षों में भारत-ब्रिटेन व्यापार दुगुना हो सकता है।

आस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए भारत के मुक्त-व्यापार समझौते के सुपरिणाम अभी से दिखने लगे हैं। भारत-ब्रिटेन समझौता तो नए हजारों रोजगार पैदा कर सकता है। जॉनसन ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार योग्य भारतीयों को वीजा देने में उदारता बरतेगी। जॉनसन और मोदी ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भी सामरिक सहकार पर सहमति व्यक्त की है। जॉनसन ने ब्रिटेन द्वारा भारत को बेचे जानेवाले शस्त्रों, नई सामरिक तकनीकों और सामुद्रिक निगरानी की कई तकनीको को देने का भी वादा किया है। दोनों राष्ट्रों ने शस्त्र-निर्माण के संयुक्त कारखाने खोलने का भी संकल्प किया है।

अफगान जनता को पहुंचाई जानेवाली भारतीय सहायता की जॉनसन ने प्रशंसा की और दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बनाने का विरोध किया। दोनों राष्ट्रों ने अफगानिस्तान में सर्वसमावेशी सरकार को जरुरी बताया। ऐसा लग रहा था कि इस दिल्ली-यात्रा के दौरान जॉनसन की कोशिश यह होगी कि वे भारत को अपनी तरफ झुकाएंगे याने उसे रूस की आलोचना के लिए मजबूर करेंगे लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। जॉनसन ने भारत की यूक्रेन-नीति की सराहना की और मोदी की तारीफ में कई कसीदे काढ़ दिए। उन्होंने ब्रिटेन में सक्रिय कई खालिस्तानी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी वायदा किया। उन्होंने भारत को खुश करने के लिए यह भी कह दिया कि वे सीमा-पार से आनेवाले आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना करते हैं। ऐसा लगता है कि इस यात्रा के दौरान जो समझौते और संवाद हुए हैं, वे इन दोनों देशों को संबंधों के नए और ऊंचे धरातल पर पहुंचा देंगे।

को भरने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर की तलाश करेगा जहां भारत काफी हद तक विफल रहा है। पीओके की रणनीतिक स्थिति को दक्षिण, पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया के संपर्क बिंदु के रूप में देखते हुए, चीन के इस कदम के महत्वपूर्ण यूरेशियन क्षेत्र में भारत की पहुंच को सीमित करने के निहितार्थ हैं।

पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर सीमा प्रबंधन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण अर्थात केवल सीमा सुरक्षा पर ध्यान देना अपर्याप्त हो गया है। भारत को न केवल निर्बाधता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, बल्कि सीमा नियंत्रण और निगरानी के लिए नई तकनीकों को अपनाने और डेटा के प्रवेश, विनिमय और भंडारण के लिए एकीकृत प्रणालियों के विकास के साथ, सुरक्षा कर्मियों और भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाले बिना पूर्ण प्रमाण सीमा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना भी है। यह याद रखना

अमेरिका को झुकाया भारत ने

यूक्रेन के बारे में भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हमारे रक्षा और विदेश मंत्रियों की इस वाशिंगटन-यात्रा के दौरान कुछ न कुछ अप्रिय प्रसंग उठ खड़े होंगे लेकिन हमारे दोनों मंत्रियों ने अमेरिकी सरकार को भारत के पक्ष में झुका लिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वह संयुक्त विज्ञप्ति है, जिसमें यूक्रेन की दुर्दशा पर खुलकर बोला गया लेकिन रूस का नाम तक नहीं लिया गया। उस विज्ञप्ति को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको नहीं लगेगा कि यह भारत और अमेरिका की संयुक्त विज्ञप्ति है बल्कि यह भारत का एकल बयान है। भारत ने अमेरिका का अनुकरण करने की बजाय अमेरिका से भारत की हां में हां मिलवा ली। अमेरिका ने भी वे ही शब्द दोहराए, जो यूक्रेन के बारे में भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहता रहा है। दोनों राष्ट्रों ने न तो रूस की भर्त्सना की और न ही रूस पर प्रतिबंधों की मांग की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह मांग जरुर की कि दुनिया के सारे लोकतांत्रिक देशों को यूक्रेन के हमले की भर्त्सना करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन की जनता की दी जा रही भारतीय सहायता का भी जिक्र किया और रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों का भी! ब्लिंकन ने भारत-रूस संबंधों की गहराई को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया। भारत प्रशांत-क्षेत्र में अमेरिकी चौगुटे के साथ अपने संबंध घनिष्ट बना रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों ने अंतरिक्ष में सहयोग के नए आयाम खोले, अब अमेरिकी जहाजों की मरम्मत का ठेका भी भारत को मिल गया है और अब भारत बहरीन में स्थित अमेरिकी सामुद्रिक कमांड का सदस्य भी बन गया है। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने भारत में मानव अधिकारों के हनन का सवाल भी उठाया। जयशंकर ने उसका भी करारा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि पहले बताइए कि आपके देश में ही मानव अधिकारों का क्या हाल है? अमेरिका के काले और अल्पसंख्यक लोग जिस दरिद्रता और असमानता को बर्दाश्त करते रहते हैं, उसे जयशंकर ने बेहिचक रेखांकित कर दिया। जयशंकर का अभिप्राय था कि अमेरिका की नीति 'पर उपदेशकुशल बहुतेरे' की नीति है। जहां तक रूसी एस-400 प्रक्षेपास्त्रों की खरीद का सवाल है, उस विवादास्पद मुद्दे पर भी जयशंकर ने दो-टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह पाबंदी का अमेरिकी कानून है। इसकी चिंता अमेरिका करे कि वह किसी खरीददार पर पाबंदिया लगाएगा या नहीं? यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। जयशंकर पहले अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्हें उसकी विदेश नीति की बारीकियों का पता है। इसीलिए उन्होंने भारत का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में कोई कोताही नहीं बरती।

- डॉ. वेदप्रताप वैदिक

महत्वपूर्ण है कि चीन, एक उभरती हुई और आक्रामक, महाशक्ति, भारत के लिए बड़ा रणनीतिक खतरा है, जिसमें पाकिस्तान बीजिंग की 'भारत को नियंत्रित करने की रणनीति' के लिए दूसरे क्रम का सहायक है। इसलिए, भारत को राजनीतिक रूप से भारत पर लक्षित चीन-पाकिस्तान नियंत्रण रणनीति के प्रभाव को कम करने के लिए वह करना चाहिए जो वह कर सकता है। एक शोध पत्र में कहा गया है कि दो मोर्चों के खतरे के परिदृश्य में, चीन के साथ सैन्य विषमता चौड़ी हो गई है जबकि पाकिस्तान के साथ पारंपरिक विषमता में अंतर कम हो रहा है। संयुक्त खतरे का मुकाबला करने के लिए, भारतीय सशस्त्र बलों को भारत-विशिष्ट सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता है। यह अंतरिक्ष युद्ध लड़ने और एलओसी और एलएसी के साथ प्रौद्योगिकी के साथ-साथ 'बूट्स ऑन द ग्राउंड' को तैनात करने में मदद करेगा। ■

इमैनुएल मैक्रों फिर चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति

● अनुज अग्रवाल

राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंद्वी विपक्षी नेता मरीन ली पेन को हरा दिया। इस तरह 44 वर्षीय मैक्रों 20 वर्षो में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। चुनाव में मैक्रों को 57 से 58 प्रतिशत मत मिले हैं। विपक्ष की उम्मीदवार ली पेन 42 से 43 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन ही जुटा पाई। मैक्रों की जीत के विरोध में पेरिस में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।

यूक्रेन विवाद पर भी पड़ेगा प्रभाव

परमाणु हथियार से संपन्न विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक फ्रांस के इस मतदान के परिणाम का यूक्रेन विवाद पर भी प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपति पद पर फिर से चुने जाने के बाद मैक्रों के सामने पहली बड़ी चुनौती जून में होने वाला संसदीय चुनाव है। विपक्षी दल शीघ्र ही चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जीत के बाद मैक्रों समर्थकों ने फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के झंडे हाथ में लेकर जश्न मनाया।लोग मैक्रों के समर्थन में नारे लगा रहे थे।

यूरोप के लिए बेहद मायने रखते हैं नतीजे

फ्रांस में इस चुनाव के लिए रविवार को शाम सात बजे तक मतदान के बाद मतगणना शुरू हुई। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों की मानें तो ये चुनावी नतीजे पूरे यूरोप के लिए बेहद मायने रखते हैं। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक मैरीने ले पेन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में उनका अभूतपूर्व स्कोर स्वत: ही एक शानदार जीत दर्शाता है। हम जिन विचारों को मानते हैं वे शिखर पर पहुंच रहे हैं। मालूम हो कि मैरीने ली पेन फ्रांस के राष्ट्रपति पद की दौड़ में तीसरी बार उतरी हैं।

मरिन जीती जातीं तो बदल जाये वैश्विक समीकरण आ जाता बड़ा भूचाल -

फ्रांस में राष्ट्रपति चुनावों के बीच जनमत पूरी तरह बंट गया है। इस बार अमेरिका समर्थक राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और रूस समर्थक दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ले पेन के बीच कड़ा मुकाबला रहा। इमैनुएल मैक्रों आरोप लगा चुके हैं कि मरिन चुनावों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मदद ले रही हैं। मरिन ने वादा किया था कि अगर वे राष्ट्रपति बनती हैं तो फ्रांस को नाटो व यूरोपियन यूनियन से अलग कर देंगी व रूस पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा देंगी।अगर ऐसा हुआ होता तो इससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाती । रुस व चीन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती व अमेरिका व ब्रिटेन को बढ़ा झटका लगता।

भारत समर्थक ले पेन ने वादा किया था कि अगर वो सरकार में आईं, तो हिजाब पहनने पर बैन लगाएंगी। वहीं, ला रिपब्लिक एन मार्च (रिपब्लिक ऑन द मूव) पार्टी के नेता इमैनुएल मैक्रों का चुनाव में एजेंडा अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहा। मैक्रों फ्रांस को सबसे बड़ी एटमी ताकत बनाने की बात भी कह चुके हैं।

मरिन का एजेंडा पूरी तरह रुस समर्थक ही है। उनकी घोषणाओं व वादों ने फ्रांस व दुनिया में भूचाल ला दिया है। फ्रांस में जनता उसी तरह दो भागों में बंट गयी है जैसा कि ब्रैंजिट के समय ब्रिटेन बंट गया था। अगर मरीन जीत जातीं तो यूरोप में व्यापक बदलावों व गुटबाजी का नया दौर प्रारंभ हो जाता।

यद्यपि वे हार गयी हैं तो भी फ्रांस व यूरोप में रूस बनाम अमेरिका की बहस व्यापक होती जाएगी और अमेरिका को यूरोप को क़ाबू में रखना मुश्किल हो जाएगा।अगले कुछ वर्षों में बदलते वैश्विक समीकरणो को गति मिलेगी और दुनिया एक झटके में दो गुटों में स्पष्ट रूप से बंट जाएगी।हर देश अपने फायदे व नुकसान के अनुरूप गुट चुनेगा। दो यूएनओ, दो विश्व बैंक और दो आईएमएफ तो डॉलर और पौंड के समानांतर रूबल और यूआन खड़े हो जाएंगे। इससे दोनो गुटों के मध्य तनाव व टकराव बढ़ता जाएगा और दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी होगी। ■

शहबाज शरीफ का कश्मीर राग दुर्भाग्यपूर्ण

● ललित गर्ग

पाकिस्तान में एक और सत्ता की तख्ता पलट का नाटक पूरी दुनिया ने देखा। सत्ता में बने रहने के इमरान खान के सारे दांवपेच बेकार साबित हुए। शनिवार देर रात नेशनल असेंबली में बहुमत खो देने के बाद सरकार गिर गई। फिलहाल विपक्ष जीत गया है। सत्ता की कमान अब देश के मंजे हुए राजनेता शाहबाज शरीफ के हाथों में आ गई है। वे तीन बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नवाज शरीफ की गैरमौजूदगी में पार्टी की अगुआई करते रहे हैं। पाकिस्तान के इस घटनाक्रम के बाद देश के राजनेताओं में ज्यादा समझदारी आएगी या दिशाशून्य हो जायेंगे? मालूम नहीं। पक्ष एवं विपक्ष का यह सारा शोर दूसरे को दोषी ठहराने का था और चुप्पी अपने दामन के दाग छिपाने की थी। यह घटनाक्रम सिर्फ किसी को सत्ता से बेदखल करने और किसी को सत्ता हासिल होने के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें इमरान खान ने अपने साथ-साथ पाकिस्तान की भी खूब फजीहत करायी। वह इस तरह बेइज्जत होकर पदमुक्त होने वाले अपने देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। वह चूंकि अपनी पूरी फजीहत कराकर रुखसत हुए हैं, इसलिए उन्हें आने वाले दिनों में राजनीतिक मोर्चे के साथ-साथ प्रशासनिक मोर्चे पर भी खूब संकटों का सामना करना पड़ेगा। उनके विदेश जाने पर एक तरह से रोक लग गई है और उन्होंने अपनी कमजोरिया, गलत नीतियों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा की वजह से अपने विरोधियों को मौका दे दिया है। दरअसल, जब आप लोकतांत्रिक और सांविधानिक संस्थाओं पर विश्वास करते हैं, तब ये संस्थाएं भी आप पर विश्वास करती हैं और मजबूती देती हैं। लेकिन जिस तरह इमरान ने खुद को बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया है, अदालत के आदेश के बावजूद संसद से बचने की अंतिम समय तक कोशिश की है, उससे उन्होंने खुद अपने लिए कांटे बिछा लिए हैं।

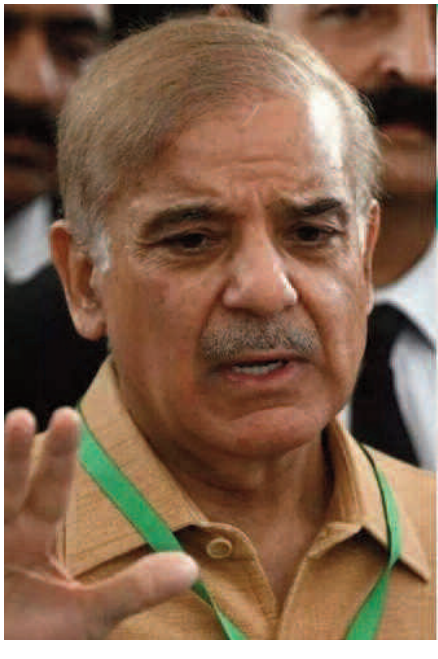

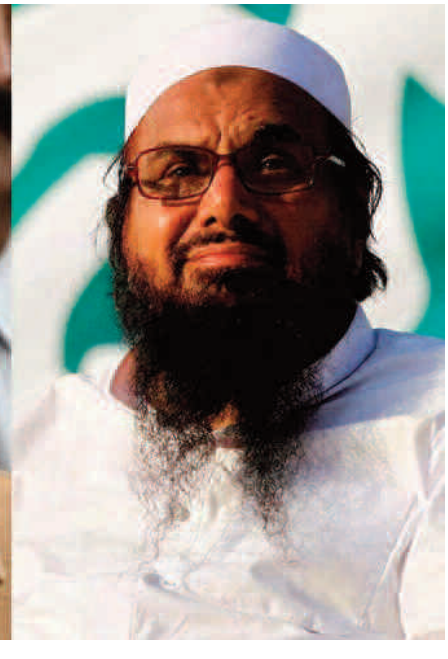

पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम और खासतौर से हाल के एक हफ्ते की गतिविधियां बता रही हैं कि पाकिस्तान के भीतर दरअसल चल क्या रहा है। सरकार गिराने के लिए इमरान खान और उनकी पार्टी विदेशी ताकतों पर आरोप लगा रही है। सेना ने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से अपने को अलग रखने की बात कही। और सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि विधायी तंत्र के घटनाक्रम को लेकर देश का सुप्रीम कोर्ट एक सजग प्रहरी के रूप में खड़ा रहा। वरना क्या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो पाता? पाकिस्तान की राजनीति में कई नेता नेपथ्य में चले गये हैं पर आभास यही दिला रहे हैं कि हम मंच पर हैं। कई मंच पर खड़े हैं पर लगता है उन्हें कोई 'प्रोम्प्ट' कर रहा है। बात किसी की है, कह कोई रहा है। इससे तो कठपुतली अच्छी जो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। जो करवाता है, वही करती है। कठपुतली के अलावा कुछ और होने का वह दावा भी नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता की स्थिति हर दौर में किसी कठपुतली से कम नहीं होती। क्योंकि कहने को वहां लोकतांत्रिक सरकारें बनती है, लेकिन उन पर नियंत्रण सेना एवं आतंकवादी संगठनों का ही रहता आया है। वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास यही रहा है कि वहां सेना किसी की सगी नहीं रही। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शाहबाज भी सत्ता में तभी तक टिकेंगे, जब तक सेना चाहेगी। वैसे भी पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने हैं। शाहबाज को सत्ता भले मिल गई हो, पर उनके सामने भी वही मुश्किलें और चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान में हर प्रधानमंत्री को विरासत में मिलती रही हैं। शाहबाज के सामने चुनौतियां अधिक इसलिये भी है कि वहां की आर्थिक स्थितियां बिखरी हुई है, अमेरिका का संरक्षण भी बिखर चुका है। जनता महंगाई के कारण त्राहि-त्राहि कर रही है।

कहने को पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार चलाने के लिए जिस परस्पर बुनियादी विश्वास की जरूरत पड़ती है, इसका अभाव पाकिस्तान में नया नहीं है। क्या इस अविश्वास को अगले प्रधानमंत्री दूर कर पाएंगे? जिन विपक्षी दलों ने एक सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उन पर अब जिम्मेदारी है कि मिलकर देश को अच्छी सरकार

शरीफ कितने रहेंगे भारत के साथ शरीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भारत के साथ दोस्ती तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों की इच्छा जताई है। यह सुखद है। वर्ना पाकिस्तानी सेना के साए में रहने वाली वहां की सरकारों के लिए भारत से संबंधों को मधुर तथा मजबूत बनाने के बारे में सोचने से पहले रावलपिंडी के आर्मी हाउस से हरी झंडी लेनी पड़ती है। अब दोनों देशों को बिना देर किए कम से कम आपसी व्यापार तथा सरहद के आरपार रहने वाली जनता को एक-दूसरे से मिलने जुलने की इजाजत देने में देरी नहीं करनी चाहिए। शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए मुसलमानों के हितों के लिए लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी मुत्ताहिदा कौमी मुवमेंट (एमक्यूएम) भी है। इसके नेता अल्ताफ हुसैन की यही मुख्य मांग रही कि मुहाजिर परिवारों को अपने बच्चों के निकाह उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली वगैरह के परिवारों में करने की इजाजत मिले। यह सच है कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खी रहने के कारण बंटवारे के वक्त बंटे परिवार हमेशा के लिए एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। खैर, शरीफ तथा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल के दिनों में हुए संदेशों के आदान-प्रदान से यह उम्मीद बंधी है कि सरहद के आर-पार रहने वाले परिवार फिर से करीब आएंगे। ये आपस में निकाह करके रि़श्तों की डोर को बांधे हुए थे। कुछ दशक पहले तकहर साल सैकड़ों निकाह होते थे, जब दूल्हा पाकिस्तानी होता था और दुल्हन हिन्दुस्तानी। इसी तरह से सैकड़ों शादियों में दुल्हन पाकिस्तानी होती थी और दूल्हा हिन्दुस्तानी। नवाब मंसूर अली खान पटौदी के रिश्त के भाई तथा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शहरयार खान ने चंदेक साल पहले अपने पुत्र के लिए भोपाल की कन्या को अपनी बहू बनाया था। उनके फैसले पर पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने शहरयार पर हल्ला बोलते हुए कहा था 'शर्म की बात है कि शहरयार खान को अपनी बहू भारत में ही मिली।' जवाब में शहरयार खान ने कहा, 'भोपाल मेरा शहर है। मैं वहां से बहू नहीं लाऊंगा तो कहां से लाऊंगा।'

आप पाकिस्तान के चोटी के अखबारों में छपे वैवाहिक विज्ञापनों को देख लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि वहां पर मुहाजिर किस तरह से पुरखों की जड़ों से जुड़े हुए हैं। आपको तमाम विज्ञापनों में ये लिखा मिल जाएगा, वर (वधू) यूपी से हों या यूपी से संबंध रखते हैं। यूपी का मतलब ही मुहाजिर से है। उधर यूपी में वे सब लोग शामिल हो जाते हैं, जो भारत से जाकर बसे थे।

तिजारती रिश्ते शुरू हों

भारत की यह भी चाहत है कि कश्मीर मसला हल होने से पहले ही दोनों पड़ोसी मुल्क अपने व्यापारिक संबंधों को एक्टिव कर लें । चूंकि शाहबाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का संबंध एक बिजनेस करने वाले परिवार से है, इसलिए वे भारत की चाहत का सम्मान करेंगे। जानने वाले जानते हैं कि शरीफ परिवार की स्टील कंपनी 'इत्तेफाक' का भारत की चोटी की स्टील कंपनी जिंदल साउथ वेस्ट (जेएसडब्ल्यू) से कारोबारी संबंध है। जेएसडब्ल्यू के चेयरमेन सज्जन जिंदल के शरीफ परिवार से निजी संबंध हैं। इस बात को कभी शरीफ परिवार ने छिपाया नहीं है।

शरीफ सीखें चीन से

पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री तथा सरकार को भारत-चीन संबंधों से सीखना होगा। भारत-चीन के बीच जवाहर लाल नेहरू के जमाने से ही जटिल सीमा विवाद है, पर इसके साथ दोनों देशों के बीच तिजारती रिश्ते भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। फिलहाल दोनों देशों का दिवपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के करीब पहुंच रहा है। साफ है कि भारत-चीन आपसी व्यापार बढ़ता ही रहेगा। तो चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के नारों को कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। हकीकत यह है कि भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों तथा मोबाइल फोन कंपोनेंट्स का बहुत बड़े स्तर पर आयात करता है। हमारी फार्मा कंपनियों की भी चीन पर निर्भरता तो खासी अधिक है। इस निर्भरता को हम कुछ महीनों में या नारेबाजी मात्र से तो खत्म नहीं कर सकते। जब तक हम खुद आत्म निर्भर नहीं हो जाते तब तक तो हमें चीन से विभिन्न उत्पादों का आयात करना होगा।

बहरहाल, अब भारत-पाकिस्तान के आपसी व्यापार की हालत को जान लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) मानता है कि अगर दोनों देशों की सरकारों की तरफ से आपसी व्यापार को गति देने की पहल हो तो 2.7 अरब ड़ॉलर का आंकड़ा 10 अरब ड़ॉलर तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान की धूल में जाती अर्थव्यवस्था को पंख लगाने की शाहबाज शरीफ को कसकर कोशिशें करनी होंगी। फिलहाल उनका देश अर्थव्यवस्था भारी संकट में है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले बेहद कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है। इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा गए हैं। वे कहते रहे कि अमेरिका उन्हें हटाना चाहता है। इस कारण अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है। हलांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को बार-बार संकट से निकाला है। पाकिस्तान की धूर्त और भ्रष्ट सेना को भी यह समझना होगा कि भारत के साथ शांति के रास्ते पर चलकर ही उनका मुल्क विकास कर सकेगा। उसका एक पक्ष व्यापारिक संबंध मजबूत करना भी है। पाकिस्तानी सेना ने देश की प्राथमिकताएं बदली हैं। पाकिस्तान में शिक्षा बजट से सात गुना अधिक है रक्षा बजट। इस सोच के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है।

शरीफ को लेकर की जा रही इन तमाम उम्मीद भरी बातों के बीच अभी उन्हें साबित करना होगा कि वे सच में अपने मुल्क का भला चाहते हुए अपनी एक असल में शरीफ प्रधानमंत्री की इमेज को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। शाहबाज शरीफ के साथ एक बड़ी चुनौती यह भी रहेगी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब घनघोर रूप से भारत विरोधी रहा है। क्या वह अब बदलेगा यह भी देखना होगा। इसके लिए शाहबाज शरीफ को पंजाब में भारतीय विरोधी मनाहैल को खत्म करना होगा। यह संभव है क्योंकि उनका और उनकी पार्टी का पंजाब में गजब का असर है।

- आर.के. सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

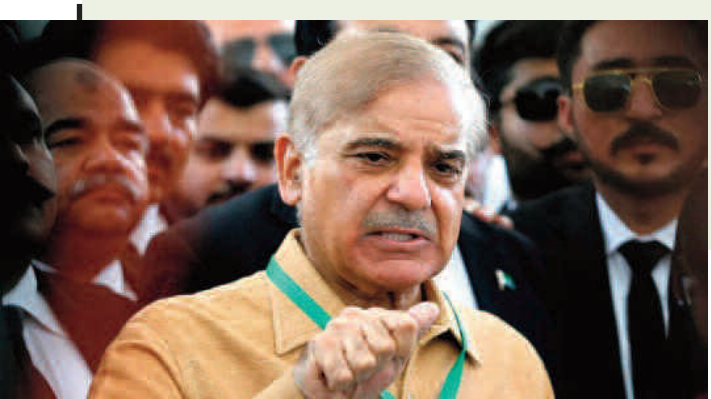

दें, सुशासन दे, लोकतंत्र को शुद्ध सांसें दे। क्या ऐसा हो पायेगा? भावी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बहुमत जुटाने के अलावा सेना को भी विश्वास में लेकर चलने की मजबूरी कदम-कदम पर झेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अगर चौपट न होती, तो शायद इमरान खान को ऐसे न जाना पड़ता। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुस्कराने के दिन आ गए हैं, क्या वाकई ऐसा है?

विडम्बना तो पाकिस्तान की हमेशा से यही रही है कि अन्दरूनी संकटों का समाधान करने की बजाय वह हमेशा कश्मीर का राग अलापती रही है। आम लोगों के संकटों एवं अभावों को दूर करने की बजाय उसका ध्यान कश्मीर पर ही लगा रहता है। आज उसकी दुर्दशा का कारण भी यही है। शाहबाज शरीफ ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले ही जिस तरह कश्मीर राग छेड़ा, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह भी इमरान खान की राह पर ही चलेंगे और उनके स्वल्प शासन में किसी रोशनी के अवतरित होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कश्मीर का राग भले ही वहां की सरकारों की विवशता हो, ऐसा न करना पाकिस्तान का गद्दार करार दिया जाता हो, लेकिन अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। कश्मीर की तरफ आंख उठाने का क्या हश्र होता है, इमरान की गति से सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कश्मीर का राग अलापने वाले इन्हीं इमरान ने अपने अंतिम भाषण में करीब दो दर्जन बार भारत के गुण गाये, उसे सशक्त बताया, उसकी ओर किसी भी राष्ट्र की आंख उठाने की हिम्मत न करने की बात कही। भले ही शाहबाज शरीफ भारत से शांति चाहते हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी के साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि यह तभी संभव है, जब कश्मीर मसले का समाधान हो। लेकिन भारत की कश्मीर पर बातचीत करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। जबसे अनुच्छेद 370 की कश्मीर में समाप्ति हुई है भारत कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करने की जरूरत महसूस ही नहीं करता। भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर पर बात करने को इच्छुक हो सकता है, क्योंकि देरसवेर यह भू-भाग भारत में आना ही है, चाहे बातचीत से आये या अन्य माध्यमों से।

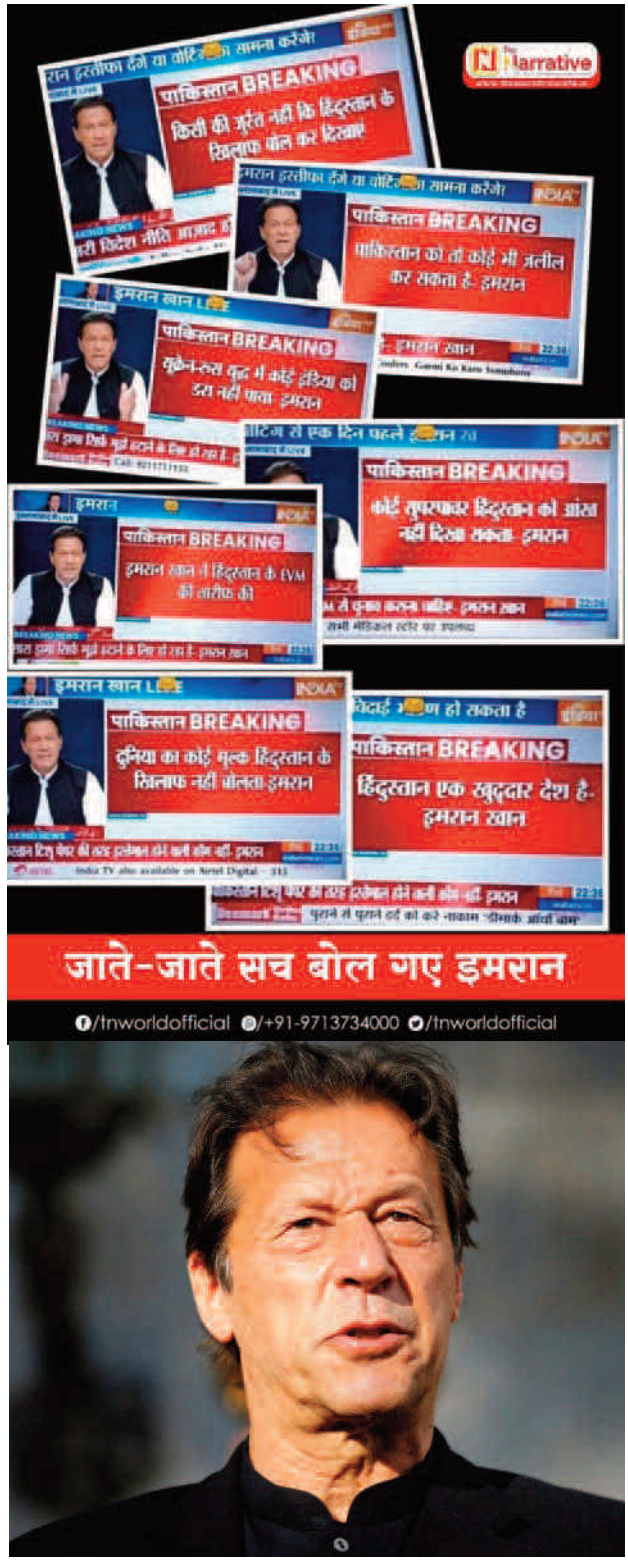

पाकिस्तान अनेक संकटों से घिरा है। वैसे भी पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने हैं। शाहबाज को सत्ता भले मिल गई हो, पर उनके सामने भी वही बड़ी मुश्किलें और चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान में हर प्रधानमंत्री को विरासत में मिलती रही हैं, बल्कि इस बार वे ज्यादा उग्र है। महंगाई से मुल्क बेहाल है। अर्थव्यवस्था बेदम है। भ्रष्टाचार चरम पर है। दुनिया भर में पाकिस्तान को सहयोग के नाम पर सन्नाटा पसरा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि शाहबाज भी उन्हीं नवाज शरीफ के भाई हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और पनामा पेपर्स मामले उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। इसके अलावा देश पर लगा आतंकवाद के गढ़ होने का ठप्पा भी अलग तरह के संकट खड़े किए हुए है। साफ है, शाहबाज की राह में भी कांटे ही कांटे हैं। इन कांटों के बीच यदि वह भारत की तरफ आंख उठाता है या कश्मीर राग अलापता है तो उसके संकट गहरे ही होने वाले हैं। इसलिये पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता और शांति कैसे कायम हो, फिलहाल यही सरकार, सेना और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य एजेंडा होना चाहिए। नया नेतृत्व अपनी अवाम के प्रति उत्तरदायित्व निभाये तो देश के करोड़ों लोगों के प्रति एक विश्वास और संरक्षण की भावना बढ़ेगी। इसी से पाकिस्तान को बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक लाभ होगा। उसके साथ व्यवहार एवं व्यापार बढ़ेगा। अन्यथा संकट ही संकट है। ■

इतिहास से मिट गए मुगल

● दिलीप पाण्डेय

CBSE ने 2022-2023 का नया पाठ्यक्रम स्कूलों को भेज दिया है । क्लास- 12 के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के कोर्स से बोर्ड ने मुगल दरबारों के इतिहास का चैप्टर हटा दिया है । क्लास- 12 में एक चैप्टर था द मुगल कोर्ट-रीकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। इस चैप्टर को अब हटा दिया गया है । इस चैप्टर में मुगलों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मुगल दरबारों के इतिहास की जानकारी दी गई थी जो कि एक तरह से मुगलों का झूठा महिमामंडन था ।

इसी तरह 11वीं क्लास में इतिहास की किताब से 'सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स' का चैप्टर हटा दिया गया है। इस चैप्टर में बताया गया था कि कैसे अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में इस्लामिक देशों का उदय हो गया। इस अध्याय में इस्लाम के जन्म और फिर खलीफा के उदय के बारे में बताया गया था। दरअसल जोर जबरदस्ती और जिहाद के युद्धों से मक्का-मदीना से चला इस्लाम अफ्रीका के देशों तक भी फैल गया था। अब किताब में इस्लाम की जोर जबरदस्ती और जिहाद के बारे में तो बताया नहीं जाता। इसलिए अच्छा यही है कि अगर सच नहीं बता सके तो कम से कम झूठ का चैप्टर ही बंद करो।

इसी तरह क्लास 10 में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में एक अध्याय है राजनीति-सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। इस अध्याय में से पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की दो उर्दू नज्में हटा दी गई हैं । ये दो नज्में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से पढाई जा रही थी। पहली नज्म है- इतनी मुलाकातों के बाद भी हम अजनबी रह जाते हैं और दूसरी नज्म है इतनी बारिशों के बाद भी खून के धब्बे रह जाते हैं। फैज अहम फैज की इन दोनों नज्मों को भारत में पढाए जाने की जरूरत नहीं थी। इसे हटाकर बोर्ड ने सही कदम उठाया है।

आपको याद होगा कि फैज अहमद फैज की एक गजल पर पूरे देश में भयंकर विवाद उठा था। हम देंखेंगे ये गजल फैज अहमद फैज ने लिखी थी। इस गजल में मूर्ति पूजा का विरोध था। जब इस गजल का विरोध किया गया तो जिहादी और कम्युनिस्टों की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। आखिरकार अब फैज का भी नाम पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। जो अच्छा फैसला है।

(नोट- कई मित्रों ने 9990521782 मोबाइल नंबर दिलीप नाम से सेव किया है लेकिन मिस्ड कॉल नहीं की, लेख के लिए मिस्ड कॉल और नंबर सेव, दोनों काम करने होंगे क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज भेजता हूं जिन्होंने नंबर सेव नहीं किया होगा उनको लेख नहीं मिलते होंगे। जिनको लेख मिलते हैं वो मिस्डकॉल ना करें प्रार्थना)

किस मुन्नी के लिए बदनाम चीफ जस्टिस?

https://youtu.be/Njmvu{ygmsY

ये मेरा यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं

मुगलों के साथ साथ नेहरू पर भी गाज गिरी है। कई पाठ्यक्रमों में नेहरू के गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को भी हटा दिया गया है ।

लेकिन मैं ये हां बोर्ड ये एक प्रार्थना करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आपको क्लास 3 से क्लास 12 तक पूरे इतिहास की किताब की समीक्षा करने की आवश्कयता है। जहां तक मेरी जानकारी है क्लास-4 से लेकर क्लास 8 तक CBSE में ही इतिहास की किताबों में तैमूर लंग का भी महिमा मंडन किया गया है जो अब तक नहीं हटाया गया है। इस पर भी बोर्ड ध्यान दे ।

और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मुगलों के चैप्टर हटाने से बात नहीं बनेगी। आप बच्चों को ये बताइए कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार करके मुगलों ने धर्मांतरण का अभियान चलाया। कैसे हिंदुओं के मुंह में गोमांस ठूंसा गया, कैसे हिंदुओं के जनेऊ उतरवाए गए? कैसे शरीयत और इस्लाम पर चलते हुए काफिर स्त्रियों का यौन दासियां बनाया गया। अगर आप ये सब बताएंगे तो आज के मुसलमानों को ये पता लगेगा कि उनके पूर्वजों के साथ आक्रमणकारियों ने कितना बुरा सलूक किया और इस तरह घरवापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। ■

आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट

धरती बचाने की अंतिम चेतावनी

● अवंतिका गोस्वामी

यह रिपोर्ट ऊर्जा, भवन, यातायात, भूमि और औद्योगिक क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले उन उपायों की विस्तृत सूची पेश करती है, जिनसे उत्सर्जन में तेजी से और सस्ते तरीके से कटौती की जा सकती है

संयुक्त राष्ट्र की जलवायु-विज्ञान संस्था, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति यानी आईपीसीसी ने चार अप्रैल, 2022 को अपनी छठी आकलन रिपोर्ट की तीसरी किस्त जारी की। इसे आईपीसीसी के वर्किंग ग्रुप-3 ने तैयार किया है, और इसका फोकस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन में कमी लाने पर है।

इस पूरी रिपोर्ट में दुनिया भर के ताजे वैज्ञानिक शोधों को शामिल किया गया है, जिसके चलते यह हजारों पेज में है। हालांकि 'समरी ऑफ पॉलिसीमेकर्स' शीर्षक वाले 63 पेज के अध्याय में इसके मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। नीचे इस अध्याय के वह छह बिंदु दिए जा रहे हैं -

1. 2019 में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, 1990 की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा था, हालांकि इसकी गति धीमी हो रही है: 2019 में, कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष, वैश्विक शुद्ध मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 59 गीगाटन था, जो 1990 की तुलना में 54 फीसदी अधिक था। शुद्ध उत्सर्जन से आशय, दुनिया के जंगलों और महासागरों द्वारा सोंके गए उत्सर्जन के बाद बचने वाले उत्सर्जन से है।

मानवजनित उत्सर्जन से तात्पर्य ऐसे उत्सर्जन से है, जो इंसान के द्वारा की चलाई जाने वाली गतिविधियों से होता है। जैसे ऊर्जा के लिए कोयले को जलाना या वनों को काटना। यह उत्सर्जन वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और उसके साथ मीथेन के उत्सर्जन से होता है।

हालांकि इसकी सालाना औसत दर जो 2000 से 2009 के बीच 2.1 फीसदी हो थी, वह 2010 से 2019 के बीच 1.3 फीसदी रह गई। कम से कम 18 देशों ने अपनी ऊर्जा प्रणाली के डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा दक्षता उपायों और कम ऊर्जा मांग के कारण लगातार 10 सालों से ज्यादा समय तक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया है।

2. कम विकसित देशों ने 2019 में वैश्विक उत्सर्जन में केवल 3.1 फीसदी की भागीदारी की। हालांकि सारी खबरें सकारात्मक नहीं हैं। कार्बन को लेकर असमानता व्यापक रूप से फैली हुई है। 2019 में कम विकसित देशों की वैश्विक उत्सर्जन में केवल 3.1 फीसदी की हिस्सेदारी थी। 1990-2019 की अवधि में उनका औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 1.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष था, जबकि वैश्विक औसत 6.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष था।

1850-2019 की अवधि में कम विकसित देशों ने जीवाश्म ईंधन और उद्योग से कुल ऐतिहासिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 0.4 फीसदी से भी कम योगदान दिया। विश्व स्तर पर, दुनिया की 41 प्रतिशत आबादी 2019 में प्रति व्यक्ति 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड से कम उत्सर्जन करने वाले देशों में रहती थी।

3. पेरिस समझौते के संकल्प काफी नहीं, 2019 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 43 फीसदी की गिरावट लानी होगी। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के संकल्पों को राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी एनडीसी के तौर पर जाना जाता है। कई देशों ने एनडीसी में पिछले साल अक्टूबर तक जो संकल्प जोड़े हैं, उनके आधार पर आईपासीसी ने पाया है कि इस सदी के अंत तक दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी, जिससे पेरिस समझौता विफल हो जाएगा।

इस योजना के विफल होने में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का योगदान ज्यादा होगा। सबसे बेहतर परिदृश्य के रूप में, जिसे सी-1 रास्ते के तौर पर जाना जाता है, दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा का अतिक्रमण करने से बचना है। इसका मतलब यह है कि अस्थायी तौर पर दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है लेकिन फिर तकनीक की मदद से हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे, जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोंक सकें।

सी-1 रास्ते पर चलने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2019 की तुलना में 2030 तक 43 फीसदी कम करना होगा यानी इसे कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष 31 जीगाटन तक लाना होगा। इसके लिए 2019 की तुलना में 2050 तक कोयला, तेल और गैस के उपयोग में क्रमश: 95 फीसदी, साठ फीसदी और 45 फीसदी की कमी लानी होगी।

4. पर्याप्त और किफायती समाधान ऊर्जा, भवन और परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में मौजूद, साथ व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन भी जरूरी। 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा, भवन, परिवहन, भूमि और अन्य क्षेत्रों में पूरे तंत्र के व्यापक कायाकल्प की

जरूरत है और इसमें प्रत्येक क्षेत्र में विकास के कम उत्सर्जन या शून्य कार्बन पथ को अपनाना शामिल होगा। ये समाधान किफायती कीमत पर उपलब्ध भी हैं।

कम उत्सर्जन वाली तकनीकों की कीमत 2010 से लगातार कम हो रही है। इकाई की लागत के आधार पर सौर ऊर्जा में 85 फीसद, पवन ऊर्जा में 55 फीसद और लिथियम आयन बैटरी में 85 फीसद की गिरावट आई है। उनका फैलाव या उपयोग, 2010 के बाद से कई गुना बढ़ गया है। जैसे कि सौर ऊर्जा के लिए यह बढ़त 10 गुना है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 गुना।

आईपीसीसी की रिपोर्ट इस बदलाव का श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र की कामयाबी को देती है, जिसमें प्रदर्शन और पायलट परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण और तय पैमाने हासिल करने के लिए सब्सिडी जैसे उपाय शामिल हैं।

रिपोर्ट में पूरे विश्वास के साथ कहा गया है कि 'कटौती के कई विकल्प, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, शहरी प्रणालियों का विद्युतीकरण, शहरी हरित बुनियादी ढांचे, ऊर्जा दक्षता, मांग पक्ष प्रबंधन, बेहतर वन और फसल या घास के मैदानों का प्रबंधन और कम खाद्य अपशिष्ट और नुकसान, जैसे उपाय तकनीकी रूप से व्यवहार में लाने के काबिल हैं। ये तेजी से लागत के दायरे में आते जा रहे हैं और आम तौर पर इन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, औद्योगिक क्षेत्र में मांग प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता और इमारतों के निर्माण में 'प्रचुरता' और 'दक्षता के सिद्धांतों को अपनाना, जैसे उपाय रिपोर्ट की रूपरेखा में सुझाए गए तमाम समाधान में शामिल हैं।

इसमें यह भी कहा गया कि लोगों के बर्ताव में स्वीकार किए जाने वाले बदलावों जैसे कि पौधों पर निर्भर खुराक को बढ़ावा देने, पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसी आदतों से भी वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।

रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि विकसित देशों के लोगों द्वारा ऐसी आदतों को अपनाया जाना ज्यादा जरूरी है।

5. सकल घरेलू उत्पाद पर इसका प्रभाव नाममात्र का होगा और उत्सर्जन में कटौती के दीर्घकालिक लाभ इसकी आज की लागत से अधिक होंगे। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कम कटौती वाले विकल्पों से भी 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में आधी कमी संभव है। वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में आज जो लागत लग रही हे, वह इसके दीर्घकालिक लाभों की तुलना में कम ही है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का वैश्विक आर्थिक लाभ, अधिकांश रिपोर्टों में इसमें लगने वाली लागत से कम है। डीकार्बोनाइजेशन में निवेश का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप-3 के सह-अध्यक्ष प्रियदर्शी शुक्ला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा- 'यदि हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस (3.6 डिग्री फारेनहाइट) या उससे नीचे तक सीमित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं, तो दुनिया का जीडापी केवल कुछ फीसदी अंक ही कम होगा।'

6. विकासशील देशों में पैसे की कमी पड़ेगी लेकिन विकसित देश कर सकते हैं इसकी भरपाई: उत्सर्जन में कटौती करने पर विकासशील देशों में आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। इन देशों में खेती, कृषि-वानिकी और जमीन के उपयोग से जुड़े अन्य क्षेत्रों में यह अंतर और बड़ा हो जाता है। हालांकि आईपीसीसी के मुताबिक, वैश्विक वित्तीय प्रणाली काफी बड़ी है और इन अंतरालों को पाटने के लिए 'पर्याप्त वैश्विक पूंजी और तरलता' मौजूद है।

आईपीसीसी की रिपोर्ट, विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक अनुदानों को बढ़ाने की सिफारिश करती है। साथ ही साथ 100 बिलियन डालर-एक-वर्ष के लक्ष्य के संदर्भ में विकसित से विकासशील देशों में सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक रूप से जुटाए गए निजी वित्त प्रवाह के स्तर में वृद्धि की जरूरत बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए विकासशील देशों में जोखिम को कम करने और कम लागत पर निजी प्रवाह का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक गारंटी के उपयोग में वृद्धि, स्थानीय पूंजी बाजार के विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रक्रियाओं में अधिक विश्वास पैदा करने जैसे उपाय अपनाने होंगे।

'समरी ऑफ पॉलिसीमेकर्स' के लिए अनुमोदन प्रक्रिया दो सप्ताह तक चलने वाली अंतर-सरकारी प्रक्रिया है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई हर लाइन की समीक्षा करने के लिए देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों की जरूरत होती है।

अनुमोदन प्रक्रिया ने इस सप्ताह के अंत में अपनी समय सीमा बढ़ा दी थी। दरअसल प्रतिनिधियों ने 'समरी ऑफ पॉलिसीमेकर्स' के विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी थी, जिससे ऐसा लगता है कि उनके हित, अपने राष्ट्रीय हितों से टकराते हैं।

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत खासतौर पर जलवायु-वित्त की मांग कर रहा था, जबकि सऊदी अरब तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के क्षेत्रों में अपनी निरंतर भूमिका देख रहा था।

इस प्रकार 'समरी ऑफ पॉलिसीमेकर्स' दस्तावेज का स्वर पूरी तरह से तटस्थ और गैर-राजनीतिक है। वह इन सवालों से टकराने से बच रही है कि इस संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। वह इस पर रोशनी नहीं डालती कि उच्च: उत्सर्जन से दुनिया को बचाने के लिए और कौन से धनी वैश्विक हित समूहों को विकासशील देशों की मदद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी।

देखना यह होगा कि इस लंबी-चौड़ी रिपोर्ट से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने में कैसे मदद मिलती है। ■

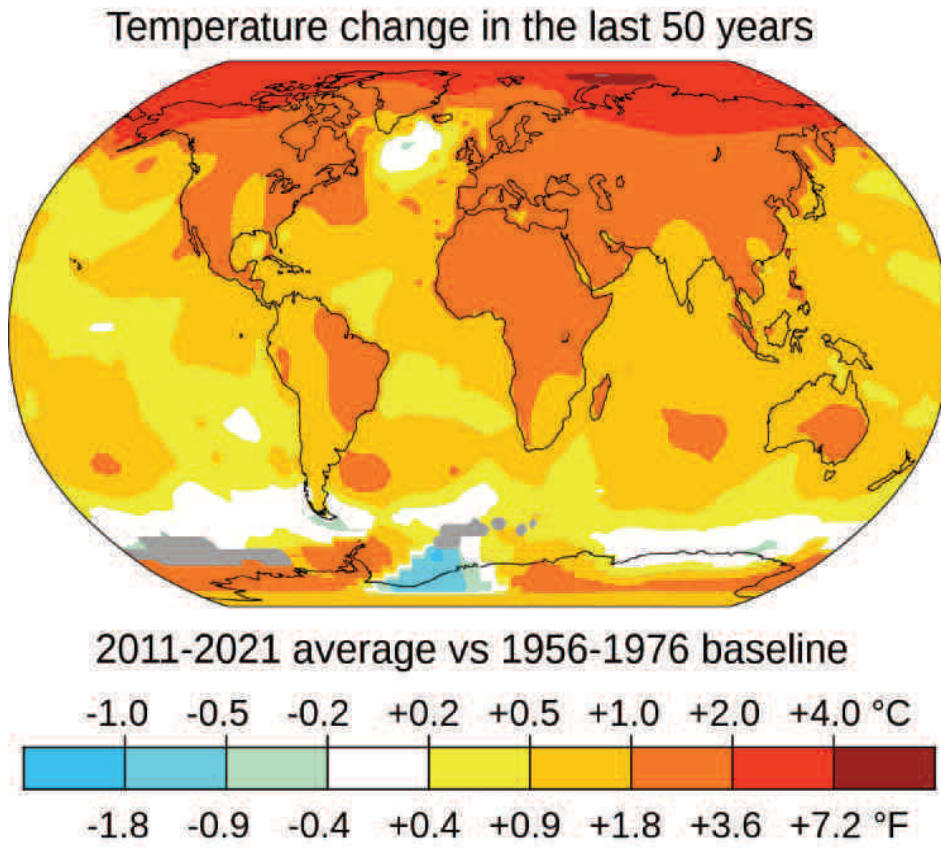

6 अरब से अधिक लोग आएंगे तेजी से बढ़ते चरम मौसम के संपर्क में

● दयानिधि

अध्ययन के मुताबिक 156.9 से 235.8 करोड़ की कुल आबादी तेजी से बढ़ती नमी, गर्मी, और ठंढ के दिनों की चरम सीमा के सम्पर्क में आएगी।

हाल में जारी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी आकलन रिपोर्ट में बताया गया है कि, ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई जलवायु संबंधी चरम घटनाएं बढ़ रही हैं तथा इनका तेजी से बढ़ना जारी रहेगा।

पेरिस समझौते ने 21वीं सदी में पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में तापमान के दो स्तर निर्धारित किए थे। आदर्श रूप में यह 1.5 डिग्री सेल्सियस और ऊपरी सीमा के रूप में यह 2.0 डिग्री सेल्सियस था।

जलवायु संबंधी खतरे जलवायु चरम सीमाओं में हो रहे बदलावों के साथ-साथ वैश्विक जनसंख्या आकार और स्थानीय जनसंख्या वितरण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होते हैं।

हाल ही में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स (आईएपी) के डॉ. किन पेहुआ और उनके सहयोगियों ने युग्मित मॉडल इंटरकंपेरिसन प्रोजेक्ट फेज 6 में वैश्विक जलवायु मॉडल के साथ जलवायु चरम सीमाओं का जनसंख्या को होने वाले खतरों की जांच की।

अध्ययनकर्तओं ने जलवायु की चरम सीमाओं और बढ़ते तापमान के तहत वैश्विक जनसंख्या को होने वाले खतरों में मध्यम वृद्धि देखी गई। तेजी से बढ़ते तापमान का स्तर दक्षिणी एशिया और मध्य अफ्रीका के इलाकों में मुख्य रूप से इस तरह की वृद्धि में अहम भूमिका निभा रहा है।

तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पर जनसंख्या में कमी के कारण पूर्वी एशिया में 2.0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के कारण, चरम सीमा पर जनसंख्या पर खतरा थोड़ा कम देखा गया है।

अध्ययन के मुताबिक 156.9 से 235.8 करोड़ की कुल आबादी तेजी से नमी या लगातार बारिश वाले दिनों, शुष्क या लगातार शुष्क दिनों, गर्मी के दिनों और ठंढ के दिनों पर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस, तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस के चरम सीमा पर पहुंच जाएगी।

बढ़ते तापमान का स्तर 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इसके अतिरिक्त, विश्व की कुल जनसंख्या के दो-तिहाई से अधिक को उपरोक्त अवधियों के दौरान सभी चार चरम सीमाओं पर भारी ठंड का सामना करना पड़ सकता है।

अध्ययनकर्ता किन ने कहा कि जाहिर है, हमें बढ़ते तापमान के तहत संभावित जलवायु के खतरों का सामना और अधिक करना होगा। यह अध्ययन एटमोस्फियरिक रिसर्च नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

इसके अलावा 1.5 डिग्री सेल्सियस बनाम 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती दुनिया स्थानीय प्रजातियों के खतरों, विलुप्त होने के खतरे बढ़ गए हैं।

ग्लोबल वार्मिंग के 2 डिग्री सेल्सियस के तहत 18 फीसदी कीड़े, 16 फीसदी पौधे, 8 फीसदी कशेरुकी पर जलवायु रूप से निर्धारित भौगोलिक सीमा के आधे से अधिक के नुकसान होने के आसार हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के तहत प्रजातियों की संख्या में 6 फीसदी कीड़ों, 8 फीसदी पौधों और 4 फीसदी तक कशेरुकियों के कम होने का अनुमान है।

अन्य जैव विविधता से संबंधित कारकों से जुड़े जोखिम, जैसे कि जंगल की आग, चरम मौसम की घटनाएं, आक्रामक प्रजातियों, कीटों और बीमारियों का प्रसार, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर प्रभाव वार्मिंग के 2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर कम होगी।

ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने से मक्का, चावल, गेहूं और संभावित रूप से अन्य अनाज फसलों, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य और दक्षिण अमेरिका में प्रभाव पड़ेगा।

कई समुदायों और क्षेत्रों के लिए काफी आर्थिक परिणामों के साथ, वैश्विक स्तर पर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए वैश्विक स्तर पर 7 से 10 फीसदी पशुधन के नुकसान होने

के आसार हैं।

महीना भर पहले अंडे देने को मजबूर कई पक्षी, क्यों आ रहा है यह बदलाव

– ललित मौर्या

शोधकर्ताओं ने अमेरिका में पक्षियों की 72 प्रजातियों पर अध्ययन किया और पाया कि करीब 33 फीसदी प्रजातियां, 25 दिन पहले अपने अंडे दे रही हैं।

बसंत आते ही वातावरण में अपने आप ही एक अनोखी सी ताजगी आ जाती है। मौसम सुहाना हो जाता है, पेड़-पौधों पर हरियाली छा जाती है, पक्षी कलरव करने लगते हैं, नए घोसले बनाते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। साल-दर-साल समय के साथ सब कुछ ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन बढ़ता इंसानी हस्तक्षेप अब इसमें बदलाव करने लगा है।

बदलाव का एक ऐसा ही सबूत हाल में सामने आया है, जब पक्षियों पर किए एक अध्ययन से पता चला है कि पक्षियों की कई प्रजातियां एक सदी पहले की तुलना में करीब महीना भर पहले अपने अंडे दे रही हैं। साथ ही वो पहले के मुकाबले कहीं जल्द अपने घोसलों को तैयार करने को मजबूर हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ एनिमल इकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

अपने इस शोध में शोधकर्ताओं ने अमेरिका में पक्षियों की 72 प्रजातियों के घोसलों और अंडे देने के समय का अध्ययन किया है। इसके लिए उन्होंने फील्ड म्यूजियम में संरक्षित घोसलों और अंडों के 1872 से 2015 के 143 वर्षों के रिकॉर्ड और वर्तमान के 3,000 से ज्यादा रिकॉर्ड का तुलनात्मक अध्ययन किया है। साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन के असर को समझने के लिए वातावरण में घोसलों के निर्माण के समय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कितना था इसका भी अध्ययन किया है।

शोध के जो निष्कर्ष सामने आए हैं उनके अनुसार बसंत के समय में आते बदलाव के चलते करीब 33 फीसदी प्रजातियां, एक सदी पहले की तुलना में करीब 25.1 दिन पहले अपने अंडे दे रही हैं। वहीं प्रवासी पक्षियों के अंडे देने के समय में करीब 18 दिनों का अंतर आया है। वहीं यदि सभी प्रजातियों पर पड़ते असर को देखें तो इनके अंडे देने का निर्धारित समय सामान्य से 10 दिन आगे खिसक गया है।

कौन है इन बदलावों के लिए जिम्मेवार

शिमला से उत्तरकाशी तक क्यों धधक रहे जंगल

शिमला के तारा देवी जंगल में इन दिनों आग लगी हुई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा सहित कई जंगल आग से घिरे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, जंगल भी धधकने लगे हैं। चिंता की बात यह है कि पहाड़ी जंगलों में आग की घटनाएं आमतौर पर मई-जून में जोर पकड़ती थीं, लेकिन इस बार तो मार्च से ही जंगल सुलग रहे हैं।

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत के 30 प्रतिशत से ज्यादा जिलों के जंगलों में भीषण आग लगने का खतरा है। बीते एक दशक में जंगल में आग लगने की घटनाओं में 10 गुना इजाफा हुआ है। पिछले दो दशकों के दौरान जंगलों में लगी आग की घटनाओं का आकलन बताता है कि इस तरह की 89 प्रतिशत घटनाएं सूखा प्रभावित जिलों में हो रही हैं। अभी गर्मी शुरू ही हुई है और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के जंगलों में जगह-जगह आग लगी हुई है। गर्मी और बढ़ी तो इस आग की जद में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के जंगल भी आ जाएंगे। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बीते दो सालों में जंगलों में आग के मामलों में 177 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसके विपरीत 2019-20 में जंगलों में आग की घटनाओं में भारी कमी दर्ज की गई थी। लेकिन उसे कोविड लॉकडाउन से जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन के दौरान जंगलों में मानव हस्तक्षेप में कमी आई थी।

जंगलों में लगने वाली आग न सिर्फ समूची धरती की गर्मी बढ़ाते हुए ऑक्सिजन देने वालें पेड़ों को कम रही है, बल्कि ये घटनाएं जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। भारत के अधिकतर जंगल सूखे हैं, शुष्क हैं। इस वजह से ये हमेशा आग के खतरे से घिरे भी रहते हैं। फिर जिस तरह से हर दस साल में लू बढ़ती जा रही है, वह भी एक मुसीबत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि 1981 से 1990 के दशक में लू के दिनों की संख्या 413 रही। वहीं 2001 से 2010 के दशक में यह बढ़कर 575 हो गई। इसके बाद 2011 से 2020 के दशक में इनकी संख्या 600 तक हो गई। इस साल का अप्रैल महीना अब तक का सबसे गर्म अप्रैल हो सकता है। सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही इस अप्रैल में 9 दिन लू का प्रभाव रहा है। 1951 से अब तक अप्रैल महीने में इतने अधिक लू भरे दिन राजधानी में नहीं नहीं आए।

जंगलों पर मंडराती आग कम हो सकती है। इसके लिए आग से संबंधित जोखिम के मैप के साथ अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान पर आधारित वॉर्निंग का ना सिर्फ सिस्टम बनाना होगा, बल्कि उसे इतना मजबूत करना होगा कि हर हाल में वॉर्निंग जारी कर सकें। कहने की जरूरत नहीं कि वन विभाग में भी लोगों की संख्या और आग का बजट - दोनों में इजाफा करना होगा। आग के सबसे अधिक जोखिम वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा सकती है। जंगलों में जहां-जहां आग लगी है, वहां दोबारा जंगल उगाने के लिए भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा। सरिस्का अभयारण्य की आग लगने की हालिया घटना से हमें सीखना चाहिए कि जलवायु की बदली हुई परिस्थितियों में जंगल में लगने वाली आग के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जरूरी है।

जंगल में आग लगने के दौरान स्थानीय स्तर पर हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। इसका असर आसपास की बड़ी आबादी पर पड़ता है। राज्य सरकारों या राज्य के वन विभागों को सरकारी स्कूलों और सामुदायिक हॉल जैसे सार्वजनिक भवनों को नए उद्देश्यों के लिए तैयार करना चाहिए। इन भवनों में स्वच्छ हवा के लिए एयर फिल्टर जैसे उपाय करने चाहिए, ताकि जंगल में आग लगने के दौरान आग और धुएं से सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय इन्हें एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल कर सके। सरकारों को जंगल में आग लगने की घटनाओं के लिए रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए।

– पूनम गौड़

खेती की मिट्टी पहले ही खराब हो चुकी है

मिट्टी बचाओ सद्गुरु द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है, जो मिट्टी के संकट को दूर करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट कर रहा है। यह अभियान, खेती की मिट्टी में जैविक (ऑर्गेनिक) सामग्री को बढ़ाने के लिए सभी देशों के नेताओं को राष्ट्रीय नीतियां बनाने और कार्रवाई करने में मदद कर रहा है।

संकट

- जैविक (ऑर्गेनिक) सामग्री की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है:
- भोजन संकट
- पानी की कमी
- जैव-विविधता (बायोडायवर्सिटी) का नुकसान
- जलवायु बदलाव
- कमाई का नुकसान
- संघर्ष और अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जाना

मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। लेकिन

खेती, जंगलों की कटाई, और दूसरी कई वजहों से ऊपरी मिट्टी बहुत तेजी से खराब और नष्ट हो रही है। विश्व स्तर पर, 52 प्रतिशत खेती की भूमि पहले ही खराब हो चुकी है। धरती संकट में है। यदि मिट्टी इसी तेजी से खराब होती रही, तो इस धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा।

समाधान

- मिट्टी में कम से कम 3-6 प्रतिशत जैविक (ऑर्गेनिक) सामग्री वापस लाना
- भूमि को वनस्पति (पेड़-पौधों) की छाया से ढंककर, और पौधों के कूड़े और पशुओं के कचरे के माध्यम से मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाना।
- धरती को निर्जन उजाड़ बनने से कैसे रोका जाए
- पूरी दुनिया में तेजी से रेगिस्तान फैलते जा रहे हैं। मिट्टी अपनी उर्वरता गंवाती जा रही हैं। निर्जन रेतीले उजाड़ रेगिस्तान में जीवन कैसे वापस लाया जा सकता है। यहां पेश हैं चार तरीके।

मंगोलिया और चीन के पश्चिमोत्तर तक फैला इलाका, दुनिया में सबसे तेज गति से रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। आकार मे ये 12 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। गोबी रेगिस्तान इसमें हर साल करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर का इजाफा कर देता है।

फैलता हुआ ये रेगिस्तान घास के मैदानों को चपट कर जाता है, गांव के गांव निगल जाता है और बड़े पैमाने पर उर्वर भूमि को एक निर्जन उजाड़ में बदल देता है। दसियों हजार लोग विस्थापित होने को विवश होते हैं और कुछ एक हजार ही उन्हीं उजाड़ों मे रहने को अभिशप्त।

मरुस्थलीकरण वो प्रक्रिया है जिसके तहत उर्वर मिट्टी रेगिस्तान में बदल जाती है। यूं तो इसके पीछे कई कुदरती वजहें भी हैं लेकिन इसके

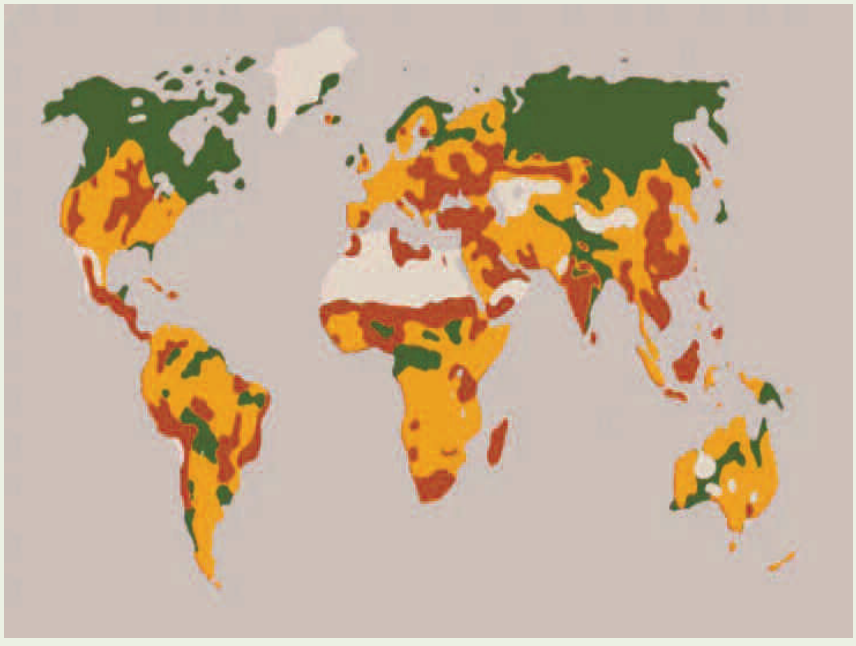

दूरुत विस्तार में इंसानों की भूमिका भी निर्णायक रही है।

बढ़ रहे हैं रेगिस्तान

बंजर धरती

पृथ्वी की सतह का एक तिहाई हिस्सा बंजर हो चुका है, और लगातार मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अलजीरिया में हॉगर पहाड़ी इलाके में हजारों साल में किस तरह मरुस्थल चट्टानों का रूप ले चुके हैं।

दुनिया में मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट की चार प्रमुख वजहे हैं- औद्योगिक कृषि में पानी का अत्यधिक इस्तेमाल, गंभीर सूखे की बढ़ती मियाद, निर्वनीकरण और मवेशियों के लिए चरागाहों का जरूरत से ज्यादा दोहन।

पहले उर्वर और हरे-भरे रह चुके लैंडस्केप रूखे-सूखे, रेतीले इलाकों में तब्दील होकर दुनिया भर में करीब एक अरब लोगों की जिंदगियों पर खतरा बने हुए हैं। लाखों प्रजातियों का जीवन भी उनकी वजह से संकट में है। आकलनों के मुताबिक इस सदी के मध्य तक धरती की एक चौथाई मिट्टी मरुस्थलीकरण से प्रभावित होगी।

ये एक चिंताजनक और गंभीर पहलू है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन हालात को फिर से ठीक किया जा सकता है।

रेगिस्तान में घनघोर बारिशों की आमद

एक स्वागतयोग्य समाधान मक्का के नजदीक मिला है। ये है अल बायदा प्रोजेक्ट। वहां रेगिस्तानी खेती के जानकारों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए रूखी उजाड़ मिट्टी में मूसलाधार बारिश की मदद से दोबारा जान फूंकी जा सकती है।

सउदी अरब में जब बारिश होती है, तो कम समय में बड़ी मात्रा में पानी गिरता है। अप्रैल 2021 में भी ऐसा हुआ था जब शहर के शहर कुछ समय के लिए जलमग्न हो गए थे। इतना सारा पानी एक साथ गिरे तो उसे थामना मिट्टी के लिए मुश्किल हो जाता है।

अल बायदा प्रोजेक्ट के पूर्व निदेशक और पुनरुत्पादक कृषि के जानकार नाइल स्पेकमैन कहते हैं, 'हमने सोचा कि अगर हम उस पानी को जमीन तक ले आते हैं तो वो पानी का एक टिकाऊ स्रोत बन सकता है, फिर चाहे 20 महीने बारिश न हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।'

इलाके में रहने वाले ग्रामीणों के साथ कृषि विशेषज्ञों ने पश्चिमी सउदी अरब की घाटी की सीमा बनाने वाली चट्टानी दीवारों के साथ साथ बांध और टैरेस बनाए। साथ ही किलोमीटर लंबी खाइयां भी तैयार की गई। अब बारिश होने पर पानी जमा होता जाता है और जरूरत वाले इलाकों को रवाना कर दिया जाता है। जहां पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर दाखिल होता रहता है। सिंचाई का ये तरीका पूरी दुनिया में कारगर रहा है और सदियों पहले दक्षिण अमेरिका में इन्का आदिवासी भी इसका इस्तेमाल करते थे।

सउदी अरब में इस प्राकृतिक चक्र को चालू करने के लिए जानकारों ने शुरुआत में कृत्रिम सिंचाई का इस्तेमाल किया था। लेकिन अहम बात ये थी कि पानी निकाला कम गया, मिट्टी में छोड़ा ज्यादा गया। जहां पहले सिर्फ रेत और पत्थर थे वहां देसी पेड़-पौधे उग आए और घास फिर से पनप गई। वे सिंचाई के बगैर भी 30 महीने लंबा सूखा भी झेल गए।

अक्षय ऊर्जा कैसे लाती है बारिश

सउदी अरब के पास उत्तर अफ्रीकी देश भी, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस प्रौद्योगिकी का परीक्षण कर रहे हैं। 90 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में फैला सहारा- धरती का सबसे विशाल रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान की तरह वो भी फैलता ही जा रहा है, कुछ इलाकों में तो हर साल करीब 50 किलोमीटर। सहारा के आसपास के इलाके शुष्क हैं लेकिन जीवित हैं। हालांकि ऐसी स्थिति ज्यादा नहीं खिचेंगी क्योंकि उर्वर मिट्टी की जो तबाही इंसानो के हाथों हो रही है उसके चलते वे इलाके दुनिया में किसी दूसरी जगह से ज्यादा तेजी से मरुस्थलीकरण की जद में हैं। रही-सही कसर गरीबी, पानी की कमी और जमीन पर मालिकाने के विवादों, टकरावों ने पूरी कर दी है। जिससे पर्यावरणीय नुकसान तेजी से होता जा रहा है। ऐसी सूरत में काम आते हैं सौर पैनल और पवनचक्कियां। रेगिस्तान विस्तार को रोकने के ये एक सशक्त उपाय हैं। कैसे ?

क्योंकि ये बारिश लाने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया कुछ यूं काम करती है: सौर पैनलों की काली सतह हवा को गरम करती है, वो वायुमंडल में और ऊपर पहुंच जाती है। उसी तरह हजारों पवनचक्कियों के डैने घूमते हैं और हवा को ऊपर की ओर धक्का देते हैं। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में भौतिकविद् और इस विषय पर एक अध्ययन की सह-लेखिका सफा मोटे कहती हैं कि, 'जब हवा के ये पिंड ऊंचाइयों में पहुंच जाते हैं तो वे ठंडा होने लगते हैं। ठंडे होते हैं तो आर्द्रता भी सघन होकर बारिश के रूप में गिरने लगती है।

बढ़ता रेगिस्तान, खतरे की घंटी

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर सहारा रेगिस्तान का एक बटा पांचवा यानी 20 प्रतिशत हिस्सा, सौर पैनलों और पवन चक्कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता तो उससे सहारा के दक्षिणी हिस्से में हर साल करीब पांच सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होती। ये नाकाफी लग सकता है लेकिन इतनी बारिश से हरित क्षेत्र 20 फीसदी बढ़ जाता और खेती में जबरदस्त उछाल आ जाता। और क्या चाहिए था- लोग भी खुश और पर्यावरण भी महफूज।

सफा मोटे के मुताबिक उस आकार का एक सोलर और विंड फार्म हर साल उससे चार गुना ज्यादा बिजली उत्पादन कर सकता है जितना पूरी दुनिया में आज खपत है। उससे अफ्रीकी देशों को और टिकाऊ बन पाने में मदद मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट को अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति का साथ मिला तो भौतिकविद सफा मोटे को पक्का यकीन है कि प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में खर्च होने वाली 20 खरब डॉलर की विशालकाय धनराशि की लागत भी निकल सकती है।

मरुस्थलीकरण से हरितीकरण की ओर

रेगिस्तान को फिर से हराभरा और उर्वर बनाने के दूसरा प्रकृति-आधारित तरीके का परीक्षण चीन में चल रहा है। सफलता भी मिल रही है।

चीन सरकार के वानिकी और घासभूमि प्रशासन के मुताबिक महज कुछ दशकों पहले तक देश में रेगिस्तान हर साल 10,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बढ़ रहे थे। आज वो हर साल 2,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में सिकुड़ रहे हैं।

लेकिन कैसे?

1988 में लोगों ने एक नमक खदान के आवागमन मार्गों की हिफाजत के लिए, राजधानी बीजिंग के पश्चिमोत्तर में स्थित कुबुकी रेगिस्तान में पेड़ लगाने शुरू किए थे। पिछले कुछ दशकों में, ये दुनिया के सबसे कामयाब वनीकरण कार्यक्रमों में से एक बन चुका है।

एक निर्धारित परिपाटी में पेड़ लगाने के बजाय, रेत के ढूहों में पेड़ों को रोपने के लिए पानी के खास फौवारे तैयार किए गए थे। ये फौवारे रेत में सूराख बनाते और साथ ही साथ पेड़ की कलमों को भी सींचते। मरुस्थलीकरण से लड़ाई के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के शीर्ष वैज्ञानिक बैरन जोसेफ ओर कहते हैं, 'इससे रोपाई का काम दस मिनट से कम होकर 10 सेकंड ही रह गया। ये एक बड़ा ही कामयाब और महत्त्वपूर्ण तरीका है।'

कुबुकी में नवजात छोटे पौधों को तेज हवा से बचाने के लिए किसान, रेत के ढूहों पर पुआल के बंडल भी रख देते हैं।

खोदा पहाड़, निकला खजाना

नई घासभूमि किसानों के लिए पैदावार के नए इलाके और मवेशियों के लिए नयी चरागाह भी बन गई है। किसान यहां लिकरिस यानी मुलैठी और दूसरी जड़ी बूटियां उगाते हैं। ये पौधे शुष्क जलवायु में ठीक से पनप जाते हैं और पारंपरिक चीनी दवाओं में उनकी काफी मांग रहती है।

कुबुकी रेगिस्तान की हरियाली का 800 किलोमीटर दूर राजधानी बीजिंग पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। वहां रेतीले तूफान से होने वाले वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

तो क्या ये माना जाए कि सही प्रौद्योगिकी से मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है?

खराब हो चुकी जमीन, मिट्टी और वनस्पति को पुनर्जीवित करना संभव है और बाधित जलचक्रों को भी फिर से सामान्य किया जा सकता है। चाहे वो प्रकृति-प्रदत तरीकों से हो या फिर हाईटेक रणनीतियों के दम पर।

लेकिन दुनिया के मरुस्थलीकृत इलाकों को वापस उर्वर और हरित बनाने के इन तरीकों में बड़ी लागत और कड़ी मेहनत लगती है। जानकार कहते हैं कि उर्वर मिट्टी को सूखने से बचाने और रेगिस्तानों को फैलने से रोकने का ही एक ही तरीका है- और वो है मिट्टी और पानी का अनवरत निर्मम दोहन बंद हो।

पाम तेल पर प्रतिबंध : शैंपू-साबुन से चॉकलेट तक के बढ़ सकते हैं दाम, इंडोनेशिया 28 अप्रैल से निर्यात पर लगाएगा पाबंदी

देश में खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम तेल का निर्यात बंद कर रहा है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा क्योंकि हम अपनी कुल जरूरतों का आधा से अधिक पाम तेल इंडोनेशिया से खरीदते हैं। पाम तेल महंगा होने से न सिर्फ खाने के तेल महंगे हो जाएंगे बल्कि शैंपू-साबुन से लेकर केक, बिस्कुट और चॉकलेट तक के दाम बढ़ जाएंगे।

विशेषज्ञों ने कहा, कई तेलों में तो पाम तेल मिलाया जाता है क्योंकि इसमें महक नहीं होती है। एफएमसीजी एवं सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी मात्रा में पाम तेल का इस्तेमाल करती हैं। भारत करीब 90 लाख टन पाम तेल खरीदता है। इसमें 70 फीसदी पाम तेल का आयात इंडोनेशिया से होता है। इंडोनेशिया से पाम तेल का निर्यात बंद होने के बाद मलयेशिया पर निर्भरता बढ़ेगी और खाद्य तेल के दाम 20 फीसदी तक बढ़ सकते हैं।

● ● ● ●

गुल हो रही बत्ती

कोयला संकट पर कोल सचिव एके जैन का कहना है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। जबकि इस संकट की मुख्य वजह विभिन्न ईंधन स्रोतों से होने वाले बिजली उत्पादन में आई तीव्र गिरावट है। जैन का कहना है कि देश के कई राज्यों में कोयले का संकट न होकर बिजली की मांग और आपूर्ति का बेमेल होना है। देश में गैस-आधारित बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आने से यह संकट और बढ़ गया है।

देश में एक बार फिर कोयला की कमी से हाहाकार मचा हुआ हैं। कई राज्य बिजली कटौती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कई शहरों में बत्ती गुल होना शुरू हो गई है। इस संकट के पीछे विदेश से आयात होने वाले कोयले के बढ़ते दाम नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य खराब वित्तीय हालत के चलते अतिरिक्त बिजली खरीदने के बजाए कटौती का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोयले की कमी पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोयला संकट यरेलू न होकर बाहरी ज्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि आज सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों को 10 फीसदी कोयला विदेश से आयात करने की अनुमति है। लेकिन कंपनियां वैश्विक मुद्रास्फीति के चलते विदेश से महंगा कोयला खरीद नहीं पा रही हैं। इससे देश की कोयला खदानों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जबकि राज्यों की वित्तीय हालत इतनी खराब है कि उनका करीब एक लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार पर बकाया है। इसलिए राज्य सरप्लस पावर खरीदने के बजाए बिजली कटौती का सहारा ले रहे हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि आज यह बात सामने आ रही है कि कोयला की बहुत कमी है तो यह बिलकुल गलत है। क्योंकि अभी भी सभी पावर प्लांट्स के पास करीब 27 मिलियन टन कोयले का स्टॉक पड़ा हुआ है। आज जो पावर प्लांट्स यह कह रहे हैं कि हमारे पास कोयला स्टॉक कम है तो उसके दो कारण हैं, पहला यह कि रेलवे की पास रैक की कमी है जिससे कोयला ज्यादा मात्रा में संयंत्र तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरा यह है कि कोल इंडिया का राज्यों की पावर कंपनियों पर बहुत बकाया है। इधर, सरकार भी कंपनियों से कह चुकी है कि जब तक वे अपना पुराना हिसाब नहीं करेंगी तब तक कोल इंडिया कोयला नहीं देगी। इसलिए आज कुछ राज्य अपनी क्षमता के हिसाब से बिजली भी खरीद रहे हे क्योंकि उनका बकाया राशि ज्यादा है।

● ● ● ●

हरियाणा में गोवंश के चारे पर भारी संकट पैदा हो गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मार उन जगहों पर है जिन जिलों में गौशालाएं सबसे अधिक है। प्रदेश के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में सबसे अधिक गौशालाएं हैं। अभी से तूड़ी के रेट 850 रुपये क्विंटल पर पहुंच गया है। परिणामस्वरूप इससे गोशालाओं का खर्च भी दोगुना हो गया है। आंकड़ों के अनुसार औसतन 2000 गाय वाली गोशाला में अकेली तूड़ी का खर्च पहले करीब 20 लाख रुपये आता था मगर अब रेट दो गुने होने से यह खर्च भी दोगुना हो गया है। पिछली बार 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल बिकी सरसों से इस बार गेहूं और तूड़े की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। प्रदेश भर में गत वर्ष की तुलना में कम एकड़ में गेहूं की बिजाई करने से इस बार तूड़े (गेहूं की फसल के अवशेष से बने पशु चारे) के दाम भी आसमान छू रहे हैं।

● ● ● ●

जलवायु परिवर्तन

मौसम की चपेट में आए तरबूज किसान, कहा- मुनाफा तो दूर लागत निकालना मुश्किल, भीषण गर्मी और बदली मौसमी परिस्थितियों में तरबूज का कम उत्पादन होने से किसानों को भारी घाटा हो रहा है

● ● ● ●

भीषण गर्मी की वजह से पंजाब में गेहूं की फसल को 20 फीसदी नुकसान का अनुमान
गेहूं की फसल खराब होने के कारण छोटे किसान नुकसान नहीं झेल पा रहे हैं और किसानों के आत्महत्या करने की खबरें आने लगी हैं

● ● ● ●

गेहूं की फसल पर 500 रुपए बोनस की मांग कर रहे हैं हरियाणा के किसान, हरियाणा के किसानों का कहना है कि इस बार गेहूं के उत्पादन में 40 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है

● ● ● ●

देश में एक और जहां जायद (ग्रीष्मकालीन) फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ है। वहीं, मार्च-अप्रैल के महीने में बढ़ती गर्मी ने इन फसलों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल यानी मार्च-अप्रैल 2022 में तापमान में हुई भारी वृद्धि से जायद फसलों को नुकसान हो सकता है।

● ● ● ●

जायद यानी ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होती है और मई-जून तक इन फसलों की कटाई हो जाती है। इनमें दलहन, तिलहन और पोषण अनाज की बुआई की जाती है। इस साल 55.76 लाख हेक्टेयर में जायद फसल लगाई गई है, जो पिछले साल 56.47 लाख हेक्टेयर से थोड़ा कम है। जबकि 2018-19 में जायद फसलों का रकबा 33.56 लाख हेक्टेयर था।

लेकिन इस साल यानी 2022 के तापमान ने सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मार्च में रिकॉर्डतोड़ गर्मी और अप्रैल के पहले सप्ताह से देश के अधिकतर हिस्से में चल रही लू (हीटवेव) की वजह से ग्रीष्मकालीन जायद फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन जायद फसलों के लिए अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक सही रहता है, लेकिन यदि तापमान 40 डिग्री से अधिक पहुंच जाए तो फसलों को नुकसान हो सकता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पप्सेज रिसर्च) के प्रिंसिपल साइंटिस्ट आदित्य प्रताप ने डाउन टू अर्थ से कहा कि ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में सबसे अधिक मात्रा समर मूंग और उड़द की होती है। चूंकि अप्रैल के पहले सप्ताह से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है और लगातार शुष्क बना हुआ है तो इसकी वजह से दलहन की इन फसलों के परागण में फर्क पड़ेगा। साथ ही, गर्मी की वजह से दालों की फलियां भी नहीं बनेगी

● ● ● ●

मध्य प्रदेश में इस बार लहसुन की पैदावार तो हुई लेकिन फसल खराब होने के कारण किसानों को मंडी में सही दाम नहीं मिल रहा है, जिस के कारण वे काफी परेशान हैं। इस वर्ष मार्च के महीने में हुई ओलावृष्टि और उसके बाद थ्रिप्स बीमारी की चपेट में आयी लहसुन की फसल को भारी नुकसान हुआ है।

● ● ● ●

पहले फल के बाद अब सब्जियों के दाम भी आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। एक तरफ बढ़ता पारा और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अब सब्जी के बढ़ते भाव लोगों को सता रहे हैं। हर चीज के दाम रिकार्ड स्तर पर हैं। नींबू ने तो लोगों का जायका बिगाड़े रखा। अभी भी 250 रुपए किलो बिक रहा है।

इस समय जनता परेशान है कि क्या खाएं जो बजट में आ जाए। टमाटर, मिर्च, लौकी, मूली जैसी आम सब्जियां भी बजट से बाहर हो रही हैं।

पर्यावरण विमर्श में नारी संचेतना

जीव और पर्यावरण का अन्योन्याश्रित संबंध सृष्टि के आरम्भ से ही रहा है। पर्यावरण से इतर मानव जीवन की कल्पना भी नामुमकिन है। वह हर पल पर्यावरण से आवृत्त है । चतुर्दिक पर्यावरण से घिरा वह पर्यावरण से प्रभावित भी होता है । और अपने कार्य व्यवहार से उसपर अपना प्रभाव भी डालता है। दोनो एक दूसरे के निर्माता और विकृतकर्ता हैं। यह क्रम एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत चलता रहता है। जिसकी तरफ सामान्यत: हमारा ध्यान ही नही जाता है। परंतु जब अकाल, भूकम्प, अतिवृष्टि,अनावृष्टि, तूफान, भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आती है तब हमारा ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर जाता है।

मानव जीवन को पुष्पित, पुल्लवित व आनंददायी बनाने के लिए प्रकृति ने उसे जन्म से ही निशुल्क उपहार में सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं! जब तक प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीमित मात्रा में उपभोग हुआ तब तक पर्यावरण संतुलित रहा। परंतु औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या, विस्फोट, शहरीकरण और विकास के कारण मनुष्य द्वारा भूमि, जल, वायु और प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममता पूर्वक दोहन किये जाने के कारण प्राकृतिक असुंतलन का प्रभाव न सिर्फ उसपर पड़ रहा है बल्कि पेड़, पौधे , पशु पक्षी तथा अन्य जीवधारियों की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गयी है । औद्योगिक इकाईयों के अपशिष्ट पदार्थ, धूल, रासायनिक, द्रव्य, गैस, धुआं, रेडिशन, उर्वरकों ने जल और वायु को गंभीर रूप से प्रदूषित किया है। जिससे मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहा है। अत: आज के भौतिकवादी समय मे हमारे सामने पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना चिंतनीय विमर्श है।

डॉ कामिनी वर्मा
ज्ञानपुर 'भदोही' (उत्तर प्रदेश)

वैज्ञानिकों की मानें तो बढ़ते उत्सर्जन के साथ-साथ वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे जलवायु में बदलाव आ रहा है। जलवायु में आता यह बदलाव अन्य मौसमों के साथ ही बसंत ऋतु को भी प्रभावित कर रहा है। इसका असर इन पक्षियों के व्यवहार और आदतों पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि ब्लूजे, येलो वॉरब्लर और फील्ड स्पैरो (गौरैया) जैसे पक्षियों की कई प्रजातियां करीब 25.1 दिन पहले ही अपने घोसलों को तैयार कर अंडे दे रही हैं।

यदि बढ़ते तापमान को देखें 1880 से हमारे ग्रह का औसत तापमान 0.08 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। वहीं 1981 के बाद से यह दर बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वैश्विक तापमान में पहले ही एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है।

वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 'एमिशन गैप रिपोर्ट 2020' के अनुसार सदी के अंत तक तापमान में होती यह वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी। ऐसे में इसके कितने विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे, उसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।

शोधकर्ताओं के मुताबिक हालांकि तापमान में कुछ डिग्री का परिवर्तन बहुत छोटा लगता हो लेकिन इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। इन बदलावों का मतलब है कि पेड़-पौधों के फैलने और कीड़ों के पनपने के समय में अन्तर आ जाएगा। यह ऐसी चीजें है जो पक्षियों के भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं।

शोध में जिन पक्षियों का अध्ययन किया है वो कीटों पर भी निर्भर हैं। इन कीटों का मौसमी व्यवहार जलवायु से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पक्षियों की कई प्रजातियां अनुकूलन के लिए अपने अंडे देने के समय में बदलाव कर रही हैं।

ऐसा ही कुछ प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में भी सामने आया था जिसके अनुसार बढ़ते तापमान के चलते यूनाइटेड किंगडम में फूल करीब एक महीना पहले खिलने लगे हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका में पक्षियों को लेकर जर्नल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि 1970 से लेकर अब तक कनाडा और अमेरिका में जंगली पक्षियों की करीब 29 फीसदी आबादी घट चुकी है, जिनकी कुल संख्या करीब 300 करोड़ है।

यह अध्ययन एक बार फिर इस बात को पुख्ता कर देता है कि बढ़ता तापमान जीवों के व्यवहार और आदतों पर व्यापक असर डाल रहा है और इन सबके लिए हम इंसान जिम्मेवार हैं। हमारी बढ़ती महत्वाकांक्षा इन निरीह जीवों को अपना निशाना बना रही है।

अपने हिस्से से कहीं ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं अमेरिका, चीन और यूरोप, सीमा में है भारत

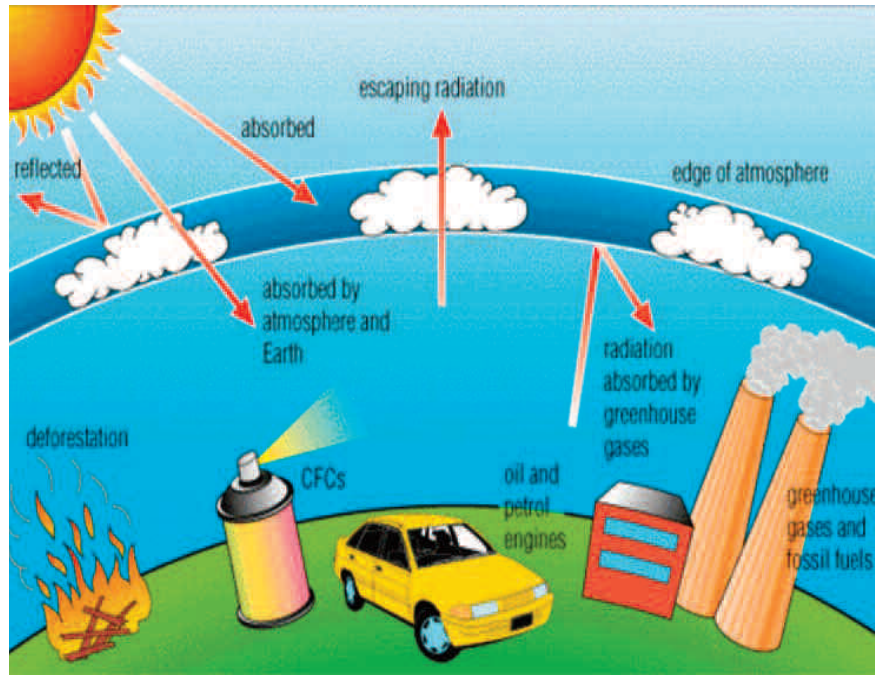

हाईड्रोजन आधारित ईंधन

नरेंद्र मोदी जी का वो इच्छे वाला ट्रम्प कार्य जिसके फलीभूत होते ही भारत को ईंधन के लिए न अमेरिकी, न रूसी, न सऊदी न कतर न खाड़ी के किसी देश की जरूरत पड़ेगी। न रूस न अमेरिका की खींचतान का दबाद भारत पर बनेगा।

इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया अपडेट मिला है जिसके विश्लेषण से कहा जा सकता है कि वर्ष 2034 तक भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर छोटी, मध्यम या बड़ी एलेट्रॉलाइजर फेक्ट्री की स्थापना हो जाएगी जो पानी को तोड़कर उससे ईंधन के लिए हाइड्रोजन गेस Hw रासायनिक खाद के लिए अमोनिया गैस और वायुमण्डल के लिए आक्सीजन हवा मिलनी शुरू हो जाएगी।

आप सबको याद होगा कि कुछ माह पहले मोदी सरकार ने देश के लिए नई हाइड्रोजन नीति घोषणा की थी। सरकार ने यह बताया था कि वर्तमान में भारत अपने ईंधन(कुकिंग गैस) की जरूरतों के लिए कतर, रूस अथवा अमेरिका से लिकवीड गैस के बड़े बड़े टैंकरो को समुद्री जहाजो पर रखकर मंगवाता है। सरकार का मानना है कि यदि हम पानी से हाइड्रोजन गैस निकाल ले तो वह ईंधन के रूप में काम आ जायेगी जो वजन में बहुत कम होती है लेकिन प्रति किलो हाइड्रोजन गैस 150 लिकवीड गैस के बराबर ऊर्जा देगी।

बजट में ऐसे प्लांटों की स्थापना के लिये PLI स्किम भी दी गई है जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि प्लांट के चालू होने के बाद टोटल प्रोजेक्ट का 30 प्रतिशत अनुदान दे दिया जाएगा। इस बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा ग्रूप इत्यादि ने ने एलेट्रॉलाइजर प्लांट की स्थापना का कार्य जापानी कम्पनियों के सहयोग से शुरू भी कर दिया है। अब नवीनतम अपडेट यह है कि बेल्जियम की एक मल्टी योरोपियन कम्पनी 'ग्रीनको जान-कारकर' द्वारा 950 मिलींयन डालर का पूंजी निवेश भारत मे कर विश्व का सबसे बड़ा एलेट्रॉलाइजर प्लांट की स्थापना कर रही है।

इस प्लांट का एलेट्रॉलाइजर पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाकर उसे पिले रंग के सिलिंडरों में भरेगा (जैसा की चित्र में दर्शाया गया है), बाकी उससे जो अमोनिया गैस निकलेगी उससे अमोनियम नाइट्रेट नामक रासायनिक खाद बनेगी तथा बाकी आक्सीजन बनकर वायुमण्डल में मिल जाएगी।

ग्रीन हाइड्रोजन एक नया ऊर्जा संसाधन है जिसका दोहन करने के लिए भारतीय उद्योग जगत के सभी दिग्गज हाथ-पांव मार रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अदानी ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल), रिन्यू पावर और अन्य जैसी कई कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में प्रवेश करने के अपने इरादे की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नीले हाइड्रोजन का उत्पादक बनने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक मीथेन से बना है।

इन कंपनियों में से एलएंडटी, आईओसीएल और रिन्यू पावर परियोजना को अंजाम देने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाएंगे। स्पष्ट रूप से, इन कंपनियों का मानना है कि हरित हाइड्रोजन दुनिया में ईंधन का एक प्रभावी और बड़े पैमाने पर स्रोत हो सकता है जो खुद को जीवाश्म ईंधन से दूर कर रहा है। इसी तरह, आईओसीएल और एलएंडटी एक साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स का उत्पादन करने के लिए एक साथ आने की योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर, यह अनुमान है कि अकेले एलएंडटी, अदानी और रिलायंस जैसे बड़े खिलाड़ी इस क्षेत्र में 6 ट्रिलियन रुपये का निवेश करेंगे।

मोदी सरकार की यह योजना है कि 2034 तक देश के हर क्षेत्र या शहर में आवश्यकतानुसार ऐसे कम से कम 700 एलेट्रॉलाइजर प्लांट स्थापित हो जावे ताकि उस हाइड्रोजन गैस को अंडरग्राउंड पाइप के जरिये अथवा सिलेंडरों में भरकर घरों घरों के किचन में पहुचा दिया जावे।

पिछले 50 वर्षों में हमने तय सीमा से करीब 1.1 लाख करोड़ टन संसाधनों का ज्यादा दोहन किया है, जिसके करीब 27 फीसदी हिस्से के लिए केवल अकेला अमेरिका जिम्मेवार है

क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप के कई देश अपने हिस्से से कहीं ज्यादा तेजी से जैविक और अजैविक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हालांकि भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश सहित 58 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शाश्वत सीमा को पार नहीं किया है। यह जानकारी हाल ही में जर्नल लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में सामने आई है।

हमें बचपन से यह पढ़ाया जाता रहा है कि इस धरती पर मौजूद संसाधन सीमित हैं ऐसे में यदि हम उनका विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। पर शायद यह बात देशों के नीति-निर्माताओं को नहीं पता, जो पिछले कई दशकों में भी संसांधनों का उचित प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं।

यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछली आधी सदी (1970 से 2017) में दुनिया के 160 देश करीब 2.5 लाख करोड़ टन संसाधनों का उपयोग कर चुके हैं, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों तरह के संसाधन शामिल हैं। देखा जाए तो हमारी संसाधनों के उपयोग की जो शाश्वत सीमा थी वो केवल 2.06 लाख करोड़ टन ही थी।

आंकड़ों की मानें तो इन 50 वर्षों में हमने करीब 1.1 लाख करोड़ टन संसाधनों का तय सीमा से ज्यादा दोहन किया है, जोकि उपयोग किए गए कुल संसाधनों का करीब 44.4 फीसदी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं जो इन संसाधनों का दोहन अपनी तय सीमा से ज्यादा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि संसाधनों के अनुचित उपयोग की बात की जाए तो उसके 74 फीसदी हिस्से के लिए केवल कुछ गिने-चुने अमीर साधन संपन्न देश जिम्मेवार हैं। वहीं इसके करीब 60 फीसदी हिस्से के लिए केवल पांच देश अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस जिम्मेवार हैं। इसके 27 फीसदी के लिए केवल अकेला अमेरिका जिम्मेवार है, जबकि चीन की हिस्सेदारी करीब 15.3 फीसदी है। वहीं 8.8 फीसदी के लिए जापान, 5 फीसदी के लिए जर्मनी और 3.5 फीसदी के लिए फ्रांस जिम्मेवार है।

(साभार - डाउन टू अर्थ पोर्टल)

मौलिक भारत विचार श्रृंख्ला-9

अजय सिंह 'एकल'

नीति आयोग सुझाए
सरकार करे - जनता भरे

● अजय सिंह 'एकल'

योजना आयोग के बारे में बहुत कम जानकारी आमतौर पर जनता में रहती है क्योंकि इसके द्वारा बनाई गई नीतियां विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से कार्यान्वित होती है। अत: नीतियों के लागू होने के जो भी अच्छे या बुरे प्रभाव होते है उसके बारे में हुई चर्चा मंत्री और मंत्रालयों तक ही सीमित रहती है। इसलिए जनता के बीच योजना आयोग के बारे में बहुत सीमित चर्चा होती है। सन 1950 में जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी तो कल्पना यह थी की यह आयोग देश में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग, अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास, तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाएगा तथा समय-समय पर इनका मूल्यांकन और प्रभाव का अध्ययन करेगा और केंद्र तथा राज्य सरकारों को सुझाव देकर देश के विकास के लिए अग्रणी संगठन बनेगा। योजना आयोग को प्रभावी बनाने के लिए ही देश के प्रधान मंत्री जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ, अनेक बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और उनके सहयोगियों की सहायता से चलने वाला योजना आयोग आशा के अनुरूप परिणाम शायद ही दे पा रहा था। प्लानिंग कमीशन द्वारा द्वितीय पांच वर्षीय योजना के लागू होने के बाद ही जवाहर लाल नेहरू की आर्थिक नीतियों पर टिप्पड़ी करते हुए अर्थशास्त्री बेल्लीकोट रघुनाथ शेनाए ने कहा था अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण लोकतंत्र को कमतर कर रहा है।

मोदी सरकार के कार्य भार संभालने के तुरंत बाद एक स्वतंत्र मूल्यांकन ऑफिस (Independent Evolution Office) को यह जिम्मेदारी दी गई की वह योजना आयोग की कार्य प्रणाली और उसके प्रभाव के बारे में बताए । आइ.ई.ओ ने अपनी आख्या में बताया की योजना आयोग एक 'कन्ट्रोल्ड कमिशन' की तरह काम करने वाली संस्था है । इसको सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए इसे 'सुधार और समाधान' करने वाली संस्था में बदलना चाहिए। इस संस्तुति को देखकर मंत्री समूह ने तय किया की योजना आयोग को पूरी तरह से नई संस्था में बदला जाना चाहिए। मोदी जी ने भी स्पष्ट कहा सरकार का काम कारोबार करना नहीं, नीतियां बनाना है। इसलिए योजना आयोग की जगह भविष्य में नीतियां तय करने वाले नीति आयोग ने ले ली। इसके जिम्मे अंतरराष्ट्रीय स्थितियों और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर योजना बनाना है। 16 बड़े स्थाई लक्ष्यों और उसके लिए 169 छोटे लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने की योजना सफलता पूर्वक लागू करके नीति आयोग को साबित करना है की योजना आयोग का स्वाभाविक भविष्य नीति आयोग है।

केन्द्रीय मंत्री समूह की संस्तुति के आधार पर 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार में प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया। भाषा की साधारण समझ रखने वाले व्यक्ति को नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में केवल नाम परिवर्तन का ही फर्क लग सकता है । परंतु NITI शब्द असल में National Institute for Transforming India का लघु रूप है। नीति आयोग के बारे में ज्यादा जानने के लिए यदि आप इसकी वेब साइट पर जा कर देखे तो संगठन के बारे में जानकारी के साथ ही अलग-अलग वर्टिकल्स मसलन शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर , ऊर्जा, उद्योग इत्यादि के बारे में हो रहे कार्य के बारे में जानकारी मिलेगी। हालांकि यह कहना कठिन है की नाम बदले जाने के बाद से पुरानी संस्था

यानी योजना आयोग के काम और नीति आयोग के काम काज के तौर तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है तो भी सकारात्मक बदलाव तो निश्चित हुए है और दिख भी रहे है। एक चूक जो योजना आयोग के बाद नीति आयोग बनने तक जारी रही वह थी इस संस्था का उप प्रधान किसी ऐसे आदमी को बनाया जाना चाहिए था जिसे समाज शास्त्र और अर्थ शास्त्र के साथ ही भारत देश की भी अच्छी जानकारी होती और दिमाग के साथ ही दिल भी देश के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचता। योजना आयोग के यूपीए सरकार के कार्य कल में दस वर्ष प्रमुख रहे डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया केवल नाम से हिन्दुस्तानी थे। पूरी जिंदगी उन्होंने वर्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्था में काम किया था अत: उनका अनुभव और कार्यशैली दोनों ही भारत की जरूरतों को पूरा करने में फेल रही। यही चूक नीति आयोग का प्रथम उप प्रधान चुनने में भी हुई।नीति आयोग के प्रथम उप प्रधान प्रोफ. अरविन्द पनघड़िया ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डाक्टरेट करने के बाद वर्ड बैंक, आईएमएफ, डबल्यूटीओ, इत्यादि में काम किया और नीति आयोग के उपप्रधान बनने से पहले मेरीलैन्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। अधिकांश समय भारत के बाहर रहने के कारण उनका भी दिमाग तो भारत के लिए काम कर रहा था परंतु दिल का सामंजस्य देश के साथ ठीक नहीं बैठ पाया नतीजतन उनके कार्यकाल में भी नीति आयोग अपनी रीति नीति को बदलकर बहुत प्रभावशाली नहीं बन पाया।अत: उन्हे अपना कार्य काल पूरा किए बिना ही वापस अमेरिका जाना पड़ा। अरविन्द पनघड़िया जी के बाद यह जिम्मेदारी सितंबर 2017 में राजीव कुमार को मिली जिन्होंने अपनी डाक्टरेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है। लेकिन उसके बाद का अधिकांश समय भारतीय संस्थाओं के साथ में विभिन्न पदों पर काम करते रहे। उनका अनुभव भारत की जरूरतों को ठीक से समझ कर उनके समाधान के लिए नीतियां बनाकर नीति आयोग को प्रभावशाली, सुधार और समाधान जैसी संस्था बनने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद पांच वर्षों के लिए होता है। अत: राजीव कुमार का कार्यकाल सितंबर 2022 में खत्म होगा परंतु तय समय से पांच महीने पहले ही राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब डा. सुमन बेरी का चुनाव उपाध्यक्ष के पद के लिए किया गया है जो अपना पदभार 1 मई 2022 को ग्रहण करेंगे। आशा की जानी चाहिए नए नेत्रत्व में नीति आयोग अपने लक्ष्य पूर्ति में पूरी तन्मयता से लगेगा और देश की उन्नति में अपना योगदान करेगा। नीति आयोग अपने काम को और अच्छे तथा प्रभावशाली तरीके से कर सके इसके लिए कुछ सुझाव है जिन पर विचार करने से देश की तीव्र उन्नति सुनिश्चित हो सकेगी।

सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है की देश की सर्वांगीण विकास की योजना जो अभी पांच सालों की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि चुनी हुई सरकार का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है। और पांच साल के कार्यकाल के बाद यदि सरकार बदल जाए तो योजना और प्रोजेक्ट की वरीयता बदल सकती है इसलिए हर सरकार पांच साल की योजना पर कार्य करती है। अब महत्व पूर्ण प्रश्न यह है की योजना बनती है देश और जनता के विकास के लिए। सरकार कोई भी हो किसी भी पार्टी या विचार धारा की हो सरकार जनता चुनती है देश के विकास के लिए, तो देश हित के काम को सरकार बदलने के साथ क्यों रुकना चाहिए? उदाहरण के लिए 1998-2004 के बीच केंद्र में जब एनडीए की सरकार थी तब देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के चतुर्भुज स्वर्णिम सड़क योजना शुरू की गई जिसमे दिल्ली, मुंबई कोलकता और चेन्नई राष्ट्रीय राज मार्ग बना कर जोड़ना था। 2004 में एनडीए सरकार के जाने के बाद यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में योजना को स्थगित कर दिया नतीजा यह हुआ की प्रोजेक्ट 10 साल बाद एनडीए सरकार के आने के बाद शुरू हो सका। इसी तरह देश में हर साल बाढ़ और सूखे के कारण जान और माल की सुरक्षा के लिए नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई दुर्भाग्य से यह योजना भी यूपीए सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दी। रक्षा क्षेत्र के लिए फ्रांस से राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव में भी 8-10 वर्षों का विलंब हो गया। अत: देश हित की इंफ्रा स्ट्रक्चर, विद्युत, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ संबंधी योजनाएं 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाई जाए और चुनी हुई सरकार को अतिआवश्यक होने पर ही उसमे परिवर्तन का अधिकार हो साथ ही रोकने का अधिकार किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। 100 साल की योजना को 50-50वर्षों फिर 25-25 वर्षों तत्पश्चात 5-5 वर्षों की योजना में बांट देने से सरकार कोई भी हो काम की कांटीनुयटी सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकारें तो आएंगी जाएंगी परंतु देश हित के काम जारी रहे यह देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। मोदी सरकार ने पहली बार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए इस वर्ष के वित्त

बजट में अगले 25 वर्षों में देश के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चरकी योजना का खाका खीचा है। यदि आवश्यक हो तो इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए कानून बनाया जाए ताकि देश हित की योजना को रोक नहीं जा सके। एक बात और, देश हित की योजनाओ को बनाने के लिए देश के बड़े समाज सेवी, उद्योगपतियों, विज्ञानियों का समूह बने जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ कर देश हित की योजनावो के लिए सुझाव दे। इन्हे पूरा करने के लिए इसी समूह के लोगों को अलग-अलग प्रोजेक्ट की देख रेख का काम दिया जाना चाहिए। तब योजना का काम सरकार पर निर्भर न होकर देश की जरूरतों के अनुरूप चल सकेगा। और किसी भी सरकार के आने या जाने से देश हित के काम बिना व्यवधान के पूरे होंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम है की केंद्र सरकार द्वारा बनाई और चलाई जाने वाली सभी योजनाओं को तीन भागों में अर्थात अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, और सामान्य में बांट दिया जाए। इंफ्रा स्ट्रक्चर, विद्युत, रक्षा, शिक्षा, रेल, स्वास्थ संबंधी योजनाए अतिमहत्व पूर्ण की श्रेणी में हो जिसमें परिवर्तन के लिए सरकार की सहमति के साथ ही जनमत संग्रह भी आवश्यक हो। बिना जनमत की सहमति के इन योजनाओं को न रोक जा सके न परिवर्तित किया जा सके। महत्वपूर्ण योजन की श्रेणी में कृषि, ग्रामीण विकास, टेक्नोलॉजी, लेबर, स्किल एवं उद्यम, जल, भारी उद्यम इत्यादि मंत्रालयों से सम्बन्धी योजना पर सरकार को परिवर्तन का अधिकार हो। बाकी बची हुई योजनाएं सामान्य की श्रेणी में रहे और इनको बनाने और परिवर्तन करने में सरकार और विपक्ष की रायसुमारी आवश्यक रखी जाए। यह परिवर्तन योजना को समय पर पूरा करने में सहायक होगा और अनावश्यक विलंब के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाएगा। इस परिवर्तन से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी।

मोदी सरकार ने गतिशक्ति योजना बना कर सोलह विभागों के आपस में समन्वय की योजना बना कर निश्चित ही सराहनीय प्रयास किया है । लेकिन यह समन्वय अभी केवल इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक ही सीमित है। नीति आयोग को चाहिए कि सभी मंत्रालयों के साथ इस तरह का समन्वय करे की किसी भी योजना के साथ जो भी प्रभावित सहयोगी संस्थान या मंत्रालय है उनके साथ समन्वय बने तथा उनकी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर योजनाओं को लागू करवाने में सहयोग करें। उदाहरण के लिए रेलवे में होने वाले अगले पांच वर्षों के प्लान को पूरा करने में जिस स्किल के लोग लगने वाले है उसके लिए शिक्षा मंत्रालय योजना बना कर विषयों में आवश्यक परिवर्तन करके संबंधित विश्वविद्यालय और कालेज में पढ़ाए जाने की व्यवस्था करे। इसी तरह यूपी में प्रस्तावित 300 कि.मी. डिफेन्स कॉरीडोर का जो निर्माण किया जा रहा है इसमे पूरी दुनिया से बड़ी और नामी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लेकर आएंगी। इसमे काम करने के लिए जिन विशेष योग्यताओंसे युक्त लोगों की जरूरत पड़ने वाली है उनका आकलन आने वाली कंपनियों के साथ समन्वय करके करना चाहिए और उन स्किल से युक्त काम करने के लिए लोग कंपनियों के उत्पादन शुरू करने के पहले तैयार हों ताकि कुशल कामगार और इंजीनियर समय से उपलब्ध हो सके। यह चिंता नीति आयोग को समय रहते करनी चाहिए। ताकि लोगों को रोजगार और आने वाले उद्यमों को कुशल इंजीनियर, कामगार इत्यादि समय से मिल सकें और उद्यम समय से अपना उत्पादन प्रारंभ कर सकें।

देश में कई दशकों से चले या रहे अनावश्यक कानून व्यापार और उद्यमों की राह कठिन करते है इनके सरली करण का ठोस प्रयास मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। इस क्रम में 1400 से ज्यादा कानूनों को रद्द किया गया है साथ ही देश में ईज आफ डूइंग बिजनेस हो इसके लिए किए गए प्रयासों की सराहना अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी पिछले वर्षों में की है। रोज मर्रा के कामों में भ्रष्टाचार भी काम हुआ है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पिछले दो सालों में कोविड-19 ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। साथ ही दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों जिन्होंने चीन में अपने उत्पादन केंद्र बनाए थे वे उद्यमी अब चीन से बाहर जाना चाह रहे है। भारत इन उद्यमिओं के लिए एक आकर्षक देश है लेकिन मलेशिया, इंडोनेशिया, मयनमार जैसे देश भी भारत के मुकाबले में खड़े है। हालांकि भारत का समर्थ राजनैतिक नेत्रत्व, बड़ी आबादी के कारण कुशल टेक्निकल और स्किलयुक्त लोगों की उपलब्धता मुकाबले के दूसरे देशों से भारत को अलग करती है परंतु इसकी अच्छी तैयारी कर ज्यादा से ज्यादा उद्यम भारत कैसे आए इसकी चिंता नीति आयोग को अग्रसक्रिय होकर करनी चाहिए। कोविड की आपदा को अवसर बनाने का इससे अच्छा समय भविष्य में मुश्किल से ही मिलने वाला है। अत: इस वैश्विक आपदा को अवसर में बदलने के लिए इसमे कहां कहां कठनाईया है इसको चिह्नित कर और इसका समाधान निकाल कर नीति आयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति करने की ओर अग्रसर हो तब संस्था सही मायनों में 'सुधार और समाधान' वाली संस्था बन सकेगी।

देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव वर्ष में नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीटूट आफ ट्रांस फार्मिंग इंडिया यदि उपरोक्त महत्वपूर्ण सुझावो पर कार्य करे तो यह देश और देशवासियों के लिए अत्यंत सुखद होगा और यह संस्थान प्लानिंग कमीशन की तरह सफेद हाथी न बन कर देश के लिए उपयोगी संस्था बनकर अपने नाम को सार्थक और जिन उद्देश्यों के लिए संस्था बनाई गई है उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगी। ■

अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची विश्व खाद्य जिंसों की कीमतें - एफएओ

● संपादन - अनुज अग्रवाल

रूस-यूक्रेन युद्ध और बेमौसमी घटनाओं के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोत्तरी लगातार जारी है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी की तुलना में मार्च में विश्व खाद्य कीमतों में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसे अब तक की सबसे अधिक वृद्धि बताया गया है।

एफएओ ने 8 अप्रैल को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'विश्व खाद्य वस्तुओं की कीमतों ने मार्च में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई।' रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें वृद्धि की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी।

एफएओ ने अपने नवीनतम खाद्य मूल्य सूचकांक रिपोर्ट में कहा, 'काला सागर क्षेत्र में युद्ध की वजह से अनाज और वनस्पति तेलों के बाजार को बड़ा झटका लगा है'।

रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में औसत सूचकांक 159.3 अंक था, जो फरवरी के स्तर से 12.6 प्रतिशत अधिक है। फरवरी 1990 में जब से एफएओ विश्व खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी कर रहा है, तब से लेकर अब तक का सबसे उच्चतम स्तर बताया गया है। अगर इसकी तुलना मार्च 2021 से की जाए तो यह अभूतपूर्व 33.6 प्रतिशत अधिक है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन मिलकर विश्व के गेहूं और मक्के के निर्यात में क्रमश: 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं। एफएओ के मुताबिक मक्के की कीमत भी बढ़ रही है। इसमें फरवरी से 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एफएओ अनाज (सेरेल) मूल्य सूचकांक फरवरी की तुलना में मार्च में 17.1 प्रतिशत अधिक था, जो यूक्रेन में युद्ध के परिणामस्वरूप गेहूं और सभी

मोटे अनाज की कीमतों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की वजह से हुआ।

एफएओ ने कहा, 'यूक्रेन में बंदरगाह बंद होने से देश से निर्यात सीमित हो रहा है, जबकि रूसी संघ से निर्यात में भी बाधाएं आ रही हैं।' यह स्थिति आगे भी जारी रहने का अनुमान लगाते हुए कहा गया है कि अभी आने वाले दिनों में कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं।

खाद्य मूल्य सूचकांक पर अपने विस्तृत नोट में एफएओ ने कहा, काला सागर क्षेत्र में शिपमेंट की आवाजाही में आई कमी की वजह से निर्यात का नुकसान हुआ और इस वजह से जहां वैश्विक कीमतें बढ़ी, वहीं आयात में कमी आई और मांग में वृद्धि हुई। खासकर उन देशों में कीमतों में अधिक वृद्धि हुई, जहां अनाज का स्टॉक कम था।

युद्ध के कारण हुए व्यवधान ने सूरजमुखी के बीज के तेल की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। एफएओ ने कहा, 'एफएओ वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक 23.2 प्रतिशत बढ़ा। इसमें सूरजमुखी के बीज के तेल की मात्रा अधिक है, क्योंकि यूक्रेन पूरी दुनिया में सूरजमुखी के बीज का तेल निर्यात करता है।

एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने मार्च में एक बयान में कहा था कि खाद्य वस्तुओं के दो प्रमुख निर्यातक देशों के बीच छिड़े युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है।

बढ़ती महंगाई, आम आदमी व आर्थिकी

- डा. जयंतीलाल भंडारी

ऐसे में अब कच्चे तेल के देश में अधिक

उत्पादन व कच्चे तेल के विकल्पों पर ध्यान देना होगा। कच्चे तेल के वैश्विक दाम में तेजी के बीच तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम में दिलचस्पी और बढ़ाना होगी। यद्यपि रूस से भारत का तेल आयात एक प्रतिशत से भी कम है, लेकिन अब रूस से तेल आयात में वृद्धि की जाना लाभप्रद होगी और कच्चे तेल आयात का भुगतान रूबल में किया जाना लाभप्रद हो सकता है।

इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने से वैश्विक जिंस बाजार के अस्त-व्यस्त होने से दुनिया के सभी देशों की तरह भारत में भी महंगाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यद्यपि महंगाई की ऊंचाई अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, पाकिस्तान आदि अधिकांश देशों में भारत की तुलना में कई गुना अधिक है। लेकिन फिर भी भारत में महंगाई से आम आदमी से लेकर अर्थव्यवस्था की मुश्किलें कम करने हेतु नए रणनीतिक प्रयासों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। गौरतलब है कि अब देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि करने की डगर पर आगे बढ़ी है। हाल ही में 22 मार्च को सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने जहां पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर और घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया, वहीं 23 और 25 मार्च को पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर 80-80 पैसे की वृद्धि की गई है। इसके पहले 21 मार्च को तेल कंपनियों ने थोक खरीददारी के लिए डीजल के दाम में एकबारगी 25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था। ज्ञातव्य है कि विधानसभा चुनावों के कारण रिकॉर्ड 137 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बदली गई थीं। इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का क्रूड बास्केट 4 नवंबर 2021 के 73.47 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 24 मार्च को 121.4 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भी इस बीच तेजी से बढ़ते रहे और 7 मार्च को 139 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गए थे। ऐसे में अगले कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी बड़ी बढ़ोतरी से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की तेज उछाल के बोझ को अधिक दिनों तक सहन कर सकती हैं। कर ढांचे के आधार पर और कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने के मद्देनजर डीजल और पेट्रोल की कीमत मौजूदा दर से करीब 19 रुपए तक महंगी हो सकती है। पिछले कुछ समय से देश में खाने के तेल के दाम आसमान पर पहुंचे हुए हैं।

उर्वरक के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं। 14 मार्च को सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर फरवरी में बढ़कर 6.07 फीसदी रही जो इससे पिछले महीने 6.01 फीसदी थी। इसमें बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य एवं पेय, परिधान एवं फुटवियर और ईंधन एवं बिजली समूहों में तेजी की वजह से हुई है। देश में खुदरा महंगाई फरवरी में बढ़कर 8 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर रही है। यह लगातार दूसरे महीने केंद्रीय बैंक के 6 फीसदी के सहजता स्तर की ऊपरी सीमा से अधिक रही है। इसी तरह थोक महंगाई की दर लगातार 11वें महीने दो अंकों में रही है। उद्योग विभाग द्वारा जारी नए आंकड़ों से पता चलता है कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर फरवरी में 13.11 फीसदी रही, जो जनवरी में 12.96 फीसदी थी। अब पेट्रोल-डीजल और गैस की मूल्य वृद्धि से महंगाई का ग्राफ और बढ़ता हुआ दिखाई देगा और महंगाई से विभिन्न मुश्किलें निर्मित होंगी। नि:संदेह कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से गरीब व मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ेंगी तथा आर्थिक पुनरुद्धार को झटका लग सकता है। महंगाई एक छिपे हुए प्रतिगामी कर की तरह है। जब तेल और जिंस की कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब व मध्यम वर्ग के साथ आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है। उद्योग-कारोबार का मुनाफा कम होता है, जिसका सीधा असर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि पर पड़ता है। चूंकि उद्योग-कारोबार कीमतों का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर डालते हैं, अतएव इससे उपभोक्ताओं की खर्च करने वाली आय कम होती है और इसका उपभोक्ता मांग पर असर पड़ता है। महंगाई बढ़ने के साथ ब्याज दरें बढ़ने व कर्जा महंगा होने की आशंका बढ़ती है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से बजट घाटे में वृद्धि होगी। बजट लक्ष्य भी गडबड़ाएंगे। वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट यूक्रेन संकट के पहले तैयार हुआ है।

इसमें कच्चे तेल की कीमतों का झटका शामिल नहीं है। बजट तैयार करते समय कच्चे तेल की कीमत 70-75 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया गया था। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि इस समय दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में महंगाई को तेजी से बढ़ने से रोकने में कुछ अनुकूलताएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। देश में अच्छी कृषि पैदावार खाद्य पदार्थों की कीमतों के नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत के पास मार्च 2022 में करीब 622 अरब डॉलर का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार चमकते हुए दिखाई दे रहा है। मौजूदा

साल के अंत तक 145 रुपए प्रति दिन से कम में गुजारा करने को मजबूर होंगें 86 करोड़ लोग

अनुमान है कि अकेले वैश्विक खाद्य कीमतों में होती बढ़ोतरी करीब 6.5 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल देगी

साल के अंत तक दुनिया भर में करीब 86 करोड़ लोग 145 रुपए (1.9 डॉलर) प्रति दिन से कम में गुजारा करने को मजबूर होंगें। मतलब कि वो लोग गंभीर रूप से गरीबी का शिकार बन जाएंगें। यह जानकारी आज ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट 'फर्स्ट क्राइसिस, देन कैटास्ट्रोफे' में सामने आई है। वहीं यदि 420 रुपए (5.5 डॉलर) प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 2022 के अंत तक दुनिया भर में करीब 330 करोड़ लोग गरीबी की मार झेलने को मजबूर होंगें।

रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में बढ़ती गरीबी के लिए महामारी के कारण आए संकट, बढ़ती असमानता, खाद्य कीमतों में होती वृद्धि और यूक्रेन में जारी युद्ध को वजह माना है। अनुमान है कि इनके चलते साल के अंत तक पहले के मुकाबले करीब और 26.3 करोड़ लोग भीषण गरीबी का सामना करने को मजबूर होंगें। देखा जाए तो यह आंकड़ा यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की कुल आबादी के बराबर है।

इतना ही नहीं ऑक्सफेम का अनुमान है कि अकेले वैश्विक खाद्य कीमतों में होती बढ़ोतरी करीब 6.5 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल देगी। वहीं विश्व बैंक का अनुमान है की कोविड-19 महामारी के चलते 2022 में करीब और 19.8 करोड़ लोग भीषण गरीबी का सामना कर रहे होंगें।

साल के अंत तक कुपोषण का शिकार होंगें 82.7 करोड़ लोग

ऐसे में इस बढ़ती गरीबी के कारण लोग अपना पेट भरने के लिए भी संघर्ष करने को मजबूर हो जाएंगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अनुमान है कि 2022 के अंत तक कुपोषण के शिकार लोगों का आंकड़ा बढ़कर 82.7 करोड़ तक जा सकता है। अनुमान है कि अकेले पूर्वी अफ्रीका में करीब 2.8 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा।

पता चला है कि अकेले 2020 में कोरोना महामारी के कारण उपजे संकट के चलते महिलाओं की आय को 60.9 लाख करोड़ रुपए की हानि हुई थी। जोकि 98 देशों के कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। विश्व बैंक की माने तो महामारी और बढ़ती असमानता ने इस क्षेत्र में पिछले दो दशकों में हुई प्रगति को पलट दिया है। जिनके कारण अकेले 2022 में करीब 19.8 करोड़ लोग चरम गरीबी का शिकार हो जाएंगे।

आज दुनिया की एक बड़ी आबादी बढ़ती कीमतों के चलते जीवन-यापन के लिए जद्दोजहद कर रही है। उनके लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी आय खाने पर खर्च करे या उससे अपने चिकित्सा सम्बन्धी बिलों का भुगतान करे। ऐसे में अंदेशा है कि आने वाले वक्त में बड़ी संख्या में लोग भुखमरी और कुपोषण का शिकार बन सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्वी अफ्रीका, यमन और सीरिया जैसे देशों में लोग ऐसी भूख और गरीबी से बुरी तरह त्रस्त हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ कमजोर देश बढ़ते कर्ज के भंवर जाल में बुरी तरह उलझ गए हैं। उन देशों में मजदूरी और क्रय शक्ति कम हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ गया है और अरबपतियों की संपत्ति नए कीर्तिमान बना रही है।

वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट 'इंटरनेशनल डेब्ट स्टेटिस्टिक्स 2022' के अनुसार पहले ही गरीबी की मार झेल रहे देशों पर 2020 में 12 फीसदी की वृद्धि के साथ कर्ज का बोझ बढ़कर रिकॉर्ड 65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं यदि निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर कुल विदेशी कर्ज की बात करें तो वो 2020 में 5.3 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 654.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था।

रिपोर्ट के अनुसार भारत पर भी कुल 42.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है, इस हिसाब से हर भारतीय करीब 30,776 रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। कर्ज का यह बोझ 2010 में करीब 21.9 लाख करोड़ रुपए का था, जो पिछले 10 वर्षों में 96 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 2020 में 42.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें से 84,254 करोड़ रुपए का तो केवल ब्याज है, जिसे लम्बी अवधि के दौरान चुकाया जाना है।

ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के उद्योगपति गौतम अडानी का भी जिक्र किया गया है। जिनकी महामारी के दौरान संपत्ति आठ गुना बढ़ गई है। उन्हें जीवाश्म ईंधन से काफी लाभ हुआ है। ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के उद्योगपति गौतम अडानी का भी जिक्र किया गया है। जिनकी महामारी के दौरान संपत्ति आठ गुना बढ़ गई है। उन्हें जीवाश्म ईंधन से काफी लाभ हुआ है।

वहीं यदि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की बात करें तो उन्हें सरकारी सब्सिडी की मदद से अरबों डॉलर का फायदा हुआ है। गौरतलब है कि उन्होंने 2021 में अरबपतियों पर लगने वाले प्रस्तावित कर की आलोचना करते हुए तर्क दिया था कि अपने धन के उपयोग को लेकर उनकी योजना मंगल पर मानवता को बसाने की है। ऐसे में असमानता की यह खाई कितनी गहरी है उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं।

इस बारे में ऑक्सफेम ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बुचर का कहना है कि यदि इस विषय में तत्काल ठोस कदम न उठाए गए तो हम मानवता को गरीबी के गर्त में जाता देखने को मजबूर होंगें। इस भयानक सम्भावना को इस तथ्य ने और अधिक बीमार बना दिया है कि दुनिया में खरबो डॉलर की संपदा पर कुछ गिने चुने प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व है, जिन्हें इस बढ़ते संकट को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

संकट के बीच भारत के चालू खाते का घाटा काफी कम है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से आम आदमी और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा नई रणनीति के साथ कदम आगे बढ़ाए जाने होंगे। चूंकि कोविड-19 का महंगाई से सीधा संबंध है, अतएव पूर्ण टीकाकरण व बूस्टर खुराक पर पूरा ध्यान जरूरी है। सरकार को बारीकी से आवश्यक चीजों के बढ़ते दाम पर नजर रखनी होगी। कालाबाजारी पर नियंत्रण करना होगा। देश को प्रतिदिन करीब 50 लाख बैरल पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत होती है। चूंकि भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी आयात करता है, इस आयात का करीब साठ फीसदी हिस्सा खाड़ी देशों मुख्यतया इराक, सऊदी अरब, यूएई आदि से आता है। ऐसे में अब कच्चे तेल के देश में अधिक उत्पादन व कच्चे तेल के विकल्पों पर ध्यान देना होगा। कच्चे तेल के वैश्विक दाम में तेजी के बीच तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम में दिलचस्पी और बढ़ाना होगी।

यद्यपि रूस से भारत का तेल आयात एक प्रतिशत से भी कम है, लेकिन अब रूस से तेल आयात में वृद्धि की जाना लाभप्रद होगी और कच्चे तेल आयात का भुगतान रूबल में किया जाना लाभप्रद हो सकता है। चूंकि मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के अप्रैल से दिसंबर के बीच पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को करीब 24 फीसदी अधिक राजस्व मिला है, अतएव आने वाले महीनों में सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल की महंगाई से बचाए रखें। जिस तरह पिछले वर्ष 2021 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक होने पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर सीमा व उत्पाद शुल्क में और कई राज्यों ने वैट में कमी की थी, वैसे ही कदम अब फिर जरूरी दिखाई दे रहे हैं। सरकार कच्चे तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सामरिक सुरक्षित भंडार से कच्चा तेल जारी करने पर भी विचार कर सकती है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा महंगाई से लड़ने हेतु वृद्धि दर को बढ़ावा देना जारी रखना होगा। विनिमय दर में स्थिरता लाने की दिशा में भी काम करना होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करनी होगी। देश के करोड़ों किसानों के द्वारा अच्छे कृषि उत्पादन और करोड़ों श्रमिकों के द्वारा अधिकतम औद्योगिक उत्पादन के लिए अधिक प्रयास करना होंगे। ऐसे विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से महंगाई को नियंत्रित रखा जा सकेगा।

क्या सिर्फ भारत की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है? दुनिया के अन्य देशों के हालात क्या हैं?

-नीरज कुमार दुबे

बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता भाजपा पर महंगाई रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मोदी सरकार वैश्विक हालात को महंगाई का कारण बता रही है तो विपक्ष का कहना है कि सरकार आम आदमी की जेब काटकर अपना खजाना भर रही है और चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। ऐसे में आम आदमी के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि सरकार सही बोल रही है या विपक्ष?

कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ऐसा कहर ढाया है कि अमीर देशों में गरीबी बढ़ गयी और गरीब देशों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। महामारी थमी और अर्थव्यवस्थाओं ने फिर से पटरी पर दौड़ना शुरू किया तो यूक्रेन पर रूस के युद्ध ने ऐसे हालात पैदा कर दिये कि कोई देश प्रभावित होने से नहीं बचा। ये जो महंगाई आपको भारत में देखने को मिल रही है वह सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि विश्व की इस समय की सबसे बड़ी समस्या हो गयी है। रूस-यूक्रेन युद्ध से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, तेल की कीमतों में इजाफे के चलते हर चीज की महंगाई बढ़ी है जिससे दुनिया के लगभग सभी देशों की सरकारों को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ रही है।

आइये आपको विश्व भर में महंगाई के हालात से रूबरू कराने के क्रम में सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं। वहां इमरान खान की सरकार पर संकट ही इसलिए आया है क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बेलगाम हो गयी है। पाकिस्तान में महंगाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं जिसके चलते इमरान खान की कुर्सी खतरे में पड़ गयी है। श्रीलंका के हालात सबके सामने ही हैं। अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका में महंगाई बेलगाम हो गयी है। श्रीलंका में हालात ये हैं कि चावल 500 और चीनी 300 रुपये किलो तक बिक रही है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, मालदीव में

बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई

खाद्य मुद्रास्फीति में एक प्रतिशत की वृद्धि एक करोड़ अतिरिक्त लोगों को गरीब बना देती है। दुनिया खाद्य मुद्रास्फीति नामक एक नई महामारी की जकड़ में है। पिछले दो वर्षों में कोविड-19 महामारी से उपजे हालात और अब रूस-यूक्रेन युद्ध ने खाद्य महंगाई को अभूतपूर्व गति से बढ़ा दिया है।

पिछले पखवाड़े कोविड-19 महामारी ने वैश्विक मीडिया में पहले पेज से अपनी जगह खो दी है। प्रमुख वैश्विक घटनाक्रम में खाद्य मुद्रास्फीति ने उसकी जगह ले ली।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के विश्लेषण के अनुसार, खाद्य महंगाई 2020 के मध्य के मुकाबले 75 फीसदी बढ़ गई है। राष्ट्रीय सांख्यकी कार्यालय द्वारा 12 अप्रैल 2022 को जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार, भारत में ग्रामीण उपभोक्ता खाद्य महंगाई में मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच 100 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। 2021-22 में भारत की वार्षिक थोक मुद्रास्फीति 13 प्रतिशत रही जो दशक में सर्वाधिक है। इसमें खाद्य एवं ईंधन के बढ़े मूल्य की बड़ी भूमिका रही।

इसका असर यह हुआ कि दुनिया में सबसे महंगा खाद्य राहत अभियान चलाने वाले वैश्विक खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) को अतिरिक्त फंडिंग के लिए मजबूरी भरी अपील करनी पड़ी। दरअसल खाद्य महंगाई के कारण डब्ल्यूएफपी का प्रतिदिन का खर्च बढ़ता जा रहा है। अब उसे राहत कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 71 मिलियन डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित हो गया है। दुनिया चर्चा कर रही है कि कैसे जीवाश्म ईंधनों में बाधा से वैश्विक तापमान के नियंत्रण हेतु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के वैश्विक प्रयास बेपटरी हो सकते हैं। ईंधन के भाव ने पहले से ही सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, चाहे वह खाद्य उत्पादन हो या परिवहन।

युद्ध ने अनाज की आपूर्ति श्रृंखला और वितरण को भी बाधित किया है, जिससे मांग व आपूर्ति का समीकरण बिगड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ चरम मौसम की घटनाएं खाद्य उत्पादन वाले क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं, जिससे कुल उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। संक्षेप में कहें तो भोजन यानी जीवन की मौलिक आधार खतरे में है।

इस संकट ने वैश्विक दुनिया की एक और कमी उजागर कर दी है। जब कोविड-19 महामारी ने दस्तक दी, तब आपस में जुड़ी वैश्विक दुनिया को अचानक होश आया और हालात बिगड़ने पर सभी देशों ने आत्मसुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लिया। खासकर अमीर देशों ने लालचवश महामारी से लड़ने के लिए जरूरी सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया और दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दिया।

खाद्य क्षेत्र भी आपस में जुड़ा है और एक-दूसरे पर खतरनाक ढंग से आश्रित है। डब्ल्यूएफपी ने इसके परिणाम को 'सीस्मिक हंगर क्राइसिस' कहा है जो दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अफ्रीका और मध्य पूर्व में भूख का संकट दिखने भी लगा है। विश्व बैंक ने चेताया है कि खाद्य मूल्य में एक प्रतिशत की वृद्धि, दुनियाभर में एक करोड़ अतिरिक्त लोगों को गरीबी की दलदल में पहुंचा देती है।

खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि दुनियाभर के गरीबों और विकासशील देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है क्योंकि इनमें से अधिकांश देश खाद्य आयातक भी हैं। उदाहरण के लिए करीब 50 देश (अधिकांश गरीब) गेहूं के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर हैं।

अतिरिक्त अनाज वाले अधिकांश देश निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न का भंडारण कर रहे हैं। इससे कम खाद्यान्न उत्पादन वाले क्षेत्रों में अनाज की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि अप्रत्याशित रूप से विश्व बैंक समूह के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डब्ल्यूएफपी और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को संयुक्त अपील करनी पड़ी, 'हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हैं कि वे कमजोर देशों को तत्काल मदद पहुंचाएं। यह मदद आपातकालीन खाद्य आपूर्ति, आर्थिक सहायता, कृषि उत्पादन बढ़ाकर और खुले व्यापार जैसे संयुक्त उपायों से पहुंचाई जाए।'

इसके अलावा तत्काल खाद्य निर्यात की भी अपील की गई। इसमें कहा गया, 'हम सभी देशों से अपील करते हैं कि व्यापार खुला रखें और खाद्य अथवा उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से बचें क्योंकि इससे सर्वाधिक संवेदनशील लोगों की तकलीफें और बढ़ जाएंगी।' यह अपील कोविड-19 की शुरुआत में वैश्विक एकजुटता दिखाने के लिए की गई अपील से मेल खाती है।

शायद यह पहली बार है जब खाद्य संकट पर वैश्विक आह्वान किया गया है। वैश्विक जगत की कथनी और करनी में फर्क रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस अपील का हश्र कोविड संकट में की गई अपील जैसा न हो।

- रिचर्ड महापात्रा

भी महंगाई चरम पर है।

थोड़ा दक्षिण एशिया से बाहर चलें और पश्चिमी देशों की ओर देखें तो अमेरिका में महंगाई ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखा जाये तो अमेरिकियों को 1982 के बाद से सबसे अधिक महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में मंदी का खतरा मंडरा रहा है जो वहां की सरकार की चिंता बढ़ा रहा है और हर चीज की बढ़ी कीमतों ने वहां आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ब्रिटेन की बात करें तो वहां भी बेतहाशा महंगाई देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनुमान जताया है कि सालाना महंगाई की दर इस साल 8.0 फीसदी को पार कर सकती है और अप्रैल में यह 7.25 फीसदी पर रह सकती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक बयान में माना है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने महंगाई के मोर्चे पर दिक्कत और बढ़ा दी है।

जर्मनी की बात कर लें तो वहां भी तीन दशक में महंगाई सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है जिससे खाने-पीने की वस्तुओं समेत बुनियादी चीजों और ईंधन के दामों में बड़ा उछाल आने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। जर्मनी में जमा पर बैंक ब्याज दरें घटने से बचत पर जोर देने वाले लोग भी निराश दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में महंगाई से इतना बुरा हाल है कि वहां की सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आस्ट्रेलिया में मई में होने वाले चुनावों को देखते हुए वहां की सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किये हैं जिसके तहत कुछ करों को कम किया गया है। तुर्की में मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 20 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तुर्की में ऊर्जा की कीमतें लागतार चढ़ रही हैं। तुर्की सांख्यिकी संस्थान के अनुसार,

उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें पिछले महीने 4.81 प्रतिशत बढ़ी हैं। महंगाई को काबू में करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने करों में कटौती का ऐलान किया है। स्पेन में महंगाई लगभग चार दशकों में सबसे तेज दर से बढ़ी है और उम्मीदों से आगे निकल गई है जिससे जनता बेहाल है। चीन में भी महंगाई बढ़ रही है और कोरोना के चलते कुछ शहरों में लगे लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

ग्लोबल महंगाई के जिम्मेदार देश रूस का खुद भी महंगाई से बुरा हाल हो गया है। रूस में वार्षिक मुद्रास्फीति 25 मार्च तक बढ़कर 15.66 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2015 के बाद से उच्चतम है। रूस में मुद्रास्फीति पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से बढ़ी है क्योंकि रूबल की गिरावट अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। रूस में खाद्य उत्पादों से लेकर कारों तक की मांग में तेज वृद्धि है क्योंकि लोगों को लगता है कि आने वाले समय में इनकी कीमत और बढ़ जायेगी। जापान की बात करें तो वहां महंगाई मार्च महीने में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यूक्रेन संकट के चलते जापान में ऊर्जा और खाद्य उत्पादों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। कनाडा में भी बढ़ती महंगाई के बीच माना जा रहा है कि 7 अप्रैल को आने वाले केंद्रीय बजट में सरकार शायद कुछ राहत उपायों की घोषणा कर सकती है। ईरान में महंगाई ने लगभग 60 सालों का, न्यूजीलैंड में 30 सालों और सिंगापुर में लगभग दस सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है तो इजराइल, इटली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, स्पेन, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेल्जियम, आस्ट्रिया आदि देशों की जनता भी महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। यही नहीं खाड़ी देशों में भी महंगाई का असर साफ देखने को मिल रहा है।

बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारों को गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाने के उपाय करने ही चाहिए। भारत की सरकार ने इस दिशा में क्या किया है यदि इस पर बात कर लें तो हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने के लिए विस्तार दे दिया गया है ताकि गरीबों को हर माह मुफ्त राशन मिलता रहे। यही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा संख्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की है और उन्हें भी राहत मिलनी ही चाहिए। अंत में एक सवाल विपक्ष से भी है जोकि इन दिनों महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिन राज्यों में वह सत्ता में है वहां महंगाई कम करने के लिए उसने क्या उपाय किये?

खुदरा मुद्रास्फीति की संभावित दर अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह 16 महीने में सर्वाधिक है। पढ़ें आरती राय की विशेष रिपोर्ट

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) की संभावित दर मार्च 2022 में 16 महीने के अपने उच्च स्तर 6.35 फीसदी तक पहुंच गई है। यह बात रॉयटर्स द्वारा जारी पोल रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के Upper Tolerance Band की यह सबसे उच्चतम लेयर है। यह तीन महीने से बढ़ती खाद्य कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण हो रही है। यह माना जा रहा है कि फरवरी के अंत में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद कच्चे तेल की कीमतों की भारी बढ़ोतरी की वजह से अप्रैल तक उपभोक्ता कीमतों गिरावट या राहत की उम्मीद नहीं है और आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है।

रॉयटर्स के सर्वे के अनुसार 48 अर्थशास्त्रियों ने पोल में मुद्रास्फीति को लेकर जो सुझाव दिया है उसके मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price index) के इंडेक्स के मुताबिक मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.07 फीसदी से बढ़कर 6.35 फीसदी हो गयी है। यह नवंबर 2020 के बाद अब तक की सबसे ज्यादा रीडिंग होगी। इस रिपोर्ट में यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि 12 अप्रैल को RBI जो डाटा जारी करेगा, वो 6.06 फीसदी और 6.50 फीसदी के बीच हो सकता है। यह महंगाई दर RBI के टॉलरेंस बैंड का शीर्ष होगा। एएनजेड के एक अर्थशास्त्री धीरज निम ने मासिक परिवर्तनों में मौसमी पैटर्न का जिक्र करते हुए कहा है कि 'हम उम्मीद करते हैं कि हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 6.30 फीसदी हो जाएगी क्योंकि खाद्य कीमतों में क्रमिक रूप से फरवरी तक तीन महीने की गिरावट के बाद सर्वाधिक वृद्धि हुई है।' रिपोर्ट के मुताबिक कई अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि मार्च में मुद्रास्फीति की दर और भी ज़्यादा हो सकती है। इस बारे में RBI डेटा 12 अप्रैल को जारी करेगा। एक्सपर्ट्स की मानें तो मुद्रास्फीति की दर 6.5 प्रतिशत तक अनुमान के मुताबिक बढ़ सकती है और यह लगातार तीसरा महीने बढ़त के साथ दर्ज होगी। अगर ऐसा रहा तो आरबीआई की महंगाई दर लिमिट की टॉलरेंस लेयर के 2-6 के ऊपर पहुंच सकती है और यह आने वाली समय के लिए एक चेतावनी है। लगातार बढ़ती जा रही खाद्य कीमतें जो किसी भी देश की मुद्रास्फीति की टोकरी का लगभग आधा हिस्सा है इस बार भी ऊपर रहने की उम्मीद है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध से संबंधित आपूर्ति की सीरीज में ग्लोबल अनाज सप्लाई, खाद्य तेलों की आपूर्ति और उर्वरक निर्यात पर भारी असर डाल रही है। रूस -यूक्रने के बीच युद्ध दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वनस्पति तेल, पाम तेल की कीमतों में इस साल लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लगातार रोजमर्रा की खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और आम जनता की थाली की बढ़ती कीमत तेजी से महसूस की जा रही है। जाहिर सी बात है कि कोरोना महामारी और उसके चलते लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी में बढ़ोतरी और लोगों की आमदनी पर नकारात्मक असर डाल चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत के एक और अर्थशास्त्री समीरन चक्रवर्ती ने इस बात का अनुमान लगाया है कि global commodity price में वृद्धि की वजह से मार्च मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ-साथ खाद्य तेलों में भी होगी। चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि 'हालांकि राज्यों में हुए चुनावों के बाद पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की शुरुआत में देरी हुई थी फिर भी खुदरा कीमतों में मार्च के आखिरी 10 दिनों में 6.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।'

अर्थ व्यवस्था

चीन भारत रूस ब्राजील साउथ अफ्रीका (BRICS) देश आपस में मिलकर एक नया पेमेंट गेटवे बनाने जा रहे हैं और मूडी फिंच

ईंधन और सिकुड़ता बाजार

देश के हर भाग में पेट्रोल डीजल की बढ़ी क़ीमत का प्रभाव समाज में दिखने लगा है ।पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी चिंताजनक संकेत है, यह बात याद रखने की है कि ऊर्जा स्रोत अर्थव्यवस्था के आधार होते हैं। विभिन्न कारणों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, ऐसे में घरेलू बाजार पर भी दबाव है। बीते 22 मार्च और छह अप्रैल के बीच पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में 10 रुपये की बढ़त हुई, जो कि दो दशकों में एक पखवाड़े में हुई सबसे बड़ी वृद्धि है।

इस वृद्धि का ही यही असर हुआ है कि मार्च के पहले 15 दिनों की तुलना में अप्रैल के पहले 15 दिनों में पेट्रोल की बिक्री लगभग 10 प्रतिशत और डीजल की बिक्री 16 प्रतिशत घट गयी। थोक और खुदरा मुद्रास्फीति की दर भी बहुत अधिक है। मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7 प्रतिशत तक पहुंच गया। पेट्रोल व डीजल की मांग घटने से वस्तुओं की ढुलाई में कमी आ सकती है। इससे भी महंगाई बढ़ेगी। बाजार पहले से ही आगाह कर रहा हैं कि महंगाई की दर सितंबर तक छह फीसदी से ऊपर रह सकती है।

इस मौसम में देश के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति बाधित होने के आसार हैं, क्योंकि कोयले की कमी हो रही है। गर्मी की वजह से बिजली की जरूरत बढ़ी हुई है। प्राकृतिक गैसों की कीमतों में भी बढ़त की गयी है। महामारी के इस काल में अभी तक रसोई गैस की मांग लगातार बढ़ती रही है, लेकिन अप्रैल के पहले पखवाड़े में इसमें 1.7 प्रतिशत की कमी आयी है। आपूर्ति श्रृंखला के अवरोधों तथा भू-राजनीतिक हलचलों के कारण औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं की लागत बढ़ रही है।

उसकी भरपाई भी मुद्रास्फीति की एक वजह है। यदि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारणों से पैदा हुई यह स्थिति अधिक समय तक बनी रही, तो बाजार में मांग में कमी का स्तर अधिक हो सकता है। इससे वर्तमान वित्त वर्ष में वृद्धि दर के अनुमानों को झटका लग सकता है। घटती मांग अर्थव्यवस्था में कुछ समय से हासिल उपलब्धियों पर पानी फेर सकती है। ध्यान रहे, मुद्रास्फीति की चुनौतियों के साथ-साथ अभी भी महामारी के नकारात्मक प्रभाव से हम उबर नहीं सके हैं।

वैसे या विश्व और भारत के संज्ञान में रहना चाहिए कि देश और दुनिया के हालात में बहुत जल्दी कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं होगा तथा आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर अस्थिरता बनी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि मुद्रास्फीति की बढ़ती दर पर उनकी निगाह है।

भारत सरकार ने भी रिजर्व बैंक से ठोस पहल करने को कहा है। जानकारों का मानना है कि रेपो रेट में बदलाव किया जा सकता है। सरकार भी पहले की तरह कीमतों में राहत देने के लिए कुछ कदम उठा सकती है, पर कब कहना मुश्किल है। कृषि उत्पादों के बाजार में आने भी लोगों की जेब को आराम मिल सकता है। यदि मांग नहीं बढ़ेगी, तो उत्पादन भी प्रभावित होगा और रोजगार में भी कमी आ सकती है। इसलिए सुधार के प्रयास जल्दी किये जाने चाहिए।

इत्यादि के जैसे रेटिंग एजेंसी।

पिछले दिनों आपने देखा की किस प्रकार भारतीय विदेश मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री की मेजबानी अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है इसके पीछे उपर की होने वाली घटना केंद्र बिंदु में है।

पहले समझिए की मूडी फिंच इत्यादि से पृथक स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी से क्या होगा। तो अमेरिका और पश्चिमी युरोप पोषित मूडी इत्यादि एजेंसिया कभी भारत जैसे देश को (और राष्ट्रवादी भारत को तो किसी भी स्थिति में नहीं) अच्छी रेटिंग नहीं देती और उससे क्या होता है? उससे होता है अधिक ब्याज दर पर अंतराष्ट्रीय धन का मिलना ।

मान लीजिए AAA plus मिला ब्रिटेन को और BBB minus मिला भारत को तो ब्रिटेन की तुलना में भारत 3-4 प्रतिशत (और अधिक भी) ब्याज देना पड़ता है और लोन के टर्म भी कठिन रखे जाते हैं यह सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग की विधि है ।

पेमेंट गेटवे भी अमेरिका केंद्रित होने से 110 करोड़ मनुष्य और तीस करोड़ परजीवियों का भारत हानि की स्थिति में रहता है ।

तो स्वतंत्र पेमेंटगेटवे और स्वतंत्र रेटिंग एंजेंसी के बाद ब्रिक्स देश बहुत कम ब्याज पर धन ले सकते हैं ।

ध्यान रहे, इसका पश्चिमी देश जबरदस्त विरोध करने जा रहे हैं क्योंकि यह उनकी संप्रभुता पर आक्रमण होगा पर इनको बुरा तो लगेगा पर दूसरी बात भी देखी जाए

यह पांच देश यदि नॉर्थ और साउथ पोल को हटा दिया जाए तो विश्व का 30 प्रतिशत भूभाग, तीन बिलियन से अधिक आबादी और 25 ट्रिलियन से अधिक की इकॉनमी और तीन देश परमाणु सक्षम है।

यह स्मरण रहे

समरथ के नहीं दोष गुसाई

ये बड़ी खबर है - केंद्र सरकार ने CBI को Amnesty International India और उसके Chief आकर अहमद पटेल के खिलाफ FCRA के उल्लंघन के मामले में कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दे दिया।

सीबीआई स्पेशल कोर्ट को 31 दिसंबर 2021 को ही इन लोगो के खिलाफ चार्जशीट दे दी गयी थी। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी खबर हुई।

बड़ी इसलिए है, कि अब भारत सरकार ने सीधा सीधा पश्चिमी Deep State and Ecosystem, जिसका नेतृत्व George Soros करता है, उसे बताया दिया है कि अब बहुत हुआ। अब उंगली टेढ़ी कर दी गयी है।

अब क्या होगा?

भारत पर 5th और 6th जनरेशन warfare का लंबा दौर आने वाला है। बड़े मीडिया ग्रुप्स, credit rating agencies, Human Rights ग्रुप्स, NGO और अन्य कई elements अब

भारत के खिलाफ एकजुट हो कर आक्रमण करेंगे। हर रोज नया प्रोपगंडा, हर रोज नया बवाल होगा।

आपको लगेगा कि George Soros क्या कोई तोप है, जो अकेला इतना भोकाल करेगा। ऐसा नही है, वो अकेला तो इतना कुछ नही कर सकता, लेकिन वो इस Deep State Ecosystem का Tool है, जिसका उपयोग कुछ बड़े देश करते हैं। सरकारें बनाने गिराने में, दुश्मन देशो में अस्थिरता फैलाने के लिए, अर्थव्यवस्था गिराने या अस्थिर करने के लिए।

क्या 2022 में घटेगी गरीबी और असमानता की खाई, या वर्षों की मेहनत हो जाएगी जाया

– ललित मौर्या

52 फीसदी आय पर काबिज है वैश्विक आबादी का 10 फीसदी सबसे अमीर वर्ग, वहीं 50 फीसदी सबसे कमजोर तबके की आबादी के पास वैश्विक आय का केवल 8 फीसदी हिस्सा है

पहले महामारी, बढ़ती कीमतें और फिर यूक्रेन-रूस के बीच चलता युद्ध इन सबने मिलकर यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या गरीबी के गहराते संकट में कुछ निजात मिलेगी या फिर 2020-21 में जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 2022 में भी जारी रहेगा। यदि दुनिया के मौजूद हालात को देखें तो इस बात की संभावना बहुत कम है।

आज संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट '2022 फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रिजिंग द फाइनेंस डिवाइड' के अनुसार महामारी के कारण उपजे वैश्विक संकट के चलते 2021 में करीब और 7.7 करोड़ लोग गरीबी के गंभीर स्तर पर पहुंच गए थे। इतना ही नहीं साल के अंत तक दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं दोबारा 2019 जितनी सबल नहीं हो पाएंगी।

रिपोर्ट का अनुमान है कि 2023 के अंत तक भी 5 में से एक विकासशील देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी वापस 2019 के स्तर पर नहीं पहुंच पाएगी।

रिपोर्ट के मुताबिक कई विकासशील देशों के लिए कर्ज के बढ़ते बोझ और उसके ब्याज ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। ऐसे में उन्हें न केवल इस महामारी से उबरने बल्कि साथ ही अपने विकास खर्च में भी जबरन कटौती करने के लिए मजबूर किया है। इतना है नहीं इस बढ़ती समस्या ने भविष्य में इस तरह की आफतों का सामना करने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित किया है।

कर्ज पर ब्याज की एवज में 14 फीसदी राजस्व खर्च कर रहे है कमजोर देश

जहां एक तरफ संपन्न देश बहुत ही कम ब्याज दरों पर उधार ली गई भारी धनराशि की मदद से महामारी का सामना करने और उससे उबरने में सक्षम थे वहीं दूसरी तरफ सबसे पिछड़े देशों ने अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए थे। जिसने उन्हें सतत विकास के मुद्दों पर निवेश करने से रोक दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार औसतन सबसे कमजोर विकासशील देश कर्ज पर लगने वाले ब्याज की एवज में अपना करीब 14 फीसदी राजस्व खर्च कर रहे हैं जोकि विकसित देशों की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। गौरतलब है कि विकसित देशों के लिए यह आंकड़ा साढ़े तीन फीसदी है।

देखा जाए तो महामारी के चलते कई विकासशील देशों को अपने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अन्य पूंजीगत व्यय के बजट में भारी कटौती करने को मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में यूक्रेन में चलते युद्ध इन चुनौतियों को बढ़ा देगा, साथ ही उनके लिए नई समस्याएं पैदा कर देगा।

ऊर्जा और वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला में पैदा होते व्यवधान, बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ विकास की गति में आती गिरावट और वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता जैसी समस्याएं और विकराल हो जाएंगी। देखा जाए तो इस महामारी के बीच वित्तीय साधनों की यह जो असमानता है वो सतत विकास के लिए बड़ा खतरा है।

कितनी गहरी है असमानता की यह खाई

अनुमान है कि महामारी ने न केवल देशों के भीतर बल्कि देशों के बीच भी असमानता को और बढ़ा दिया है। हालांकि महामारी से पहले भी देशों में असमानता की यह खाई काफी गहरी थी और लगातार बढ़ रही थी। देखा जाए तो दुनिया की 10 फीसदी सबसे अमीर आबादी, विश्व की करीब 52 फीसदी आय पर काबिज है। वहीं सबसे कमजोर तबके की 50 फीसदी आबादी के पास वैश्विक आय का केवल 8 फीसदी हिस्सा है।

रिपोर्ट का मानना है कि युद्ध के चलते कई विकासशील देशों में कर्ज और भुखमरी का संकट और बढ़ जाएगा। हालांकि इस युद्ध से पहले भी महामारी से उबरने का मार्ग और कठिन हो गया था। आंकड़ों के मुताबिक विकासशील देशों में हर 100 में से केवल 24 लोगों के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध हैं।

जबकि विकसित देशों में यह उपलब्धता

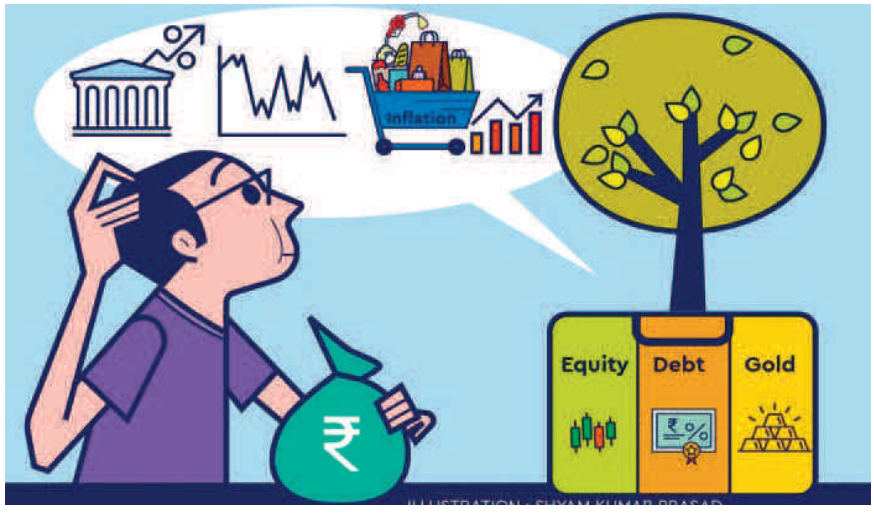

अन्नदाता और उसकी मुसीबतें

यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने दुनियाभर में खाद्य-प्रणाली पर किए जा रहे अनुसंधानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यही नहीं, विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि यूक्रेन पर लगातार रूसी आक्रमण का परिणाम है कि विश्व में खाद्य आपूर्ति की स्थिरता ही बुरी तरह से डगमगा गई है।

ध्यान रहे कि यूक्रेन गेहूं का एक प्रमुख निर्यातक देश के रूप में विश्व में जाना जाता है, लेकिन रूसी आक्रमण से इस साल की फसल को भारी खतरा पैदा हो गया है।

यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण उसके वित्तीय संकट के साथ ही सभी वैश्विक खाद्य प्रणालियों पर भी दबाव बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन और रूस दुनिया के कुल गेहूं का 14 प्रतिशत उत्पादन करते हैं और इनका दुनिया के गेहूं में निर्यात का हिस्सा 30 प्रतिशत है।

साथ ही साथ दुनिया के 60 प्रतिशत सूरजमुखी तेल का उत्पादन भी यही दो देश करते हैं। दोनों के देशों के बीच चल रहे युद्ध ने अब यह निर्यात को खतरे में डाल दिया है।

इस युद्ध के कारण अधिकांश यूक्रेनी किसान अत्यधिक तनाव में जीने पर मजबूर हैं। कारण कि एक तरफ वे वर्तमान में अपनी इस साल की फसल की देखभाल कर रहे हैं तो दूसरी ओर अपने देश के लिए भी एक सैनिक की भूमिका निभाते हुए रूसी सैनिकों से लड़ने पर मजबूर हैं यानी यूक्रेनी किसानों को दो-दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है।

वाशिंगटन डीसी स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रॉब वोस के अनुसार, 12 अप्रैल तक कुल 16 देशों ने खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण आपूर्ति में यह उल्लेखनीय कमी मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही है।

इसका प्रभाव दुनिया के कुछ सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। सोमालिया, सेनेगल और मिस्र सहित कम से कम 26 देश, रूस और यूक्रेन के गेहूं पर 50 से लेकर 100 प्रतिशत तक निर्भर हैं।

यदि यह युद्ध अनवरत रूप से और जारी रहता है तो पहले से ही कोविड-19 महामारी के कारण कर्ज से दबे इन गरीब देशों को दुनिया के अमीर देशों से अधिक उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़े बिना नहीं रहेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह अत्याधिक कर्ज इन गरीब देशों की स्थिति को श्रीलंका और अब धीरे-धीरे नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए कर्ज लेना किसी समस्या का दीर्घकालिक हल नहीं है।

विश्वस्तर पर जैव विविधता के नुकसान का प्रमुख कारण है कि सभी प्रकार की खेती ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन में 30 प्रतिशत का योगदान करती है। कम से कम इस प्रकार की

नीतियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे कम से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो। तभी खाद्य आपूर्ति की स्थिति को आसानी से बहाल किया जा सकता है।

वाशिंगटन डीसी स्थित एक पर्यावरण थिंक टैंक विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार लगभग एक तिहाई वैश्विक खेत पशुचारे का उत्पादन करते हैं। यदि वे कम पशु उत्पादों को खाते हैं तो मनुष्य बहुत कम भूमि का उपयोग करके अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

दूसरा, विश्व स्तर पर उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का एक तिहाई हिस्सा थाली तक कभी नहीं पहुंच पाता। वास्तव में यह उत्पादन श्रृंखला में ही कहीं खो जाता है या घरों में पहुंचने के बाद बर्बाद हो जाता है।

कटाई और भंडारण के तरीकों में सुधार संभावित रूप से नुकसान को कम कर सकता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को अधिक जिम्मेदार विकल्प का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा सकते हैं।

तीसरा, खेती के तहत अधिकांश भूमि पर गेहूं, चावल, मक्का, सोया और आलू जैसी खाद्य फसलों का कब्जा है। यह खेती जैव विविधता के नुकसान में योगदान देती है। यदि खेती में अधिकतर फलियां, नट और सब्जियों को शामिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में विविधता लाई जाए तो इससे पर्यावरण और आम लोगों को लाभ होगा, क्योंकि ये फसलें महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करती हैं।

जैव ईंधन उगाने के लिए वर्तमान में उपयोग की जा रही फसल भूमि को वापस खाद्य फसलों में परिवर्तित किया जा सकता है। अमेरिका में लगभग 40 प्रतिशत मक्का का उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि फसल भूमि पर उगाए जाने वाले जैव ईंधन जलवायु को स्वच्छ बनाने में उतने उपयोगी नहीं हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में खाद्यान्न संकट की आहट महसूस हो रही है, मगर कीर्तिमान अनाज उत्पादन ने भारतीय किसानों की पसीने की महक देश को नया आत्मविश्वास दिया है। निस्संदेह कोरोना दुष्काल के बाद लगे सख्त लॉकडाउन के दौरान केवल कृषि क्षेत्र ने देश की जीडीपी को संबल दिया। इस बार बैशाखी की बयार किसानों में नई उमंग भर गई है दूसरी ओर किसानों की अंतहीन समस्याएं खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं।

जैसे मौसम की मार के चलते अनाज की गुणवत्ता में गिरावट आई है, वहीं किसानों को मंडियों में अनाज ले जाने से लेकर बेचने तक की प्रक्रिया में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह देखने में आता है कि सत्ताधीश ग्रामीण विकास, सड़कों व मंडियों के रखरखाव तथा सुविधाओं के विस्तार के लिये आवंटित धन को अन्य मदों में खर्च कर देते हैं। इससे अन्नदाता की अंतहीन समस्याओं का समाधान संभव नहीं होता। सर्वाधिक अनाज उत्पादक प्रदेश पंजाब से उदाहरण सामने आया है, वहां जब ग्रामीण विकास फंड के दुरुपयोग के चलते केंद्र ग्रांट पर रोक लगाने की बात कर रहा था। उसके बाद वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने कानून में बदलाव लाकर समस्या का युक्तिसंगत समाधान निकाला। पंजाब सरकार ने केंद्र की शर्तों के अनुरूप पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश-2022 को मंजूरी दे दी। इसके बाद राज्य सरकार रूरल डेवेलपमेंट फंड

यानी आरडीएफ का पैसा केवल ग्रामीण विकास पर खर्च करेगी जिससे 1100 करोड़ रुपये की इस ग्रांट के पंजाब को मिलने का रास्ता साफ हुआ। दरअसल, इस ग्रांट को लेकर पंजाब का केंद्र से टकराव चल रहा था क्योंकि पूर्ववर्ती बादल व अमरेंद्र सरकार पर अनुदान का इस्तेमाल ग्रामीण विकास के बजाय अन्य कार्यों में खर्च करने के आरोप लगे। अब पंजाब सरकार कह रही है कि ग्रांट की धनराशि मंडियों व खरीद केंद्रों की सड़कों के निर्माण, मरम्मत, पेयजल व्यवस्था व भंडारण आदि पर खर्च की जायेगी। इस बात का पूरे देश में अनुसरण होना चाहिये

हरियाणा के किसान भी गर्मी की वजह से कम पैदावार के संकट से जूझ रहे हैं। उन्हें भरोसा दिया गया है कि गेहूं की पैदावार औसत से कम हुई तो बीमा कंपनियां नुकसान की भरपाई करेंगी। दरअसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि विशेषज्ञ प्रत्येक गांव में फसल की औसत पैदावार का निर्धारण करेंगे। जनवरी में बेमौसमी बारिश व मार्च माह के मध्य में अप्रत्याशित गर्मी से गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। आशंका है कि रबी की दूसरी फसलों का उत्पादन भी अन्य वर्षों के मुकाबले कम रह सकता है। राज्यों में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। दस से पंद्रह फीसदी कम उत्पादन की बात कही जा रही है। वहीं किसानों को अधिक तापमान के चलते कई तरह की अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में खड़ी फसलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। झुलसाती गर्मी व तेज हवा आग को फैलाने की वजह बनती हैं वहीं पंजाब की मंडियों में गेहूं की फसल एफसीआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं आने से खरीद एजेंसियां खरीद में संकोच कर रही हैं। इसके बाद राज्य एजेंसियों के इंस्पेक्टर्स हड़ताल पर चले गये। यदि गेहूं की कम मानकों पर खरीद होती है और एफसीआई द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती तो उसकी जवाबदेही इन इंस्पेक्टरों की होती है जिसके चलते वे कुछ समय के लिए खरीद प्रक्रिया से हट गये। ऐसा कमोबेश हर राज्य में होता है।

कई राज्यों ने खरीद सीजन में गेहूं के सिकुड़े दानों के नियमों पर पुनः विचार करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया था जिसे बाद में केंद्र ने मान भी लिया। गर्मी के कारण गेहूं की फसल पर पड़े प्रभाव के आकलन का दायित्व इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा गया है।इस संस्थान की चार टीमें देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रही हैं। विशेषज्ञों की टीमों ने विभिन्न जनपदों की मंडियों में पहुंचकर नमूने ले रहे हैं। निस्संदेह, खून-पसीने से फसल उगाने वाले किसानों की समस्याओं के प्रति सत्ताधीशों को संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए ताकि किसान खुशी-खुशी मंडी पहुंचे और प्रसन्न मन से अनाज का दाम लेकर घर जायें।

प्रति 100 लोगों के लिए 150 टीकों की है। ऐसे में महामारी का सामने करने में यह कमजोर देश कितने सक्षम है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं।

चौंकाने वाली बात है कि 2021 में विकासशील देशों 10 वर्ष के करीब 70 फीसदी बच्चे बुनियादी पाठ को भी पढ़ने में असमर्थ थे। 2019 की तुलना में देखें तो इस आंकड़े में करीब 17 फीसदी की वृद्धि आई है। 2021 में खाद्य कीमतें पहले ही दशक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं।

ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को डर है कि यूक्रेन में जारी संकट के चलते कई देशों में आर्थिक सुधार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हालांकि विकसित देशों में महामारी के बाद बढ़ते निवेश के चलते आर्थिक विकास की दर दोबारा पटरी पर लौटने लगी है।

रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 के दौरान दुनिया में गरीबी, सामाजिक सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में निवेश पर जो कुछ प्रगति हुई है। वो विकसित और कुछ गिने चुने बड़े विकासशील देशों में हुई कार्रवाई से प्रेरित है। इसमें कोविड-19 पर खर्च किए 1,293.6 लाख करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2020 में आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है जो बढ़कर अपने उच्चतम स्तर तक 12.3 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। 13 देशों ने इस दौरान ओडीए में कटौती की है। हालांकि देखा जाए तो इसके बावजूद विकासशील देशों की विशाल जरूरतों के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है।

इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव लियू जेनमिन का कहना है कि विकसित देशों ने पिछले दो वर्षों में यह साबित कर दिया है कि कैसे सही निवेश की मदद से लाखों लोगों को गरीबी के भंवर से बाहर निकाला जा सकता है। उनके अनुसार सशक्त और स्वच्छ इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा या सार्वजनिक सेवाओं की मदद से ऐसा कर पाना संभव है।

अंतराष्ट्रीय समुदाय के विकास की आधारशिला इसी प्रगति पर निर्मित की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकासशील देश भी इसी स्तर पर निवेश कर सकें। साथ ही असमानता को कम किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की वो शाश्वत ऊर्जा बदलावों को अपना सकें।

गौरतलब है कि इससे पहले ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट 'फर्स्ट क्राइसिस, देन कैटास्ट्रोफे' में भी दुनिया में बढ़ती गरीबी को लेकर कुछ ऐसे ही खुलासे किए थे। इसके अनुसार साल के अंत तक दुनिया भर में करीब 86 करोड़ लोग 145 रुपए (1.9 डॉलर) प्रति दिन से कम में गुजारा करने को मजबूर होंगें। वहीं यदि उनकी आय का हिसाब 420 रुपए (5.5 डॉलर) प्रतिदिन के आधार पर लगाएं तो 2022 के अंत तक दुनिया के करीब 330 करोड़ लोग गरीबी की मार झेल रहे होंगें।

विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट 'इंटरनेशनल डेब्ट स्टेटिस्टिक्स 2022' से पता चला है कि 2020 में पहले ही गरीबी की मार झेल रहे देशों पर 12 फीसदी की वृद्धि के साथ कर्ज का बोझ बढ़कर रिकॉर्ड 65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। वहीं यदि निम्न और मध्यम आय वाले देशों की बात करने तो उनपर कुल विदेशी कर्ज इस दौरान 5.3 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 654.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ■

मुफ्तखोरी की राजनीति गंभीर आर्थिक संकट को न्यौता

● ललित गर्ग

भारत की राजनीति में खैरात बांटने एवं मुफ्त की सुविधाओं की घोषणाएं करके मतदाताओं को ठगने एवं लुभाने की कुचेष्टाओं में सभी राजनीतिक दल लगे हैं। महज राजनीतिक लाभ एवं वोट बैंक को प्रभावित करने के उद्देश्य से मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना सरकारों के आर्थिक असंतुलन के साथ ही आत्मघाती उपक्रम है। केंद्र सरकार को उन राज्यों को चेताना चाहिए जो कर्ज चुकाने की क्षमता खोते चले जाने के बाद भी मुफ्त की योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे उत्पन्न गंभीर आर्थिक संकट को नजरअंदाज करना राजनीतिक अपरिवक्वता का द्योतक है, वही अवसरवादी एवं स्वार्थ की राजनीति को पनपाने का जरिया है। इस तरह की मुफ्त की संस्कृति एवं जनधन को खैरात में बांटने से किस तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून एवं व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है, इसका ताजा उदाहरण है श्रीलंका। वहां की स्थितियां जिस तेजी से बिगड़ रही हैं, वे भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई हैं।

भारत में यह कैसा लोकतांत्रिक ढ़ांचा बन रहा है जिसमें पार्टियां अपनी सीमा से कहीं आगे बढ़कर लोक-लुभावन वादे करने लगी हैं, उसे किसी भी तरह से जनहित में नहीं कहा जा सकता। बेहिसाब लोक-लुभावन घोषणाएं, अपने आर्थिक संसाधनों से परे जाकर और पूरे न हो सकने वाले आश्वासन पार्टियों को तात्कालिक लाभ तो जरूर पहुंचा सकते हैं, पर इससे देश के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक हालात पर प्रतिकूल असर पड़ने की भी आशंका है। प्रश्न है कि राजनीतिक पार्टियां एवं राजनेता सत्ता के नशे में डूबकर इतने आक्रामक कैसे हो सकते है? यह स्थिति चिन्ताजनक है। इसी तरह की स्थितियों से श्रीलंका में आर्थिक हालात बिगडने और महंगाई के बेलगाम हो जाने के कारण एक ओर जहां जनता का अंसतोष बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता भी गहराती जा रही है। करीब-करीब

हर जरूरी वस्तु के आसमान छूते दामों से नाराज श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर रही है और वहां के राष्ट्रपति को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें?

श्रीलंका के बेकाबू होते हालात भारत के लिये एक सबक है, क्योंकि पिछले कुछ दौर से भारत में हर दल में मुफ्त बांटने की संस्कृति का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की बेतूकी एवं अतिश्योक्तिपूर्ण घोषणाएं एवं आश्वासन राजनीति को दूषित करते हैं, जो न केवल घातक है बल्कि एक बड़ी विसंगति का द्योतक हैं। किसी भी सत्तारूढ पार्टी को जनता की मेहनत की कमाई को लुटाने के लिये नहीं, बल्कि उसका जनहित में उपयोग करने के लिये जिम्मेदारी दी जाती है। इस जिम्मेदारी का सम्यक् निर्वहन करके ही कोई भी सत्तारूढ पार्टी या उसके नेता सत्ता के काबिल बने रह सकते हैं।

श्रीलंका की आर्थिक स्थिति जिन कारणों से बिगड़ी, उनमें चीन से कठोर शर्तों पर लिया गया कर्ज तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा वे लोकलुभावन नीतियां भी उत्तरदायी हैं, जो आर्थिक नियमों को धता बताती थीं। कर्ज के बढने और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते जाने के बाद भी इन नीतियों को आगे बढ़ाकर श्रीलंका ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया। यह ठीक है कि भारत श्रीलंका के हालात पर नजर रखे हुए है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। इसी के साथ ही उन कारणों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके चलते श्रीलंका गहरे संकट में धंस गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल में

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की तो कई अफसरों ने यह कहा कि कुछ राज्यों की ओर से मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने का जो काम किया जा रहा है, वह उन्हें श्रीलंका जैसी स्थिति में ले जा सकता है। इन अफसरों की मानें तो कर्ज में डूबे राज्य मुफ्तखोरी वाली योजनाएं चलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।

प्रश्न है कि क्या सार्वजनिक संसाधन किसी को बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने चाहिए? क्या जनधन को चाहे जैसे खर्च करने का सरकारों को अधिकार है? तब, जब सरकारें आर्थिक रूप से आरामदेह स्थिति में न हों। यह प्रवृत्ति राजनीतिक लाभ से प्रेरित तो है ही, सांस्थानिक विफलता को भी ढकती है, और इसे किसी एक पार्टी या सरकार तक सीमित नहीं रखा जा सकता। केजरीवाल सरकार कैंपेन चलाकर आम आदमी की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये सरकार की तथाकथित योजनाओं को बताने में खर्च कर दिये हैं कि किस तरह उन्होंने दिल्ली को चमका दिया है। किस तरह मुक्त पानी-बिजली देने के नाम पर सरकारी खजाना खाली कर रहे हैं। जबकि दिल्ली के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। इस तरह का बड़बोलेपन एवं मुफ्त की संस्कृति को पढ़े-लिखे बेरोजगारों ने अपना अपमान समझा। कई बार सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वे अपने लोगों के अभाव, भूख, बेरोजगारी जैसी विपदाओं से बचा सकें। लेकिन जब उनके पास इन मूलभूत जनसमस्याओं के निदान के लिये धन नहीं होता है तो वे मुफ्त में सुविधाएं कैसे बांटते है? क्यों करोड़ो-अरबो रूपये अपने प्रचार-प्रसार में खर्च करते हैं?

अर्थव्यवस्था और राज्य की माली हालत को ताक पर रखकर लगभग सभी पार्टियों व सरकारों ने गहने, लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन से लेकर चावल, दूध, घी तक बांटा है या बांटने का वादा किया है। यह मुफ्तखोरी की पराकाष्ठा है। मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, लगभग मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त विवाह, मुफ्त जमीन के पट्टे, मुफ्त मकान बनाने के पैसे, बच्चा पैदा करने पर पैसे, बच्चा पैदा नहीं (नसबंदी) करने पर पैसे, स्कूल में खाना मुफ्त, मुफ्त जैसी बिजली 200 रुपए महीना, मुफ्त तीर्थ यात्रा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब मुफ्त। मुफ्त बांटने की होड़ मची है, फिर कोई काम क्यों करेगा? मुफ्त बांटने की संस्कृति से देश का विकास कैसे होगा? कैसे सरकारों का आर्थिक संतुलन बनेगा? पिछले दस सालों से लेकर आगे बीस सालों में एक ऐसी पूरी पीढ़ी तैयार हो रही है या हमारे नेता बना रहे हैं, जो पूर्णतया मुफ्त खोर होगी। अगर आप उनको काम करने को कहेंगे तो वे गाली देकर कहेंगे, कि सरकार क्या कर रही है?

विडम्बना एवं विसंगति की हदें पार हो रही है। ये मुफ्त एवं खैरात कोई भी पार्टी अपने फंड से नहीं देती। टैक्स दाताओं का पैसा इस्तेमाल करती है। हम 'नागरिक नहीं परजीवी' तैयार कर रहे हैं। देश का टैक्स दाता अल्पसंख्यक वर्ग मुफ्त खोर बहुसंख्यक समाज को कब तक पालेगा? जब ये आर्थिक समीकरण फैल होगा तब ये मुफ्त खोर पीढ़ी बीस तीस साल की हो चुकी होगी। जिसने जीवन में कभी मेहनत की रोटी नहीं खाई होगी, वह हमेशा मुफ्त की खायेगा। नहीं मिलने पर, ये पीढ़ी नक्सली बन जाएगी, उग्रवादी बन जाएगी, पर काम नहीं कर पाएगी। यह कैसा समाज निर्मित कर रहे हैं? यह कैसी विसंगतिपूर्ण राजनीति है? राजनीति छोड़कर, गम्भीरता से चिंतन करने की जरूरत है।

वर्तमान दौर की सत्ता लालसा की चिंगारी इतनी प्रस्फुटित हो चुकी है, सत्ता के रसोस्वादन के लिए जनता और व्यवस्था को पंगु बनाने की राजनीति चल रही है। राजनीतिक दलों की बही-खाते से सामाजिक सुधार, रोजगार, नये उद्यमों का सृजन, खेती को प्रोत्साहन, ग्रामीण जीवन के पुनरुत्थान की प्राथमिक जिम्मेवारियां नदारद हो चुकी है, बिना मेहंदी लगे ही हाथ पीले करने की फिराक में सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। जनता को मुफ्तखोरी की लत से बचाने की जगह उसकी गिरफ्त में कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे हैं। लोकतंत्र में लोगों को नकारा, आलसी, लोभी, अकर्मण्य, लुंज बनाना ही क्या राजनीतिक कर्तृता-धर्तृताओं की मिसाल है? अपना हित एवं स्वार्थ-साधना ही सर्वव्यापी हो चला है?इन स्थितियों के कारण श्रीलंका जैसे हालात विभिन्न राज्यों में बनने की आहट सुनाई देने लगी है।

बेरोजगारी, व्यापार-व्यवसाय की टूटती सांसें एवं किसानों की समस्याओं को भी हल करने में ईमानदारी बरतने की बजाय सरकारें इसी तरह के लोक-लुभावन कदमों के जरिए उन्हें बहलाती रही हैं। ऐसी नीतियों पर अब गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। अपने राज्य की स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हरेक सरकार का अहम दायित्व है, लेकिन उनकी मुकम्मल सुरक्षा मेट्रो या बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा में नहीं, बल्कि अन्य सुरक्षा उपायों के साथ टिकट खरीदकर उसमें सफर करने की आर्थिक हैसियत हासिल कराने में है। हकीकत में मुफ्त तरीकों से हम एक ऐसे समाज को जन्म देंगे जो उत्पादक नहीं बनकर आश्रित और अकर्मण्य होगा और इसका सीधा असर देश की पारिस्थितिकी और प्रगति, दोनों पर पड़ेगा। सवाल यह खड़ा होता है कि इस अनैतिक राजनीति का हम कब तक साथ देते रहेंगे? इस पर अंकुश लगाने का पहला दायित्व तो हम जनता पर ही है। ■

तो हिन्दी से दूर जाती कांग्रेस

● आर.के. सिन्हा

देश के आठ पूर्वोतर राज्यों के सभी स्कूलों के दसवीं कक्षा तक में पढ़ने वाले बच्चों को हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाने पर वहां के सभी राज्य सरकारें राजी हो गईं हैं ङ्क 22 हजार हिन्दी के अध्यापकों की भर्ती की जा रही है तथा नौ आदिवासी जातियों ने अपनी बोलियों की लिपि देवनागरी को स्वीकार कर लिया है। क्या इन जानकारियों में आपको कहीं हिन्दी को थोपने के संकेत मिलते हैं? लेकिन, कांग्रेस तो कम से कम यही मानती है। कांग्रेस के नेता यह कहते हैं कि सरकार महंगाई तथा बेरोजगारी जैसे गंभीर मसलों पर बात करने की बजाय हिन्दी को गैर-हिन्दी भाषियों पर थोपने की चेष्टा कर रही है।

दरअसल विगत दिनों केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपर्युक्त जानकारियां देश के साथ सांझा की थीं। उसके बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में उतर आए। जयराम रमेश ने ज्ञान दिया कि 'हिन्दी राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा।' एक तरह से वे और उनके मित्र अभिषेक मनु सिंघवी हिन्दी के खिलाफ वक्तव्य देते हुए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने लगे। देश की ये सभी महान शख्सियतें गैर हिन्दी भाषी होने पर भी हिन्दी के प्रसार-प्रचार के लिए सक्रिय रहीं। ये सभी हिन्दी की ताकत को जानते थे। क्या कांग्रेस के इन नेताओं को इतना भी नहीं पता कि भगत सिंह तो हिन्दी के ही पत्रकार थे? पंजाब से संबंध रखने वाले भगत सिंह की मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। इसके बावजूद वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से छपने वाले अखबार 'प्रताप' में पत्रकार के रूप में काम करते रहे थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचींद्रनाथ सान्याल की सलाह पर भगत सिंह विद्यार्थी जी से मिले। वे 'प्रताप' में बलवंत सिंह के नाम से लिखते थे, जो खासतौर पर नौजवानों के बीच खासे लोकप्रिय थे। भगत सिंह पंजाबी पत्रिका किरती के लिए भी रिपोर्टिंग और लेखन कर रहे थे।

देखिए संविधान में बहुत सोच ङ्क विचार कर हिन्दी की स्वीकृति दी गई क्योंकि इसकी सर्वत्र राष्ट्र भाषा के रूप में मान्यता आज के 75 वर्ष पूर्व भी थी। जब अनुच्छेद 343 में देवनागरी में लिखी हिन्दी को सर्वसम्मति से मान्यता मिली तो वह 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' ही मानी गई। बाद में चलकर 'कोई राजभाषा' 'कोई सरकारी भाषा' और 'कोई आधिकारिक भाषा' कहने लगा। सरदार पटेल ने दिनांक 13.10.1949 को अपने एक महत्वपूर्ण संदेश हिन्दी के लिए 'राष्ट्र भाषा' का प्रयोग ही किया है। जयराम रमेश यह याद रखें कि हिन्दी भारत के करोड़ों लोगों की प्राण और आत्मा है। हिन्दी प्रेम और सौहार्द की भाषा है। ये सबको जोड़ती है। इसका बार-बार अनादर करना बंद करें। वे जब हिन्दी को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो वे हिन्दी भाषियों को निराश करते हैं।

उम्मीद के मुताबिक, अमित शाह की जानकारी के बाद तमिलनाडू में भी हिन्दी का राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है। पर यह विरोध जमीन पर नहीं है। दक्षिणी राज्यों में अब हिन्दी का विरोध रत्तीभर भी नहीं रहा। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन आज जो कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार हिन्दी को गैर-हिन्दी भाषी राज्यों पर थोपने की कोशिश कर रही है, वे तब कुछ तो नहीं बोले थे जब तमिलभाषी एचसीएल टेक्नोलोजीस के खरबपति फाउंडर चेयरमेन शिव नाडार ने कुछ समय पहले एक स्कूल के कार्यक्रम में कहा था- 'हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों को अपने करियर को चमकाने में लाभ ही मिलेगा।' वे भारत के सबसे सफल कारोबारी माने जाते हैं और पूरे देश में लाखों पेशेवर उनकी कंपनी में काम करते हैं। हिन्दी का विरोध करने वालों को शिव नाडार जैसे सफल उद्यमी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने 1960 के दशक में तमिलनाडू में हुए हिन्दी विरोधी आंदोलन को स्वयं देखा था।

बहरहाल, तमिलनाडू को लेकर यह कहना होगा कि वहां पर हिन्दी फिल्मों को देखने के लिए जनता जिस तरह से सिनेमा घरों में उमड़ती है, वहां के सियासी नेता पर हिन्दी विरोध की बातें करना नासमझी ही माना जाएगा। जिस

अंग्रेजी नहीं, हिन्दी हो सम्पर्क भाषा

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सशक्त भारत-निर्माण के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रासंगिकता व्यक्त करते हुए कहा कि जब अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले राज्यों के लोग आपस में बातचीत करें तो उन्हें अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को या देश की ही किसी अन्य भाषा को इसका माध्यम बनाना चाहिए।' निश्चित ही बातचीत एवं व्यवहार की भाषा के रूप में हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने से राष्ट्रीय विकास के नए क्षितिज खुलेंगे, नवाचार के नए-नए आयाम उभरेंगे। भारतीय भाषाओं में बातचीत, व्यवहार, चिंतन एवं शिक्षण से सृजनात्मक एवं स्व-पहचान की दिशाएं उद्घाटित होगी। वास्तव में स्व-भाषाएं विचारों, विचारधाराओं, कल्पनाओं और अपने व्यापक सामाजिक-राष्ट्रीय दर्शन की स्पष्टता का माध्यम बनती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करते हुए मातृभाषा एवं क्षेत्रिय भाषाओं को प्रतिष्ठापित करने का अनूठा उपक्रम किया जा रहा है। इसको लेकर देश में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने एवं इन्हीं भाषाओं में उच्च शिक्षा दिये जाने एवं राजकाज में उनका उपयोग किये जाने की स्थितियां निर्मित होने लगी है, जो एक शुभ-संकेत है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए स्वभाषा का सम्मान का अनूठा उपक्रम है। अब हिन्दी को राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किये जाने की अपेक्षा है।

हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। अत: वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है 'राजभाषा' कहलाती है। राजभाषा किसी देश या राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा होती है जो समस्त राजकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। राजाओं और नवाबों के जमाने में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। हिंदी के विकास के लिए राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो, लेकिन विडम्बना है कि आज भी अधिकांश सरकारी कार्य अंग्रेजी में ही होते हैं एवं न्यायालयों में तो अंग्रेजी का ही वर्चस्व कायम है।

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवत: तीसरी सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली सबसे सशक्त वैज्ञानिक भाषा है। जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी को बहुत से लोग राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं। राष्ट्रभाषा से अभिप्राय है किसी राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? यद्यपि हिंदी का व्यवहार संपूर्ण भारतवर्ष में होता है, लेकिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। चूंकि भारतवर्ष सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से विविधताओं का देश है। इस राष्ट्र में किसी एक भाषा का बहुमत से सर्वमान्य होना निश्चित नहीं है इसलिए भारतीय संविधान में देश की चुनिंदा भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा है। शुरू में इनकी संख्या 16 थी, जो आज बढ़ कर 22 हो गई हैं। ये सब भाषाएं भारत की अधिकृत भाषाएं हैं, जिनमें भारत देश की सरकारों का काम होता है। भारतीय मुद्रा नोट पर 16 भाषाओं में नोट का मूल्य अंकित रहता है और भारत सरकार इन सभी भाषाओं के विकास के लिए संविधान अनुसार प्रतिबद्ध है।

वर्तमान समय में हिन्दी एवं मातृभाषाओं का महत्व एवं उपयोग अधिक प्रासंगिक हुआ है। क्योंकि सर्वतोमुखी योग्यता की अभिवृद्धि एवं स्व-पहचान के बिना युग के साथ चलना और अपने आपको टिकाए रखना अत्यंत कठिन होता है। नई शिक्षा नीति ने इस बात को गंभीरता से स्वीकारा है, निश्चित ही यह भारत को एक ज्ञानमय समाज में रूपांतरित करने वाली सफल योजना साबित होगी। हमारे पास आज दुनिया तक पहुंचने का शानदार सु-अवसर है जो अब से पहले शायद कभी नहीं था। हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है, जो इन तमाम बदलावों को साकार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हमें सिर्फ सकारात्मक प्रयासों के साथ सही दिशा में बढ़ने एवं मातृभाषा एवं स्वभाषा में शिक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। अपनी इस युवा जनशक्ति का सदुपयोग कर हम महाशक्ति बनने की दिशा में सार्थक हस्तक्षेप कर सकते हैं। अपने युवाओं को नये कौशलों और नये ज्ञान से लैस कर दुनिया में परचम लहरा सकते हैं। जिसमें स्वभाषा, स्व-संस्कृति एवं स्व-पहचान की सार्थक भूमिका है।

भारत सुपर पावर बनने के अपने सपने को साकार कर सकता है। इस महान उद्देश्य को पाने की दिशा में विज्ञान, तकनीक और अकादमिक क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान करने के अभियान को तीव्रता प्रदान करने के साथ मातृभाषाओं एवं हिन्दी में शिक्षण एवं राजकाज में उपयोग को प्राथमिकता देना होगा। हिन्दी एवं मातृभाषाओं के प्रति प्रतिबद्धता के साथ नए भारत के निर्माण का आधार प्रस्तुत करना होगा, इससे नव-सृजन और नवाचारों के जरिए समाज एवं राष्ट्र में नए प्रतिमान उभरेंगें।

हिन्दी एवं मातृभाषाएं सम्पूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। भारत का परिपक्व लोकतंत्र,

प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्व भर में एक उच्च स्थान रखता है, उसी तरह भारत की गरिमा एवं गौरव की प्रतीक हिन्दी एवं मातृभाषाओं को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में हिन्दी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी कामकाज, स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी शिक्षा में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, इस दिशा में वर्तमान सरकार के प्रयास उल्लेखनीय एवं सराहनीय है, लेकिन उनमें तीव्र गति दिये जाने की अपेक्षा है। क्योंकि इस दृष्टि से महात्मा गांधी की अन्तर्वेदना को समझना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाषा संबंधी आवश्यक परिवर्तन अर्थात हिन्दी को लागू करने में एक दिन का विलम्ब भी सांस्कृतिक हानि है। मेरा तर्क है कि जिस प्रकार हमने अंग्रेज लुटेरों के राजनैतिक शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, उसी प्रकार सांस्कृतिक लुटेरे रूपी अंग्रेजी को भी तत्काल निर्वासित करें।' लगभग पचहत्तर वर्षों के आजाद भारत में भी पूर्व सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं को उनका गरिमापूर्ण स्थान न दिला सके, यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी राष्ट्रीयता पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह है।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।

प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां निश्चित रूप से यह बोध कराने के लिए पर्याप्त हैं कि अपनी भाषा के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। निज भाषा देश की उन्नति का मूल होता है। निज भाषा को नकारना अपनी संस्कृति को विस्मरण करना है। जिसे अपनी भाषा पर गौरव का बोध नहीं होता, वह निश्चित ही अपनी जड़ों से कट जाता है और जो जड़ों से कट गया उसका अंत हो जाता है।

शिक्षा एवं सरकारी कामकाज में हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की घोर उपेक्षा होती रही है, इन त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थिति को नरेन्द्र मोदी सरकार कुछ ठोस संकल्पों एवं अनूठे प्रयोगों से दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है, उनको मूल्यवान अधिमान दिया जा रहा है। ऐसा होना हमारी सांस्कृतिक परतंत्रता से मुक्ति का एक नया इतिहास होगा। अमित शाह के आह्वान पर हम हिन्दी को राजकाज, व्यवहार एवं प्रयोग की भाषा बनाये, तभी दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही हिन्दी अपने देश में भी गौरवान्वित हो पायेगी।

- ललित गर्ग

तमिलनाडु के नेता हिन्दी का विरोध करते हैं, वहां पर आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, आमिर खान और अक्षय कुमार की फिल्में खूब देखी जाती हैं।

महात्मा गांधी से ज्यादा इस देश को कोई नहीं जान-समझ सकता। गांधीजी का विचार था कि दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार-प्रसार जरूरी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वे पेशावर और उसके आसपास जाकर जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं तो वे अपनी हिन्दी में उर्दू तथा अरबी के कुछ शब्दों को जोड़ लेते हैं। जब वे दक्षिण भारतीय राज्यों में जाते हैं तो वे संस्कृत के शब्दों को शामिल कर लेते हैं। इससे वे अपने श्रोताओं को अपनी बात बेहतर तरीके से समझाने में सफल हो जाते हैं।

अभिषेक मनु सिंघवी का हिन्दी की बात करने पर भड़कना इसलिए और भी कष्टप्रद है, क्योंकि; उनके पूज्य स्वर्गीय पिता और चोटी के विधिवेत्ता डॉ. लक्ष्मी मल सिंघवी जीवनपर्यंत हिन्दी के पक्ष में बोलते-लिखते रहे। जानेमाने कवि, लेखक, भाषाविद एवं संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद लक्ष्मी मल सिंघवी ने हिन्दी के वैश्वीकरण और हिन्दी के उन्नयन की दिशा में सजग, सक्रिय और ईमानदार प्रयास किए थे। वे भारतीय संस्कृति के राजदूत, ब्रिटेन में हिन्दी के प्रणेता और हिन्दी-भाषियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। जैन धर्म के इतिहास और संस्कृति के जानकार के रूप में मशहूर लक्ष्मी मल सिंघवी ने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें से अनेकों हिन्दी में हैं। अफसोस कि उनके पुत्र अभिषेक मनु सिंघवी अब हिंदी का जिक्र आते ही भड़कने लगे हैं।

अगर बात हिन्दी को लेकर चल रही राजनीति से हटकर करें तो पूर्वोत्तर राज्यों की जनता लगातार हिन्दी से जुड़ रही है। वह हिन्दी पढ़-सीख रही है। अब आप पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर लीजिए। आपको वहां पर हिन्दी जानने-समझने वाले सब जगह मिल जाएंगे। देखिए हिन्दी तो अब सारे देश के आम-खास की भाषा बन ही चुकी है। कोई चाहे या न चाहे इस पर किसी को संदेह नहीं होगा। जो कांग्रेस महंगाई तथा बेरोजगारी पर सरकार को घर रही है, वह इन बिन्दुओं पर कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करती। बेशक, महंगाई और बेरोजगारी गंभीर मसले हैं। इनका देश को हल करना होगा। कांग्रेस को यह भी तो बताना होगा कि उसने अपने शासन काल में क्या किया? पर इसका यह मतलब तो नहीं होता कि अन्य विषयों पर काम ही न हो।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

भारत में आईएएस अधिकारियों की कमी, संघवाद की पवित्रता पर सवाल

● सत्यवान 'सौरभ'

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (कैडर) नियम 1954 आईएएस अधिकारियों की विभिन्न राज्य सेवाओं से संबंधित है। ये अधिकारी राज्य और केंद्र दोनों की सेवा करते हैं। आईएएस (कैडर) नियम के तहत कुछ राज्य संवर्ग के अधिकारी कुछ वर्षों की सेवाओं को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए प्रतिनियुक्त होते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में राज्य संकट पैदा करने वाली मौजूदा रिक्तियों के अनुसार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक अधिकारियों की संख्या प्रदान करने में विफल रहे हैं।

1991 के उदारीकरण के बाद आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती में भारी कमी के चलते 1991 से पहले के स्तर पर बहाल करने में केंद्र को लगभग 20 साल लग गए। 1 जनवरी, 2021 तक, अखिल भारतीय स्तर पर आईएएस अधिकारियों की कमी 23 प्रतिशत थी। राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का केंद्र द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है जिन्हें राज्य सिविल सेवाओं से पदोन्नति या चयन द्वारा आईएएस के लिए नियुक्त किया जाता है। लगभग 2,250 अधिकारियों का यह बड़ा कैडर, जिनके पास अपार क्षेत्र अनुभव है, राज्य-बांधे रखते है।

अत्यधिक प्रतिबंधात्मक शर्तें, विकास प्रोत्साहन नीति, प्रस्ताव सूचियों की वार्षिक सूची का खात्मा, लंबे समय की स्थगन अवधि, अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि, आदि के रूप में केंद्र में संयुक्त सचिवों के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए वर्षों की सेवा नासमझी है क्योंकि यह ठीक वही चरण है जब वे अच्छी नौकरी सामग्री, शक्ति, प्रतिष्ठा और भत्तों के साथ पदों पर काम कर रहे होते हैं। इसलिए, उनमें से बड़ी संख्या में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाते और संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध होने में विफल रहते हैं।

राज्य सरकार केंद्र में राज्य सवर्ग के अधिकारी को तैनात करने में देरी करती है। इस से निपटने के लिए केंद्र राज्य के साथ परामर्श करने के लिए केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करे और बाद वाले अधिकारियों के नामों को पात्र बनाए। मौजूदा मानदंडों के अनुसार, राज्यों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त करना होता है और किसी भी समय यह कुल संवर्ग संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।

यदि राज्य आईएएस अधिकारियों की वफादारी पर संदेह करना शुरू कर देते हैं, तो वे आईएएस संवर्ग के पदों की संख्या और आईएएस अधिकारियों के उनके वार्षिक प्रवेश को भी कम कर सकते हैं। वे राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों को अधिक से अधिक पदों को संभालने के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। समय के साथ, आईएएस अपनी चमक खो देगा, और सबसे अच्छा और सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार अब कैरियर के रूप में आईएएस का चयन नहीं करेंगे। अदूरदर्शी निर्णय राजनीति को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अल्पकालिक उपाय के रूप में कुछ वर्षों के लिए सालाना भर्ती किए गए आईएएस अधिकारियों की संख्या को लगभग 200 तक बढ़ाया जाना चाहिए। सभी राज्यों में संवर्ग समीक्षा से कई आईएएस अधिकारियों को गैर-रणनीतिक पदों से मुक्त कर कमी को कम किया जाए। राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों से संबंधित फैले हुए केंद्रीय मंत्रालयों को कम करे, जिससे आईएएस अधिकारियों की मांग और राज्यों के दायित्वों में कमी आयेगी। राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों के लिए आईएएस में उनकी नियुक्ति और मसूरी में उनके प्रशिक्षण के तुरंत बाद उप सचिवों / निदेशकों के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कम से कम दो साल तक काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

वर्तमान में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपारदर्शी और मनमाने ढंग से होने के लिए बहुत बदनाम है। केंद्र को सीधे अपने संयुक्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों और सचिवों को आईएएस अधिकारियों में से 'प्रस्ताव पर' चुनना चाहिए, जो चयन की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकारों में समकक्ष ग्रेड में कार्य कर रहे हैं - उसी तरह जैसे वह उप सचिवों / निदेशकों को चुनता है। कैबिनेट सचिव सभी मुख्य सचिवों के साथ रचनात्मक बातचीत करके संकट को हल करे या प्रधान मंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इससे पहले कि चीजें हाथ से बाहर हो जाए। भारत जिस स्थिति का सामना कर रहा है, वह 1947 के समान है जब भारत ने अपने भारतीय सिविल सेवा के लगभग 60 प्रतिशत अधिकारियों, ब्रिटिश और मुस्लिम को खो दिया था, जब देश आज की तुलना में कहीं अधिक चुनौतियों से घिरा हुआ था। सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ दिखाई और कुछ वर्षों के भीतर ही प्रांतों के साथ काम करके इस कमी को पार कर लिया। सहकारी संघवाद की पवित्रता और राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक दक्षता के हितों की मांग है। ■

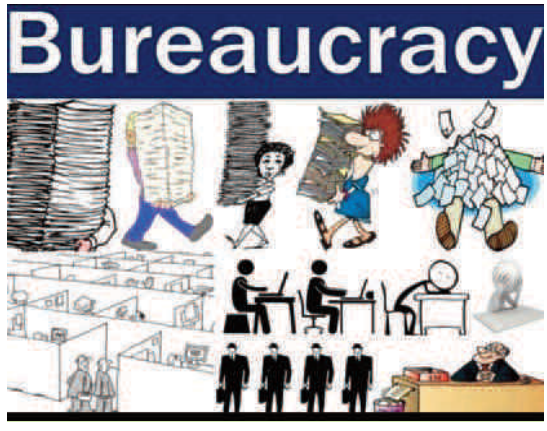

गहलोत का सियासी दर्द और पायलट की तिकड़म कांग्रेस के लिए भारी तो नहीं पड़ेगी?

● रामस्वरूप रावतसरे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कई बार सचिन पायलट खेमे की बगावत से पैदा हुए सियासी संकट का जिक्र कर चुके हैं। हाल ही में सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद रणनीति बदलाव के सवाल पर जवाब दिया कि इसी पर तो चर्चा हो रही है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष को फैसला करना है। सचिन पायलट के बयान के कुछ ही घंटों के बाद गहलोत ने सिविल सर्विसेज डे पर कल्चरल इवेंट में भाषण देते हुए फिर से बगावत को रिकॉल कर दिया। सियासी संकट के समय 34 दिनों तक क्या हुआ, कहां रहे ,सारी बातों को पुन: बता दिया। यह भी बताया कि वे लिखा कर लाये है। इसलिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बने है।

इस सबंध में सियासी पण्डितों का कहना है कि सचिन पायलट जब भी दिल्ली जा कर सोनिया गांधी या किसी कांग्रेसी नेता से मिलते है, तो अशोक गहलोत के दिल की धड़कन बढ जाती है। अन्दर का दर्द ना चाहते हुए भी उनके के मुखरबिंद से बाहर आ जाता है। गत दिनों सियासी संकट के समय क्या हुआ सभी को मालूम है। जिसे मालूम नहीं था या वह मालूम करना ही नहीं चाहता था। उसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जबरदस्ती बता दिया या बता दे रहे है। खैर दर्द को इस प्रकार बार बार बताना भी बहुत बड़ा सियासी दर्द के होने का संकेत है। जो कुशल सियासी डॉक्टरों के मध्य रह कर भी अपने आप को दर्द से दूर नहीं कर पा रहे है। फिर गहलोत साहब का यह पांच साला सफर लगभग पूरा होने में है। सदन में भी बहुमत का पूरा आंकड़ा है, फिर यह दर्द समय असमय क्यों उठ जाता है? क्या इस दर्द के रहते सरकार का पुन: आगमन हो सकेगा? इस पर कांग्रेसी नेताओं के ब्यान तथा उनकी गतिविधियां ही हालातों को स्पष्ट कर रही है।

हालांकि कांग्रेस के नेता यह कहते हुए नहीं अघाते है कि वे आगामी चुनावों में फिर सत्ता में आयेंगे। लेकिन इनके द्वारा सत्ता में आने के जो प्रयास किये जा रहे है उनमें इनके ही लोग सुराख कर रहे है। गत दिनों कांग्रेस का सदस्यता का अभियान चलाया गया। जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। राजस्थान में सत्ता में काबिज कांग्रेस के हालात भी किसी से छुपे नहीं है। पार्टी में मची खींचतान का असर चुनावों से डेढ़ साल पहले ही नजर आने लगा है। हाल ही में कांग्रेस के ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान ने पार्टी के हालातों की पोल खोलकर रख दी है। अपने आप को पार्टी के दिग्गज नेता कहलाने वाले कई मंत्री इस अभियान में 500 मेंबर भी नहीं जोड़ सके हैं।

अभियान में युवा नेताओं का प्रदर्शन सीनियर से बेहतर रहा है। 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस नेता 1000 मेंबर भी नहीं बना पाए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के क्षेत्र डीग-कुम्हेर में 266 और मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के क्षेत्र उदयपुरवाटी में केवल 130 मेंबर बने हैं। आरएलडी कोटे से मंत्री सुभाष गर्ग के क्षेत्र भरतपुर में कांग्रेस 471 मेंबर ही बना सकी है।

15 अप्रैल तक चले अभियान में कांग्रेस ने 19 लाख मेंबर बनाए हैं, लेकिन 100 विधानसभा क्षेत्रों में आंकड़ा पांच हजार से कम है। कई मंत्रियों के इलाकों में भी कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई है। 100 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़े नेता अब ऑफलाइन मेंबर जोड़कर साख बचाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 5000 से ज्यादा मेंबर बनाने वाले 100 विधानसभा क्षेत्रों का डेटा सार्वजनिक कर दिया, बचे हुए 100 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का परफॉर्मेंस कमजोर है।

कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली और ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के क्षेत्र से ज्यादा मेंबर बनाए हैं। टीकाराम जूली का क्षेत्र अलवर ग्रामीण चैथे और दिव्या मदेरणा का क्षेत्र ओसिया पांचवें नंबर पर है। ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान खत्म होने के बाद जारी की गई रैंकिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र सरदापुरा 11वें, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का क्षेत्र लक्षमणगढ सातवें और सचिन पायलट का क्षेत्र टोंक 59वें नंबर पर है। केवल 30 नेता ही ऐसे हैं जो 20 हजार से ज्यादा ऑनलाइन मेंबर बना पाए हैं।

कांग्रेस के केवल 30 नेता ही 20 हजार से

ज्यादा मेंबर बना पाए हैं। कांग्रेस के 100 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां के नेता पांच हजार से कम नए ऑनलाइन मेंबर जोड़ पाए हैं। दंगे वाले क्षेत्र करौली में कांग्रेस के केवल 735 मेंबर बने हैं। यहां से बसपा से कांग्रेस में आए लाखन सिंह मीणा विधायक है। बिजली कंपनी के एईएन से मारपीट के आरोपी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के क्षेत्र बाड़ी में कांग्रेस के 526 मेंबर बने हैं। सरकार से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक भरत सिंह के क्षेत्र सांगोद में कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान में केवल 140 मेंबर बने हैं। भरत सिंह विधानसभा के बजट सत्र में एक दिन भी विधानसभा नहीं आए थे।

15 अप्रैल तक डिजिटल मेंबरशिप अभियान में कांग्रेस ने 15 लाख का आंकड़ा पार किया है तो ऑफलाइन मेंबरशिप अभियान में 14 लाख का आंकड़ा पार कर के कुल 29 लाख सदस्य बनाकर अपनी लाज बचाने का काम किया है।

सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं। इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी युवा नेताओं को आगे बढ़ाने और सत्ता और संगठन में पद दिए जाने का सुझाव कांग्रेस आलाकमान को दिया था।

सूत्रों की माने तो पायलट और सोनिया गांधी के बीच हुई मुलाकात के बाद सचिन पायलट को संगठन में कोई बड़ा पद मिलने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें फिर से प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। चर्चा यह भी है कि उन्हें आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाकर भेजा जा सकता है। इससे पहले सचिन पायलट ने 8 अप्रैल को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। उस दौरान भी कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी थी। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद सचिन पायलट कैंप की बची हुई डिमांड को भी पूरा किया जा सकता है।

दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पिछले डेढ़ साल से बिना किसी पद के पार्टी में काम कर रहे हैं। वही राजस्थान में साल 2023 में

विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सचिन पायलट कैम्प चाहता है कि विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को आगे रखकर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए जिससे सरकार प्रदेश में फिर से रिपीट हो सके। सचिन पायलट भी लगातार दावा कर रहे हैं कि पहली बार राजस्थान में परंपरा टूटेगी और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आयेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पायलट की लोकप्रियता आज भी प्रदेशभर में बनी हुई है। यह लोकप्रियता तब है, जब पिछले साढ़े तीन वर्ष में सीएम गहलोत ने पायलट को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गहलोत आज भी पायलट पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हैं।

पायलट और उनके समर्थकों को अब यह भी समझना होगा कि प्रदेश कांग्रेस में असली हाईकमान अशोक गहलोत ही हैं। सोनिया गांधी तो खुद अशोक गहलोत से राय लेकर कांग्रेस को चला रही हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोग कांग्रेस को मजबूत करने की कितनी भी राय दे दें, लेकिन इन सभी रायों पर गहलोत की राय भारी है। यदि प्रदेश कांग्रेस में सचिन पायलट को आलाकमान द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दे दी भी जाती है तो, अशोक गहलोत का सियासी दर्द अब तक रह रह कर उठ रहा था। फिर लगातार दहाड़े मारेगा जो कि किसी भी रूप में कांग्रेस के पक्ष में नहीं होगा। इसलिए सोनियां गांधी और उनके सलाहकार पंजाब जैसी गलती राजस्थान में नहीं करेगें।

वर्तमान समय में जो हालात प्रदेश कांग्रेस के बने हुए है, उसके अनुसार आगामी चुनावों में कांग्रेस का पुन: सत्ता में आना एक स्वप्न सा लगता है। एक मंच पर आकर भी कांग्रेसी नेता एकजुट नही हो पाते है तो कार्यकर्ताओं से कितनी उम्मिद की जा सकती है। वैसे भी कार्यकर्ता को लम्बे समय तक बरगलाकर नहीं रख सकते, जहां धर्म और राष्ट्रवाद की आंधी चल रही हो। ■

सांबा में नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन की दिशाएं

● ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल ही में की गयी जम्मू-कश्मीर यात्रा पर इसलिए देश की निगाहें थीं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह पहली बार जम्मू-कश्मीर की धरती पर पहुंचे। उनकी इस यात्रा ने अनेक सकारात्मक संदेश दिये, शांति एवं विकास का माध्यम बना है। निश्चित ही उनकी यह यात्रा इस प्रांत में एक नई फिजां का सबब बनी है। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का वो गहना है जिसे जब तक सम्पूर्ण भारत के साथ जोड़ा नहीं जाता, वहां शांति, आतंकमुक्ति एवं विकास की गंगा प्रवहमान नहीं होती, अधूरापन-सा नजर आता रहा है। इसलिए इसे शेष भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण है और यह कार्य मोदी एवं उनकी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से वहां एक नया दौर शुरू किया है। इसके लिये जम्मू में मोदी ने पंचायत दिवस के अवसर पर केवल देश भर के पंचायत अधिकारियों को ही संबोधित नहीं किया, बल्कि इस केंद्र शासित प्रदेश की विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने के साथ कश्मीर एवं लद्दाख की जनता को भी यह संदेश दिया कि भारत सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अतीत की भूलों को सुधारना और भविष्य के निर्माण में सावधानी से आगे कदमों को बढ़ाना, हमारा संकल्प होना चाहिए। इसी संकल्प को मोदी ने सांबा के अपने उद्बोधन में व्यक्त किया है।

नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में किए गए कार्यों का विवरण देकर यह भी रेखांकित किया कि अब कैसे विकास एवं जनकल्याण के काम तेजी से हो रहे हैं? न केवल विकास योजनाएं आकार ले रही है, बल्कि वहां शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना है, आतंकवादी घटनाओं पर भी नियंत्रण किया जा सका है। मोदी की सरकार आने के बाद से जम्मू-कश्मीर के विकास को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सका है। सही समय पर केंद्र सरकार ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के साथ शेष वांछित कार्यों को पूरा करने के लिए वैसी ही दृढ़ता दिखाई है जैसी अनुच्छेद 370 हटाते समय दिखाई थी और देश के साथ दुनिया को यह संदेश दिया था कि कश्मीर में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं, कश्मीर भारत का ताज है और हमेशा रहेगा।

मोदी की कश्मीर यात्रा इसलिये महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि वहां के लोगों ने साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय-विखण्डन, आतंकवाद तथा घोटालों के जंगल में एक लम्बा सफर तय करने के बाद अमन-शांति एवं विकास को साकार होते हुए देखा है। उनकी मानसिकता घायल थी तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। इन स्थितियों के बीच मोदी ने वहां के लोगों का विशेषतकर युवाओं का इन शब्दों के साथ ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया कि आपके माता-पिता, दादा-दादी को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनका आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने इस वचन को पूरा करके दिखाएंगे। आशा की जाती है कि उनकी इन बातों का सकारात्मक असर पड़ेगा। वैसे भी बीते कुछ समय में वहां अनेक ऐसे विकासमूलक काम हुए हैं, जो पहले नहीं हुए। विकास की योजनाएं तीव्रता से आकार ले रही है, इनमें विदेश से निवेश भी शामिल है। गौर करने लायक बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री के साथ वहां गए प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के टॉप बिजनेस लीडर्स भी शामिल थे, जो जम्मू-कश्मीर में निवेश में खास रुचि ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूएई की कंपनियां वहां 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करने वाली हैं। जम्मू-कश्मीर के लिए यह निश्चित ही नई बात होगी। इन सबके माध्यम से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर में शांति और सौहार्द के साथ लोकतंत्र और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जम्मू-कश्मीर को अशांत और संवेदनशील क्षेत्र बनाए रखने की कोशिश में लगे तत्वों को सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे ही संदेशों से होती है।

जम्मू के सांबा क्षेत्र के एक छोटे से गांव पल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन एक उजाला है। शांति की स्थापना का संकल्प है। जनता को आश्वासन है विकास एवं आतंकमुक्त जीवन की ओर अग्रसर करने का। वहां की आम जनता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ एवं सौहार्द की

परिपक्वता दिखाई दे रही है। मोदी की यह यात्रा ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब यह प्रांत विभिन्न चुनौतियों से जूझकर बाहर आ रहा है। वहां के राजनीति के मंच पर ऐसा कोई महान् व्यक्तित्व नहीं है जो भ्रम-विभ्रम से प्रांत को उबार सके। वहां के तथाकथित संकीर्ण एवं पूर्वाग्रहग्रस्त नेतृत्व पर विश्वास टूट रहा है, कैसे ईमानदार, आधुनिक एवं राष्ट्रवादी सोच और कल्याणकारी दृष्टिकोण वाले प्रतिनिधियों का उदय हो सके, इस ओर ध्यान देना होगा। इस दिशा में मोदी की इस यात्रा की निर्णायक भूमिका बनेगी। नि:संदेह अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और यह बदलाव दिखने भी लगा है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना शेष है। जो घटनाएं हो रही हैं वे शुभ का संकेत नहीं दे रही हैं। घाटी में अशांति, आतंकवादियों की हताशापूर्ण गतिविधियां, सीमापार से छेड़खानी- ये काफी कुछ बोल रही हैं। वहां देर-सबेर और संभवत: परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव तो होंगे ही, लेकिन चुनाव कराने के पहले आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम लगाने की जो चुनौती है, उससे भी पार पाना होगा। तमाम आतंकियों के सफाये के बाद भी कश्मीर में जिस तरह रह-रह कर आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उनके चलते कश्मीरी हिंदुओं की वापसी फिलहाल संभव नहीं दिख रही। भले ही कुछ भी करना पड़े, इस काम को संभव बनाना होगा, क्योंकि तभी आतंकियों और उनके समर्थकों को यह संदेश जाएगा कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यह भी सर्वथा उचित होगा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएं।

मोदी की जम्मू यात्रा से कई उजाले हुए हैं। इस यात्रा से जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ यहां की स्थिति पर चिंता जाहिर करने वाले बाहर के लोगों को भी रोशनी की किरणें दिखाई दी है, यह शुभ एवं श्रेयस्कर है। यह तथ्य भी सामने आया कि राज्य में लोकतंत्र को जीवंत करने का एक बड़ा काम इस बीच बगैर शोर-शराबे के पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 20000 करोड़ रुपये से ऊपर की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दिया यह तथ्य इस मामले में ज्यादा प्रासंगिक है कि पिछले छह महीने में राज्य में 80 लाख पर्यटक आए हैं। बहरहाल, जम्मू-कश्मीर के साथ परेशानियों का पुराना सिलसिला रहा है। खास तौर पर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार भी सवालों के घेरे में हैं। 2018 से ही लगातार राष्ट्रपति शासन चल रहा है। ऐसे में शांति व्यवस्था और विकास संबंधी सरकार के दावों की भी असल परीक्षा इसी बात से होनी है कि वहां कितनी जल्दी विधानसभा चुनाव करवा कर निर्वाचित सरकार को शासन का जिम्मा सौंप दिया जाता है और लोगों को सामान्य लोकतांत्रिक माहौल मुहैया कराया जाता है।

भारत की महानता उसकी विविधता में है। साम्प्रदायिकता एवं दलगत राजनीति का खेल, उसकी विविधता में एकता की पीठ में छुरा भोंकता रहा है, घाटी उसकी प्रतीक बनकर लहूलुहान रहा है। जब हम नये भारत-सशक्त भारत बनने की ओर अग्रसर हैं, विश्व के बहुत बड़े आर्थिक बाजार बनने जा रहे हैं, विश्व की एक शक्ति बनने की भूमिका तैयार करने जा रहे हैं, तब हमारे जम्मू-कश्मीर को जाति, धर्म व स्वार्थी राजनीति से बाहर निकलना सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में घाटी को अग्रसर करने में मोदी सरकार के प्रयत्न सराहनीय एवं स्वागतयोग्य है। घाटी की कमजोर राजनीति एवं साम्प्रदायिक आग्रहों का फायदा पडोसी उठा रहे हैं, जिनके खुद के पांव जमीन पर नहीं वे आंख दिखाते रहे हैं। अब ऐसा न होना, केन्द्र की कठोरता एवं सशक्तीकरण का द्योतक हैं। राष्ट्र के कर्णधारों! परस्पर लड़ना छोड़ो। अगर तेवर ही दिखाने हैं तो देश के दुश्मनों को दिखाओ। ■

विदेशी चंदे पर मौलिक भारत के दृष्टिकोण पर उच्चतम न्यायालय की मुहर

FCRA 2020 में किये गए बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, कोर्ट ने अपने फैसले में विदेशी चंदे पर कई अहम टिप्पणियां कीं।

सुप्रीम कोर्ट ने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में 2020 में किये गए बदलाव को सही ठहराया है। इस बदलाव में विदेश से आर्थिक अनुदान लेने वाली संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वह स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में ही अपना प्राथमिक FCRA अकाउंट खोलें। इसके अलावा विदेशी चंदे को खर्च करने के तरीके पर भी नए नियम बनाए गए थे। कोर्ट ने अपने 132 पन्नों के फैसले में विदेशी चंदे पर कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि विदेश से चंदा पाना कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिस पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती है। यहा पूरी दुनिया में देखा गया है कि विदेशी दानदाताओं की मौजूदगी देश की आंतरिक नीतियों पर असर डाल सकती है। कोर्ट ने कहा कि देश विदेशी चंदे से नहीं नागरिकों के संकल्प से मजबूत होता है।

विदेशी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि देश में दानदाताओं की कमी नहीं। सामाजिक संस्थाओं को कोशिश करनी चाहिए कि उनसे मदद लें। सरकार को यह अधिकार है कि वह चाहे तो विदेशी अनुदान पर पूरी तरह रोक का भी कानून बना सकती है। FCRA में हुए बदलाव को नोएल हार्पर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने इसे अतार्किक और असंवैधानिक बताया था। उनका कहना था कि सामाजिक कार्यों के लिए विदेश से अनुदान लेने वाले संगठन देश भर में हैं। उन्हें एक ही बैंक की एक ही शाखा में अकाउंट खोलने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

विदेशी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव के तहत FCRA में जो अन्य प्रावधान जोड़े गए थे, वो ये हैं-

FCRA में जोड़े गए प्रावधान

- विदेशी चंदा पाने वाली संस्था उसे किसी और संस्था को ट्रांसफर नहीं कर सकती।
- अनुदान पाने वाली संस्था अपने प्रशासनिक कामों में अधिकतम 20 फीसदी ही खर्च कर सकती है। पहले यह सीमा 50 प्रतिशत तक थी। यानी संस्था विदेशी चंदे का आधा हिस्सा अपने प्रशासनिक खर्चे में दिखा सकती थी।
- FCRA के तहत पंजीकृत संस्था के मुख्य लोगों को आधार कार्ड का ब्यौरा देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस ए एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी टी रविकुमार की बेंच ने इन बदलावों को सही करार दिया। हालांकि, कोर्ट ने आधार कार्ड का ब्यौरा देने के नियम में रियायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि FCRA रजिस्टर्ड संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने पासपोर्ट का विवरण भी दे सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि मौलिक भारत का गठन विदेशी चंदे से खड़े किए गए देश विरोधी आंदोलनों के खिलाफ देश को जागृत करने एवं राष्ट्रवादी व सनातनी दर्शन पर आधारित नीतियो को लागू करवाने हेतु राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया था।

– मौलिक भारत

इससे अधिक संतुष्टि और कहाँ

नर सेवा - नारायण सेवा। नोएडा के धार्मिक रूप जागरूक व संवेदनशील अनेक प्रबुद्धजनों की पहल व सहयोग से निर्धन व अशक्त लोगों के लिए मौलिक भारत के 卐 मंदिर संकुल और सेवा अभियान 卐 के अंतर्गत 卐 माँ अन्नपूर्णा रसोई卐 नियमित रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर , सेक्टर 56, नोएडा में चल रही है जिसमें प्रतिदिन 400 से अधिक लोग दोपहर को निशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। जब भी समय मिलता है इस अभियान में कार सेवा अवश्य करता हूँ।आप भी जुड़ सकते हैं इस अभियान से ।

- मौलिक भारत

भूगोल
GEOGRAPHY
एक वैकल्पिक विषय (हिंदी माध्यम)
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS
By S.M.Zaki Ahmad
(Classes Every Friday & Saturday)
Register now and Avail 50% discount
Career Plus Online
CAREER PLUS online.com

इतिहास
एक वैकल्पिक विषय (हिंदी माध्यम)
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS
By करुणेश चौधरी सर
(Classes Every Friday & Saturday)
Register now and Avail 50% discount
Career Plus Online
CAREER PLUS online.com

ANTHROPOLOGY
By K Mukesh Sir
FREE SEMINAR
14th April Time: 4 PM
The best optional strategy for UPSC and all state PCS
New batch starts from
18th APRIL
Registration & admission started.
UPSC online classroom programme
COURSE FEATURES
Classes starts from basic and Focus on concept building
Reference notes to strengthen your Preparation.
Focus on writing skills development.
15 Tests and discussion.
Prior registration and admission is must.
To join classes download our app CAREERPLUSONLINE
Offline: 45000/-
Online: 29999/-
Offline & Online courses offered :
Anthropology foundation
Anthropology Main 2022
Anthropology crash course
Anthropology Test Series
Correspondence course
Q & A personalize guidance
Career Plus
EDUCATIONAL SOCIETY
A Legacy of 25 Years
44 SELECTIONS IN IAS 2020
H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Contact : 9310151465,9891186435, 9811069629,011-27654588
Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com

IAS, PCS
Career Plus Online
संस्कृत साहित्य
द्वारा- आर.सिंह
अद्यतन नोट्स, दो माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम
नया बैच प्रारंभ
दो दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला के साथ
(21 एवं 28 मार्च, समय 3 बजे से)
Quality Improvement Program for Old Students
Test Series Available
Career Plus
EDUCATIONAL SOCIETY
301/A, 37,38,39,3rd Floor, Ansal Building Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

लोक प्रशासन
Public Administration
एक वैकल्पिक विषय (हिंदी माध्यम)
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS
By HARUN SIR
(Classes Every Friday & Saturday)
Register now and Avail 50% discount
Career Plus Online
CAREER PLUS online.com

POLITICAL SCIENCE
राजनीति विज्ञान
एक वैकल्पिक विषय (हिंदी माध्यम)
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS
By SUDHIR SIR
(Classes Every Friday & Saturday)
Register now and Avail 50% discount
Career Plus Online
CAREER PLUS online.com

This issue Published on 1st May, 2022 Postal Registration No. G-3/DL (N)/252/2020-22, Postal dt. 1st & 2nd Every Month

R.N.I. No. - DELHIN/2009/30089

Career Plus People - Born to Lead

2022 IAS/PCS 2023

PRELIMS • MAINS • PRELIMS CUM MAINS

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi Medium

SUBJECTS AVAILABLE

GEN. STUDIES (for Prelims/Mains), CSAT & ESSAY

HISTORY | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY

POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION

SANSKRIT "LITERATURE" | HINDI "LITERATURE"

By Most Renowned & Competent Facilities under the Leadership & Direction of

Mr Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha

Silver Jublee Year (Since 1997)

Career Plus

English / हिन्दी Medium Hostel Facility

EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

Study Material & Test Series

44 SELECTIONS IN IAS 2020

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Mukherjee Nagar, Delhi-9

9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com